राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 04] पन्द्रहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का तैंतीसवां दिवस [संख्या: 13

मंगलवार,

25 फरवरी 2020

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री रामनारायण मीना।

मत्स्य अवतार दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की योजना

180. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में महापुरुषों तथा धार्मिक अवसरों से सम्बन्धित तिथियों को सार्वजनिक या ऐच्छिक अवकाश घोषित किये जाते हैं? यदि हां, तो किस आधार पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार मत्स्य अवतार दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या वर्ष 2020 में सार्वजनिक एवं ऐच्छिक अवकाश घोषित किये गये हैं? यदि हां, तो किस आधार पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) राज्य में महापुरुषों तथा धार्मिक अवसरों से सम्बन्धित तिथियों की आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए राज्य स्तर पर निर्णय लिया जाकर सार्वजनिक या ऐच्छिक अवकाश घोषित किये जाते हैं।

(2) हिन्दू धर्म के मत्स्य अवतार हेतु कोई अवकाश घोषित नहीं किया गया है।

(3) जी हां। वर्ष 2020 हेतु सार्वजनिक एवं ऐच्छिक अवकाश घोषित किये गये हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट “क” पर संलग्न है। उक्त अवकाश पूर्व

(ऊर्जा मंत्री)
वर्षों की भांति तथा सम्बन्धित दिवस के महत्व एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए घोषित किये गये हैं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, आज हमारी पार्टी शासन में है। उधर बैठे लोग हमारे ऊपर यह...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): एक सैकण्ड तो बोलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, प्रश्न पूछिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जब विष्णु भगवान के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार हैं, आप कृष्ण जयंती, दूसरी जयंती, क्रिश्चियन्स के भगवान की, नववर्ष की छुट्टी कर रहे हैं। ईसा मसीह की छुट्टी है, गुरू गोविंद सिंह दशम गुरू थे, उनकी छुट्टी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए, प्लीज।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): मेरा आपसे अर्ज करना है कि जो प्रथम अवतार हैं, नीचे वालों की आप छुट्टी कर रहे हैं, इस अवतार के बारे में आपको क्या कहना है? सरकार जब निर्णय लेती है, मुख्य मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, ये हिन्दू धर्म की आस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न नहीं है तो मैं अगला प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): आप कृपा करके एक तो इसका और दूसरा इस वर्ष घोषित करेंगे या नहीं करेंगे? अगले वर्ष घोषित करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया राज्य में 21 ऐच्छिक अवकाश घोषित किये हुए हैं, 29 सार्वजनिक अवकाश घोषित किये गये हैं। इनमें मत्स्य अवतार से सम्बन्धित न तो राजस्थान में बल्कि राजस्थान के आस पास किसी भी प्रदेश में अथवा हमारे देश के किसी भी हिस्से में अभी तक की सूचना के अनुसार कोई छुट्टी नहीं होती है। यह सूचना मैं इनको दे चुका हूं।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना

(श्री रामनारायण मीना)

चाहूंगा कि यह मंत्रिमंडल निश्चित करता है, विष्णु भगवान के प्रथम अवतार हैं, कोई घोषित करे या नहीं करे, राजस्थान सरकार के व्यूज क्या हैं? क्या हमारी भावना की सरकार कद्र करेगी, आदर करेगी, सम्मान करेगी?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो कई अवतार हैं लेकिन मुख्य रूप से दस अवतार माने गये हैं। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। अब इन दस अवतारों में से रामनवमी की, कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी वगैरह होती है। ऐसे तो और त्योहारों के बारे में भी लोग कहेंगे कि इन सारे अवतारों की छुट्टी करें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): कर रखी है, अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री मदन दिलावर।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10 फरवरी, 2020)

कोटा सम्भाग में मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा

2. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा सम्भाग के किस-किस जिले में पिलाई व रखवाली करते समय अक्टूबर, 2019 से फरवरी, 2020 तक कितने किसानों की मौतें कब और कैसे हुईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सर्दी में भी कृषि क्षेत्र में पिलाई हेतु बिजली रात्रि को देने से मौतें हुईं, यदि हां, तो मृतकों के परिजनों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) कोटा सम्भाग में माह अक्टूबर, 2019 से 18 फरवरी, 2020 तक झालावाड़ जिले में 03, बूंदी जिले में 02, बारां जिले में 01 एवं कोटा जिले में 02, कुल मिलाकर 08 किसानों की मृत्यु हुई है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) कोटा सम्भाग (कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी) में रात्रि को बिजली देने से पिलाई करते समय किसी की भी मौत सर्दी के कारण नहीं हुई है।

(स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)
परन्तु दिनांक 10.12.2019 को रामगंज मण्डी के सुकेत निवासी कंवरलाल की मृत्यु धनिया काटते समय ठंड के कारण शाम को 05.30 बजे तबीयत खराब होने पर रात्रि 09.30 बजे हुई है। ठंड लगने से मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता का प्रावधान मापदण्डों में नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): जिनकी आपने सूची दी है, इनको कितनी आर्थिक सहायता आपने दी? आपके मापदण्ड क्या हैं, स्पष्ट करें?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सुरेन्द्र कुमार, जिसकी मृत्यु हुई, वह विद्युत करंट लगने से हुई; रोडूलाल की सांप काटने से हुई, राजाराम की जहरीले कीड़े से हुई; रामेश्वर कुमावत की सर्पदंश से मृत्यु हुई; प्रहलाद धाकड़ की भी सर्पदंश से मृत्यु हुई; रामविलास, जो धाकड़खेड़ी, अंता तहसील के रहने वाले थे, की सिंचाई रखवाली करते समय मृत्यु हुई; हीरालाल निवासी सहरावदा, तहसील रामगंज मण्डी की सिंचाई करते हुए मृत्यु हुई और कंवरलाल निवासी सुकेत, इनकी भी खेत पर धनिया काटते समय मृत्यु हुई। रहा सवाल इस बात का कि इनको कितना-कितना पैसा दिया गया, सुरेन्द्र कुमार को 2 लाख, रोडूलाल को 2 लाख, राजाराम को 2 लाख, रामेश्वर कुमावत को 2 लाख, प्रहलाद धाकड़ को 2 लाख। अब रह गये बाकी के तीन आदमी। ये तीन आदमी, जो रामविलास रह गये, इन्होंने आवेदन ही नहीं किया, इनका कोई आवेदन मण्डी कमेटी को प्राप्त नहीं हुआ। रामगंज मण्डी के जो दूसरे हीरालाल थे, इनके परिजनों ने न तो एफ.आई.आर. दर्ज करवाई, न पोस्टमार्टम करवाया और न ही आवेदन दिया। इसी तरीके से कंवरलाल, इन्होंने आवेदन तो दिया लेकिन राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना की गाइड लाइन में कवर न होने की वजह से इनको कोई राशि नहीं मिल पायी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आपने, एक तो मैंने मापदण्ड पूछे थे, वे नहीं बताए। मैं जानना चाहता हूं कि आवेदन नहीं दिया तो ये नाम आपके पास कहां से आये? नाम आ गये तो स्वत: ही डिपार्टमेंट ने जाकर उनके आवेदन क्यों नहीं लिए?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): स्वत: ही जाने का कोई नहीं है लेकिन इनका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम से पता लगा, दोनों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आयी,

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही जानकारी मिली है। दूसरी बात, आपने पूछा कि राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अन्दर प्रावधान क्या हैं? प्रावधान तो बहुत लम्बे-चौड़े हैं। मैं आपको लिखकर दे दूंगा लेकिन सर्दी के कारण अगर कोई मौत होती है तो उसको कम्पन्सेशन नहीं दिया जाता। वजह यह है कि ये दुर्घटना होने पर तो देते हैं, सर्दी दुर्घटना नहीं होती। सर्दी में आप कपड़े वगैरह पहनकर जाओ, आराम से अंगीठी लेकर साथ में जाओ। दुर्घटना के दौरान होती, खेत में काम करते हुए।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुरेश टाक। माननीय सदस्य, प्लीज, अलाउ नहीं है। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: सब गम्भीर मामले हैं। बैठ जाएं प्लीज। तीन प्रश्न अलाउ हैं। मैंने तीन प्रश्न अलाउ कर दिये। अंकित नहीं होगा। Not allowed. बोलिए, श्री सुरेश टाक।

किशनगढ़ की गुंदोलाव झील पर बनी क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनर्निर्माण

181. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि किशनगढ़ कस्बे में स्थित संत नागरीदास पैनोरमा में पहुंचने के लिए गुंदोलाव झील पर बनी हुई पुलिया के क्षतिग्रस्त तथा जीर्ण-शीर्ण होने से विभाग द्वारा पुलिया से वाहनों एवं आमजन का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त झील पर नयी पुलिया के निर्माण हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गयी? क्या सरकार अब नयी पुलिया बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पैनोरमा पर पहुंचने हेतु नेशनल हाइवे नम्बर 8 से सड़क मार्ग भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। I will name you. I will deprive you. आप बाहर जाइए। अलाउ नहीं है। आप सीनियर होकर ऐसा करते हैं। आपने प्रश्न पूछा, जवाब दिलवा दिया। पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो क्या करेंगे? दूसरा प्रश्न लेकर आइए। प्रश्न में जैसा चाहेंगे वैसा होगा क्या? आप मापदण्ड पूछिए, मापदण्ड का अलग लेकर आइए। नहीं, अलाउ नहीं है। माननीय मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय, प्लीज। कटारिया जी, I will not set a wrong example, मैं नाम लूंगा आपका। I will name you. आप बाहर निकलिए। प्लीज, सब जाइए। आप सब जाइए। माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

उप मुख्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के अन्तर्गत किशनगढ़ कस्बे में स्थित संत नागरीदास पैनोरमा में पहुंचने के लिए गुंदोलाव झील पर क्षतिग्रस्त पुलिया होने के कारण माह मई 2019 से यातायात का प्रवेश निषेध किया गया है।

(2) उक्त झील पर नयी पुलिया के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा क्रमांक एफ 7(38)/ए & एफ/एसआरएफ/अनु-2/डी-446, दिनांक 11.09.2018, राशि रुपये 340.00 लाख की जारी की गयी थी। उक्त कार्य हेतु दिनांक 11.09.2018 एवं 17.12.2018 को दो बार निविदाएं आमंत्रित करने के उपरान्त भी किसी बोलीदाता द्वारा निविदा में भाग नहीं लिया गया। उक्त झील पर पुलिया निर्माण कार्य को पूर्ण करवाने का प्रयास किया जा रहा है।

(3) जी हां। यह सड़क क्षतिग्रस्त है। नेशनल हाईवे 8 (पुराना) से पैनोरमा जाने वाली सड़क का पुनर्निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कराया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आपसे कह दिया मैंने। Enough is enough.

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि सड़क का दो बार टेंडर हो गया, राशि कम होने की वजह से निविदादाता इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप अपनी जगह पर जाएं। बोलना है तो लीडर बोलेंगे, नहीं बोलना है तो वाक आउट करिए...(व्यवधान) कोई एडवोकेसी की जरूरत नहीं है। There is no need of advocacy.

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, सुरेश जी रुकिए। एक मिनट, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का पहले भी प्रश्न था, आज यह स्थगित प्रश्न के माध्यम से आया है। आठ लोगों की मृत्यु हुई है, इसको स्वीकार किया है। जिस विषय को लेकर कह रहे हैं कि उसके नोर्म्स में नहीं आता, मैं सोचता हूं कि ऐसा नहीं है। किसान अगर खेती करते समय, किसी भी कारण से, करंट लगने से, जानवर काटने से, या किसी और कारण से खेत में खेती करते हुए मरता है तो उसको निश्चित रूप से आपके कृषि विभाग का, मतलब जो मण्डी समिति है, उसको दो लाख रुपये देने का कानूनी अधिकार है। यह भी खेत में काम करते हुए मरा है। ठंड से मरा है, इसके कारण इससे अलग नहीं, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, अध्यक्ष जी, इतने नाराज मत होइए।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, मैं आपका सम्मान करता हूं। आपदा प्रबंधन के सम्बन्ध में नहीं है, कृषि के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा जाए, माननीय सदस्य को प्रश्न समझकर पूछना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये सीनियर मैम्बर हैं, फ्लाउट करें अध्यक्ष को, फिर आप एनकरेज करें, यह गलत है। यह प्रश्न आपदा प्रबंधन में था। आपदा प्रबंधन की गाइड लाइन में नहीं है, वह बता दिया। अलग प्रश्न उठाकर, उसका तरीका यही है। (व्यवधान) आप अध्यक्ष की व्यवस्था को इस तरह डिक्टेट करना चाहें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): बाकी लोगों को जो सहायता मिली, आपदा राहत के तहत नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, मैं खड़ा हूं, आप सीनियर हैं। आप बैठें तो। इस प्रश्न, पोस्टपोंड को मैंने उसी जगह लगवाया, यह पहली बार

(श्री अध्यक्ष)

परम्परा की है कि पोस्टपोंड आइटम को जिस जगह था, मैंने उस जगह लगवाया। यदि सरकार से उत्तर दिलाने की नीयत नहीं होती तो मैं दो नम्बर पर क्यों लगवाता। दो नम्बर पर था उसको पोस्टपोंड करवाया। प्रश्न आपदा प्रबंधन के सम्बन्ध में, आपदा प्रबंधन की जो गाइड लाइन है उसमें नहीं है, बात खतम हुई। (व्यवधान) आप एक लीडर को भी नहीं मान रहे। आप लीडर हैं या ये लीडर हैं? (व्यवधान) अगला प्रश्न। हो गयी बात। सुरेश टाक।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप नाराज मत होइए।

श्री अध्यक्ष: लीडर को ही नहीं मान रहे। House cannot be used, यह कोई तरीका है? आपकी लीडरशिप इश्यू को मैं डील करूंगा As a Leader of Opposition, I am giving you an opportunity. फिर खड़े हो जाते हैं, आप अपने लीडर को भी नहीं मानना चाहते। यह ठीक परम्परा नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछा गया है कि क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, यह कृषि में कवर होता है। यह आपदा का प्रश्न आपने माना होगा या क्या हुआ होगा, जो आप उत्तर दे रहे हैं उसमें आप बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। फिर खण्ड एक, खण्ड दो, इसका मतलब ऊपर के सात लोगों को जो पैसा मिला है वह कृषि विपणन बोर्ड से, अर्थात कृषि मण्डी से मिला है। यह आठवां व्यक्ति है, यह भी कृषि में ही कवर होता है, जैसे ऊपर सात कवर होते हैं, वैसे ही आठवां भी कवर होता है, तो आपने इसको "ना" कैसे लिखा?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आठ में से जिन पांच व्यक्तियों को दो-दो लाख रुपये दिये गये हैं। राजीव गांधी कृषक सहायता योजना, 2009 के अन्तर्गत दिये गये हैं। मैं यह लिस्ट आपके पास भेज देता हूं, इसमें आप अगर यह बता दें कि सर्दी के कारण कोई आदमी मरता हो तो उसको दिया जाता है, कम्पनसेशन दिया जाता है या नहीं दिया जाता। अगर आप यह बता देंगे तो मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूंगा। आपके पास यह लिस्ट भेज देता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। अगला प्रश्न, सुरेश टाक।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा उप मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस पुलिया निर्माण के दो टेंडर जारी हुए, आपने जवाब में लिखा, पर यह राशि कम होने की वजह से कोई भी निविदादाता इसमें भाग नहीं ले रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस राशि को बढ़ाकर क्या आप पुन: टेंडर लगा रहे हैं? आप क्या किशनगढ़ में नयी पुलिया निर्माण की सौगात देने जा रहे हैं?

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष जी, जैसा कि इस उत्तर में लिखा गया है, इस राशि के अन्तर्गत दो बार टेंडर फ्लोट किया गया, किसी भी व्यक्ति ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। सम्भवत: यह राशि कम हो सकती है। इसलिए मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले वित्तीय वर्ष में इसकी राशि बढ़ाकर दुबारा टेंडर करने का काम करेंगे।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): थैंक यू सर।

प्रश्न संख्या 182

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। अर्जुन लाल जीनगर।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री मेवाराम।

जोधपुर शहर में सीवरेज लाइन को शिफ्टिंग करवाने की योजना

183. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) **श्रीमती मीना कंवर** (शेरगढ़) के स्थान पर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में वर्षों पूर्व सीवरेज लाइन व सीवरेज होदी का निर्माण करवाया गया था? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सीवरेज लाइन व सीवरेज होदियों पर लगे हुए ढक्कन कहीं-कहीं सड़क लेवल से काफी ऊपर व कहीं-कहीं पर लेवल से काफी नीचे होने के कारण राहगीरों की सड़क दुर्घटना का कारण बन रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त सड़क के मध्य से सीवरेज लाइन व सीवरेज होदियों को हटवाकर सड़क से अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय ऊर्जा मंत्रीजी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अर्जुन जीनगर ने बोल दिया क्या?

श्री अध्यक्ष: मेवाराम जी पूछ रहे हैं।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): 183.

श्री अध्यक्ष: 183. माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, आपको जवाब देना है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): स्वायत्त शासन देंगे।

श्री अध्यक्ष: ऊर्जा का है, आपको जवाब देना है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): धारीवाल साहब देंगे।

श्री अध्यक्ष: हां, धारीवाल साहब।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नींद में हैं। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरा नाम आते ही क्या उचकचीटी होती है आपके?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्लीज। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। जयपुर शहर की बसावट के पश्चात् सर्वप्रथम 1935 में सीवर लाइन व सीवरेज होदी बनायी गयी थी। सीवर लाइन व सीवरेज होदी के कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जोधपुर है, जयपुर बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वे कह रहे हैं आप जयपुर बोले या जोधपुर?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां साहब?

श्री अध्यक्ष: खण्ड एक आपने स्टार्ट किया वह जोधपुर शहर से किया या जयपुर शहर से? (व्यवधान) प्लीज, अब आप ही बोलें तो फिर मेरा काम खतम है। आप इसका जवाब वापस स्टार्ट करें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दुबारा बोलूं? (व्यवधान) क्या हो गया?

श्री अध्यक्ष: जोधपुर देखकर जयपुर याद आ गया, आप तो शुरू करो। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जोधपुर के नाम से ही घबराहट चालू हो जाती है। (व्यवधान) जोधपुर वालों के सामने बैठने से तो पता नहीं और क्या हो जाता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): काम की बात करो। (व्यवधान) क्या मजाक है?

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप इन लोगों को समझाओ न...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: धारीवाल साहब, चेयर की तरफ एड्रेस कीजिए, मेरी शक्ल ठीक है। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी बहुत, it's too much. माननीय मंत्रीजी, प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) जी हां। जोधपुर शहर की बसावट के पश्चात् सर्वप्रथम 1935 में सीवर लाइन व सीवरेज होदी बनायी गयी थी। सीवर लाइन व सीवरेज होदी के करवाये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। सीवर लाइन की होदियों के ढक्कन सड़क मरम्मत के दौरान सड़क के लेवल के बराबर नहीं लिए जाने के कारण सीवर लाइन के ढक्कन रोड लेवल से नीचे/ऊपर रह जाते हैं। जोधपुर शहर में लगभग 91,500 सीवरेज के ढक्कन हैं। जिनमें से सर्वे कर लेवल से ऊपर/नीचे 858 सीवरेज ढक्कनों को रोड के लेवल में किया जा चुका है। जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर अंकित है। नगर निगम द्वारा प्रत्येक वार्ड में ढक्कनों को लेवल करने का कार्य निरन्तर रूप से किया जाता रहता है।

(3) जी नहीं। जोधपुर शहर में सीवरेज लाइन लगभग 1,300 किमी. से अधिक है। सड़क के दोनों साइडों की तरफ पानी, बिजली व अन्य सुविधाओं की लाइनें सड़क के नीचे हैं तथा सभी मैनहोल में प्रोपर्टी कनेक्शन भी किये हुए हैं। विभिन्न सड़कों की चौड़ाइयों तथा विभिन्न आवश्यक जन सुविधाओं की लाइनें सड़क के नीचे होने से सीवर लाइन को रोड की साइड में करवाया जाना सम्भव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्रीजी से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि सीवरेज लाइन में होदी व ढक्कन रोड लेवल से नीचे

(श्री मेवाराम जैन)
हैं, काफी तो हटा दिये हैं, बाकी वाले कब तक हटा देंगे, क्योंकि उससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। कब तक हटाएंगे?

मेरा दूसरा प्रश्न है, अगर रोड के दूसरी साइड सीवरेज लाइन के होदी व ढक्क्न को चेंज कर दिया जाए तो दुर्घटनाएं होने से बच सकती हैं व सीवरेज लाइन ठीक हो सकती है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बाबत निवेदन कर चुका हूं कि सड़क के दोनों साइड पानी, बिजली व अन्य सुविधाओं की लाइनें सड़क के नीचे हैं। सभी मैनहोल्स में प्रोपर्टी कनेक्शंस भी किये हुए हैं। विभिन्न सड़कों की चौड़ाई, विभिन्न आवश्यक जन सुविधाओं की लाइन सड़क के नीचे होने के कारण सीवर लाइन को रोड की साइड में नहीं किया जा सकता, एक बात।

दूसरा सवाल यह था कि कब तक क्या हो जाएगा और क्या-क्या हो रहा है? ढक्कनों को रोड लेवल तक मरम्मत करने हेतु प्रत्येक वार्ड में पांच लाख रुपये अर्थात् कुल राशि 325 लाख रुपये के कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं, जिसके तहत आवश्यकतानुसार जोधपुर शहर में सीवरेज लाइन के ढक्कनों को परिवर्तित करने का कार्य किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सतीश पूनियां।

बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति पर अनुदान

184. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे -

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पानी की कमी के कारण सरकार द्वारा बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति पर अनुदान दिया जा रहा है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति पर फसलवार, उम्रवार एवं माहवार सिंचाई तकनीक की सिफारिशें जारी की गयी हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रेगिस्तानी क्षेत्र बीकानेर एवं जैसलमेर के धोरों में बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति अपनाने को प्रोत्साहन देने हेतु नहर का अधिक पानी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) जी हां। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति पर अनुदान दिया जा रहा है। विभिन्न कृषक श्रेणी व विभिन्न सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर देय अनुदान का विवरण परिशिष्ट "1" पर अंकित है।

(2) जी नहीं। बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति पर फसलवार, उम्रवार एवं माहवार सिंचाई तकनीक की सिफारिश राज्य में कृषक के खेत व क्षेत्र विशेष की मृदा संरचना व संघटन, जलवायु तथा पानी की गुणवत्ता अलग-अलग होने से राज्य स्तर से सिफारिश जारी नहीं की जाती है बल्कि योजना क्रियान्वयन दिशा-निर्देश के अनुसरण में संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा कृषक के मृदा एवं जल परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर तकनीकी-आर्थिक प्रतिवेदन तैयार कर समय-सारणी के साहित्य की प्रति कृषक विशेष को उपलब्ध करायी जाती है।

(3) बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति के प्रोत्साहन हेतु संयंत्र स्थापन पर प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत लघु-सीमान्त कृषकों व अन्य कृषकों को क्रमश: 70 व 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। जल संसाधन विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार रेगिस्तानी क्षेत्र बीकानेर एवं जैसलमेर के धोरों में बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति अपनाने पर अधिक पानी दिये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाह रहा हूं कि वर्ष 2019-20 के दौरान कौन-कौनसे जिलों में कितने ड्रिप स्वीकृत किये गये और उनके भुगतान का विवरण क्या है? इसमें नये और पुराने कितने हैं?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019-20 में 80 हजार हैक्टेयर का लक्ष्य था। इसमें 50 हजार हैक्टेयर में तो फव्वारा और 30 हजार हैक्टेयर में ड्रिप लगाया गया। प्रगति रिपोर्ट यह है कि 30 हजार हैक्टेयर में फव्वारा लग चुका है और 15 हजार हैक्टेयर एरिये में ड्रिप लगाया जा चुका है और बाकी कार्य मार्च तक प्रगति पर हैं। जिलेवार सूची मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): अध्यक्ष महोदय, इसमें राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना, आर.ए.सी.पी. की कितनी राशि किन-किन जिलों में स्वीकृत की गयी है?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अलग

(श्री लालचन्द कटारिया)

से है। आर.ए.सी.पी. का जो विवरण आपने मांगा है, मैं आपको आज ही उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री शंकर सिंहजी रावत।

जवाजा (ब्यावर) में पट्टी, कातलों पर काश्तकारों से रॉयल्टी वसूलने पर रोक की कार्ययोजना

185. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र ब्यावर की पंचायत समिति जवाजा के आसपास के काश्तकारों द्वारा अपने खेतों के आसपास उपलब्ध पट्टियों, कातलों और मोडिया से अपने मकान बनाने तथा उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलायी जा रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त काश्तकारों से वर्तमान में रॉयल्टी वसूल की जा रही है जो कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बंद कर दी गयी थी? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल) (श्री प्रमोद भाया के स्थान पर): (1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र ब्यावर की पंचायत समिति जवाजा में खनिज पट्टी कातला (फिलाइट सिस्ट) का कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं होने से खनिज पट्टी कातला/मोडिया का खनन अनुमत नहीं है। अत: काश्तकारों द्वारा उक्त खनिज का उपयोग मकान बनाने अथवा इसे बेचकर आजीविका चलाया जाना वैध कृत्य नहीं है।

(2) जी नहीं। उक्त क्षेत्र में खनिज पट्टी कातला (फिलाइट सिस्ट) का कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं होने से वर्तमान में रॉयल्टी वसूल नहीं की जा रही है। पूर्व में भी किसी भी सरकार द्वारा खनिज पट्टी कातला/मोडिया पर रॉयल्टी में छूट प्रदान नहीं की गयी है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, पिछली किसी भी सरकार ने तो यह चालू नहीं की लेकिन पिछले विधान सभा बजट सत्र के अन्दर माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया था कि वह काश्तकार जो अपना मकान बनाने के लिए ट्रैक्टर ले जाते हैं, उन पर किसी प्रकार की रॉयल्टी लागू नहीं होगी। यह आदेश भी दिया। अभी तक क्रियान्विति नहीं हो रही है। किसान ऐसे

(श्री शंकर सिंह रावत)

ही लुटते जा रहे हैं। उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं तो यह जवाब चाह रहा हूं। क्या उनसे ऐसे ही रॉयल्टी वसूल करेंगे पुलिस के द्वारा?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वहां अभी कोई खनिज नहीं है, न रॉयल्टी का कोई ठेका है। इस तरह की रॉयल्टी ठेका, पट्टी कातला ले जाने को अवैध खनिज माना गया है इसलिए इस तरह की कोई व्यवस्था पिछली सरकार में भी नहीं थी, मैंने विभाग से जानकारी ली है, इस तरह की कोई घोषणा मंत्रीजी ने पहले नहीं की।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सर, यह रिकार्ड पर है। मैं असत्य नहीं बोला। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड पर है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जांच करेंगे, दिखवा लेंगे आपकी बात को। जांच करवा लेंगे।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): आप दिखवा लीजिये। माननीय भाया साहब थे मंत्रीजी, उन्होंने जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री फूल सिंह मीणा।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): जवाजा में सरकार की रॉयल्टी वसूल नहीं हो रही।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात की जांच करवा लेंगे।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): आप रोक लगाने के लिए जवाब दिला दीजिये, साहब।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी कह रहे हैं, पहले आपने कहा उसकी जांच करवा लेंगे, फिर बात करेंगे। बैठ जाएं।

अगला प्रश्न। श्री फूल सिंह मीणा।

उदयपुर ग्रामीण में नवीन गैस एजेंसी खोलने की योजना

186. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में जनवरी, 2020 तक ऐसे कितने परिवार हैं जो गैस कनेक्शन से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नयी गैस एजेंसी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में वर्तमान में आवेदन करने वाले 840 परिवार गैस कनेक्शन से वंचित हैं। एजेंसीवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में 22 गैस एजेंसियां कार्यरत हैं तथा 58,181 गैस कनेक्शंस जारी हैं। नयी गैस एजेंसी खोलने के क्रम में राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल कम्पनियों के अनुसार उदयपुर जिले की गिर्वा एवं बड़गांव तहसीलों की कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट लम्बित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं खण्ड-एक में, कि 840 परिवारों को कनेक्शन कब तक मिलेगा? साथ ही, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 58,181 लाभार्थी हैं, केवल एक ऐसी एजेंसी है नूतन गैस, उसके पास में 19,900 गैस कनेक्शंस हैं क्योंकि वह विशेष वजूद रखती है। अध्यक्ष महोदय, उसमें 32 कनेक्शंस ऐसे हैं, जो कनेक्शन जिनके नाम पर बोल रहा है, गैस की टंकी उनके पास नहीं जा रही है। 14 कनेक्शंस ऐसे हैं, जिनकी टंकी गोदाम से निकल रही है, उनको पता तक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, इस गैस एजेंसी के बारे में जो डाइरेक्ट ऑनलाइन से उनके आधार कार्ड लेकर उन्होंने उनका सत्यापन कर लिया वे ऐसे कनेक्शंस उठा रहे हैं। क्या मंत्री महोदय, इसकी जांच करके उस गरीब आदिवासी जनता को न्याय दिलाया जाएगा या नहीं, पहला प्रश्न।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपने यह सवाल किया है कि 840 गैस कनेक्शन से वंचित हैं, उनको पास की गैस एजेंसियों से समीक्षा करके जुड़वा देंगे।

दूसरा, आपने नूतन गैस एजेंसी के बारे में 19 हजार से ऊपर गैस कनेक्शंस की बात कही है। इसकी हम जांच कराने के बाद में, यदि अनियमितताएं पायी जाती हैं, तो हमारे पास जो कार्यवाही है, हम जांच कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, बाकी का अधिकार भारत सरकार को है। हम कोई निरस्त नहीं कर सकते, ज्यादा उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते। हम भारत सरकार को लिखेंगे और जो हमारी पावर है, हम नोडल डिपार्टमेंट हैं,

(श्री रमेश चन्द मीना)

तो उस हिसाब से जो कार्यवाही कर सकते हैं और भारत सरकार को लिखा जाएगा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, दूसरे खण्ड में मैंने यह पूछा है कि क्या नयी एजेंसी खोलने का विचार रखते हैं? क्योंकि ट्राइबल एरिया है और अगर नहीं खुलती है तो क्या यह गैस एजेंसी, उनको होम डिलीवरी करने का ऐसा पाइंट चिह्नित करेगी या नहीं?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): फिजिबिलिटी के आधार पर खोला जाएगा, जो भारत सरकार के नार्म्स हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी रिफिल की स्थिति क्या है। आपकी जो स्थिति ग्रामीण की है, अति दुर्गम है तो 600 पर है, ग्रामीण में वैसे ढाई हजार पर है तो हम यह भारत सरकार से अनुरोध करेंगे कि आपके यहां गैस एजेंसी खुले।

श्री अध्यक्ष: कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह जो आपकी श्याम एच.पी. गैस एजेंसी है, इसी के पास 804 पैंडिंग एप्लीकेशंस हैं। बाकी एक भी गैस एजेंसी के पास पैंडिंग नहीं है। दूसरा, जो फिगर आपने दिया है, कुछ एजेंसियां ऐसी हैं, जिनके पास 80 कनेक्शंस हैं, किसी के पास 349 हैं, किसी के पास 866, 219, 500, ये गैस एजेंसियां कैसे सर्वाइव करती होंगी। एक गैस एजेंसी के पास 19,000 कनेक्शंस हैं, दूसरी के पास 80 कनेक्शंस हैं, ये आखिर किस तरह से गैस एजेंसियां सर्वाइव कर रही हैं और कैसे चल रही हैं? एक ही एजेंसी के पास 804 गैस कनेक्शंस पैंडिंग हैं, ये कब से पैंडिंग हैं, इतने लम्बे समय तक एक ही एजेंसी के पास? बाकी सबने जीरो कर दिया, फिर इसी के पास पैंडिंग होने का क्या कारण है?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने जो सवाल किया है, फाइंडिंग का तो, जो गैस एजेंसियां हैं, जो पूरा टोटल आया है, श्याम एच.पी. के पास में तो यह हम इसमें दिखवा लेंगे। कहां पर कितनी, जहां ज्यादा संख्या है, पुरानी गैस एजेंसियां हैं, वे पहले से उनके पास रिफिल हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, एक मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट। आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जब आप क्वेश्चन जांचते होंगे, तब आपके मन में भी यह सवाल तो आता होगा कि केवल और केवल 804 पैंडिंग हैं, वे भी केवल एक के हैं, तो क्यों हैं, यह प्रश्न तो आपके दिमाग में खड़ा ही हुआ होगा। जब लिस्ट आपने देखी होगी तो एक के पास 80 कनेक्शन, एक के पास 19,000 कनेक्शंस हैं, तो यह कैसे सम्भव हो रहा है, यह कैसे हो रहा है?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह एक साल से नहीं है। ये पहले से ही हैं, आज की बात नहीं है। आपने भी, आप यह कह रहे हैं कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, प्रश्न आता होगा। माननीय नेता, प्रतिपक्ष, हम एक कमेटी बनाकर, आपको जो लग रहा है न, जांच करा लेंगे। जो अनियमितता होगी, हम यहां पर पेश कर देंगे, जो भी रिपोर्ट होगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अशोक डोगरा।

बूंदी बस स्टैण्ड के अन्यत्र स्थानान्तरण की कार्ययोजना

187. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार बूंदी जिला मुख्यालय पर स्थित रोडवेज बस स्टैंड को सुव्यवस्थित तरीके से बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त बस स्टैंड को वर्तमान स्थान से अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी हां। यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, बूंदी में आधुनिक सुविधायुक्त बस स्टैंड का निर्माण करवाना चाहती है किन्तु निगम की वर्तमान वित्तीय स्थिति के मद्देनजर निगम के वित्तीय स्रोतों से निर्माण कार्य वर्तमान में सम्पादित करवाया जाना सम्भव नहीं है।

रोकड़ तरलता एवं वित्तीय साध्यता होने पर निगम के जिला मुख्यालय, बूंदी के बस स्टैंड पर सुव्यवस्थित तरीके से निर्माण कार्य करवाए जा सकेंगे।

(2) जी नहीं। बूंदी बस स्टैंड को वर्तमान स्थान से अन्यत्र स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा और इनसे यह अनुरोध है कि ये बूंदी जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं तो बूंदी जिले में जाते होंगे तो एक बार बस स्टैंड की भी हालत देखें कि बस आती है तो इतनी धूल उड़ती है कि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। गिट्टी ऐसे उछलती है कि लोगों का माथा भी फूट जाता है। आप तो यह बता दें कि पिछले दस वर्षों में निगम ने कितना पैसा बूंदी बस स्टैंड के रखरखाव के लिए दिया है?

दूसरा, आपने यह कहा कि पैसे की सुगमता पर यह किया जाएगा तो यह कितने दिन में कर दिया जाएगा?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने विधायकजी को पत्र लिखा है और इनसे यह कहा है कि आप अपने कोटे से दस-दस लाख रुपये देकर रोडवेज बस स्टैंड के लिए वहां पर खर्च करें, ताकि रोडवेज बस स्टैंड ठीक हो सके और ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप भूतपूर्व मंत्री रहे हैं और आप बैठे-बैठे बोल रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): बूंदी बस स्टैंड का मैंने खुद ने दौरा किया है, आप उसको अन्यत्र स्थानांतरित करवाना चाहते हैं। वह अन्यत्र स्थानांतरित इसलिए नहीं हो सकता कि वहां के मास्टर प्लान में रोडवेज बस स्टैंड के लिए वह जगह निर्धारित है। वहां पर वह कलेक्ट्रेट के पास में है, कचहरी के पास में है, मिड में है तो आप उसको क्यों बाहर निकालना चाहते हैं? वहां की जनता तो बाहर भेजना ही नहीं चाहती। तीन किलोमीटर दूर आप उसको ले जाना चाहते हैं। मैं खुद बूंदी बस स्टैंड का दौरा करके आया हूं।

मैंने सब माननीय सदस्यों से यह रिक्वैस्ट की है कि आप दस-दस, बीस-बीस लाख रुपये लगाइये, आप ही के क्षेत्र का बस स्टैंड है। नयी बसें हम लेकर आ गये हैं, उस अड्डे को सुधरवाने की जिम्मेदारी आप लो और आपके लिए वहां पर नयी बसें हम भेजेंगे।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जो विधायक कोष की बात कर रहे हैं, वहां पर पीने के लिए पानी भी नहीं था, मेरे विधायक कोष से ही ट्यूबवैल लगा है। वहां पर बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी तो मेरे विधायक कोष से कुर्सियां और बैंचेज लगवायी हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछें।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): मेरे पिछले कार्यकाल में दस लाख रुपये का

(श्री अशोक डोगरा)

काम मेरे द्वारा हुआ है और मैं अभी भी दस लाख रुपये और देने को तैयार हूं लेकिन मंत्रीजी यह बताएं कि निगम की तरफ से वहां पर कितना पैसा खर्च कराएंगे?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय सदस्य को मैं धन्यवाद दूंगा। आप इस दस लाख रुपये को तो 25 लाख रुपये कर दो। दस लाख रुपये को 25 लाख रुपये करने के साथ, मैं इतना कह सकता हूं कि यह जो बस स्टैंड पर खर्चे की बात कर रहे हैं, अभी रोडवेज प्रबंधन ने सबसे बड़ा एक फैसला लिया है कि हम रोडवेज की 876 नयी बसें लेकर आये हैं। इलेक्ट्रिक बसें लेकर आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्रश्न का जवाब दें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इनको आप टोकते ही नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: यह काम मेरा है। मेरा काम आप कर लें। आप मंत्री रहे हैं। Can you force a Minister? Can you force him? आप खुद मंत्री रहे हैं। माननीय मंत्रीजी, बूंदी का प्रश्न है, नहीं हो सकता तो यह बात कह दीजिए, बात खतम। अगला प्रश्न। श्री रामलाल शर्मा।

नवीन प्राथमिक विद्यालयों को भूमि आबंटन

188. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में प्रदेश में नवीन प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितने-कितने प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सभी विद्यालयों के लिए भूमि आबंटन कर दी गयी है? यदि हां, तो किन-किन प्राथमिक विद्यालयों की भूमि आबंटन की गयी है? यदि नहीं, तो किस-किस विद्यालय को किन-किन कारणों से भूमि का आबंटन नहीं किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त नवीन प्राथमिक विद्यालयों के लिए वर्ष 2019-20 में सरकार द्वारा बजट आबंटन किया गया है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा परिवर्तित बजट घोषणा 2019-20 में 50 नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गयी, जिसमें से शैक्षिक सत्र 2019-20 में कुल दो नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका जिलेवार विवरण निम्नानुसार है-

जिला	ब्लाक	विद्यालय का नाम
सीकर	लक्ष्मणगढ़	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कुमास जाटान
बांसवाड़ा	आनंदपुरी	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कुण्डफला ढोढिया

(2) उक्त नवीन खोले गये प्राथमिक विद्यालयों में से राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुमास जाटान, ब्लाक लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर को भूमि आबंटित की जा चुकी है।

राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुण्डफला ढोढिया, ब्लाक आनंदपुरी, जिला बांसवाड़ा वर्तमान में असेफा भवन में संचालित किया जा रहा है। भूमि आबंटन के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं।

(3) नवीन प्राथमिक विद्यालयों हेतु कार्यरत शिक्षकों के वेतन हेतु एकमुश्त राशि आहरण वितरण अधिकारी को जारी की जाती है।

नवीन प्राथमिक विद्यालयों के ढांचागत (इन्फ्रास्ट्रक्चर्ल) सुविधाओं के विकास हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार आवश्यक प्रस्ताव समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत आगामी वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2020-21 में भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाएंगे।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने पिछले बजट भाषण के अन्दर यह घोषणा की थी कि इस सत्र के अन्दर 50 नये प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे और आपने जवाब दिया है कि आपने सिर्फ दो स्कूल खोले हैं। एक आपने अपने विधान सभा क्षेत्र में खोला है और एक बांसवाड़ा में खोला है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो भी प्राथमिक विद्यालय मर्ज किये थे, वे नियमानुसार किये थे और यदि वे नियमानुसार मर्ज नहीं किये थे तो आप हमेशा यह आरोप लगाते हो कि 20 हजार प्राथमिक स्कूल बंद कर दिये तो आप 20 हजार प्राथमिक विद्यालय कब तक खोलने का विचार रखते हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने प्रश्न का विस्तार करके बहुत अच्छा किया। मैं यह जवाब देना चाहता हूं कि आपने 22,200 स्कूल मर्ज या बंद करने का काम किया, जिनमें से 2,450 तो आपने स्वयं ने ही वापस उनको डी-मर्ज कर दिया। आज की तारीख में भी 19,754 विद्यालय हैं जो भवन बिलकुल इनको बददुआएं दे रहे हैं कि हमारा क्या होगा? हमारे बच्चे उस भवन में नहीं पढ़ सकते। (व्यवधान) आप बैठिए-बैठिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आप चालू कर दो न।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी भी मैं यह कहना चाहता हूं कि जयपुर जिले में भी 1,324 विद्यालय भवन खाली पड़े हैं, बंद करने के कारण से। एक मिनट, आपके चौमूं में भी 97 भवन खाली पड़े हैं और हमने प्रस्ताव मंगवाये हैं कि आपने जो गलतियां कीं राजस्थान के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की, हम उनके प्रस्ताव मंगवा चुके हैं और यह जब सेशन चालू होने वाला है, उसमें वे सारे विद्यालय, जितने आर.टी.ई. नोर्म्स के विपरीत बंद किये हैं, वे खोलने का काम करेंगे। आपके विधान सभा क्षेत्र में भी आठ-नौ प्रारम्भिक विद्यालय वापस खोलने के प्रस्ताव हैं, अगर वहां पर बच्चे होंगे तो वे इसी सत्र में, इसी अप्रैल-मई में वापस खोलने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यहां पर बहुत जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सोचता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपसे ही सीखा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): धीरे-धीरे, आराम से, शांति से।

आपको वर्ष 2019-20 का बजट केवल और केवल राजस्थान में शायद पहली बार 50 स्कूल खोलने के लिए दिया और उसमें से भी आपने नहीं खोले तो क्या आपके पास पैसा उपलब्ध नहीं था या आपके पास स्टाफ उपलब्ध नहीं था या आप यह निर्णय नहीं कर सके कि ये 50 स्कूल कहां खुलेंगे। इससे ज्यादा मैं यह सोचता हूं, स्कूल खोलने के प्रति, इतनी सहृदयता आपने दिखायी कि 50 में से केवल दो खोले और केवल 30-35 दिन ही अब पूरे साल के बाकी रह गये हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता, प्रतिपक्ष ने यह पूछा कि आप विद्यालय नहीं खोलना चाहते। अगर हम विद्यालय नहीं खोलना चाहते तो हम क्यों तो जिला कलेक्टर के यहां पर कमेटी बनाते? क्यों हम एस.डी.ओ. के यहां पर कमेटी बनाते? आपके समय में जितने प्रारम्भिक विद्यालय आर.टी.ई. नोर्म्स के विपरीत बंद कर दिये...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप तो इसका जवाब दे दो कि आप ये क्यों नहीं खोल पाये? आप तो इसका जवाब दो कि पचास में से केवल दो खोले और 48 क्यों नहीं खोल पाये? इसका जवाब चाहिए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): इसी का दे रहा हूं। यह था नये भवन का। जब 19,754 भवन खाली पड़े हैं तो फिर नये भवन बनाने की आवश्यकता कहां पड़ गयी? हम खोल देंगे जहां पर भी बच्चे होंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): आज 19,754 भवन खाली पड़े हैं, उनमें विद्यालय खोलेंगे। विद्यालय भवन की आवश्यकता कहां पर पड़ गयी? अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हमारी सरकार तत्काल बजट उपलब्ध कराएगी, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री समारामजी। समारामजी, एक मिनट।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्रीजी से यह सीधा प्रश्न है मंत्रीजी, आप तो ये बता दो कि आपने प्रस्ताव मंगवा लिए, ये प्रस्ताव आप पांच साल तक मंगवाते रहेंगे क्या? आप एक डेट निर्धारित कर दो कि इतनी तारीख तक आर.टी.ई. नोर्म्स के खिलाफ अगर गलत बंद किये हैं तो उनको खोल दोगे, आप यह बताओ न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलकुल ठीक बात है। आर.टी.ई. नोर्म्स के विपरीत आपने जो बंद किये हैं और जिनमें 15 से भी अधिक प्रारम्भिक विद्यालय में छात्र होंगे और एक किलोमीटर से दूर होंगे उनको इसी सेशन में खोलने का काम करेंगे, एक भी बंद नहीं रहने देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री समाराम गरासिया।

सालगांव बांध परियोजना की क्रियान्विति

189. श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में सालगांव बांध परियोजना की DPR लगभग रुपये 250 करोड़ की तैयार हुई थी जो अब तक क्रियान्वित नहीं हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना को क्रियान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): जल संसाधन विभाग द्वारा माउण्ट आबू के पेयजल समस्या के निराकरण हेतु सालगांव बांध परियोजना का प्रशासनिक तखमीना राशि रुपये 250.54 करोड़ का दिनांक 19.06.2018 को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को स्वीकृति हेतु भिजवाया गया है। परियोजना की क्रियान्विति, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उपरान्त की जानी प्रस्तावित है।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने बढ़िया जवाब दिया। मेरा आपसे यह निवेदन है कि प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति कब तक निकलेगी? पूरे प्रदेश में हिल स्टेशन आबू पर्वत एक ही है जहां पर देश-विदेश के लोग आते हैं। आप कब तक स्वीकृति निकालेंगे?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 24 अप्रैल, 2019 को जल संसाधन विभाग ने जलदाय विभाग को इसकी स्वीकृति हेतु लिखा है। आगामी नीति निर्धारण समिति में इसे विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा और साधनों की उपलब्धता के अनुसार इस पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मदन दिलावर।

रामगंज मण्डी में ग्रामीण विकास योजनाओं का बकाया भुगतान

190. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में विगत 5 वर्षों में ग्रामीण विकास की कैटल शेड योजना, अपना खेत अपना काम तथा खेत में तलाई का निर्माण योजनान्तर्गत स्वीकृतियां जारी की गयी थीं? यदि हां, तो क्या उनका अब तक भुगतान नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मदन दिलावर)

(2) उपरोक्त बकाया का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

(3) क्या यह भी सही है कि कतिपय प्रकरणों में आवेदक के आधार कार्ड सक्रिय न होने अथवा बैंक खाता संख्या गलत होने के कारण भुगतान नहीं हो पाया है? यदि हां, तो ऐसे कितने प्रकरण हैं? उक्त को अब कब तक भुगतान कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उप मुख्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में गत 5 वर्षों में ग्रामीण विकास की महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कैटल शेड योजना, अपना खेत अपना काम तथा खेत में तलाई निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गयी हैं।

उनमें से 15 कार्यों की राशि रु. 4,69,996/- का भुगतान भारत सरकार से महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सामग्री मद में राशि प्राप्त नहीं होने के कारण अभी तक बकाया है। प्रकरणवार आवेदक का नाम, पता, बकाया राशि का विवरण परिशिष्ट “1” पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त बकाया राशि का भुगतान भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर नियमानुसार कर दिया जाएगा।

(3) जी हां। कोटा जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में पंचायत समिति लाडपुरा में 10, पंचायत समिति खैराबाद में 260, कुल 270 अकुशल श्रमिकों का भुगतान आधार कार्ड सक्रिय न होने, बैंक खाता संख्या गलत एवं खाता बन्द होने के कारण नहीं हो पाया है। उक्त श्रमिकों के कई बार एफ.टी.ओ. जनरेट किये गये, लेकिन एफ.टी.ओ. बार-बार रिजेक्ट हुए। उक्त श्रमिकों के खाता संख्या एवं आधार कार्ड प्राप्त किये जाकर भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से इन दो वर्षों में कब-कब राशि प्राप्त हुई? क्या आपने उनका समायोजन कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर भेज दिया और कितनी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजना शेष है?

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी में लाना चाहता हूं कि जब यह प्रश्न पूछा गया था, उस समय आपके विधान सभा क्षेत्र में 270 श्रमिकों का भुगतान बकाया था। कभी आधार कार्ड गलत होता है, कभी खाते का नम्बर गलत होता है,

(श्री सचिन पायलट)

लेकिन आज आपकी जानकारी में बता रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका प्रश्न रामगंज मण्डी का है और पूछ रहे हो राजस्थान का। वे रामगंज मण्डी का जवाब दे रहे हैं।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आपने जब प्रश्न लगाया था तब 270 लेबर का पेमेंट ड्यू था बिकोज आफ आधार कार्ड या बैंक खाता। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि आज वह संख्या शून्य है। सब लोगों का भुगतान कर चुके हैं। आपने भारत सरकार के बारे में पूछा है तो भारत सरकार के 1,377 करोड़ रुपये बकाया हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कोशिश करें कि जो गरीब श्रमिक हैं, जो काम कर चुके हैं, 1,377 करोड़ रुपये जो मैटीरियल कम्पोनेंट है, वह भारत सरकार का बकाया है। जहां तक लेबर का प्रश्न है, 17 फरवरी, 2020 तक लेबर कम्पोनेंट की हण्डरेड परसेंट पेमेंट हो चुकी है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो भारत सरकार ने सामग्री मद में पैसा दिया था, आपने उन सबका उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया क्या? और भेजा तो कब भेजा?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्लीज, रामगंज मण्डी से कहां पहुंच गये। अगला प्रश्न। (व्यवधान) I will not allow you, आप मंत्री रहे हो। (व्यवधान) मंत्री रहे हो आप। श्री अविनाश, अगला प्रश्न। प्लीज, आपका रामगंज मण्डी का प्रश्न है, 270 श्रमिकों का पेमेंट हो गया, फिर आप वहां जा रहे हैं, प्लीज।

प्रश्न संख्या 191

अगला प्रश्न। श्री अविनाश।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में पेयजल की उपलब्धता

192. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री वासुदेव देवनानी)

(1) क्या यह सही है कि अजमेर विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं में पेयजल हेतु नई पाइप लाइन बिछाने व उच्च जलाशयों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता है? यदि हां, तो कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पेयजल योजनाओं के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त आवासीय कालोनियों में पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) अजमेर विकास प्राधिकरण की निम्न आवासीय योजनाओं में नयी पाइप लाइन बिछाने व उच्च जलाशयों के निर्माण की आवश्यकता है:-

1. पृथ्वीराज नगर
2. डी.डी. पुरम्
3. महाराणा प्रताप नगर
4. तबीजी अफोर्डेबल योजना (राईजिंग लाइन की आवश्यकता है)
5. पंचशील ई-ब्लाक
6. विजयाराजे सिंधिया नगर

(2) अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न पत्र जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को लिखे गये:-

पृथ्वीराज नगर	पत्र दिनांक 17.05.2010, 07.12.2015
डी.डी. पुरम्	पत्र दिनांक 21.05.2014, 26.05.2015
महाराणा प्रताप नगर	पत्र दिनांक 07.12.2015
तबीजी अफोर्डेबल योजना	पत्र दिनांक 09.01.2015, 04.06.2015
पंचशील ई-ब्लाक	पत्र दिनांक 23.07.2019
विजयाराजे सिंधिया नगर	पत्र दिनांक 29.07.2019

(3) अजमेर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में पेयजल व्यवस्था का कार्य डिपोजिट वर्क के तहत पी.एच.ई.डी. से ही कराया जाता है। उपरोक्त योजनाओं में पूर्व में तखमीने की राशि अत्यधिक होने के कारण प्राधिकरण

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

द्वारा अनेकों पत्रों के माध्यम से लिखा भी गया है। पी.एच.ई.डी. से अभी संशोधित तखमीने प्राप्त नहीं हुए हैं। तखमीने प्राप्त होने पर प्राधिकरण द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ए.डी.ए. की इन आवासीय योजनाओं में कितने लोग आबंटी हैं, उनसे कितनी राशि वसूल की गयी है और इन योजनाओं में तकनीकी राशि कितनी-कितनी है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कुल मिलाकर छह योजनाएं हैं। अब छह योजनाओं में प्लाट की राशि तो मूल ली ही जाती है, जब प्लाट दिया जाएगा तो अलग-अलग प्लाट की अलग-अलग राशि है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): कुल कितनी राशि?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह मेरे पास फिगर्स नहीं हैं, यह फिगर्स मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। लेकिन हर योजना के अलग-अलग प्लाट की अलग-अलग रिजर्व प्राइस होती है। उसी हिसाब से पैसा लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पेयजल पर पूछो, कहां जा रहे हो आप?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब सवाल यह है, आपने पूछा पृथ्वीराज नगर योजना, यह योजना 2007 में चालू की गयी थी। कुल मिलाकर वहां पर 2007 से लेकर अभी तक सिर्फ 7 मकान बने हैं और उसमें भी 5 मकानों में ही रहवास है। नम्बर-दो डी.डी. पुरम्, यह 2012 में प्रारम्भ की गयी थी, इसमें भी सिर्फ 5 मकान बने हुए हैं, जिनमें रहवास नहीं है। महाराणा प्रताप योजना, यह 2001 में हमारे वक्त में हमने चालू की थी। इसमें 185 मकान बने हुए हैं। 185 मकानों में आंशिक रूप से पानी की सप्लाई पी.एच.ई.डी. के द्वारा आज भी दी जा रही है। इसी प्रकार तबीजी अफोर्डेबल योजना, यह 2011 में हमारे ही द्वारा चालू की गयी थी। यह निजी विकासकर्ता की योजना थी। विकासकर्ता के द्वारा काम अधूरा छोड़ दिया गया। इस योजना में कोई रहवास नहीं है। इसके बाद पंचशील योजना आती है। पंचशील योजना 2016 में प्रारम्भ की गयी। इसमें भी आज तक कोई रहवास नहीं है। दिनांक 23.09.2019 को हमने फिर पत्र लिखा है पी.एच.ई.डी. को, ताकि वह अपना संशोधित तखमीना भेजे। हम इस पर काम शुरू कर चुके हैं। विजयाराजे सिंधिया, यह 2008 में आपने

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)
चालू करवायी, लेकिन इसमें कोई रहवास नहीं है। 29.07.2019 को हमने ही पी.एच.ई.डी. को संशोधित तखमीना भेजने के लिए लिखा है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो लोग कैसे रहेंगे। 2010 से लगातार 2019 तक ए.डी.ए. केवल पत्र-व्यवहार करता रहेगा तो वहां के लोगों की पानी की समस्या का कब तक समाधान होगा? यह ए.डी.ए. और पी.एच.ई.डी. का विषय है लेकिन इसके साथ जनता उसको भुगत रही है। इस प्रश्न का उत्तर आप दिलवाएं क्योंकि वास्तव में ये 2010 से पत्र लिख रहे हैं। पत्र लिखने का काम सरकार का है या उसका समाधान करने का काम भी सरकार का है। फिर कालोनियां क्यों बनायीं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह बात सही है कि पत्र लिखे गये हैं क्योंकि उन्होंने जो तखमीना बनाकर दिया था, वह संशोधित करने के लिए पत्र लिखे हैं। तखमीने में रकम ज्यादा आ रही थी। वहां पर उतनी रकम बनती नहीं थी लेकिन ताज्जुब यह है कि जब यह प्रश्न आपका आया तब मैंने इसको देखा तो अजमेर डवलपमेंट ऑथोरिटी में पानी के लिए कोई इंजीनियर ही नहीं है इसलिए पी.एच.ई.डी. पर आधारित रहना पड़ता है। यह सारा का सारा काम तो श्रीमान्, आपका था।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह किसका काम है, सबका काम है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह आपका काम था। आप पांच साल तक शासन में रहे। आपने अजमेर डवलपमेंट आथोरिटी का सत्यानाश कर दिया। आपके टाइम पर ये सारी की सारी योजनाएं पूरी हो सकती थीं। जो हमारे वक्त में भी चालू हुईं उनको भी आपने पूरा नहीं किया और आपके वक्त में जो चालू हुई आप वे भी पूरा नहीं कर पाये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): पांच साल आप भी रहे। अभी भी सवा साल से आप हैं तो यह "आप" और "हमारे" के चक्कर में पी.एच.ई.डी. और ए.डी.ए. दोनों के झगड़े हैं। पी.एच.ई.डी. के मंत्री बैठे हैं, आप दोनों मिलकर समाधान क्यों नहीं करते। आखिर अजमेर की जनता कब तक त्राहि-त्राहि करेगी?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हम तो समाधान करने में लगे हुए हैं लेकिन आपने पांच साल क्या किया? (व्यवधान) आपने पांच साल तक क्या किया? यह तो आप ही की कांस्टीट्युएंसी का सवाल है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 2010 का सवाल है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पानाचन्द मेघवाल।

पशु चिकित्सालयों में विभिन्न संवर्गों के रिक्त पद

193. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में प्रदेश में कितने पशु चिकित्सालय और उप केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के कई सरकारी पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों और कर्मचारियों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला बारां में कई पशु चिकित्सा उप केन्द्र बन्द हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे व क्यों?

(4) वर्तमान में प्रदेश के पशु चिकित्सालयों में कौन-कौनसी दवाएं नि:शुल्क उपलब्ध करवायी जा रही हैं तथा जिला बारां में विगत एक वर्ष में कौन-कौनसी दवाइयां उपलब्ध करवायी गयीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पशुओं के लिए जीवनरक्षक दवाओं का अभाव है? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या सरकार जिला बारां में चिकित्सकों व अन्य पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) वर्तमान में प्रदेश में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रदेश की पशु चिकित्सा संस्थाओं में पशु चिकित्सा कर्मियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(3) जी हां। बारां जिले में वर्तमान में स्टाफ के अभाव में अक्रियाशील पशु चिकित्सा उप केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट "3" पर संलग्न है।

(पशुपालन मंत्री)

(4) पशुपालन विभाग द्वारा वर्तमान में पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजनान्तर्गत उपलब्ध करवायी जा रही औषधियों का विवरण परिशिष्ट "4" पर उपलब्ध है।

बारां जिले के पशु चिकित्सालयों में गत एक वर्ष से उपलब्ध करवायी गयी औषधियों का विवरण परिशिष्ट "5" पर संलग्न है।

(5) जी नहीं।

(6) जी हां। रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): अध्यक्ष महोदय, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी के पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार से नि:शुल्क दवा योजना लागू की गयी थी, चाहे वह मनुष्य के लिए हो या पशु के लिए हो, मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिस प्रकार से मनुष्य की दवाओं में वृद्धि की है, क्या आप पशुओं के इलाज के लिए जो नि:शुल्क दवा योजना लागू की गयी है, उसमें भी कुछ दवाएं बढ़ाने का प्रयास करेंगे?

नम्बर दो, बारां जिले में चाहे डाक्टर हो, कम्पाउंडर हो या नर्सिंग स्टाफ हो, जो पद लम्बे समय से रिक्त हैं क्या उनको प्राथमिकता के आधार पर भरने का प्रयास करेंगे?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, गत सैशन या बजट सत्र था उसमें ही पशुओं की दवाओं में पहले वृद्धि कर दी गयी, सरकार द्वारा 138 तरह की दवाएं नि:शुल्क की गयी हैं। जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि बारां जिले में अभी हाल ही में 2,100 पशुधन सहायकों की जो नयी भर्ती हुई है उसमें से 38 आपके बारां जिले में लगाये जा चुके हैं। 24 पशु चिकित्सक कोर्ट में केस जीत कर आये हैं, उनमें से दो की भर्ती आपके यहां बारां जिले में कर दी गयी है।

रही आपके अटरू विधान सभा क्षेत्र की, उसमें गत माह में 15 पशुधन सहायकों की नियुक्ति की जा चुकी है। आपके दो उप केन्द्र खोले जा चुके हैं जिनमें से आठ में, पुराने जो थे, उनकी भी भर्ती कर दी गयी है।

मैं सदन के हमारे सभी सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि जो गत घोषणा की गयी थी उसमें 400 उप केन्द्र इस बार मार्च तक खोलने हैं और 400 अगले साल खोलने हैं। किसी भी माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में

(श्री लालचन्द कटारिया)

यदि अभी वर्तमान में नहीं खुले और जहां अप्रैल के बाद में खोलने हैं वे दे सकते हैं, वहां सभी जगह खोल दिये जाएंगे। नि:शुल्क दवा दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री चेतन सिंह चौधरी।

नागौर की पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान

194. श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर मे कितनी गौशालाएं पंजीकृत हैं? वर्तमान में गौशालाओं में किस-किस पशु पर कितना-कितना अनुदान दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में क्या सरकार गौशालाओं को दिये जा रहे अनुदान को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आवारा पशुओं हेतु नन्दीशालाओं के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो उक्त योजना में उक्त जिले में कितने आवेदन प्राप्त हुए व उनमें से कितने स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया) (श्री प्रमोद भाया (गोपालन मंत्री) के स्थान पर): (1) नागौर जिले में कुल 576 गौशालाएं पंजीकृत हैं।

पात्र गौशाला में आवासित बड़े गौवंश हेतु 40 रुपये तथा छोटे गौवंश हेतु 20 रुपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम 180 दिवस की सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है।

(2) वर्तमान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 से सहायता राशि की दरों में वृद्धि की जा चुकी है। पूर्व में बड़े गौवंश हेतु 32 रुपये तथा छोटे गौवंश हेतु 16 रुपये की दर से सहायता दी जा रही थी, जिसको वित्तीय वर्ष 2019-20 में बढ़ाकर क्रमश: 40 रुपये तथा 20 रुपये किया जा चुका है।

(3) परिवर्तित बजट 2019-20 में सरकार द्वारा आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नन्दीशालाएं स्थापित करने बाबत घोषणा की गयी।

योजनान्तर्गत अभी तक आवेदन नहीं मांगे गये हैं।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा अक्टूबर, 2019 में मंत्रीजी ने बीकानेर में यह घोषणा की कि जो 184 दिन का अनुदान है, उसको बढ़ाकर 275 दिन का करवा दिया जाएगा। क्या मंत्रीजी या सरकार यह मंशा रखती है कि गौशालाओं को 275 दिन का अनुदान दिया जाए?

दूसरा, खण्ड 3 में मुझे जो जवाब दिया गया कि योजना अन्तर्गत अभी तक आवेदन नहीं मांगे गये हैं, मैं आपके सम्मुख मंत्रीजी को यह बताना चाहूंगा कि मेरे पास एक पत्र है कार्यालय, संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, नागौर, क्रमांक: 5338, दिनांक 12.09.2018, इसकी बैठक कार्यवाही विवरण में दो नम्बर बिन्दु यह बोलता है, मूल्यांकन के आधार पर पशुपालन विभाग द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था हेतु बनाये गये नागौर कार्य क्षेत्र के लिए समिति द्वारा सर्वसम्मति से दादू दयाल गौशाला एवं जीवदया ट्रस्ट, रूण का नन्दी गौशाला संचालन हेतु चयन किया गया। नम्बर तीन, मूल्यांकन के आधार पर पशुपालन विभाग द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था हेतु कुचामन सिटी कार्यक्षेत्र के लिए बनायी गयी समिति द्वारा सर्वसम्मति से एक ही संस्था द्वारा आवेदन करने के कारण श्री गोपाल गौशाला, डीडवाना का नन्दी गौशाला संचालन हेतु चयन किया गया।

जब जवाब यह आ रहा है कि योजना अन्तर्गत अभी तक आवेदन नहीं मांगे गये तो यह चयन कैसे कर लिए गये? साहब, बड़ा भारी अव्यवस्था का आलम है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसी जानकारी माननीय सदस्य दे रहे हैं, वह मेरे पास नहीं है। जिस गौशाला का आपने जिक्र किया है उसका पत्र आप मुझे दे दें, मैं इसको आज ही दिखवा लेता हूं।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): साहब, 2019 मैं चयन कर लिया गया।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): हां, मैं वही कह रहा हूं। मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। मैं इसको आज ही दिखवा कर, जो भी कार्यवाही होगी, आपको अवगत करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राजेंद्र राठौड़।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अपात्रताधारियों द्वारा रियायती दरों पर ली गयी खाद्य सामग्री की जांच

195. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत सरकारी कर्मचारियों व संविदा कर्मचारियों द्वारा गरीबों को मिलने वाले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत गेहूं रियायती दरों पर लिए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित अपात्र लाभार्थियों की जांच के बाद सरकार इनसे अनुदानित दरों पर ली गयी खाद्य सामग्री की राशि वसूलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वंचित पात्रताधारी का नाम जोड़ने व अपात्र के नाम हटाने हेतु कोई अभियान चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत सरकारी कर्मचारियों द्वारा रियायती दरों पर राशन सामग्री प्राप्त करने की शिकायतों पर की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। अपात्र लाभार्थियों की जांच के बाद नियमानुसार बाजार दर से स्थापित नियमों के अन्तर्गत विहित प्रक्रिया द्वारा शीघ्र वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूचियों में जोड़ने एवं अपात्र व्यक्तियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाये जाने के लिए सतत अपीलीय प्रक्रिया दिनांक 05.11.2015 से लागू है। विभागीय आदेश दिनांक 06.11.2019 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में अंकित अपात्र व्यक्तियों का सत्यापन कार्यक्रम राज्य में चलाया जा रहा है। सत्यापन कार्यक्रम के परिणामों के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची से हटाना प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने परिशिष्ट 'अ' के अन्दर जो सूची दी है, उसमें कालम 2 में लिखा है एन.एफ.एस.ए. लिस्ट के सत्यापन के दौरान पाये गये सरकारी कर्मचारियों की संख्या। मतलब जो लोग सरकारी कर्मचारी होते हुए भी एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत लाभ ले रहे थे उनकी संख्या 17,453 है और आपने इसी में कहा कि इस लिस्ट में जिन कर्मचारियों के नाम हटाये हैं उनकी संख्या 5,963 है। मेरा पहला सवाल है कि जब आपके सामने यह बात आ गयी 17,453, तो इनके नाम क्यों नहीं हटाये? नम्बर एक बात।

नम्बर दो बात, आपने खण्ड दो में कहा है कि इनकी जांच के बाद इनसे नियमानुसार बाजार दर से वसूली करेंगे। आप वसूली करेंगे, पर कंडक्ट आफ सर्विस रूल्स में, इन्होंने तथ्य छिपाकर जो लाभ लिया है, क्या आप इनके विरुद्ध सी.सी.ए. 16 के अन्दर भी कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे या नहीं?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सबसे पहले, माननीय उप नेता महोदय, मैं बताना चाहूंगा, आपने कहा कि 5,963 के खिलाफ कार्यवाही की गयी है, यह प्रक्रियाधीन है, जांच कर रहे हैं कि व्यक्ति का नाम वास्तव में किसी और ने जुड़वा दिया हो, डीलर ने जोड़ लिया हो क्योंकि अभी अलवर में एक ऐसा वाकया आया था जिसमें पूर्व कलेक्टर, जो जिला जयपुर रह चुके हैं, उनका नाम भी इस खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल था, उन्होंने एक बार भी गेहूं नहीं लिया। तो बायोमेट्रिक सत्यापन कौन ले रहा है, डीलर ले रहा है या कोई अन्य व्यक्ति ले रहा है, या परिवार के लोग ले रहे हैं, इसकी हम समीक्षा करवा रहे हैं। और भी जो लोग हैं, यह संख्या तो छोटी है, अभी हमने रेंडम रूप से किया है, प्रक्रिया लगातार चलेगी, इसमें और भी लोग निकलेंगे। क्योंकि हम आप लोगों की तरह नहीं कर रहे हैं, आप लोगों ने एक साथ 80 लाख लोगों के नाम काट दिये। हम वास्तव में जो अपात्र व्यक्ति है, उसको नोटिस दे रहे हैं कि आपका नाम है, नहीं तो हम पी.डी.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही करेंगे, आपसे वसूली करेंगे, विभाग को कार्यवाही के लिए लिखेंगे। हम यह सारी प्रक्रिया कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल किया कि जब आपके सामने 17,453 का नाम आ गया तो आपने इनको हटाया क्यों नहीं? नम्बर एक बात। नम्बर दो बात, आप जांच की प्रक्रिया कब पूरी कर लेंगे?

मंत्री महोदय, क्या यह सही है कि दिसम्बर, 2018 से लेकर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दिसम्बर, 2019 तक आपने राजस्थान के अन्दर इस जांच के नाम पर 64,470 लोगों के नाम हटाये हैं? क्या यह सही है या गलत है?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 64 हजार लोगों के नाम नहीं हटाये हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कितने हटाये हैं, बता दो।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अपने आप ही, समावेशन की श्रेणी में जो लोग नहीं आते हैं, स्वत: ही...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, अगर मेरा फिगर गलत है तो बता दो कितने हैं, सही कर दो। (व्यवधान)

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अभी बता रहा हूं, आपको हटाने का बता रहा हूं। हटाये हुए नाम हैं हमारे पास, 3 लाख 68 हजार 354 लोग हैं, जो हटाये गये हैं। ये स्वत: ही हट रहे हैं जो समावेशन की श्रेणी से ऊपर आ चुके हैं और हमारे पास जोड़े गये नामों की जो संख्या है, 31 लाख 53 हजार 720, ये नाम हमने एक साल के अन्दर जोड़े हैं। (व्यवधान) फिगर देख रहा हूं मेरे पास।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। सुश्री दिव्या मदेरणा।

शहीदों के आश्रितों के लिए की गयी घोषणाओं का क्रियान्वयन

196. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत पांच वर्षों में प्रदेश में कितने सैनिक शहीद हुए? नाम व पदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा शहीदों के परिवारों के लिए क्या-क्या घोषणाएं की गयीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शहीदों के आश्रितों के सम्बन्ध में की गयी उक्त घोषणाओं के क्रियान्वयन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सैनिक कल्याण मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) विगत पांच वर्षों में प्रदेश में कुल 82 सैनिक शहीद हुए हैं।

नाम, पदवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(सैनिक कल्याण मंत्री)

(2) सरकार द्वारा शहीदों के परिवारों के लिए की गयी घोषणाओं का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) जी हां। शहीदों के आश्रितों के सम्बन्ध में की गयी घोषणाओं के क्रियान्वयन की कार्यवाही सतत प्रक्रिया के तहत सम्पादित की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:

1. श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर के वार्ड नम्बर 25 में गंदे पानी की निकासी न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से सिरोही जिले के घरट में शिक्षा कर्मी नानाराम गरासिया की बेटी को कालेज द्वारा दिये गये नोटिस के बाद श्री गरासिया द्वारा आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3. श्री राजकुमार रोत एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राजकीय महाविद्यालय, सीमलवाड़ा में भवन के अभाव में छात्रों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।
4. श्री गोपीचन्द मीणा एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से कोटड़ी पंचायत समिति में प्रधान पति द्वारा नियमित बैठकों का संचालन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
5. श्री सुभाष पूनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में कथित तौर पर शराब माफियाओं की शिकायत करने पर पुलिस द्वारा 72 वर्षीय पूर्व सैनिक के साथ बेरहमी से मारपीट किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6. श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की पंचायत समिति सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी एवं झल्लारा के सरपंचों को विकास अधिकारियों के कारण कार्य करने में आ रही बाधा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

7. श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं में पेयजल की गम्भीर समस्या से कानून व्यवस्था बिगड़ने की सम्भावना के सम्बन्ध में।

8. श्री सुमित गोदारा, सदस्य की ओर से बीकानेर जिले में शिक्षा विभाग में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक के पद पर कार्य जूनियर अधिकारी द्वारा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9. श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के पावा से कोथेलाव व भाचुन्दा जाने वाले मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

10. श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के पशुपालकों की 150 भेड़ों को निम्बाहेड़ा क्षेत्र में लुटेरों द्वारा लूटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. श्री फूलसिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की ग्राम पंचायत बलीचा के उच्च माध्यमिक विद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

12. श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से राजस्थान पत्रिका समूह के सिविल लाइन्स स्थित एक परिसर में दर्जनों पुलिस कर्मियों द्वारा तलाशी की कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

13. श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती में पदों की कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

14. श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली में विद्यालय भवनों के जीर्ण-शीर्ण होने से जनधन की हानि होने की आशंका के सम्बन्ध में।

15. श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से प्रदेश में फेल्सपार खनिज को अवैध रूप से राज्य से बाहर ले जाए जाने से सरकार को करोड़ों रुपये की राजस्व हानि होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

16. श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से आर.पी.एस.सी. द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक भर्ती, 2013 में रिक्त रहे 1211 एस.सी./

(श्री अध्यक्ष)

एस.टी. के रिक्त पदों को 2018 एल.डी.सी. भर्ती में नहीं जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

17. श्री रामप्रसाद एवं एक अन्य सदस्य की ओर से अनुसूचित क्षेत्रों में माइक्रो फाइनेंस कम्पनियों द्वारा आदिवासी महिलाओं के समूहों को मंहगी ब्याज दर पर ऋण देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

18. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से प्रदेश के अफीम उत्पादक कृषकों के डोडा-चूरा को सरकार द्वारा नष्ट किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

19. श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से प्रदेश में बजरी के अवैध परिवहन में लगे वाहनों की वजह से बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती अनिता भदेल, श्री रामप्रसाद, श्री चन्द्रभान सिंह आक्या एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ को उनके प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में बरसात के पानी का संग्रहण करने हेतु हर घर में पोण्ड बनवाए जाने के सम्बन्ध में।

2. श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत के मगरा क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

3. श्री विजयपाल मिर्धा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में।

4. श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में किसानों को विद्युत कृषि कनेक्शन लेने में आ रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

5. श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से प्रदेश में प्रेस-पत्रकारों की समस्याओं का निराकरण करवाए जाने के सम्बन्ध में।

6. श्री जोगेश्वर गर्ग, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जालौर में विगत पखवाड़े हुए अनहोनी दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिलवाए जाने के सम्बन्ध में।

7. श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में नगरपालिका द्वारा करवाए जा रहे सीवरेज कार्यों में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

8. श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से सरकार द्वारा "डी" श्रेणी के बांधों को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किये जाने से उनके रख-रखाव में आ रही समस्या के सम्बन्ध में।

9. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर के वन क्षेत्र में बांध, एनीकटों व मूलभूत सुविधाओं के अभाव में स्थानीय निवासियों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

10. श्रीमती शोभारानी कुशवाह, सदस्य की ओर से धौलपुर जिले में चम्बल लिफ्ट सिंचाई योजना की धीमी गति से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

11. श्री अर्जुनलाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सोनीयाना, तहसील भदेसर के भवन की जमीन को जमाबंदी में विद्यालय के नाम दर्ज करवाए जाने के सम्बन्ध में।

12. श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु बाड़मेर लिफ्ट कैनाल योजना के कार्य को गति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

13. श्री चेतन सिंह चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में सड़क सुरक्षा निधि के तहत बने ट्रोमा सेंटर की राज्य सरकार द्वारा विधिवत शुरुआत नहीं करने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

14. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नदबई में ऊर्जा विभाग का अधिशासी अभियंता कार्यालय न होने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

15. श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू की ग्राम पंचायत वाटेरा द्वारा विक्रय विलेखों को जारी करने में हुए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 25 फरवरी, 2020 को शून्यकाल में बोलने हेतु 26 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा निम्न पर्चियां निकाली गयीं:-

क्र. सं.	नाम मा. विधायक	विषय
1.	श्री बलजीत यादव	राज्य में कर्मचारियों द्वारा नयी पेंशन स्कीम का विरोध किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2.	श्री जगसीराम कोली	विधान सभा क्षेत्र रेवदर के आबूरोड ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करवाए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3.	श्री गोपीचन्द मीणा	बेणेश्वर धाम के विकास नहीं होने व संत मावजी महाराज के चौपड़ों का संधारण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्य, आज 131, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद माननीय मंत्रीजी एम.एल.ए. के प्रोटोकाल के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे।

श्रीमती अनिता भदेल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राजस्थान लोक सेवा आयोग की कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा में एस.सी./एस.टी. के बैकलाग का 2018 में समायोजन

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी कि अभी कुछ समय पहले हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री महोदय धरने पर बैठे थे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्लीज, ऐसे नहीं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आरक्षण को लेकर वे धरने पर बैठे थे। उन्होंने कहा था कि हम आरक्षण को खतम नहीं होने देंगे लेकिन जिस व्यवस्था को उनके स्वयं के प्रदेश में उनको करना है, उसमें क्या हो रहा है, उसकी ओर उनका ध्यान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आरपी.एस.सी. द्वारा वर्ष 2013 में कनिष्ठ लिपिक भर्ती निकाली गयी थी। इसमें 7,773 पद थे। जिनमें से अनुसूचित जाति और जनजाति के 1,995 पद थे। इन पदों में से 1,138 पद एस.सी. के और 857 पद एस.टी. के थे। इनकी लिखित परीक्षा 23.10.2016 को और टंकण दक्षता परीक्षा 07.03.2017 को पूर्ण हुई, 08.03.2017 को इनका रिजल्ट निकाला गया। इसका जो अंतिम परिणाम जारी हुआ उसमें सिर्फ 784 एस.सी. और एस.टी. के अभ्यार्थियों को नियुक्ति दी गयी। इसका मतलब साफ है कि 784 पद ही भरे गये। जबकि जो शेष 1,211 पद हैं, जिनमें से 506 पद तो एस.सी. के हैं और 705 पद एस.टी. के हैं, ये पद रिक्त रह गये।

अध्यक्ष महोदय, कार्मिक विभाग का नियम है कि 3 साल के अन्दर-अन्दर यदि दूसरी भर्ती निकलती है तो इन बैकलाग के पदों को उनके साथ जोड़ा जाएगा। कार्मिक विभाग द्वारा वर्ष 2018 में पुन: एल.डी.सी. की भर्ती निकाली गयी। एल.डी.सी. की भर्ती को अब आर.पी.एस.सी. नहीं करती है। मंत्रालयिक कर्मचारी बोर्ड अब इस भर्ती को करता है। मंत्रालयिक कर्मचारी बोर्ड ने जो वैकेंसी निकाली, उसके कुल 12,906 पद थे। इन पदों में से 1,638 तो एस.सी. के हैं और 1,452 पद एस.टी. के हैं। इस तरह यदि हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ें तो ये जो पद हैं 1,211, जो पहले रिक्त हो गये हैं उनको 2018 की भर्ती में जोड़ना था लेकिन उनको जोड़े बगैर यह वैकेंसी निकाल दी गयी और अब जो बेरोजगार लोग हैं, वे बार-बार सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि ये 2013 के जो पद रह गये हैं, जो बैकलाग के पद हैं उन बैकलाग के पदों को भी इनके साथ जोड़ा जाए ताकि एक साथ अभ्यर्थी मिल जाएं और इन पदों पर भी जो आरक्षित पद हैं उनका सही मायने में उपयोग हो सके।

सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है तो मैं आपके माध्यम से

(श्रीमती अनिता भदेल)

सरकार का ध्यान पुन: आकर्षित करना चाहूंगी कि यदि वह एससी. और एस.टी. के लोगों का भला चाहती है और चाहती है कि रिजर्वेशन का लाभ उनको पूरी तरह से मिले तो बैकलाग के पदों को पुन: जोड़ा जाए और पुन: इसकी वैकेंसी निकाली जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री रामप्रसाद।

अनुसूचित क्षेत्रों में माइक्रो फाइनेंस कम्पनियों द्वारा महिला समूहों को उच्च ब्याज दर पर ऋण

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 50 के अन्तर्गत मैं स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित क्षेत्र में वैसे साहूकारों द्वारा जो कर्ज दिया जाता है उसमें 5 परसेंट जेवर और जमीन पर तो देते ही आ रहे हैं और बिना जमीन व जेवर के भी 5 से 10 और 20-20 परसेंट तक ब्याज वसूला जाता है। सरकार की तरफ से उस इलाके में बेरोजगारों को लोन वगैरह पास होता है तो बैंक इनको, आज तक, पास हो जाने के बाद भी लोन नहीं देते हैं। लेकिन अभी शिड्यूल्ड एरिये में स्थिति है कि 20 से 25 महिलाओं के समूह बनाकर माइक्रो फाइनेंस कम्पनियां उस इलाके में काम कर रही हैं। वे उन समूहों को लोन देती हैं। वे लोन तो बैंकों के माध्यम से देती हैं, लेकिन वसूली का काम सीधे करती हैं, जिससे उनको यह भी नहीं पता चलता है कि उसमें कितना ब्याज है और कितना नहीं, यहां तक कि वहां के समूह की जो औरतें हैं, रात के ग्यारह-ग्यारह बजे तक, जो वसूली पार्टियां होती हैं, जो एजेण्ट होते हैं, वे उनसे लोन वसूलने जाते हैं। औरतें घर छोड़कर भाग जाती हैं। अंधेरे में तो ऐसी स्थितियां वहां पैदा हो रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए जो माइक्रो फाइनेंस कम्पनियां चल रही हैं, जैसे फिन कैप, फिन कार्प्स, ऐसी बहुत सारी कम्पनियां हैं, इनके बारे में हमने जिलाधीश महोदय से बात की थी कि इनकी जांच करायी जाए और जो ऐसी कम्पनियां हैं, उनको पाबन्द किया जाए, क्योंकि वे जो लोग हैं, वे गांवों में लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। इसलिए सरकार से निवेदन है कि इन माइक्रो फाइनेंस कम्पनियों की जांच कराकर तत्काल उनको रोका जाए, जिससे आम लोग परेशान होने से रुक सकें।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

अफीम उत्पादकों का डोडा चूरा नष्ट करने की बजाय उसके अन्य उपयोग की अनुमति

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि चित्तौड़गढ़ में अफीम की अच्छी पैदावार होती है, अफीम के काफी पट्टे हैं और वर्षों से वहां अफीम पैदा हो रही है। अफीम का पट्टा मिलने के बाद किसान लोग अपने खेत में चले जाते हैं और वहीं रहते हैं, वहीं अपने खेत की रखवाली करते हैं। चार महीने तक सर्दी में बहुत ज्यादा ठिठुरन रहती है तो भी वे लोग वहां पर रहते हैं। बहुत मुश्किल से वह अफीम पैदा होती है। अफीम पैदा होने के बाद वे किसान उसे गवर्नमेंट के पास जमा करवा देते हैं। पहले डोडा चूरा सरकार ठेका पद्धति के द्वारा खरीद लेती थी, उससे लोगों को काफी आमदनी भी होती थी। उस पैसे से लोग मजदूरी वगैरह का भुगतान कर देते थे। पिछले तीन-चार साल से अफीम के डोडा चूरा को जलाया जा रहा है, इससे किसान काफी आक्रोशित हैं, क्योंकि इससे हमारी पैदावार बंद हो गयी है, हमारा सब कुछ बंद हो गया है। इसलिए उस डोडे चूरे को सरकार अपने लेवल पर खरीद ले, जिससे मुआवजे के रूप में किसानों को पैसा मिलेगा। किसान आज की तारीख में बहुत ज्यादा दुखी हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि किसान का अफीम डोडा चूरा सरकार खरीदे। अगर नहीं खरीद सकती तो उस डोडे चूरे का खाद भी बहुत अच्छा होता है, उसको जलाए नहीं, उसको खाद के रूप में खेतों में बिखेर दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से निवेदन है कि किसानों को मुआवजे के रूप में पैसे दे और उस डोडे चूरे को कभी जलाने का नाम नहीं ले, उनको मुआवजा दे या खाद के रूप में उपयोग करे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

अवैध बजरी परिवहन वाहनों द्वारा दुर्घटनाएं

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, संवेदनशीलता का नकाब ओढ़ी सरकार के सामने मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समाचार पत्रों के पन्ने उलटते हैं तो रोज उनमें बेखौफ बजरी माफिया के बजरी परिवहन में लगे वे सारे वाहन कहीं न कहीं किसी न किसी को कुचलने का काम करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, गांवों के टेढ़े-मेढ़े रास्तों से गुजरते ये वाहन, चाहे रिहायशी इलाका हो, चाहे राजधानी का हो या जिला मुख्यालय का हो, उन सारों में दौड़ते हुए रोज दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं, रोज कई-कई जो इन्होंने बैरिकैडिंग लगा रखी है, नाके लगा रखे हैं उनसे गुजरते हैं। माननीय अध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, अभी कल की घटना है मलारना डूंगर, सवाई माधोपुर में भरी दोपहर में एक दम्पत्ति अपनी स्कूटी पर बैठकर जा रहे थे, भरतलाल और भगवती, एक ट्रैक्टर दौड़ता हुआ आया, जिसमें बजरी भरी हुई थी उसने उनको कुचल दिया, इस पर लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मलारना डूंगर वही जगह है, जहां सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने खुद खड़े होकर, डी.वाई.एस.पी. की गाड़ी खड़ी थी, लम्बी कतार लगी हुई थी उन्होंने अवैध वसूली का एक वीडियो बनाया। वह वीडियो एसपी. को दिया, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये घटनाएं इसलिए हो रही हैं, ये इतने बेखौफ हो गये, जटियाना में, बिलाड़ा में, खेतड़ी की काटली नदी में, सब जगह हैलोजन लाइट लगाकर रात को जब अवैध खनन करते हैं तो उसके बाद वे गंतव्य स्थल पर पहुंचने की जल्दी में दुर्घटनाएं करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी फरवरी की मुख्य-मुख्य घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। कल शाहपुरा के अन्दर भी राजेन्द्र खटीक, जीतू खटीक की कुचलने से दुर्घटना में मृत्यु हो गयी; 21 फरवरी को नयापुरा, टोंक में उप मुख्य मंत्रीजी के इलाके में दुर्गालाल शर्मा को कुचल कर मार डाला, ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी; इसी तरह मांगरोल में इटावा मोड़ पर रविवार को छह वर्ष के एक बालक को कुचल कर मार डाला; 18 तारीख को भैंरूपुरा, टोंक के अन्दर तीन नौजवानों को कुचल डाला। यह आज की बात नहीं है। लगातार हर जगह पर, जिस प्रकार, मैं निवेदन करूं, पूरे राजस्थान में इस प्रकार की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, लेकिन सरकार संज्ञान नहीं लेगी। सरकार ने इनको पूरी तरह से बेखौफ कर दिया। रोज दुर्घटनाओं पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के अन्दर समाचार प्रकाशित होते हैं, फोटो प्रकाशित होते हैं, अवैध खनन की खबरें प्रकाशित होती हैं, अवैध वाहनों की खबरें प्रकाशित होती है, पर सरकार कोई कार्यवाही करेगी भी नहीं, सरकार कार्यवाही करना भी नहीं चाहती, सरकार की मंशा भी नहीं है क्योंकि यह संवेदनशील सरकार है।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

वर्षा जल संग्रहण हेतु हर घर में पोण्ड निर्माण

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत बरसात के

(श्री रामलाल शर्मा)

पानी को बचाने के लिए घर-घर पोण्ड बनाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि राजस्थान में आज यदि कमी किसी की है तो पानी की है। "रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून, बिन पानी न उबरे मोती मानस चून।" यह वाक्य आज का नहीं बरसों पुराना है। वर्षों पहले पानी की इस गम्भीर समस्या के प्रति लोगों के मन में ये विचार थे। आज राजस्थान के अधिकांश ब्लाक ड्राई हो चुके हैं, शेष रहे भी कुछ वर्षों बाद पूर्णत: सूख जाएंगे।

महोदय, आज से बीस वर्ष पहले जयपुर जिले के किशनगढ़-रेनवाल में जौ की बहुत बड़ी मण्डी हुआ करती थी यहां राजस्थान से ही नहीं, देश के विभिन्न राज्यों से व्यापारी जौ खरीदने के लिए, व्यापार करने के लिए आते थे। लेकिन धीरे-धीरे पानी सूख जाने के बाद आज किशनगढ़-रेनवाल और आस पास के गांवों से पीने का पानी भी बीसलपुर से लाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जयपुर जिले में आने वाले समय में पीने के पानी का गम्भीर संकट पैदा होने वाला है। अत: अब एक मात्र विकल्प हमारे पास बचता है तो वह है बरसात के पानी की एक-एक बूंद बचाने का काम हम करें। अत: सरकार द्वारा जिस प्रकार पूरे देश में शौचालय बनाने के लिए 12 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर घर-घर शौचालय बनाये गये, उसी प्रकार राजस्थान में एक या दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर घर-घर में पोण्ड बनाने की अति आवश्यकता है, जिससे आने वाले समय में पानी के संकट से निजात मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शोभा चौहान। (अनुपस्थित) श्री विजयपाल मिर्धा।

डेगाना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सुविधा विस्तार

श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डेगाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डेगाना की हालत जर्जर व खस्ता है, 40 बैड के इस केन्द्र में सुविधा के नाम पर शून्य है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्षेत्र की जनसंख्या व जनहित को ध्यान में रखकर सी.एच.सी. में बैड्स की संख्या

(श्री विजयपाल मिर्धा)

40 से बढ़ाकर 100 की जाए तथा भवन की मरम्मत हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने के साथ में शौचालय व पेयजल आदि मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाए, क्योंकि यहां पर प्रतिदिन पांच सौ ओ.पी.डी. व एक हजार आयी.पी.डी. प्रतिमाह हैं। स्टेरिक सेंटर होने के कारण प्रतिदिन नसबंदी आपरेशन भी होते हैं। डेगाना राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा होने के कारण दुर्घटना के केस भी आते हैं, जिनमें से कई जटिल केसों को अजमेर रैफर करना पड़ता है। डेगाना नागौर से 80 किलोमीटर व अजमेर से 70 किलोमीटर दूर होने के कारण 60 किलोमीटर की परिधि में लगभग तीन लाख की आबादी निवास करती है।

लोगों को बड़े आपरेशन के लिए अजमेर व नागौर जाना पड़ता है, जिससे गरीब जनता पर आर्थिक भार पड़ता है। अतः मैं मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डेगाना में बैड्स की संख्या सौ की जाए, भवन मरम्मत के साथ अन्य सुविधाओं को बढ़ाया जाए और ब्लड बैंक खोला जाए, जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हाकम अली खां।

फतेहपुर में किसानों को विद्युत कनेक्शन

श्री हाकम अली खॉ (फतेहपुर): सर, धन्यवाद। मैं पहले एक छोटा-सा निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप पहले 295 पढ़ें। फटाफट पढ़ें।

श्री हाकम अली खॉ (फतेहपुर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में किसानों के विद्युत कृषि कनेक्शनों की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। महोदय, हमारी सरकार किसानों के प्रति बहुत संवेदनशील है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को कि उन्होंने पांच साल तक किसानों के बिजली बिल नहीं बढ़ाने की घोषणा की है।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में रोजगार के लिहाज से कोई बड़ा उद्योग-धंधा नहीं है। यहां के अधिकतर लोग कृषि पर ही निर्भर हैं, लेकिन किसानों को कृषि हेतु कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। किसान जब अपने कुएं पर कनेक्शन हेतु फाइल जमा करवाने जाता है तो अधिकारियों द्वारा डार्क जोन है, इसलिए कनेक्शन नहीं होगा, पहले जिला कलेक्टर से एन.ओ.सी.

(श्री हाकम अली खॉ)

लाओ आदि कई तरह की बहानेबाजी कर किसानों की फाइल जमा नहीं की जाती है और न ही कनेक्शन दिया जाता है, जिससे किसानों को बड़ी समस्या हो रही है। अत: मेरा माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के किसानों की परेशानी को देखते हुए इच्छुक किसानों को यथाशीघ्र कृषि कनेक्शन दिये जाने के आदेश जारी करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री जोराराम कुमावत।

पत्रकारों की समस्याओं का निराकरण

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय जी, लोकतंत्र के चार स्तम्भ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका व पत्रकारिता हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकार बन्धुओं द्वारा दबंगता, निष्पक्षता से कार्य कर, समाज में फैली बुराइयों को उजागर कर लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है।

पत्रकार बन्धु गांव, ढाणी, शहर व दुर्गम स्थलों पर भी पहुंच कर समाचारों का संकलन करते हैं और निष्पक्षता से समाचार पत्रों या टीवी चैनलों पर प्रचारित करते हैं। इस कार्य में कई पक्ष या लोग इनसे नाराज भी हो जाते हैं। कई बार पत्रकारों के साथ मारपीट की घटनाएं होती हैं, मुकदमे भी होते हैं। लेकिन राजस्थान प्रदेश में कोई पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं होने के कारण पत्रकारों को भी पूरा न्याय नहीं मिलता है। पत्रकारों की सुरक्षा हेतु महाराष्ट्र व हरियाणा की तर्ज पर इण्डियन फैडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट के मसौदे के आधार पर राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की आवश्यकता है।

पत्रकारों की देश व राज्य के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। उनकी सेवा के लिए वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन, जनसम्पर्क निदेशालय में पत्रकारों के लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने, पत्रकार व उसके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा की राशि बढ़ाने, शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत पत्रकारों को आवास निर्माण हेतु नि:शुल्क भूखण्ड आबंटन करने, पत्रकारों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने, राज्य पथ परिवहन की बसों में नि:शुल्क यात्रा की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पत्रकारों की इन समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और इनके समाधान की आशा भी रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगेश्वर गर्ग।

जालौर में दुर्घटनाग्रस्त मृतकों के आश्रितों को मुआवजा

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विगत पखवाड़े में अलग-अलग गांवों में विभिन्न प्रकार की अनहोनी घटनाएं घटित होने के कारण अनेक मौतें हुई हैं। दिनांक 03 फरवरी, 2020 को नून गांव में मकान का छज्जा गिरने से श्री भूभूत जी पुत्र श्री प्रागजी राजपुरोहित (उम्र 81) एवं श्रीमती रमेश देवी पत्नी श्री किशोर सिंह राजपुरोहित (उम्र 42) का निधन हो गया।

इसी प्रकार 11 फरवरी, 2020 को रात में सांथू गांव में एक झोंपड़े में आग लगी। उस झोंपड़े में गैस सिलेण्डर भी रखा हुआ था। श्री भानाराम पुत्र श्री राणाराम भील ने उस सिलेण्डर को आगग्रस्त झोंपड़े में से निकालने का प्रयास किया। उसी दौरान उस गैस सिलेण्डर में विस्फोट हो जाने से श्री भानाराम भील (उम्र 27 वर्ष) का निधन हो गया।

ऐसी ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बावतरा गांव के निवासी श्री दीपाराम पुत्र श्री हाथी रामजी पुरोहित (उम्र 35 वर्ष) एवं श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री दीपाराम पुरोहित (उम्र 30 वर्ष) का करंट लगने से निधन हो गया। मेरा इस सदन के माध्यम से राजस्थान सरकार से निवेदन है कि इन तीनों दु:खद घटनाओं में असमय काल कवलित हुए पांचों व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में थे। अत: उन्हें तुरंत सहायता प्रदान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। कृपया उक्त पांचों मृतकों के परिवारों को राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त आर्थिक सहायता पहुंचाने की व्यवस्था कर राहत प्रदान कराए।

श्री अध्यक्ष: श्री रामप्रताप कासनियां।

सूरतगढ़ में सीवरेज कार्यों में अनियमितताएं

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मैं आपका ध्यान नगरपालिका सूरतगढ़ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जहां पिछले 4-5 वर्ष से सीवरेज का कार्य चल रहा है। इसमें करोड़ों रुपये का घोटाला हो रहा है, जिसमें सेफ्टी टैंकों को खाली करवाने के नाम पर करोड़ों रुपये डकारे गये, जबकि सेफ्टी टैंक खाली किये ही नहीं गये। इसी प्रकार पाइप लाइनें खुदाई में क्षतिग्रस्त होने के बहाने से भी करोड़ों रुपये बिना पाइप

(श्री रामप्रताप कासनियां)

डलवाए, लगभग 65-70 लाख रुपयों का भुगतान उठा लिया गया। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा पूर्व में जांच करवाने हेतु शिकायत की गयी। जांचकर्ता अधिकारी, भ्रष्टाचार में लिप्त/भ्रष्ट अधिकारी द्वारा जांच कर इनका मुंह बंद करवा दिया गया एवं इन्हें कमीशन देकर जांच में लीपापोती करके गोलमाल कर दिया गया।

जनता के साथ न्याय नहीं किया गया। हालात अभी भी जस के तस हैं। कार्य बकाया पड़े हैं। रोड वगैरह बनाने में सही मानकों के अनुसार मैटेरियल नहीं लगाया जा रहा है। हालात बहुत ही दयनीय हैं। जगह-जगह सड़कें टूटी हुई हैं। गली-गली में खड्डे पड़े हैं एवं सीवरेज के जो चैम्बर बनाये गये हैं, रोड के लेवल से तीन इंच से छह इंच तक ढक्कन रोड से ऊपर लगे हुए हैं।

राहगीर पैदल चलते हैं तो टकराकर गिर जाते हैं। साइकिल सवार, स्कूटर, मोटरसाइकल व कार वाले भी इन चैम्बरों से टकराकर गिर जाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे लोगों के हाथ-पैर टूट जाते हैं। जानमाल की हानि होती है। ये जो सीवरेज लाइनें डाली जा रही हैं, सुविधा के स्थान पर दुविधा साबित हो रही हैं। मैं सरकार से उक्त प्रकरण की जांच किसी ईमानदार अधिकारी से करवाने की मांग करता हूं ताकि जनता का पैसा सही ढंग से लग सके, एवं शेष कार्य तुरंत पूरा कराने का आदेश प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: श्री खुशवीरसिंह।

'डी' श्रेणी बांधों के पंचायतों को हस्तांतरण से रखरखाव की समस्या

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सरकार ने पंचायतों को अधिकार देने के निर्णय के अन्तर्गत कई विभाग हस्तान्तरित किये, जिनमें सिंचाई विभाग के बांध भी थे। सिंचाई के बांधों को सरकार ने चार श्रेणियों A.B.C.D. में विभक्त कर "D" श्रेणी के बांधों को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरण के नाम से सिंचाई विभाग ने अपने कर्मचारी, जिन पर उक्त बांधों की नहरों का संधारण व बांध का रखरखाव करने की जिम्मेदारी थी, उन्हें हटा दिया, लेकिन उक्त बांधों की मछली के ठेके से प्राप्त आय विभाग ही ले रहा है। दूसरी तरफ, सिंचाई का राजस्व भी राजस्व विभाग में जमा हो रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त बांधों का रखरखाव व मरम्मत सम्बन्धी कार्य पंचायतों के पास किसी प्रकार का फण्ड

(श्री खुशवीरसिंह)

उपलब्ध नहीं होने से प्रभावित हो रहे हैं, जिससे बांध टूटने की कगार पर हैं। ऐसे मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र में रेणीया, डिगोंर, कन्टालिया, कोलर, मगरतालाब, जोगड़ावास, फुलाद इत्यादि बांध हैं। इसी क्रम में पूर्व में जनता जल योजना के तहत जलदाय विभाग द्वारा पंचायतों को एक कार्मिक की तनख्वाह का भुगतान भी किया जाता था। साथ ही विद्युत बिल पंचायतों द्वारा जमा करवाने पर विभाग ग्राम पंचायतों के खाते में उक्त बिल की राशि हस्तांतरित करता था, लेकिन पिछली सरकार ने विद्युत बिलों व कार्मिक की तनख्वाह का भुगतान करना बन्द कर दिया, जिससे जे.जे.वाई. के तहत पंचायतों को अपने विकास कोष की अधिकांश राशि पेयजल के विद्युत बिलों व कार्मिक की तनख्वाह पर खर्च करनी पड़ रही है। ऐसे में पंचायतों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने से विकास गति थम गयी है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि पंचायत के अधीन सिंचाई के बांधों के रख-रखाव, नहरों के संधारण हेतु व जे.जे.वाई. के विद्युत बिलों तथा कार्मिक हेतु अलग से बजट उपलब्ध कराए।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

बानसूर के वन क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत बानसूर वन क्षेत्र में बांध, एनीकट एवं मूलभूत आवश्यकताओं के सम्बन्ध में निवेदन है कि गर्मी का सीजन आने वाला है, जिससे गर्मी में पानी की समस्या आएगी। पानी का विषय गम्भीर है और जलस्तर दिन-पर-दिन घटता जा रहा है। इस समस्या से निजात पाने के लिए बांधी, एनीकट बनाने की महती आवश्यकता है। खरकड़ी, रामपुर, सबलपुरा, लेकड़ी, गढी, मुण्डावरा, वामनबास कांकड़, जयसिंहपुरा छीन्ड, नाथूसर, लोज, झींड, धीरपुर, लागलहेडी, मालेरा, कालीपहाड़ी, हाजीपुर, धामला का बास, हमीरपुर डोईवाली लोज वन क्षेत्र में आने वाले बांध, एनीकटों को बनाने की एन.ओ.सी. लेनी पड़ती है, जो वन विभाग नहीं देता, जिससे जलस्तर घटता जा रहा है। एनीकटों के निर्माण से वन्यजीवों को भी पीने का पानी आसानी से मिल सकेगा। वन विभाग वाले कहते हैं कि बांध के निर्माण से हमारे वन्य जीव गांवों के नजदीक आ जाएंगे। उनसे पूछा जाए कि आज वर्तमान में रोज प्रत्येक दिन वन्य जीव गांवों में आ रहे हैं और एक-दो पशुओं को खाकर जाते हैं तथा यह आम बात हो चुकी है।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

चार-पांच दिन पहले गांव रतनपुरा, कराना में घर में घुसकर 27 भेड़ों को एक साथ मार दिया। आये दिन ऐसी घटनाएं होती हैं तथा उनको मुआवजा भी नाममात्र का दिया जाता है।

इन गांवों में वन विभाग द्वारा एन.ओ.सी. नहीं दिये जाने से स्थानीय निवासियों को सड़क, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, पक्के मकान जैसी अनेक मूलभूत सुविधाओं सहित अनेक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसलों तथा पशुओं के किये जा रहे नुकसान का मुआवजा भी सरकार द्वारा नाममात्र का दिया जाता है, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए।

अत: मेरा पुन: माननीय वन मंत्री महोदय व सरकार से निवेदन है कि कृपया वन क्षेत्र से लगते गांवों में बांधी, एनीकट बनवाने की अनुमति दिलवाने की कृपा करें जिससे गांवों का जलस्तर बढ़ सके।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शोभारानी कुशवाह।

धौलपुर चम्बल लिफ्ट सिंचाई योजना के कार्य की धीमी गति

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि धौलपुर जिले में बी.जे.पी. सरकार में किसानों की परेशानी देखते हुए चम्बल लिफ्ट सिंचाई योजना की शुरुआत की गयी थी और जब तक बी.जे.पी. सरकार थी तब तक उस योजना का काम बहुत तेजी से चल रहा था, लेकिन जब से कांग्रेस सरकार आयी है, तब से उसका काम धीमा हो गया है। अध्यक्ष महोदय, यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो धौलपुर जिले के किसानों का उद्धार करेगी। इस योजना का हमारे किसान भाई बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए इस काम को एक समय सीमा के अन्दर पूरा कराया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जिन-जिन गांवों में यह सिंचाई की योजना है, उनमें इसके साथ अगर पीने का पानी भी गांव वालों को उपलब्ध करा दिया जाए तो जो धौलपुर जिले में पेयजल की समस्या है वह भी दूर हो जाएगी, क्योंकि आज की डेट में वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है। कईकई क्षेत्रों में तो ट्यूबवैल की पहुंच से भी नीचे है और कई क्षेत्रों में पानी है भी तो वह पीने योग्य नहीं है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, जिन-जिन गांवों में यह योजना सिंचाई के लिए पहुंचाई जा रही है उन सभी गांवों में सिंचाई के साथ-साथ पीने योग्य पानी की लाइन भी

(श्रीमती शोभारानी कुशवाह)

पहुंचाई जाए तो किसानों की सिंचाई के साथ-साथ पीने योग्य पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जीनगर। (अनुपस्थित)

श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु बाड़मेर लिफ्ट कैनाल योजना

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत मैं आपका ध्यान अत्यंत ही जनहित के मुद्दे के ऊपर आकर्षित कर रहा हूं कि सीमावर्ती सुदूर जिला बाड़मेर में पेयजल की विकट समस्या है। इस समस्या के समाधान हेतु बाड़मेर लिफ्ट कैनाल पेयजल परियोजना के तहत पार्ट "अ", "ब" एवं "स", अलग-अलग चरणों में पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गयीं, जिनके माध्यम से विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर, बायतू एवं शिव में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना था। इसके तहत बाड़मेर जिला मुख्यालय तक नहर का मीठा पानी पहुंच गया है, लेकिन पार्ट "ब" एवं "स" के तहत स्वीकृत कार्य बिल्कुल नहीं के बराबर चल रहे हैं। कार्यकारी एजेंसी द्वारा इस कार्य को बहुत ही धीमी गति से किया जा रहा है, जिसके कारण तय समय में पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। पार्ट "अ" तथा "ब" में जी.एल.आर. का अधिकांश कार्य अधूरा पड़ा है तथा पार्ट "स" का कार्य भी अभी तक शुरू नहीं हो पाया है।

महोदय, आगामी गर्मियों में पेयजल की समस्या और विकट होगी। अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि बाड़मेर लिफ्ट कैनाल के कार्य में गति देकर उक्त कार्य को अतिशीघ्र पूरा कर पेयजल सप्लाई सुनिश्चित कराने का श्रम करावें।

श्री अध्यक्ष: श्री चेतन सिंह चौधरी।

डीडवाना में निर्मित ट्रोमा सेंटर की शुरुआत

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में सड़क सुरक्षा निधि के तहत 4 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से ट्रोमा सेंटर का निर्माण करवाया गया जिसमें आउटडोर के साथ ही ट्रोमा एग्जामिनेशन हाल, प्लास्टर रूम, ट्रोमा

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

आब्जर्वेशन वार्ड, ट्रोमा आयी.सी.यू., माइनर आपरेशन थियेटर, दो मेजर ऑपरेशन थियेटर, एक्स-रे, सी.टी. स्कैन व एम.आर.आई. कक्ष का निर्माण ट्रोमा सेंटर में किया गया। लेकिन राज्य सरकार की स्वीकृति नहीं मिलने से ट्रोमा सेंटर को विधिवत शुरू नहीं कर पाने से इसका लाभ आमजन को नहीं मिल पा रहा है।

राजकीय बांगड़ चिकित्सालय में मरीजों के लिए 200 बैड की सुविधा है तथा लगभग प्रतिदिन 800 से 1000 आउटडोर रोगी अस्पताल में आते हैं। प्रतिवर्ष 20 हजार मरीज अस्पताल में भर्ती रहकर इलाज करवाते हैं। इस अस्पताल में ब्लड बैंक की सुविधा भी उपलब्ध है तथा अस्पताल में भवन सुविधा व उपकरणों हेतु राशि स्वीकृत होने तथा विभिन्न प्रकार की अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी आज दिन तक ट्रोमा सेंटर स्वीकृत नहीं है। डीडवाना, लाडनूं, जायल, मोलासर, छोटी खाटू, खुनखुना सहित यहां के आस-पास लगभग 50 किलोमीटर परिधि के सभी गांवों के लोगों के लिए सिर्फ बांगड़ अस्पताल ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने का प्रमुख केन्द्र है। डीडवाना का अस्पताल एक नेशनल हाईवे लाडनूं-ब्यावर-उदयपुर तथा दो मेगा हाईवे किशनगढ़-हनुमानगढ़ व सीकर-डीडवाना गुजरते हैं और इन मार्गों पर कई बार गम्भीर हादसों के शिकार हुए लोगों को भी उपचार के लिए यहां लाया जाता है। ट्रोमा सेंटर के अभाव में न केवल लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, बल्कि तुरन्त उपचार नहीं मिल पाने की स्थिति में कई बार पीड़ित की मौत तक हो जाती है। सुविधा के अभाव में गम्भीर घायलों को हायर सेंटर रैफर किया जाता है और नजदीक ट्रोमा सेंटर सीकर है जो कि लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है। एक अनुमान के अनुसार यदि ट्रोमा सेंटर की पूरी सुविधाएं डीडवाना अस्पताल में हों तो मौत के आंकड़ों में 50 प्रतिशत तक की कमी लायी जा सकती है।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि राजकीय बांगड़ चिकित्सालय में ट्रोमा सेंटर की स्वीकृति जल्द से जल्द दिलवाने की कृपा कराएं।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगेन्द्र सिंह अवाना।

नदबई में ऊर्जा विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय की स्थापना

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत नदबई विधान सभा क्षेत्र में ऊर्जा विभाग के अधिशासी

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

अभियंता का कार्यालय न होने से आमजन को हो रही समस्या के सन्दर्भ में ध्यान आकर्षित करता हूं।

विधान सभा क्षेत्र नदबई में ऊर्जा विभाग के अधिशासी अभियंता का कार्यालय न होने से आमजन को हो रही समस्या के सन्दर्भ में सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र नदबई में ऊर्जा विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय क्रमश: नदबई, डहरा मोड़, उच्चैन व सेवर में हैं लेकिन अधिशासी अभियंता कार्यालय विधान सभा मुख्यालय नदबई में न होकर भरतपुर में है, जिसकी दूरी 40 किलोमीटर है, जिससे आमजन को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नियमानुसार 10 हजार उपभोक्ताओं पर एक सहायक अभियंता होता है, जबकि नदबई में 29,282 उपभोक्ता हैं। नदबई में अधिशासी अभियंता कार्यालय नहीं होने और वर्तमान उक्त कार्यालय की दूरी अधिक होने से उपभोक्ताओं का कार्य भी समय पर नहीं हो पाता है। अत: आमजन की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए यहां पर दो सहायक अभियंता कार्यालय व एक अधिशासी अभियंता कार्यालय खुलवाया जाना अति आवश्यक है।

महोदय, इस क्रम में मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार अधिशासी अभियंता का कार्यालय नदबई विधान सभा मुख्यालय पर खुलवाने का श्रम करे।

श्री अध्यक्ष: श्री समाराम गरासिया।

पिण्डवाड़ा-आबू में ग्राम पंचायत वाटेरा द्वारा विक्रय विलेखों में भ्रष्टाचार

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि ग्राम पंचायत वाटेरा द्वारा 50,000/- (पचास हजार रुपये) लेकर 1,200 की रसीद दी गयी। पट्टाधारकों को कब्जा भी नहीं मिला एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही भी नहीं हुई।

मेरे द्वारा पत्र क्रमांक 2019-20/114, दिनांक 23.09.2019 द्वारा श्रीमान् जिला कलेक्टर, सिरोही को ग्राम पंचायत वाटेरा में पंचायत द्वारा ग्रामीणों को डी.एल.सी. के पट्टे देने हेतु 50 हजार रुपये लेकर रसीद 1200/- की दी गयी। ग्रामीणों को बिलानाम भूमि में पट्टे दिये, जिनको भूमि नहीं दी गयी, जिसका परिवाद पत्र दिया गया।

56]नि. 295 के त.वि. उल्लेख-25 फरवरी 2020-पर्ची के मा. से उ. गये मुद्दे

(श्री समाराम गरासिया)

जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा पत्र क्रमांक पंचायत/जांच/2019/592, दिनांक 24.09.2019 से विकास अधिकारी, पिण्डवाड़ा को जांच हेतु आदेशित किया गया। विकास अधिकारी द्वारा अक्टूबर, 2019 में जिला कलेक्टर को जांच प्रतिवेदन भेजा गया। जांच प्रतिवेदन में लोगों से पैसा लेना, वार्ड पंच व उप सरपंच ने लोगों से 41,000/- रुपये लेना एवं 1,200/- की रसीद देना कबूल किया गया। एक व्यक्ति शंकरलाल/केसाजी घाची ने वार्ड पंच के खाते में बैंक आफ बड़ौदा खाता नं. 4365010000108 में दिनांक 11.09.2017 को 15,000, 28.08.2017 को 15,000, 02.09.2017 को 45,000/- रुपये जमा करवाये। कई पट्टा बुक्स में 3 प्रतियां गायब पायी गयीं।

16 पट्टे वार्ड पंच व उप सरपंच के रिश्तेदारों को जारी किये गये, 9 पट्टे सरकारी कर्मचारी व पत्नी/माता के नाम से जारी किये गये, 5 पट्टे गांव के बाहरी लोगों को रा.प.रा. नियम, 1996 के नियम 158 के तहत जारी किये गये। सभी विक्रय विलेख रा.प.रा. नियम, 1996 के नियम 158 में दुबारा पट्टे जारी किये गये, 17 लोगों को पुराना वास देने के बावजूद रा.प.रा. नियम, 158 में दुबारा पट्टे जारी किये गये, 30 लोगों को बिलानाम भूमि में पट्टे दिये गये।

इस प्रकार ग्राम पंचायत वाटेरा द्वारा विक्रय विलेखों को जारी करने में भारी भ्रष्टाचार किया गया। सरकारी कर्मचारियों, बाहर गांव के लोगों को पट्टे जारी किये गये। जनप्रतिनिधियों ने अपने स्वयं व अपने रिश्तेदारों के नाम, विक्रय विलेखों से तीन प्रतियां गायब होना...

ग्राम पंचायत द्वारा सभी उपरोक्त विक्रय विलेख रा.प.रा. नियम, 1996 के तहत जारी किये गये। परंतु जिला प्रशासन द्वारा दोषियों से मेल मिलाप कर जांच रिपोर्ट को दबा दिया गया एवं उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री अध्यक्ष: श्री बलजीत यादव।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

राज्य कर्मचारियों द्वारा नई पेंशन स्कीम का विरोध

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, 2004 से पहले सरकारी कर्मचारियों को, जब वे रिटायर होते थे तो,

(श्री बलजीत यादव)

उनको जी.पी.एफ., ग्रेच्युटी 20 लाख रुपये एक मुश्त मिलते थे और उसके बाद में, उनके बेसिक वेतन का 50 प्रतिशत एवं अन्य लाभ सहित उनको पेंशन के रूप में जीवन भर मिलता था। लेकिन 2004 के बाद से जो कर्मचारी नियुक्त हुए, उनको नई पेंशन स्कीम में डाल दिया गया और उस पैंशन स्कीम के अन्दर प्रत्येक महीने कर्मचारी की सैलरी का 10 परसेंट कटता है और 10 परसेंट सरकार जमा कराती है। उसे सरकार एन.एस.डी.एल. कम्पनी में जमा करा देती है। यह एन.एस.डी.एल. उस पैसे को शेयर मार्केट में लगाती है। जब कर्मचारी रिटायर होता है उस वक्त यदि शेयर मार्केट में मंदी हो तो जो पैसा उसका जमा है, वह पैसा भी उसका कम हो जाता है। रिटायरमेंट के वक्त उसका जो टोटल पैसा जमा होता है, उसका 60 परसेंट दिया जाता है। उस 60 परसेंट के ऊपर भी 30 परसेंट के लगभग टैक्स के रूप में कट जाता है। 40 परसेंट जो बचता है वह शेयर मार्केट में रहता है, उससे जो प्रोफिट होता है, वह उसको पेंशन के रूप में दिया जाता है।

ऐसा ही मैं एक उदाहरण बताऊंगा जो केवल नाम मात्र का होता है। एक पैराटीचर प्रबोधक के रूप में नियुक्त एवं स्थायी हुई। उनकी 60 साल की उम्र होने पर जब 2017 में रिटायर हुईं, उसके बाद से उनको लगभग 1000 रुपये महीना पेंशन मिल रही है, जो न के बराबर है। गैस का एक सिलेण्डर भी उसका नहीं आता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि सरकार को कोई आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा। चार लाख के लगभग कर्मचारी नयी पेंशन स्कीम में आ चुके हैं। अगर सरकार पुरानी पेंशन स्कीम लागू करती है तो सरकार को प्रत्येक महीने, कर्मचारी का जो 10 परसेंट जमा होता है, लगभग 2,035 से 2,040 तक, सरकार को 200 करोड़ का फायदा प्रत्येक महीने होगा, यानी ढाई हजार करोड़ रुपया सरकार को मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकारी नौकरी का चार्म ही इस बात के लिए था। आदमी देखता कि बुढ़ापा स्वाभिमान के साथ, मान-सम्मान के साथ कट जाएगा, किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस वर्तमान युग में हम बुजुर्ग लोगों की हालत देख रहे हैं। वृद्धा आश्रम की जो संख्या बढ़ती जा रही है, वह इस बात का प्रमाण है कि बुजुर्गों के साथ अत्याचार हो रहा है। इस सैल्फिश जमाने में, बहू-बेटे बुजुर्गों को निकाल रहे हैं। आये दिन मुकदमे हो रहे हैं, आये दिन अख़बार में पढ़ते हैं। इसलिए

(श्री बलजीत यादव)
सरकार से यह मेरी दरख्वास्त है कि सरकार राजस्थान के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में डाले, उनके साथ न्याय करे। इससे सरकार को भी फायदा होगा, यहां के कर्मचारियों को भी फायदा होगा और बुजुर्गों का सम्मान भी जिंदा रहेगा। इसलिए सरकार इसके ऊपर ध्यान दे और जल्द से जल्द इसका निर्णय करे। एक-दो स्टेट ने ऐसा किया भी है...

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): इसलिए मैं चाहता हूं राजस्थान सरकार भी जल्द से जल्द कोई सकारात्मक सोच रखते हुए निर्णय ले।

श्री अध्यक्ष: श्री जगसी राम।

रेवदर के आबूरोड ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासियों का धर्म परिवर्तन

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर और आबू रोड, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पिछली 23.02.2020 को दूना कांकर, आबू रोड ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर ईसाई मिशनरियों द्वारा आबू रोड क्षेत्र में अवैध रूप से धर्मांतरण की गतिविधियां चलाकर, गरीब जनता को तरह-तरह का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाया गया।

अध्यक्ष महोदय, ईसाई मिशनरियों द्वारा आबू रोड क्षेत्र में अवैध रूप से कुई सांगणा और इसके आस पास का जो क्षेत्र है, वहां पर लगभग 10 करोड़ की लागत से एक चर्च सरकारी भूमि पर बनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो गतिविधियां फैलाई जा रही हैं। मैं समझता हूं कि सिरोही जिले, आबू रोड में ही नहीं पूरे राजस्थान के विभिन्न जिलों में इस प्रकार की गतिविधियां फैलाई जा रही हैं।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि अभी सुबह मैंने जानकारी ली तो आबू रोड के आदिवासी भाइयों ने जो निर्णय लिया है, इस पर यदि गम्भीरता से निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों के अन्दर आबू रोड क्षेत्र के तमाम आदिवासी और विभिन्न संगठन, यहां सड़कों पर आएंगे और इस कारण जो 10 करोड़ की लागत से चर्च बनाया गया, सरकारी भूमि पर...। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इन सारी गतिविधियों के प्रकरण सामने आएं, ताकि आने वाले दिनों के अन्दर किसी प्रकार की गतिविधियां नहीं फैलाई जाएं।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपीचंद मीणा।

बेणेश्वर धाम का विकास एवं मावजी महाराज के चौपड़ों का संधारण

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, मुझे आज बेणेश्वर धाम के विकास एवं मावजी महाराज के चौपड़ों के संधारण हेतु बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं अध्यक्ष महोदय, बोलने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे दो मिनट ज्यादा बोलने का मौका देना, भले ही मुझे बाद में बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। लेकिन, मैं यह चाहता हूं कि संत मावजी महाराज ने आज से तीन सौ साल पहले वांगड़ की धरती, साबलपुरी गांव में जन्म लिया था। उन्होंने बेणेश्वर धाम पर तपस्या की थी और तपस्या के दरमियान 12 पोटी चौपड़े लिखे थे, 12 पोटी का मतलब होता है जो पहले बैलों के ऊपर लेकर चलते थे, वे 12 पोटी चौपड़े लिखे थे और उन चौपड़ों में उन्होंने आने वाले समय की सारी भविष्यवाणी लिखी थी और उस भविष्यवाणी के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा भगवान ने 9 अवतार लिए, यह बताया जाता है, लेकिन 9 अवतारों ने कभी भी भविष्यवाणी नहीं लिखी थी लेकिन दसवां अवतार होगा, जिसके बारे में विस्तृत उन चौपड़ों में लिखा गया है। उन चौपड़ों में जो लिखा है मैं उसके 5-7 वाक्य आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है आकाश गाड़ी चालैगी, कहने का मतलब हवाई जहाज आज चल रहे हैं। बिना बलद गाड़ी चालैगी, इसका मतलब बिना बैल से जो मोटर साइकिल, बस वगैरह चल रही हैं। डोरिये दीवा लागसे, जो आज हमारे हर जगह लाइटें हो गयीं। वायरो बात करसे, मतलब आज हमारे सबके पास मोबाइल हो गये। गेहूं चावल गणमा मिलसे, आज हम सब लोग राशनकार्ड के माध्यम से दुकान पर जाकर ले रहे हैं और पलिए पाणी मिलसे, आज बोतलों में पानी बिक रहा है। जात-परजात में नातरो थासे, यह भी हो गया। इन्होंने यह कहा, वाग साली दोई जोड़े बंधासे, सब लोग आज हिलमिल के रह रहे हैं। यही नहीं, फिर उन्होंने यह भी कहा ऊंच नीच का भेद मिटसे, वह भी हो गया। एक बात और बताई थी कि गुजरात नो दीवो बेणेश्वर आवसे और दिल्ली में बैठसे, दुनिया में डंको बाजसे, वह नरेन्द्र भाई मोदी थे जो बेणेश्वर आकर दिल्ली में बैठे और पूरी दुनिया में उनका नाम चल रहा है, वह भी इस चौपड़े में लिखा हुआ है। बेणेश्वर धाम की धरती सेंटर पाइंट है, यह भी इन्होंने बताया। इस दुनिया का सेंटर पाइंट बेणेश्वर धाम को माना गया है। चौपड़ों में जो भविष्यवाणी लिखी

(श्री गोपीचंद मीणा)

गयी है, जिसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सरकार से अनुरोध करूंगा कि इनके संधारण हेतु, इनका हिन्दी एवं संस्कृत में अनुवाद हेतु, मालविया जी जब टी.ए.डी. मंत्री थे, उन चौपड़ों के अनुसंधान के लिए, हिन्दी अनुवाद के लिए उस समय उन्होंने 60 से 70 लाख रुपया बजट पास किया था। लेकिन वह बजट न मालूम आज कहां गया, उसका कोई पता नहीं। मैं चाहूंगा वह बजट आप वापस दिलाकर इन चौपड़ों का संधारण करें।

साहब, दो मिनट मुझे देना, आगे और कहना चाहूंगा, आपसे मेरा अनुरोध है यह 6 चौपड़े थे। एक चौपड़ा दिल्ली में है, एक चौपड़ा अंग्रेज लेकर चले गये थे, उस समय अंग्रेजों का राज था। क्या सरकार हमारे उस चौपड़े को वापस लाना चाहती है? एक चौपड़ा उदयपुर में सलूम्बर तहसील में शेषपुर में पड़ा है। एक चौपड़ा भोजपुर, आसपुर तहसील में पड़ा है। एक बांसवाड़ा में है, एक बेणेश्वर धाम में है। इन चौपड़ों का हिन्दी अनुवाद कराने के लिए मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं। यही नहीं, मैं आपसे और भी बात कहना चाहूंगा बेणेश्वर धाम के विकास हेतु पिछले समय, वर्तमान की स्थिति तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन पिछले समय में उसके लिए 255 करोड़ का मास्टर प्लान बनाकर हमने यहां भिजवाया था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं जो 255 करोड़ का मास्टर प्लान है, उसका प्रपोजल बनाकर आप भारत सरकार को भेजें ताकि उस बेणेश्वर धाम का विकास हो सके।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया, माननीय सदस्य।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): मैं कहना चाहूंगा आप सबका आशीर्वाद मिले, मैं सदन से कहना चाहूंगा कि इस काम को करने में आप सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, यह उम्मीद करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री भरत सिंह, 131।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सांगोद में गुमशुदा बच्चों की मानव तस्करी

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष जी, नियम प्रक्रिया 131 के तहत मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान दिलवाना चाहता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दिनांक 14.06.2018 को थाना भीमगंज मण्डी, जिला कोटा शहर पर फरियादी मोडूलाल पुत्र चतरा, जाति बादरी, उम्र 60 वर्ष, निवासी बलपुरा थाना सिमलिया, जिला कोटा की लिखित तहरीर रिपोर्ट पर बालक गोपी के लापता होने के बाबत मुकदमा नम्बर 270/18, धारा 363 आयी.पी.सी. में दर्ज कर अनुसंधान सहायक पुलिस अधीक्षक, वृत चतुर्थ, कोटा शहर द्वारा किया जा रहा है। दौराने अनुसंधान बालक गोपी की पतारसी बाबत थाना भीमगंज मण्डी, कोटा शहर व अन्य दूसरी टीमें, जिसमें मानव तस्करी विरोधी यूनिट, कोटा शहर द्वारा गुमशुदा बालक गोपी की रेलवे स्टेशनों व अन्य शहरों के विमंदित चिल्ड्रन होम आदि विभिन्न जगह पर तलाश की गयी। गोपी के पिता का आरोप है कि आखिरी बार उसे पुलिस के दो सिपाही मोटर साइकिल पर बैठाकर ले जाते हुए देखे गये। किन्तु फरियादी द्वारा न इस बाबत एफ.आयी.आर. में किसी का नाम अंकित करवाया गया, न ही बाद में पुलिस अनुसंधान के दौरान दिनांक 14.06.2018 को जो 161 सी.आर.पी.सी. के बयान लेखबद्ध किये गये, उस समय भी फरियादी मोडूलाल व इसकी पत्नी कजोड़ी बाई ने किसी अपहरणकर्ता का नाम लिया। इसके पश्चात् इसके बड़े पुत्र रघुवीर ने भी अपने कथन में लेखबद्ध होने की दिनांक 23.06.2018 तक किसी अपहरणकर्ता का नाम नहीं लिया। फरियादी मोडूलाल द्वारा अपने साले की लड़की मीना का हवाला देते हुए पेश किये गये परिवादों में भीमगंज मण्डी के कांस्टेबल शिवराज और बीरबल पर बालक गोपी को ले जाने का आरोप लगाया गया है। फरियादी की रिश्तेदार मीना व उसके परिवार के अन्य सदस्य थाना भीमगंज मण्डी क्षेत्र के क्षेत्राधिकार वाले स्थान रेलवे स्टेशन कोटा जंक्शन के बाहर अनावश्यक रूप से घूमते रहते हैं और आने-जाने वाले यात्रियों से भीख मांगते रहते हैं। लेकिन जेब तराशी आदि की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रोटेक्टिव पुलिसिंग के तौर पर उक्त कांस्टेबलगण इन लोगों को समय-समय पर उक्त स्थान से हटाते रहते हैं। इन लोगों को उक्त स्थान पर इकट्ठे नहीं होने देने के कारण ये लोग उक्त दोनों कांस्टेबलगण को खूब बखूबी से पहचानते हैं। इसी कारण हो सकता है कि रंजिशवश उक्त कांस्टेबलगण का नाम बालक गोपी को ले जाने के सम्बन्ध में फरियादी और उसकी रिश्तेदार लड़की मीना के द्वारा लिया जा रहा है। फरियादी की रिश्तेदार मीना के जुबानी कथन के अलावा किसी अन्य गवाह से या तकनीकी साक्ष्य से कोई भी बात की ताईद नहीं हुई है कि गुमशुदा बालक गोपी का अपहरण शिवराज हैड कांस्टेबल या बीरबल कांस्टेबल द्वारा किया

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

गया हो। इसके विपरीत जो तथ्य सामने आया है, वह यह है कि 16.06.2018 को कोटा से दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेन स्वर्ण मंदिर मेल के एस 9 कोच में सवार वेंडर भंवर सिंह ने अपने कथनों में बताया कि उक्त बालक को उसने स्वयं ने दिनांक 16.06.2018 को उक्त सवारी गाड़ी में देखा। उस दिन उक्त वेंडर का लाइसेंस नहीं होने से उसके विरुद्ध रेलवे एक्ट के तहत कार्यवाही आर.पी.एफ. थाना, कोटा जंक्शन द्वारा की गयी। इससे उक्त गवाह द्वारा बालक गोपी को स्वतंत्र रूप से स्वर्ण मंदिर ट्रेन में दिनांक 16.06.2018 को घटना के 6 दिन बाद देखा जाना बताया गया है। इससे उक्त बालक गोपी का किसी के द्वारा अपहरण नहीं किया जाना और किसी व्यक्ति द्वारा बंधक नहीं बनाया जाना अब तक के अनुसंधान से स्पष्ट हुआ है। प्रकरण में गुमशुदा बालक गोपी की तलाश पतारसी व अनुसंधान जारी है। अब तक के अनुसंधान से बालक गोपी का किसी के द्वारा अपहरण किया जाना और किसी व्यक्ति द्वारा बंधक बनाया जाना सामने नहीं आया है। प्रकरण में गुमशुदा बालक गोपी की तलाश पतारसी व अनुसंधान निरन्तर जारी है।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, उसमें बताया गया था कि 2014 और 2019 के बीच में हमारे मुल्क में 3,18,748 बच्चे गुम हुए हैं और राजस्थान में 6,175 बच्चे गायब हैं, लापता हैं। जो रिपोर्ट भारत सरकार ने प्रकाशित की थी उसमें यह उल्लेख किया गया है कि मानव तस्करी से इनको जोड़कर देखा जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रकरण आज का नहीं है, एक साल आठ महीने पुराना है और इस प्रकरण को सदन में रखने से पहले मैं पुलिस के अधिकारियों से लगातार सम्पर्क में रहा हूं। काफी विस्तार से पुलिस ने जो प्रयास किये हैं, उसका उत्तर मेरे पास है। मैंने तो सिर्फ इतनी ही बात कही है कि जिस जिले से माननीय गृह मंत्रीजी आते हैं और जिस जिले से मैं आता हूं, वहां पुलिस और अपराधियों के बीच में गलत काम करने में अच्छा जबर्दस्त गठजोड़ है। अनेक प्रकरणों के अपराध में पुलिस लिप्त पायी गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, मोटर साइकिल पर बैठा कर ले जाते हुए इस बच्चे का जो वीडियो है, वह स्वयं मैंने देखा है। उसके पहले जो कोटा के आई.जी. हैं, जो आज नहीं हैं, उनका कहीं और स्थानांतरण हो गया है, एस.पी. का भी स्थानांतरण हो गया है, इन्होंने वह वीडियो स्वयं देखा है।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

मेरा तो इतना ही कहना है कि जिस जिले में पुलिस के लोग-बाग अपराध से जुड़े हुए हैं वहां आखिरी बार दो कांस्टेबल, और यह बच्चा बोल नहीं सकता, गूंगा-बहरा है, इसको ये पुलिस वाले अच्छी तरह से जानते हैं और यह भी जानते हैं, यह बात, जो इन्होंने दर्शायी, वह सही है, तो यह अत्यंत गम्भीर प्रकरण है कि मानव तस्करी से पुलिस के इंवाल्वमेंट में, क्योंकि हमारे यहां के पुलिस के लोग-बाग गोवा में रंगरेलियां मनाते हुए अपराधियों के साथ देखे गये हैं। उस पृष्ठभूमि में इसकी जांच कराना आवश्यक होगा।

(13.00 बजे)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बात का सवाल है कि पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ देखने को मिलता है, खास तौर पर कोटा शहर और कोटा जिले में इस प्रकार की कई घटनाएं हुई हैं, मैं खुद इस बात को स्वीकार करता हूं और जो आपने गोवा का आरोप लगाया है, उन लोगों को भी प्रताड़ित किया गया है, उन लोगों को भी नौकरी से बर्खास्त भी किया गया है और कइयों को 16 सी.सी. का नोटिस भी दिया गया है। यह बात सही है, लेकिन जिन दो व्यक्तियों के लिए आप कह रहे हैं, बीरबल और शिवराज के लिए, यह शिवराज हैड कांस्टेबल है और यह बीरबल भी आउटस्टैंडिंग कांस्टेबल है। मैं इन दोनों आउटस्टैंडिंग कांस्टेबल के बारे में आपको बताता हूं आपको ध्यान होगा कि भीमगंज मण्डी थाने में एक ज्वैलर का मकान था। ज्वैलर दुकान पर गया हुआ था और उसी के नौकर के द्वारा पीछे से चुपचाप आ करके उसकी पत्नी और उसकी लड़की की हत्या कर दी गयी थी। हत्या के तीसरे रोज ही, यह डबल मर्डर था और तीसरे रोज ही इस शिवराज नामक हैड कांस्टेबल ने वहीं मुलजिम पकड़ लिया था, क्योंकि इसके बराबर में ही वह मुलजिम बैठा हुआ था। उसके हाथ में जब 70,000 रुपये का मोबाइल उसने देखा तो उसको शक हुआ। उसने उसी वक्त उसको दबोच लिया और दबोच करके उससे हां भरवा ली कि हां साहब, वाकई मैंने मर्डर किया है। दूसरा आदमी, यह जो बीरबल है, इस बीरबल और शिवराज, इन दोनों की टीम ने ही जीवाणु को पकड़ा था, तो ये आउटस्टैंडिंग लोग हैं। यह हो सकता है कि ये लोग भिखारी हैं और थाना भीमगंज मण्डी के क्षेत्र में ही रेलवे का सारा क्षेत्र आता है और वहां पर बाकायदा हर कार पर, जो रेड लाइट पर वहां पर रुकती है, वहां पर ये भीख मांगते रहते हैं इसलिए इनको भगाने के लिए हो सकता है

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कि उसको बैठाकर ये कहीं जा रहे हों और वह वीडियो आपने देखा हो। लेकिन इस बाबत पुलिस के द्वारा जो प्रयास किये गये हैं, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): अध्यक्ष जी, मेरे पास जानकारी है। मैंने सब मान लिया। माननीय अध्यक्ष जी, जिन आउटस्टैंडिंग पुलिस वालों की ये बात कर रहे हैं, मैं सदन की नालेज में लाना चाहूंगा कि जो गोवा में पकड़े गये थे उनमें भी एक बहुत आउटस्टैंडिंग मोगा था, आउटस्टैंडिंग था वह। सारी डिजिटल धोखाधड़ी को वह ही पकड़ता था तो आउटस्टैडिंग लोगों में गलत काम करने की भी आउटस्टैंडिंग शक्ति होती है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि हो सकता है जो आप कह रहे हैं वह मैं उस बात से एग्री करता हूं। उसको आउटस्टैंडिंग क्यों बनाया गया था और कैसे बनाया गया था किन अधिकारियों के द्वारा उसको आउटस्टैंडिंग बताया गया था, उसके बारे में तो...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, किस्सा लम्बा हो जाएगा लेकिन ओखा, गुजरात के रेलवे स्टेशन पर आर.पी.एफ. स्टाफ को एक बालक गोपी के हुलिये के जैसा मिला, उस बालक को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये कोटा पुलिस को दिखाया गया। कोटा पुलिस ने उसके पिता मोडूलाल को बुला लिया। मोडूलाल ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग देख करके बता दिया कि हां यह मेरा लड़का गोपी है। उसका नतीजा यह हुआ कि गुजरात पुलिस भेज करके उस लड़के को यहां पर बुलाया गया। जब सामने आया तो मोडूलाल ने मना कर दिया कि यह लड़का मेरा नहीं है। इसका मतलब यह है कि पुलिस प्रयासरत है।

दूसरी बात मैं आपको और बताता हूं कि जिस तरीके से बबलू ठाकर ने नागदा में, नागदा से जो जानकारी मिली, और गुमशुदा गोपी को रेलवे स्टेशन के ऊपर उसने देखा, तो वहां पर किसी लड़के को स्वर्ण मंदिर ट्रेन में, वह दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ था, वह मंदबुद्धि था तो उसने हाथ जब आगे किया तो उसने कुछ चने इसके हाथ में दे दिये, दे करके इससे पूछा कि 'कहां' तो उसने कहा 'अहां', मतलब कहीं जा रहा हूं। इस तरीके की बात भी सामने

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आयी। उस दिन भी इस अवैध वेंडर के लिए भी पुलिस ने देखा कि कहीं वेंडर झूठ तो नहीं बोल रहा है, उस रोज उसकी ड्यूटी नहीं थी तो उसके खिलाफ केस भी बनाया तो उससे यह साबित होता है कि, साहब, वह वहां मौजूद था और मौजूद होकर देखा। उस वेंडर का इस परिवार से या पुलिस से कोई लेना-देना नहीं था इसलिए वह झूठ नहीं बोल सकता।

तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, राजस्थान पत्रिका में एक खबर छपी थी कि गद्दों में छुप करके यूरोप से अफ्रीकी आ रहे हैं। राजस्थान पत्रिका में जो फोटो छपी, वह फोटो देख करके पुलिस को यह डाउट हुआ कि शायद गोपी का फोटो हो तो राजस्थान पत्रिका के दफ्तर में जाकर पुलिस द्वारा वे दो फोटो मंगवाए गये। दो फोटो वहां से लिये और दो फोटो मोडूलाल गोपी के पिता से लिये गये। दोनों अलग-अलग लिफाफे में मुहरबंद करके एफ.एस.एल. को भेजे गये लेकिन एफ.एस.एल. की रिपोर्ट में यह आया कि ये दोनों फोटो अलग-अलग हैं। उसका पता नहीं लगा। मेरा निवेदन यह है कि पुलिस अभी तक प्रयासरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह पुराना केस हो चुका है। लेकिन यह विश्वास रखना चाहिए कि पुलिस के द्वारा जितने भी आज तक, मानव तस्करी विरोधी यूनिट के द्वारा और ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड वैबसाइट के द्वारा तथा थाना स्तर पर, यह भी बात होती है कि, साहब, टीवी में भी बराबर विज्ञापन देते हैं, समाचार पत्रों में भी लिखते हैं। मुश्तरे भी करवाए जाते हैं। गुमशुदा बच्चों के पास मोबाइल होने की स्थिति में तकनीकी साक्ष्य की तलाश भी की जाती है। बराबर कोशिश की जा रही है, लेकिन यह बच्चा मंदबुद्धि भी है, मंदबुद्धि के साथ-साथ मूक-बधिर भी है। अब ऐसे बच्चे को पकड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर भी लगातार पुलिस इस बात के लिए प्रयासरत है और मैं माननीय सदस्य को यही आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप विश्वास रखिए एक न एक रोज यह जरूर उसके परिवार को बरामद करके पहुंचा दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। 131, श्री संयम लोढ़ा।

माधव विश्वविद्यालय भुजेला (पिण्डवाड़ा) द्वारा आबंटन शर्तों की अवहेलना

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत माधव

(श्री संयम लोढ़ा)

विश्वविद्यालय भुजेला (पिंडवाड़ा) द्वारा आबंटन शर्तों की अवहेलना करने एवं बेशकीमती राजकीय भूमि पर अतिक्रमण पर कार्यवाही हेतु माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा, सिरोही को विश्वविद्यालय के लिए जमीन आबंटित की गयी। निजी विश्वविद्यालय को शिक्षा विभाग, ग्रुप-4, राज्य सरकार द्वारा 26.07.2007 की निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की गाइड लाइन के निर्देशों की पालना करनी होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विश्वविद्यालय की अनियमितताओं की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई। सरकार को शिकायत प्राप्त होने पर 07.04.2017 को तत्कालीन माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के गठन की जो रिपोर्ट है, वह तीन सदस्यों ने दिनांक 07.06.2017 को दी, जिसमें किसी तरह की कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पायी गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग, ग्रुप-3 के आदेश, दिनांक 17.05.2012 द्वारा मानव भारती ट्रस्ट को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पिंडवाड़ा तहसील में ग्राम भुजेला स्थित खसरा नम्बर 146/8, रकबा 69 बीघा 13 बिस्वा किस्म नहरी 2 में से 41 बीघा 5 बिस्वा एवं ग्राम वाडा के खसरा नम्बर 146/1, रकबा 17 बीघा 1 बिस्वा, किस्म नहरी 2 में से 8 बीघा 15 बिस्वा, कुल 50 बीघा भूमि भू-राजस्व अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत आबंटन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। यह है कि उक्त आदेश की पालना में जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा दिनांक 15.06.2012 को 50 बीघा जमीन आबंटित की गयी और मूल आवंटन नक्शा जारी किया गया। आबंटन की शर्त संख्या 4 में उल्लेख है कि भूमि का उपयोग सर्वथा उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए भूमि आबंटित की गयी है। शर्तों की पालना नहीं होने पर भूमि राज्य सरकार में निहित होगी। शर्त संख्या 5 में उल्लेख है कि आबंटित भूमि पर निर्मित भवन एवं संस्थान का उपयोग जनता के लाभ के लिए किया जाएगा। जिला कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार संस्थान द्वारा आबंटन से पूर्व इस सम्बन्ध में कोई पत्र पेश किया जाना नहीं पाया गया, बल्कि उप खण्ड अधिकारी पिंडवाड़ा के पत्रांक-1086, दिनांक 20.07.2018 से मानव भारती चैरिटेबल ट्रस्ट को मोजा-भुजेला के खसरा नम्बर 1/146, रकबा 28 बीघा 8

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

बिस्वा में से रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1963 के तहत आबंटित/नियमित करने के लिए जिला कार्यालय को प्रेषित प्रस्ताव के साथ संलग्न संस्था का उक्त पत्र दिनांक 10.04.2018 जिला कार्यालय को प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित अनुसार है, कंस्ट्रक्टेड एरिया 10 बीघा, स्पोर्टस ग्राउंड फैसिलिटीज 10 बीघा, हर्बल गार्डन/पार्क 10 बीघा, पार्किंग 5 बीघा और ओ.सी.एफ./रोड्स 15 बीघा।

उक्त संस्थान ने आबंटन के पश्चात दिनांक 25.06.2012 को उस भूमि का सीमांकन कर कब्जा सौंपने हेतु तहसीलदार पिण्डवाड़ा को लिखा। ग्राम भुजेला के खसरा नम्बर 146/3 बीघा 16 बिस्वा किस्म भूमि नहरी 2 में अप्रार्थी ने बिना इजाजत संवत् 2072 में खरीफ में परकोटा निकालकर अतिक्रमण किया था, जिसका प्रकरण नायब तहसीलदार, भावरी में दिनांक 02.09.2015 को मुकदमा नम्बर 3/2015 दर्ज हुआ एवं वाडा में खसरा नम्बर 2699/146 में 7 बीघा 5 बिस्वा किस्म नहरी 2 सरकारी जमीन पर उक्त संस्थान द्वारा बिना इजाजत संवत् 72 खरीफ में कब्जा कर परकोटा निकाल कर अतिक्रमण किया गया था। जिसका प्रकरण न्यायालय, नायब तहसीलदार, भावरी में दिनांक 02.09.2015 को मुकदमा संख्या 4/2015 दर्ज हुआ था। तरमीम दुरुस्ती का प्रकरण विचाराधीन होने से न्यायालय, नायब तहसीलदार, भावरी ने उक्त प्रकरण को ड्रोप कर दिया था एवं पटवारी हलका भारजा को, बाद तरमीम अतिक्रमण पाया जाता है तो, भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे। उप खण्ड अधिकारी, पिण्डवाड़ा के निर्णय दिनांक 14.09.2016 के अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत तरमीम दुरुस्ती के आदेश दिये गये थे, जिसको उप खण्ड अधिकारी, पिण्डवाड़ा के आदेश दिनांक 20.02.2018 द्वारा उक्त आदेश दिनांक 14.09.2016 को पुनरावलोकन करते हुए अपास्त कर दिया था। अत: मूल आबंटन आदेश के साथ संलग्न नक्शे अनुसार तरमीम कर दी गयी आबंटित भूमि के अतिरिक्त भूमि पर संस्थान द्वारा किये गये अतिक्रमण को चिह्नित करने के लिए उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाड़ा के आदेश, क्रमांक 1636/17.02.2020 द्वारा कमेटी गठित कर सीमांकन किया गया, जिसमें यह पाया गया कि माधव विश्वविद्यालय मानव भारती चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मोजा भुजेला के खसरा नम्बर 1/146 में रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर अवैध रूप से बहुमंजिला भवन एवं परकोटा बनाकर तथा मैदान पर

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है, जिसका प्रकरण 188/2020 बनाकर भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही के आदेश न्यायालय, नायब तहसीलदार, भावरी को जारी किये गये हैं तथा प्रकरण संख्या 189/2020 द्वारा मोजावाड़ा के खसरा नम्बर 2750/146 में 4 बीघा 15 बिस्वा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण दर्ज कर दिनांक 19.02.2020 को ट्रस्ट को दफा 1991 के तहत नोटिस जारी किये गये हैं, जिसकी आगामी पेशी दिनांक 28.02.2020 रखी गयी है।

उक्त भूमि पर अतिक्रमण पक्का निर्माण, परकोटा, जिसे पूर्व में हटा दिया गया था, उसका मलबा पड़ा है, उसको हटाने के निर्देश न्यायालय, नायब तहसीलदार, भावरी को दिये गये हैं। माधव विश्वविद्यालय, भुजेला, तहसील पिण्डवाड़ा द्वारा वन विभाग के केवरली वन खण्ड के खसरा नम्बर 23 व 24 पर अनधिकृत कब्जा कर पक्की दीवार का निर्माण किया गया था, जिसके क्रम में दिनांक 12.08.2019 एवं 24.01.2020 को वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त सर्वे कर वन विभाग की भूमि पर किये गये अनधिकृत कब्जे, पक्की दीवार को जे.सी.बी. की सहायता से ध्वस्त कर उक्त भूमि को वन विभाग के कब्जे में लिया गया। मानव भारती ट्रस्ट द्वारा दिनांक 26.11.2015 को प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट, 1956 तरमीम दुरुस्ती बाबत लैंड रिकार्ड आफिसर एस.डी.ओ. पिण्डवाड़ा को प्रस्तुत किया गया था, जो दिनांक 24.09.2016 को निरस्त कर लैंड रिकार्ड आफिसर एस.डी.ओ. ने अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार करते हुए मौजा भुजेला के खसरा नम्बर 2856/146 में पूर्व में की गयी तरमीम को निरस्त को करते हुए प्रार्थी के कब्जे अनुसार तहसीलदार, पिण्डवाड़ा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस में संशोधन अनुसार तरमीम करने के आदेश जारी किये गये हैं। जिसके पुनरावलोकन द्वारा दिनांक 20.02.2018 को तत्कालीन लैंड रिकार्ड आफिसर, एस.डी.ओ., पिण्डवाड़ा ने त्रुटिपूर्ण मानते हुए अपास्त किया और मूल आबंटन आदेश के अनुरूप तरमीम करने के आदेश तहसीलदार, पिण्डवाड़ा को प्रदान किये।

प्रार्थना-पत्र धारा 136 के अन्तर्गत आदेश न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत दिये गये हैं। कार्यालय रिकार्ड के अनुसार तत्कालीन उप खण्ड अधिकारी, पिण्डवाड़ा के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं किया जाना पाया गया है। जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जयपुर को 11.03.2019 के द्वारा अवगत कराया गया है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत को भवन निर्माण की स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने का कोई प्रावधान नहीं होने तथा ग्राम पंचायत, भारजा द्वारा जारी भवन निर्माण स्वीकृति पंचायती राज नियम 161 (2) (ख) का उल्लंघन जारी किया गया है तथा सरपंच, ग्राम पंचायत भारजा के विरुद्ध धारा 38 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति पिण्डवाड़ा को दिनांक 13.10.2017 द्वारा निर्देशित किया गया है। संस्था को सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये जाने पर ही निर्माण कार्य शुरू करने हेतु पाबंद किया गया है। जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा पंचायती राज विभाग, जयपुर से निर्माण स्वीकृति जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी तथा निर्माण स्वीकृति फीस हेतु फीस की दर के बाबत मार्गदर्शन चाहा है, जो प्रक्रियाधीन है।

संस्था द्वारा मुख्य द्वार के पास 5 दुकानें निर्मित की गयी हैं, जिनकी लम्बाई 70X61 फीट नेशनल हाईवे 27 के मध्य बिन्दु से 132 फीट के दायरे में संस्थान के प्रवेश द्वार के आगे का रैम्प, बोर्ड, मंदिर और सीढ़ियां, दुकान के आगे का चबूतरा निर्मित है, जिसकी माप करने पर लम्बाई X चौड़ाई 270X100 फीट, कुल 27,000 वर्गफीट का निर्माण नेशनल हाईवे की रोड सीमा के 132 फीट के दायरे में निर्मित पाया गया। संस्थान द्वारा मुख्य द्वार के पास निर्माण की जांच उप खण्ड अधिकारी, पिण्डवाड़ा द्वारा किये जाने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा मुख्य द्वार के पास 5 व्यवसायिक दुकानें निर्मित की गयी हैं, जिसकी लम्बाई/चौड़ाई 70X60 फीट है। इस प्रकार संस्थान ने भूमि आबंटन आदेश दिनांक 15.06.2012 में वर्णित शर्त संख्या 4 का उल्लंघन किया है। उप खण्ड अधिकारी, पिण्डवाड़ा के आदेश क्रमांक 1636, दिनांक 17.02.2020 द्वारा कमेटी गठित कर सीमांकन किया गया है, जिसमें पाया गया है कि माधव विश्वविद्यालय, मानव भारती चैरिटबल ट्रस्ट द्वारा मौजा भुजेला के खसरा नम्बर 1/146 में रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर अवैध रूप से बहुमंजिला भवन एवं परकोटा बनाकर तथा मैदान पर कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है, जिसका प्रकरण संख्या 188/2020 बनाकर भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही के आदेश नायब तहसीलदार, भावरी को जारी कर दिये गये हैं तथा मोजावाड़ा के खसरा नम्बर 2750/146 में 4 बीघा 15 बिस्वा

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया। पक्का निर्माण परकोटा, जिसे पूर्व में हटा दिया गया, उसका मलबा मौके पर पड़ा होने से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 189/2020 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किये गये हैं। आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.02.2020 को रखी गयी है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य बैठें। अंकित नहीं होगा। यह कोई तरीका नहीं है। आप, जब मन हो खड़े हो जाएंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में जो पूछा गया था, उसका कोई भी लिखित उत्तर आपने विधान सभा को नहीं दिया और एक लाइन में अपना जवाब यहां पर दे दिया। आपने यह जो जवाब दिया है, उससे पूरे राजस्थान की जनता के सामने यह जानकारी आ गयी कि आपने भू-माफिया को जमीन दी थी या एक शिक्षण संस्था को दी थी। कानून का मखौल उड़ाने का यह एक क्लासिक एग्जाम्पल है।

माननीय मंत्रीजी, आप तो खुद वकील रहे हैं। 136 में कलेक्टर ने जवाब दिया है कि ये मूल आबंटन नक्शा जारी किया गया और 2012 में यह आबंटित की गयी है। 136 में एस.डी.ओ. ने 2016 में जो आर्डर किया, क्या वह उसके लिए काम्पीटेंट था। उसके बाद उसके आर्डर को दूसरे एस.डी.ओ. ने 2018 में क्वैश किया, क्या वे इसके लिए काम्पीटेंट थे? कलेक्टर ने इस संस्थान को पाबंद किया कि वह अवैध निर्माण नहीं करे, इसके बाद उसने 7 मंजिला भवन खड़ा कर दिया। उसके तीन साल बाद कलेक्टर चिट्ठी लिख रहा है, राज्य सरकार को, उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए भेजा है। आप खुद यह स्वीकार कर रहे हैं कि वर्णित शर्त संख्या 4 का उल्लंघन किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आबंटन की शर्त संख्या 4 का उल्लंघन करने के कारण आपने यह जो भूमि आबंटित की है, वह राज्य सरकार में निहित करने का आप इरादा रखते हैं, नम्बर वन। नम्बर 2, जिन एस.डी.ओज. ने कोर्ट में बैठकर अनलॉफुल काम किया है, उन दोनों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही

(श्री संयम लोढ़ा)

करने की मंशा रखते हैं? तीसरा, जिस कलेक्टर ने 2019 में यह चिट्ठी लिखी है, उस कलेक्टर के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चीज तो यह आयी कि धारा 4 का उल्लंघन किया गया है तो आप क्या करना चाहते हैं? हमारे एस.डी.ओ. उप खण्ड अधिकारी, पिण्डवाड़ा के द्वारा पाया गया है कि 70X60 फीट, जिसकी लम्बाई संस्थान को भूमि आबंटन आदेश दिनांक इतने में वर्णित शर्त संख्या 4 का उल्लंघन किया गया है। यह एस.डी.ओ. का आब्जर्वेशन है, सरकार के पास आएगा, सरकार इसका परीक्षण कराएगी। जो आबंटन की शर्तें हैं, अगर उनकी पालना नहीं पायी गयी तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्यवाही होगी।

दूसरा, आपने कहा कि एस.डी.ओ. ने 136 में क्यों कर दिया, गलत कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एस.डी.एम. ही लैंड रिकार्ड आफिसर होता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): एल.आर. एक्ट के तहत 136 में दुरुस्ती करने का अधिकार एस.डी.एम. को होता है। एस.डी.ओ. ने पहले जो संशोधन किया, आदेश पारित किया, वह जुडिशियल कैपेसिटी में किया था। दूसरे एस.डी.ओ. ने चूंकि उसकी रिव्यू पीटिशन सुनी है, या तो किसी भी आदेश की आप रिव्यू ला सकते हैं या उसकी अपील की जा सकती है। वह रिवीजन में गया, नहीं रिव्यू पीटिशन, रिवीजन अलग चीज है। किसी आदेश की रिवीजन होती है, रिव्यू उसी फैसले के ऊपर पुनरावलोकन की दरख्वास्त दी जाती है। पुनरावलोकन उसने करके यह पाया कि गलत आदेश किया है तो उसको निरस्त कर दिया गया है। तीसरी और कोई बात हो तो कहें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सारी चीज़ें रिकार्ड पर आ गयीं। 132 फीट की नेशनल हाईवे की पैरीफेरी के अन्दर 27 हजार फुट निर्माण कर दिया। सात मंजिला भवन अवैध रूप से खड़ा कर दिया। फोरेस्ट की लैंड पर कब्जा कर दिया। सरकारी जमीन सवा चार बीघा पर अवैध निर्माण कर दिया। ये कोई यूनिवर्सिटी है या माफिया है?

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न क्या है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको स्वयं को ध्यान में है कि इसका प्रमोटर इतना शातिर है कि आपके खुद के नाम का भी

(श्री संयम लोढ़ा)

दुरुपयोग करता है, इस यूनिवर्सिटी के मामले के अन्दर, आपकी खुद की जानकारी के अन्दर है।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। ये खड़े हैं और आप बोल रहे हैं। प्लीज नीचे बैठिए।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): 000

श्री अध्यक्ष: आपका मामला होगा, क्या मतलब है? आपको अधिकार था बोलने का, आप नीचे बैठें। अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, आप सुन नहीं रहे हैं। मैं आपको नेम कर दूंगा। I will name you, आप सीनियर आदमी हैं। आपको भी अधिकार है। आप लेकर आइए, कोई मना कर रहा है क्या?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस यूनिवर्सिटी के द्वारा डिग्रियां बेचना..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, टू द पाइंट।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): टू द पाइंट ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे तथ्य रिकार्ड पर आने के बावजूद भी सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। माननीय सदस्य, बैठें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें तीन चीजें हैं। एक तो यह है कि जो जमीन आबंटित की गयी है, क्या उसकी पालना वह कर रहा है या नहीं कर रहा है? एक इश्यु यह है कि उसने सरकारी भूमि के ऊपर अवैध निर्माण कर लिया, बहुमंजिला कुछ बना लिया। तीसरा, यह है कि नेशनल हाईवे के ऊपर उसने अतिक्रमण कर लिया। चौथा, यह है कि जो एस.डी.ओ. ने किया, वह उसके अधिकार में था या नहीं। मैंने एस.डी.ओ. वाला तो जवाब दे दिया। जो अतिक्रमण सरकारी भूमि पर बिना आबंटन के किया गया है, उसकी जांच कर ली गयी है, सीमांकन कर लिया गया है और उस नायब-तहसीलदार को धारा 91 में कार्यवाही करने का अधिकार है, 28 तारीख है। मैं आपके माध्यम से सदन को और सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र सरकार, जिस जमीन को आबंटित नहीं किया गया था, उसके ऊपर अगर उसका किसी भी प्रकार का अतिक्रमण है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री अंजना उदयलाल। माननीय सदस्य, मंत्रीजी खड़े हैं, बैठे-बैठे बोल रहे हैं। यह गलत है।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा-54(14) के अन्तर्गत निम्नांकित अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड का अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

1. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2018-19;

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

2. राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2018-19;

दी राजस्थान अरबन को-ऑपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड का अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं आक्षेप-पत्र (वर्ष 2018-19)

3. दी राजस्थान अरबन को-ऑपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं आक्षेप-पत्र वर्ष 2018-19;

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

4. राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड, जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2018-19;

राजस्थान सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की आडिट रिपोर्ट (वर्ष 2018-19)

5. राजस्थान सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, जयपुर की आडिट रिपोर्ट वर्ष 2018-19;

(श्री अंजना उदयलाल)

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड का

आडिट प्रतिवेदन एवं पूर्ति रिपोर्ट (वर्ष 2018-19)

6. राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड, जयपुर का ऑडिट प्रतिवेदन एवं पूर्ति रिपोर्ट वर्ष 2018-19;

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड की

लेखा परीक्षा रिपोर्ट (वर्ष 2018-19)

7. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड की लेखा परीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2018-19;

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड की

लेखा परीक्षा रिपोर्ट (वर्ष 2018-19)

8. राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर की लेखा परीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2018-19.

श्री अध्यक्ष: याचिका का उपस्थापन। श्री धर्मेन्द्र कुमार।

याचिका

पीलीबंगा में खेल स्टेडियम का निर्माण

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में खेल स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री चेतन सिंह चौधरी।

डीडवाना में वर्षा जल एवं गंदे पानी की निकासी व्यवस्था

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के नगरपालिका क्षेत्र में वर्षा जल एवं गंदे पानी की निकासी की कार्ययोजना बनाये जाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती मंजु देवी।

जायल में सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पद

श्रीमती मंजु देवी (जायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र जायल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरे जाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री फूल सिंह मीणा।

उदयपुर ग्रामीण में क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण स्थित क्षतिग्रस्त पुलिया का पुन: निर्माण कर जनता को राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री पानाचन्द मेघवाल।

कुंजेड़ (बारां) में पुलिस चौकी का पुलिस थाने में क्रमोन्नयन

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में पुलिस चौकी कुंजेड़, जिला बारां को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी स्टेटमेंट देंगे।

शासकीय वक्तव्य

राजकीय समारोह में माननीय विधायकों का प्रोटोकोल

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, शासन द्वारा समय-समय पर परिपत्र/आदेश जारी किये जाकर राजकीय भवनों, आंशिक अथवा पूर्ण रूप से राजकीय धनराशि से निर्मित भवनों के शिलान्यास/उद्घाटन कार्यक्रम व अन्य राजकीय समारोह, जो राजकीय धनराशि से आयोजित हों, चाहे वे किसी राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम या स्वायत्तशासी...

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी खड़े हैं, प्लीज, आप बैठिए। यह तरीका नहीं है, बोल रहे हैं, आप खड़े हो गये। आप पाइंट आफ आर्डर करके कर सकते हैं लेकिन यह तरीका नहीं है कि आप बीच में बोलें। आपको अधिकार है। माननीय चीफ व्हिप साहब, माननीय सदस्य ने कहा है आफिसर्स दीर्घा में व्यवस्थाओं का ध्यान रखें। मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दोबारा से बोलूं?

श्री अध्यक्ष: आप आगे पढ़िए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ठीक है।

स्वायत्तशासी संस्था के हों, में जन-प्रतिनिधियों यथा सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, नगरीय निकायों के मेयर, सभापति, अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं जन-प्रतिनिधियों विशेषत: कार्यक्रम स्थल से सम्बन्धित जन-प्रतिनिधिगण को आवश्यक रूप से आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में निर्दिष्ट किया गया है। परंतु समय-समय पर माननीय जन-प्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों से स्पष्ट होता है कि अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार से जारी इन परिपत्रों/आदेशों की पालना में लापरवाही बरती जा रही है, जो कि अत्यंत गंभीर विषय है। अत: उक्त क्रम में जारी परिपत्रों, परिपत्रों का वर्ष पढ़ देता हूं। काफी लंबा-चौड़ा है, 1995, 1999, 2002, 2007, 2011, 2015 और 2018। इसके पहले, जो आखिरी में निकला, वह 2018 में निकला कि अतिक्रमण में निम्नलिखित दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते हैं, आपरेटिव पार्ट है।

(1) राजकीय भवनों आंशिक अथवा पूर्ण रूप से राजकीय धनराशि से निर्मित राजकीय भवनों/सार्वजनिक भवनों के शिलान्यास/उद्घाटन कार्यक्रम व अन्य राजकीय समारोह, जो राजकीय धनराशि से आयोजित हों, जो किसी राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम या स्वायत्तशासी संस्था, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के हों, में स्थानीय जन-प्रतिनिधियों यथा सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, नगरीय निकायों के मेयर, सभापति, अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं जन-प्रतिनिधियों को, विशेषत: कार्यक्रम स्थल से सम्बन्धित जन-प्रतिनिधिगण को आवश्यक रूप से आमंत्रित किया जाए।

(13.29 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

(2) माननीय जन-प्रतिनिधियों को राजकीय भवनों के शिलान्यास/ उद्घाटन, सार्वजनिक समारोह से सम्बन्धित सूचनाएं तीव्रतर संचार साधनों/माध्यमों से भेजी जाएं, ताकि वे समय पर उन्हें मिल जाएं।

(3) यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जन-प्रतिनिधियों के द्वारा सूचना की प्राप्ति की पुष्टि सम्बन्धित अधिकारी के द्वारा कर ली गयी है।

(4) जनप्रतिनिधि के बैठने की समुचित व्यवस्था की जाए तथा ध्यान रखा

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जाए कि समारोह में आमंत्रित किसी जन प्रतिनिधि को, किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। समारोह में आमंत्रित जन प्रतिनिधियों के ससम्मान बैठने की व्यवस्था की जाए।

(5) सरकारी सेवकों को सांसदों/विधायकों से सम्पर्क के दौरान सदैव शिष्टता व सम्मान दर्शित करना चाहिए।

(6) इस बात का भी सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए कि उन्हें क्या कहना है। उन्हें धैर्यपूर्वक सुनना व उचित जवाब देना चाहिए।

(7) राजकीय भवनों के शिलान्यास/उद्घाटन/लोकार्पण आदि जन प्रतिनिधियों के द्वारा ही सम्पन्न करवाए जाएं। अधिकारीगण राजकीय भवनों का शिलान्यास/उद्घाटन/लोकार्पण आदि नहीं करें। शिलालेखों पर अपना नाम भी अंकित नहीं करें।

(8) राजकीय कार्यों को विकास आदि से सम्बन्धित क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, अधिकारी उनके बारे में अनावश्यक घोषणा नहीं करें, न ही कोई आश्वासन दें।

(9) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों/ भवनों एवं बस्तियों अथवा राज्य सहायता से निर्मित विभिन्न परियोजनाओं के नाम भी अधिकारियों द्वारा संबोधित नहीं किये जाएं।

(10) राज्य सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न अभियानों, विभिन्न जन सुनवाई कार्यक्रमों और राजकीय समारोह में अधिकारीगण साफ़ा-माला नहीं पहनेंगे।

सभी सम्बन्धित अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिशा निर्देशों की अवहेलना को राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम, 1971 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा तथा दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में ली जाएगी।

अत: समस्त राजकीय विभागों, राजकीय उपक्रमों, बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्था, आदि में पदस्थापित समस्त अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, 13.04.2018 को प्रशासनिक सुधार समन्वय विभाग/अनुभाग-एक से आदेश जारी हुए थे। उसके अतिक्रमण में लगभग वही बातें दोहरा दीं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, सवाल इस बात का है कि आज मंत्री महोदय को यह स्टेटमेंट क्यों देना पड़ा। राजस्थान की जन आदत बन गयी, हर पांच साल में सत्ता परिवर्तन की। आज हम सब सदन में बैठे हैं, हम सब जन प्रतिनिधि हैं। चाहे वह जन प्रतिनिधि सत्तारूढ़ दल के हों या इस दल के हों। इन्होंने सर्कुलर की बात कही। 2018 के सर्कुलर के अतिक्रमण में, मैं 2018 के सर्कुलर के दो शब्द, जो विशेष थे, वह पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

दिनांक 06.03.2018 को दी गयी अध्यक्षीय व्यवस्था, विधान सभा के अध्यक्ष जी ने कहा कि उन्हें अब विधान सभा के विशेषाधिकार हनन का दोषी भी माना जा सकता है। अगर किसी कार्यक्रम के अन्दर जन प्रतिनिधियों का सम्मान नहीं होगा तो उनको दोषी भी माना जाएगा। यह बात पहले भी थी कि राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम, 1971 के विरुद्ध परिपत्र का उल्लंघन होगा, उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी। मैं पूछना चाहता हूं, आपका शासन आ गया, शासन में अदला-बदली होती रहती है, यह क्या कारण है?

सभापति महोदय, दूसरों की बात नहीं, मैं लगातार एक विधान सभा से सात बार कांग्रेस को पीटकर आ रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैंने एक आयुष औषधालय का उद्घाटन कर दिया, जिनको मैंने हराया, अगर उनका बयान सुनकर पढ़ाऊं, इन्हें पट्टी लगाने का शौक है, विधान सभा सत्र के बाद दुबारा उद्घाटन करूंगा, मंडेलिया। सभापति महोदय, यह एक मंडेलिया नहीं। आप देखें, चित्तौड़ में जो हुआ, नव निर्मित भंडार गृह का उद्घाटन, अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान त्रिलोकचंद जाट, अध्यक्ष, ग्रामीण ब्लाक कांग्रेस कमेटी, चित्तौड़गढ़; मुख्य अतिथि हैं सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, मुख्य समन्वयक, ए.आई.सी.सी. सदस्य चित्तौड़गढ़। इसमें पुष्पा सिद्ध, पूर्व प्रधान; श्रीमती संतोष मीणा, पूर्व प्रधान; यह क्या है? अगर इस प्रकार के कार्यक्रम हों, सवाल इस बात का नहीं है कि आपने परिपत्र जारी कर दिया, माला भी नहीं पहनेंगे। यह किंवदन्ती बन गयी, विशेष तौर से आपके यहां से इनको संरक्षण मिल जाता है, कभी प्रभारी मंत्रीजी कह देते हैं कि यहां का एम.एल.ए. होगा राजेन्द्र राठौड़, जीत गया तो जीत गया, हमारी सरकार है, हम उद्घाटन करेंगे। मैं मेरा उदाहरण दे रहा हूं। मैं सात बार जीता हुआ व्यक्ति हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र रतनगढ़ में अम्बेडकर भवन बी.जे.पी. के शासनकाल में स्वीकृत हुआ, बी.जे.पी. के शासनकाल में पूरा हुआ। आयुष औषधालय जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, हमारी पट्टी तोड़कर इसका उद्घाटन दुबारा करवाएंगे आप?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, हमारी हालत क्या है, प्रभारी मंत्री जाते हैं, वहां अपना दरबार लगाते हैं, जिला कलेक्ट्रेट में मीटिंग करते हैं, हम अगर उस परिसर में, सभा कक्ष में प्रवेश कर जाएं तो, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, अपने आप कुर्सी उठाकर एक कोने में बैठ जाएं तो बैठ जाएं, यह क्या हो रहा है? हम डैमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं, हम लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं।

इस प्रकार का व्यवहार एक बार नहीं, प्रोटोकाल की एक लिस्ट निकली है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, Table of Precedence issued by the Government of Rajasthan, अध्याय 1-3 (बी) इसमें नोटिफिकेशन जारी हुआ है इस नोटिफिकेशन में 23वें नम्बर पर चीफ सैक्रेटरी आफ राजस्थान, 22वें नम्बर पर मैम्बर आफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली, यह प्रोटोकाल तोड़ दीजिए। आज चीफ सैक्रेटरी से ऊपर हमें प्रोटोकाल में रखा गया है। जब कभी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, प्रोटोकाल की लाइन में चीफ सैक्रेटरी के आगे हमें खड़ा करते हो, हमारे साथ क्या हो रहा है? जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य को ग्राम सभा में इसलिए नहीं जाने दिया कि ग्राम सभा में इनसे हारे, वे पहले बैठे थे। मैं समझता हूं कि यह परिपत्र जारी किया है, लेकिन आप एकाध के विरुद्ध कार्यवाही करें।

सभापति महोदय, मैंने उद्घाटन कर दिया, बिल्डिंग खाली पड़ी है, आयुष औषधालय की आठ करोड़ से बनी बिल्डिंग में इसलिए स्टाफ शिफ्ट नहीं हुआ कि राजेन्द्र राठौड़ उद्घाटन कर आया, कौन होता है। यह पीड़ा मेरी नहीं है, हर एक के मन में पीड़ा है।...(व्यवधान) ये हालात बने हुए हैं। मैं आज जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मंत्री महोदय, गरूर में मत रहो। समय का चक्र घूम रहा है। समय का पहिया घूमने के साथ अगर आप यह चाहते हो कि इसी प्रकार का व्यवहार हम करें, तो आपको कैसा लगेगा? समय बता रहा है, 0.5 फीसदी का अंतर हे। हम भी वहां आ सकते थे। इसलिए गरूर में मत रहो। आपके मंत्री, प्रभारी मंत्री, ज़िले के मंत्री, विभाग के मंत्री जब यह कहेंगे कि उद्घाटन मत करवाना, उद्घाटन की आवश्यकता नहीं है, जब खुद आपके मंत्री यह कहेंगे कि उद्घाटन कर दिया, उद्घाटन स्थल पर आप चले गये, सभापति महोदय, ए.ईएन. नहीं आता जे.ईएन. नहीं आता। राजस्थान में यह पहली बार हो रहा है, हम अगर कहीं दौरे पर चले जाएं, टेलीफोन करके कहें कि मैं अमुक गांव की चौपाल पर खड़ा हूं, जे.ईएन. साहब यहां पानी आये 15 दिन हो गये, तो कहते हैं कि आप दफ्तर में आ जाना, यह क्या है? आप इन ब्यूरोक्रेट्स

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

को सर पर नचा रहे हो। यह आपको भी डसेंगे और हमें भी डसेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि अब तक हमारी जो शिकायतें हैं, इस बात को यूं मत छोड़ो। आप हमारी शिकायतें लीजिए, शिकायतों के आधार पर आप सी.सी.ए. में कार्यवाही करो, रूल्स में कार्यवाही करो। तत्कालीन अध्यक्ष जी ने इस कुर्सी पर बैठकर कहा, उन पर विशेषाधिकार हनन का मामला जारी हो, तब इनको ठीक अक्ल आएगी।

सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत पीड़ाजनक बात है। हम अपने आपको अपमानित महसूस करते हैं। मुझे कहते हुए दु:ख और तकलीफ है। अगर मैं न करूं तो मेरे सारे मैम्बर्स से पूछ सकते हो कि क्या हालत हो रही है ...(व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, अलाउ नहीं करूंगा। बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। माननीय सदस्य, विराजिए। परम्पराओं का निर्वहन कीजिए। (व्यवधान)

(सदन कूप में)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आगमन)

माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर जाइए। माननीय सदस्य, अपने स्थान पर जाइये। अंकित नहीं होगा। विराजिए। अपने स्थान पर जाइए। प्लीज, सहयोग करें। (व्यवधान) अपने स्थान पर जाइए। प्लीज, अपने स्थान पर जाइए। माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर जाइए। आपकी बात सुन ली, सरकार के संज्ञान में आ गयी। अपने स्थान पर जाइए। अपने स्थान पर जाइए। प्लीज, सहयोग करें, प्लीज, अपने स्थान पर जाएं। पधारिए, पधारिए, स्थान पर जाइए, विराजिए, विराजिए। अपने स्थान पर जाइए। विराजिए, विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, विषय गम्भीर है। यह केवल पक्ष और विपक्ष के लिए नहीं है। जन प्रतिनिधि आप भी हो सकते हैं, जन प्रतिनिधि हम भी हो सकते हैं। आपने समय पर निर्देश जारी कर दिये, कई बार जारी कर दिये। इस विषय पर सदन में कई बार मसले पहले भी उठ चुके हैं, चर्चा हो चुकी है। इस चर्चा से कुछ समस्या का समाधान नहीं होगा। केवल यहां बोल लेंगे, छप जाएगा, इससे अर्थ नहीं है। मैं चाहता हूं कि जहां-जहां इस प्रकार की घटना हुई, जिस-जिस अधिकारी की उपस्थिति में हुई, उन सारे प्रकरणों को इकट्ठा करें और प्रत्येक की जांच करके सम्बन्धित

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अधिकारी को लगाएं। वास्तव में जहां जिसने जिस प्रकार की भी गलती की है, अगर उसे आप दण्ड नहीं देंगे तो आपका और हमारा बोलना निरर्थक हो जाएगा। अभी हम बोल रहे हैं, अगली बार आप बोलोगे। ये अधिकारी इसी तरह से आपकी और हमारी बेइज्जती करते रहेंगे।

मैं सोचता हूं कि मैं विषय को बहुत ज्यादा लम्बा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि इसकी कोई पुख्ता व्यवस्था तभी हो सकेगी, चाहे आपके साथ हुआ हो, तो भी शिकायत करिए, हमारे साथ हुआ तो भी हम शिकायत करें। प्रत्येक शिकायत के निस्तारण के लिए कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, जिसको भी आप समझते हैं, उसे लगाइए, और लगाने के बाद प्रकरण के अनुसार विषय का निस्तारण करके उसका कोई हल निकालेंगे, तब तो इसका परमानेंट हल होगा। बाकी यह जो निर्देश जारी करना, ये निर्देश तो पच्चीसों बार जारी हो गये और उसके बाद भी उनका उल्लंघन हो गया। निर्देश जारी करना समस्या का स्थायी हल नहीं है। स्थायी हल यह है, चाहे कोई भी हो, आज आप हैं, कल मैं होऊंगा, कोई तीसरा भी होगा। आज मेरे साथ हुई, कल आपके साथ भी होगी। मैं सोचता हूं कि जन प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुनकर आता है। उसका मान-सम्मान होना हम सबका उत्तरदायित्व है। आज हम हैं, इस कारण से नहीं। आज हम हैं, कल हम पूर्व हो जाएंगे। लेकिन कम से कम जन प्रतिनिधि का सम्मान इस लोकतंत्र में बना रहे, इसके लिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से भी विनम्र निवेदन है कि प्रत्येक के साथ जो भी घटना हुई है, उसको लिखित में दें। उसके बाद किसी जिम्मेदार अधिकारी को लगा करके, जब उसमें आपको प्रूव हो जाता है कि हां इसमें इस प्रकार की अनियमितता हुई है, गलत नाम लिख दिये गये हैं, या उसको नहीं आने दिया। अभी जहाजपुर के माननीय सदस्य को तो मीटिंग में ही नहीं जाने दिया। मतलब उनके साथ जिस प्रकार की हाथा-पाई की स्थिति आ गयी, ... (व्यवधान) अब ऐसी स्थिति है तो ऐसा लगता है कि मैं सोचता हूं ... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं सामान्य रूप में ही आपसे कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं नहीं, आप इस आसन पर विराजमान हैं। इस लोकतंत्र के आसन का सम्मान रखना, मैं सोचता हूं कि आपकी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जिम्मेदारी है। हमारा तो कष्ट हो सकता है लेकिन भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों, इसकी जिम्मेदारी आसन की है। मैं चाहूंगा कि पुख्ता व्यवस्था, कोई माननीय सदस्य उधर से बोलना चाहें तो बोलें, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप और हम सब चाहते हैं कि इस प्रकार की एक तरह से जन प्रतिनिधि की तौहीन न हो। इसकी पुख्ता व्यवस्था करने के लिए कोई परमानेंट रास्ता और तरीका निकाल करके, और जो हो चुकी है, उसकी जांच के आदेश दे करके उसकी जांच कराएं, इतना ही निवेदन है।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज, एक मिनट विराजिए आप, एक मिनट विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य आप बीती बता दें। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सदस्य की बात, जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य की बात ...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, आज पता लग रहा है, जब मैंने प्रश्न लगाया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए आप। विराजिए। विराजिए। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, आज पता लग रहा है...(व्यवधान) हम अनुरोध करते हैं कि किसी के साथ ऐसा नहीं हो... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, आपके नेता महोदय बोल लिए। आप विराजिए, एक मिनट, मैं बात कर रहा हूं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): लेकिन क्या हुआ था पिछली साल। पिछले चार-पांच वर्षों में क्या किया। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट।

श्री सभापति: आप बोलेंगे?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं चाहता हूं कि माननीय ...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): प्रश्न लगाया, फिर भी क्या कहा। बुलाते ही नहीं थे, माननीय सभापति महोदय ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्या। (व्यवधान) विराजिए आप। मैं अलाउ नहीं करूंगा। अंकित नहीं होगा। विराजिए आप, विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, प्लीज। एक मिनट। आप लोगों को सदन चलाना है? प्रतिपक्ष के माननीय नेता अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ये भावनाएं व्यक्तिगत माननीय नेता, प्रतिपक्ष की नहीं हैं। यह परम्परा है। आज इधर है, कल कोई उधर होगा, उधर वाला इधर होगा। ये गम्भीर मसला है। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय, बैठिए आप। आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। हम इसको एंडलैस नहीं कर सकते। इस पर शाम तक चर्चा नहीं करा सकते। हमको समाप्त करना पड़ेगा। निश्चित रूप से मामला गम्भीर है। मैं स्वयं भी माननीय नेता, प्रतिपक्ष की बात से सहमत हूं। माननीय मंत्री महोदय, मैं यह निर्देश देता हूं कि इस तरह की जो भी घटनाएं घटित हों,... (व्यवधान) विराजिए, जो भी माननीय सदस्य, जिनके साथ यह बात हुई है, वे अपनी बात माननीय अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दें। माननीय मंत्री महोदय, आप यह बात एन्श्योर करें कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। चर्चा समाप्त। श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक सैकिण्ड।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसका जवाब दे देता हूं, साहब। आपने जो शंकाएं प्रकट कीं ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक सैकिण्ड, एक सैकिण्ड। आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, एक सैकिण्ड। जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य के साथ जो घटना हुई, वह हमारे विधायक दल की बैठक में भी अपनी बात कहते-कहते रो पड़े। इतना मैन हैंडलिंग जहां हुआ है, मैं सोचता हूं कि एक सैकिण्ड उनके मन की बात सुन लें, वे हल्के हो जाएंगे।

श्री सभापति: वे अपनी बात लिखकर माननीय अध्यक्ष तक पहुंचा दें। इसको समाप्त करना पड़ेगा। (व्यवधान) समाप्त करना पड़ेगा। अलाउ नहीं करूंगा। श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय...

श्री सभापति: बिलकुल नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): पाइंट आफ इंफार्मेशन।

श्री सभापति: बिलकुल नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): पाइंट आफ इंफार्मेशन। पाइंट आफ इंफार्मेशन।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में आ चुकी है यह बात। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए आप, विराजिए आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, जैसा अभी उप नेता महोदय ने बताया कि ऐसे परिपत्र तो पहले भी निकल चुके हैं, आप इस परिपत्र को गौर से पढ़ें, और जो इसके पहले परिपत्र निकला था, वह निकला था 05.04.2018 को चीफ सैक्रेटरी निहाल चंद गोयल के द्वारा। उसमें सिर्फ दो बिन्दु थे, सिर्फ दो बिन्दु थे। इसमें कुल मिला करके 8-10 बिन्दु हैं। 10 बिन्दुओं में वे चीजें हैं, जो आपके शासनकाल में परिपत्र निकला था, उसमें नहीं हैं।

उसमें कुछ नहीं है, अलावा इसके कि आपको निमंत्रण दिया जाएगा और आपको सादर वहां पर बैठने के लिए जगह दे दी जाएगी। इतनी व्यवस्था की जाएगी। अगर इसकी पालना नहीं होगी तो सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होगी। बस इतना-सा है।

इसमें यह देखिए आप, कहां से कहां तक है। इसमें बाकायदा यह है कि सूचना उसको देनी पड़ेगी। जो अधिकारी सूचना देगा, वह कम से कम उसकी प्राप्ति भी लेगा। वह भी संचार के माध्यमों से देगा और तुरंत देगा। इसके अलावा बाकायदा उसकी प्रतिष्ठा को देखते हुए उसको ऊपर स्टेज पर जगह दी जाएगी। ये सब बातें हैं। कुल मिला करके इतनी-सी बात है।

आपने जहां यह बात कही कि मंडेलियाजी ने यह कहा तो यह तो हर आदमी कुछ भी कह सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। (व्यवधान) इसमें क्या दिक्कत है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपके हारे हुए प्रत्यशी कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपके बीच में बोला नहीं हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेहरबानी करके सुनिये आप। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय मंत्री महोदय कुछ बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। चर्चा समाप्त। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अभी आपकी भी बात बता देता हूं। (व्यवधान) चिंता मत करो।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। माननीय मंत्री महोदय, प्लीज। चर्चा समाप्त।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, जहां तक सवाल इस बात का है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: जाइए, अपने स्थान पर जाइए आप। स्थान पर जाइए। कुछ अच्छे संस्कार भी सीख लो। (व्यवधान) जब यहां सदन में इस तरह का आचरण कर रहे हैं तो वहां क्या करते होंगे आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

धरना

(श्री गोपी चन्द मीणा, माननीय सदस्य द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, जहां तक सवाल इस बात का है कि राष्ट्राध्यक्ष, जैसे आपने बात उठायी, उप नेता महोदय ने कि राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो हमें नहीं बुलाया जाता। (व्यवधान) ठहर जाएं, बोल लेने दें।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज, चर्चा समाप्त। चर्चा समाप्त। श्री बृजेन्द्र सिंह ओला। (व्यवधान)

विराजिए, माननीय सदस्य, विराजिए। श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय सभापतिजी...

श्री सभापति: माननीय नेता महोदय, मैंने स्पष्ट निर्देश दे दिये। मैंने स्पष्ट निर्देश दे दिये। माननीय मंत्री महोदय ...(व्यवधान)

(श्री गोपी चन्द मीणा, माननीय सदस्य द्वारा सदन कूप में धरना समाप्त)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आगमन)

बिलकुल नहीं बुलाऊंगा, बिलकुल नहीं बुलाऊंगा। बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। बिलकुल नहीं करूंगा। हाईजैक नहीं करने दूंगा, बिलकुल नहीं करने दूंगा।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

चर्चा समाप्त। कोई अधिकार नहीं है। मैंने कह दिया कि माननीय अध्यक्ष महोदय को आप लिखित में दें। अधिकार दे दिया उनको कि वे माननीय अध्यक्ष महोदय को लिखित में देंगे। नहीं, बिलकुल नहीं। आप अपने स्थान पर पधारें। आप प्लीज, अपने स्थान पर पधारें। अपने स्थान पर पधारें। विराजिए।

माननीय नेता, प्रतिपक्ष, काफी लोग बोलने वाले हैं। आप विराजिए, अपने स्थान पर जाइए। अच्छे संस्कार सीख लो। सदन में आपका यह आचरण है। जब चाहे खड़े होकर आप यहां पर आ जाते हैं। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप से अपना-अपना स्थान ग्रहण)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, अभी तो 21 तारीख को लाहोटीजी को बुलाकर बैठाया था जिस पर नतीजा यह निकला कि प्रतिपक्ष के नेता ने और इनके पार्टी प्रेसिडेंट ने बुलाकर लाहोटी को डांटा, अख़बार ने लिखा है यह सारा। (व्यवधान)

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

मैं जब स्वायत्त शासन मंत्री था, 1998 में जब श्रीमती किरण माहेश्वरीजी वहां की चेयरमैन थीं, इनको बुला-बुलाकर मैं पास में बैठाता था। भूल गयीं? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, मेरी भावना को समझने का प्रयास करें। मैं विषय को इधर-उधर टालने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं यह चाहता था कि जिस प्रकार की ये घटनाएं हुई हैं जहाजपुर के माननीय सदस्य के साथ तो manhandling कलेक्टर की उपस्थिति में हुई। मैं यह चाहता हूं कि जब तक आप इन विषयों को लेकर जिनको भी जिस प्रकार की शिकायत है, उनकी जांच के बारे में आप अगर आश्वस्त नहीं करोगे तो हम यह सदन नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय। माननीय मंत्री महोदय।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करता हूं कि इस परिपत्र की पूर्ण रूप से पालना की जाएगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आगे नहीं, जो हो चुकी। आगे के लिए नहीं, जो हो चुकी। आगे के लिए तो बाध्य हैं। ऐसा नहीं हो सकता।

श्री सभापति: एक मिनट, आप विराजिए।

मैं यह निर्देश देता हूं कि माननीय सदस्य लिखित में अपना, जो भी उनकी समस्या है, जो भी उनके साथ घटना घटी, वह माननीय अध्यक्ष महोदय तक आप पहुंचा दें। माननीय अध्यक्ष महोदय जो भी निर्णय करेंगे, आप व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय को लिखित में अपनी पीड़ा बता दें। विराजिए। चर्चा समाप्त। श्री बृजेन्द्र सिंह ओला। विराजिए। माननीय सदस्य, आप विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री सभापति: विराजिए, आप बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं। कुछ तो सीख लीजिए, आप बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं। श्री बृजेन्द्र सिंह

(श्री सभापति)

ओला। कृपया, शांत रहें। विराजिए, विराजिए। उम्र बहुत छोटी है, अभी बहुत कुछ सीखना है। विराजए, विराजिए। अध्याय समाप्त हो जाता है, इस तरह से। बहुत कुछ सीखना है। (व्यवधान)

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2020-21 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

किसी भी शासन का बजट उसके आय और व्यय का केवल एक लेख पत्र ही नहीं होता है बल्कि उस राज्य की जनता की उसके प्रति बहुत भावनाएं होती हैं, बहुत आशाएं होती हैं और उनके अनुरूप हर शासन बजट बनाने की चेष्टा करता है। इस बार के बजट में बजट प्रस्तुत करते समय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कुछ क्षेत्रों पर थ्रस्ट रखा है। जिसमें से पहला क्षेत्र उन्होंने नीरोगी राजस्थान को चुना है।

मैं इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी राज्य, कोई भी व्यक्ति जब तक वह स्वस्थ नहीं होगा, तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता है। निरोगी राजस्थान के बारे में बजट में जो व्यवस्था की है, उस पर मैं अपने कुछ सुझाव आपके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगा।

नीरोगी राजस्थान का लक्ष्य हम तब ही प्राप्त कर सकेंगे जब मेडिकल कालेज से लेकर उप स्वास्थ्य केन्द्र तक को हम मजबूत करेंगे। इसके लिए जरूरी यह है कि मेडिकल कालेज हो या चाहे जयपुर का एस.एम.एस. हास्पिटल हो, चाहे डिवीजनल हैडक्वार्टर के हास्पिटल्स हों, उन सबमें हम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएं। चाहे वह मानव संसाधन हो, चाहे वह मशीनरी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो।

माननीय सभापति महोदय, आज स्थिति यह है कि राजस्थान में हमने चिकित्सा सेवाएं तो बहुत खोल दीं, पर उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कहीं पर भवन नहीं है, कहीं पर डाक्टर्स नहीं हैं, कहीं पर पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है तो सबसे पहले तो हमको उस स्थिति पर ध्यान देना पड़ेगा और उनको मजबूत करना पड़ेगा।

हमने लगभग सभी जिलों में मेडिकल कालेज खोल दिये हैं, पर आज

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

स्थिति यह है, चाहे पहले की सरकार थी, उन मेडिकल कालेजेज में एम.सी.आई. की मंजूरी के लिए दूसरी जगह से स्टाफ भेजना पड़ता है। चाहे प्रोफेसर हो, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, हमको इस सारी व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। सारे स्टाफ की, चाहे वह मेडिकल कालेज के लिए, प्रोफेसर्स की, एसोसिएट प्रोफेसर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, सबकी सुनियोजित तरीके से भर्ती करनी पड़ेगी। उनको सब तरह के इक्विपमेंट्स देने पड़ेंगे। इसके लिए हमने जो 14 करोड़ रुपये के धन की व्यवस्था की है, चाहे उसको और बढ़ाना पड़े तो बढ़ाएं।

इसी तरह से जिला अस्पतालों को भी सुदृढ़ करना पड़ेगा। आज स्थिति यह है कि जिला अस्पताल तो एक तरह से रैफरल हास्पिटल बन गये हैं। उसका परिणाम यह है कि सवाई मानसिंह हास्पिटल जो हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा हास्पिटल है, वह एक तरह से सारे राजस्थान की व्यवस्था को झेलते-झेलते चरमराहट की स्थिति में है। हर साल उसमें कोई न कोई बिल्डिंग बनायी जाती है, कोई और व्यवस्था की जाती है। फिर भी समूचे राजस्थान से आने वाले मरीजों का वहां पर इलाज होने में काफी समय लगता है। इसलिए हमको डिवीजनल हास्पिटल्स को मजबूत करना पड़ेगा, हमको जिला अस्पतालों को मजबूत करना पड़ेगा। जो कालेजेज अपन फेजेज में खोल रहे हैं, उनको भी पहले से जो मेडिकल कालेजज चल रहे हैं, चाहे वह एस.एम.एस. मेडिकल कालेज है, चाहे वह उदयपुर का आर.एन.टी. मेडिकल कालेज है, चाहे वह अजमेर का मेडिकल कालेज है, चाहे बीकानेर का मेडिकल कालेज है, उनके लेवल पर हमको उन मेडिकल कालेजेज को लाना पड़ेगा। वर्तमान में जो स्थिति है, उसको देखते हुए तो इन मेडिकल कालेजेज को हमारे पुराने मेडिकल कालेजेज के समकक्ष लाने में हमको बहुत समय लगेगा। इसलिए जब इसको थ्रस्ट एरिया ही रखा है, चाहे दूसरे में हम एलोकेशन कम कर दें, पर हैल्थ के लिए हमारे बजट को और बढ़ाएं।

इसी तरह से जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उनमें भी आज बहुत सारों में भवन नहीं है, बहुत सारों में स्टाफ नहीं है, बहुत सारों में मशीनें नहीं हैं, हमको उनको भी मजबूत करना पड़ेगा।

इसी तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, बहुत सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में समुचित स्टाफ नहीं है, उनको भी मजबूत करना पड़ेगा। कइयों में तो भवन भी नहीं हैं। इसी तरह से उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, बहुत सारे उप स्वास्थ्य केन्द्रों में भवन नहीं हैं, कहीं पर ए.एन.एम. नहीं है, कहीं पर दूसरी तरह की व्यवस्था नहीं है तो उसको भी हमको मजबूत करना पड़ेगा।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

नि:शुल्क दवा योजना, एक बहुत अच्छी योजना राजस्थान में शुरू की गयी जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, उस समय से यह योजना चल रही है। उस समय पहले 200 दवाइयां शुरू की गयी थीं, फिर उसको 400 तक ले गये थे और अब उसमें और दवाइयां जोड़कर उसको करीबन 650 तक ले गये। अब उसमें नि:शुल्क जांचें भी सम्मिलित की गयी हैं, पर उसका लाभ तब ही जनता को मिलेगा जब हम उसका समुचित उपयोग इस रूप में करें कि उसके लिए समस्त स्टाफ की व्यवस्था हो। उस स्कीम को दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं। जिस तरह की व्यवस्था जयपुर में है, नि:शुल्क दवा देने की, उसी तरह की व्यवस्था को हमको प्राइमरी हैल्थ सेंटर तक ले जाना पड़ेगा इसलिए इन सारी व्यवस्थाओं को हम करेंगे, तब ही नीरोगी राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

(14.00 बजे)

नीरोगी राजस्थान में हैल्थ का सबसे ज्यादा जरूरी कम्पोनेंट है, वह शुद्ध पेयजल है। माननीय सभापति महोदय, आज भी राजस्थान के 60 परसेंट एरिया में हम शुद्ध पेयजल दे रहे हों, इसका हम दावा नहीं कर सकते। जहां पर भी हम पेयजल दे रहे हैं, कहीं पर तो वह खारा पानी है, कहीं पर उसमें साल्ट ज्यादा है, कहीं उसमें फ्लोराइड ज्यादा है। इन सबको भी हमें डब्ल्यू.एच.ओ. के स्टेंडर्ड पर लाना पड़ेगा। हिन्दुस्तान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में निचले पायदान में जो राज्य हैं, उनमें हम हैं। इसलिए हो सकता है कि इस बार इस बजट को नीरोगी राजस्थान के लिए समर्पित किया गया है परंतु इसमें पेयजल का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है तो पेयजल के लिए हमको कोशिश यह करनी चाहिए। भारत सरकार ने भी यह घोषणा की है कि हम हर घर में टैप वाटर पहुंचाएंगे। पर जो पानी हम दें, वह कम-से-कम पीने के लायक तो हो। पहले की स्थिति यह थी कि वहीं पर तो व्यक्ति पानी पीता था, वहीं पशु पानी पीता था, वहीं और दूसरे जंगली जानवर जोहड़ों में पानी पीते थे, उस स्थिति से तो हम बाहर आ गये। नहीं तो यहां मेरे साथी बैठे हैं बांसवाड़ा-डूंगरपुर के, और जगह पर भी कई लोगों के खारवा हो जाता था। यह एक बीमारी होती थी जो पैर को खराब कर देती थी। उससे हमने निजात पायी और अब स्थिति यह आ गयी कि पानी जो हम जमीन से ले रहे हैं, वह लेते-लेते इतने डीप तक चले गये कि उसकी क्वालिटी खराब हो गयी है। हमको सरफेस वाटर पर आना पड़ेगा। उसी सरफेस वाटर के तहत हम इंदिरा गांधी

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

नहर का पानी कई जिलों में दे रहे हैं। यहां भी हम घोषणा करते हैं और जब गांवों में जाते हैं तब भी घोषणा करते हैं कि हम बहुत मीठा पानी, हिमालय का पानी आपको दे रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, स्थिति दूसरी है। उसमें पंजाब की फैक्ट्रियों का अपशिष्ट आता है, उसमें सीवरेज के नाले छोड़े जाते हैं। इसलिए ग्यारह जिलों में जो पानी आ रहा है, वह शुद्ध पानी मिले, उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए कि हम पंजाब सरकार से सम्पर्क करें, भारत सरकार से सम्पर्क करें और यहां तक कि हम ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी जाएं या सुप्रीम कोर्ट में जाएं। नहीं तो एक ट्रेन आती है, जो गंगानगर जिले से बीकानेर आती है। उसका नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया। इस तरह की जो व्यवस्था है, उनको हम दूर करेंगे तभी हम निरोगी राजस्थान की तरफ बढ़ पाएंगे।

दूसरा बिन्दु उसमें रखा गया कृषि का, माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान की जी.डी.पी. में कृषि का 25 प्रतिशत योगदान है और हमने इस बजट में 8.50 प्रतिशत कृषि को आबंटन किया है। इस कृषि में भी वानिकी उसी में शामिल है, सहकारिता उसी में शामिल है, पशुपालन उसी में शामिल है, मछली पालन उसी में शामिल है, भेड़पालन उसी में शामिल है, तो कृषि के बजट को हमको बढ़ाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, किसान, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, उसकी चर्चा हो रही है कि उसकी लागत का डेढ़ गुना उसको दिलाने की कोशिश की जाएगी। आज स्थिति यह है कि किसान का इनपुट का पैसा बढ़ता जा रहा है और उसकी कृषि की उपज के पैसे बढ़ते नहीं हैं। यह ठीक है कि यह केन्द्र का विषय है, पर राज्य सरकार को उसके लिए भारत सरकार को लिखना चाहिए, अपने प्रयत्न करने चाहिए कि किसान की लागत का उसको समुचित मूल्य मिले।

माननीय सभापति महोदय, किसान के लिए आज बहुत बड़ी समस्या आवारा पशुओं की हो गयी है। आवारा पशुओं की स्थिति यह है कि कई जगह तो किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया है। वैसे भी हम अनाज को लेबोरेट्री में पैदा नहीं कर सकते, अनाज तो किसान के खेत में ही पैदा होगा। एक जमाना यह था कि अमेरिका से पी एल 480 के तहत माइलो, ज्वार, लाल गेहूं आता था, उससे लोगों के खुजली हो जाती थी। यह देश और प्रदेश का किसान था, जिसने मेहनत करके देश को आत्मनिर्भर बनाया। हमारा भी उस किसान के प्रति दायित्व बनता है कि हम भी उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारें। आज

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

जो आवारा पशुओं की स्थिति है, उसने बहुत भयंकर रूप ले लिया है। उसके लिए हमने घोषणा भी की है कि हर पंचायत समिति में एक नन्दीशाला खोलेंगे। आप चाहे कितनी ही गौशालाएं और नन्दीशालाएं खोल लें, इस समस्या का हल नहीं हो सकता। इस समस्या का हल एक ही है कि आप किसान को गौधन के लिए अनुदान दें। इससे न केवल आपके, जो दूसरी तरह के अनुदान दिये जाते हैं, उनमें भ्रष्टाचार रुकेगा, बल्कि उस पर प्रभावी कार्यवाही हो सकेगी। न तो आप इतनी गौशालाएं खोल सकते, न इतनी नन्दीशालाएं खोल सकते और न इतना अनुदान दे सकते। आप इसका अध्ययन करवाएं। इसके अध्ययन के लिए कोई कमेटी बनाकर या दूसरी कार्यवाही करके यह कोशिश करें कि सीधा किसान को आप, जो गौवंश है, उसके लिए जो अनुदान गौशाला को देते हैं, उसी रेट पर आप उसको अनुदान दें, जिससे वह इस समस्या से हल पा सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, किसान की एक दूसरी समस्या बीजों की है। पहले परम्परागत रूप से किसान अपने बीज उत्पादन करता था। हमारे यहां भी बाजरे का बीज जखराना, अलवर में बहुत प्रसिद्ध था। आगे-पीछे से उसके काट देते थे। उससे अच्छा तो उत्पादन होता था और अच्छा चारा मिलता था। अब जो बीज आ रहे हैं, वह इस तरह के आ रहे हैं कि आपने एक फसल ले ली तो दूसरी बार भी आपको दुकान से ही बीज लाना पड़ेगा। यह एक अन्तरराष्ट्रीय गिरोह है, जिसने किसान को अपने कब्जे में ले लिया है। इसमें भी जो बीटी बीज है, उसके दुष्प्रभाव को जांचे-परखे बिना हमने डब्ल्यू.टी.ओ. के दबाव में आकर इसको स्वीकार कर लिया। इसलिए आपको किसान को अधिकार देना पड़ेगा कि वह अपना बीज स्वयं उत्पादन कर सके और उसको अपने खेत में उपयोग कर सके।

माननीय सभापति महोदय, किसान की दूसरी बात बिजली की है। पहले किसान को जो सब्सिडी दी जा रही थी, वह उसके बिजली के बिल पर दी जा रही थी। बाद में अभी यह आदेश जारी कर दिये कि उसके खाते में आएगी। माननीय सभापति महोदय, 30-30 लोगों का एक खाता है और उनके दादा के नाम से वह कनेक्शन चल रहा है। आप सब्सिडी किसको देंगे, उसमें से किसको देंगे, किसके खाते में देंगे? इसलिए आप उस व्यवस्था को पुन: चालू करें। हम गांवों में जाते हैं तो बहुत ज्यादा इस बात की चर्चा है। किसान को, उसका जो पहले सिस्टम था, वही चालू करें। इसमें करप्शन की कहीं गुंजाइश

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

है ही नहीं, क्योंकि कनेक्शन है, बिल है, एक आदमी के नाम से है। वह बिल में ही अगर कट जाएगा तो उसमें भ्रष्टाचार होने की कहां गुंजाइश है। इसलिए सरकार इस पर विचार करे कि किसान को बिल पर यह बिजली की सब्सिडी दे।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात, फसल के टाइम पर किसान को खाद की दिक्कत आती है। इसके लिए तो इस बजट में व्यवस्था की है कि हम उसका भंडारण बढ़ाएंगे। तीसरी बात, किसान के लिए सरकार को यह करना चाहिए कि जब उसकी फसल होती है तब तो भाव गिर जाते हैं, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत होती है और आनन-फानन में वह बेच देता है। आप यह व्यवस्था करें कि उसकी फसल को कहीं आप रखवा लें और उसको 50-60 प्रतिशत फसल के अंगेस्ट में पेमेंट कर दें। जब उसके भाव अच्छे आएं तो उसको बेचें और उस किसान के पैसे काट लें व बाकी के पैसे उसको दे दें। इसके अलावा किसान के लिए भंडारण की व्यवस्था करनी पड़ेगी और किसान को परम्परागत खेती से हटने के लिए भी प्रोत्साहित करना पड़ेगा। चाहे वह फल की खेती हो, सब्जी की खेती हो और व्यापारिक खेती हो। इस तरह से हमको बढ़ावा देना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, थ्रस्ट एरिया एक यातायात का है। हमारे राजस्थान में जब प्रदेश का गठन हुआ और 1949 में सारी मिलाकर 14 हजार किलोमीटर सड़कें थीं। चाहे वह डामर की हो या आलवेदर रोड थी। अब पिछले 70 साल में 2 लाख 64 हजार किलोमीटर सड़कें हमारे यहां बन गयीं और सड़कों के लिए हमने इस बजट में काफी कम एलोकेशन रखा है। आपका यह जो सड़कों का आधारभूत ढांचा है, यह आपको उद्योग में भी सहयोग करता है, यह आपके कृषि जिंसों को बाजार तक ले जाने में सहयोग करता है, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी सुविधा प्रदान करता है। किसी भी देश और राज्य की सड़कें अच्छी होंगी तो वह निश्चित रूप से विकास कर सकेगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह रहेगा कि जो बजट सड़कों के लिए दिया है, उसको और बढ़ाएं, नहीं तो हम इन सड़कों की मेंटीनेंस ही नहीं कर सकेंगे। वैसे ही हम देश में नेशनल हाईवे के मामले में, और सड़कों के मामले में बहुत पीछे हैं। जहां देश का प्रति 100 किलोमीटर घनत्व 148 किलोमीटर है, वहां हमारा घनत्व मात्र 70 किलोमीटर है तो इसको बढ़ाने

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

की जरूरत है। हमने हमारे जन घोषणा-पत्र में यह कहा था कि हम धार्मिक स्थलों के लिए भी सड़कों की व्यवस्था करेंगे तो उसके लिए भी बजट में व्यवस्था की जाए तो अच्छा रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस एरिये से आता हूं, वह हरियाणा से लगता है और स्थिति यह है कि हमारे यहां आठ रुपये ज्यादा पैट्रोल और डीजल मिलता है और वहां आठ रुपये सस्ता मिलता है। इससे दो तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, एक तो लोग अवैध तरीके से ड्रम में और किसी चीज में उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और फिर अवैध तरीके से बेचते हैं। दूसरा स्टेट के एक्सचेकर को उससे नुकसान होता है। हमने लोक सभा चुनाव के टाइम में हमारे लोक सभा वाले चुनाव घोषणा पत्र में भी डाला था कि हम पैट्रोलियम पदार्थों को जी.एस.टी. के अन्तर्गत लाने के लिए इस बात को आगे बढ़ाएंगे। जी.एस.टी. काउंसिल में हर स्टेट का प्रतिनिधित्व है, हमारा भी प्रतिनिधित्व है। हमको यह चेष्टा करनी चाहिए कि हम उसको जी.एस.टी. के अन्दर शामिल करवाएं। आप जब भी हमारे उधर से दिल्ली जाते होंगे, आप जब हरियाणा में घुसेंगे तो दोनों तरफ लाइन में पैट्रोल पम्प लगे हुए हैं, उससे न केवल राजस्व की हानि होती है बल्कि लॉ एंड आर्डर की भी प्राब्लम उत्पन्न होती है। एक माफिया जाता है, जो ईजी मनी कमाता है वह कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करता है। मैं समझता हूं कि हमारी लिमिटेशंस हैं, पर हम को इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए कि हम उसको जी.एस.टी. के अन्तर्गत लाएं।

सभापति महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं, उसमें 6 साल पहले इसी सदन ने खेल विश्वविद्यालय का विधेयक पास कर दिया। उस विधेयक को शायद परमार साहब ने ही पायलट किया था। उस खेल विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर लगा दिया, उसकी जमीन आबंटित हो गयी, ओ.एस.डी. लगा दिया, उसका आफिस चलने लग गया, 6 साल तक उसमें कोई भी काम नहीं हुआ। अब मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह रहेगा कि उस विश्वविद्यालय के लिए बजट की व्यवस्था करें, उसका पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करें और उसको फंक्शन में लाएं, जिससे झुंझुनूं जिले की, सीकर जिले की, शेखावाटी की और सारे राजस्थान की खेल जगत में जो प्रतिभाएं हैं, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। उस समय जब इस विधेयक को लाये थे तो मैं भी सदन में था, यह बात आयी थी कि यह हमारा दूसरा विश्वविद्यालय

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

होगा। इससे पहले तमिलनाडु में इस तरह का विश्वविद्यालय है। छह साल तक उस पर कोई काम नहीं हुआ, पर अब हम यहां वापस आ गये हैं तो उसको चालू किया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनू): मैं जिस जिले से आता हूं उसके सारे ब्लाक भूजल के मामले में क्रिटिकल स्थिति में हैं, अति दोहन की स्थिति में हैं। उस जिले के लिए और चूरू के लिए राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली पांच स्टेट्स के मध्य यमुना वाटर का एक समझौता हुआ। उसके लिए हमारे सामने बैठने वाले माननीय सदस्यों ने यह कहा कि हम इसको वहां से पाइप में लाएंगे और 4 महीने में इसका काम शुरू हो जाएगा, वह शुरू नहीं हुआ क्योंकि हरियाणा उस पानी का उपयोग कर रहा है तो वह तो देगा क्यों?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनू): उसको राजस्थान में लाने के लिए झुंझुनूं जिला, जो वीरों की भूमि है, जो सबसे ज्यादा सैनिक देता है, जो शिक्षा में सबसे आगे है, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा पैरास्टाफ देता है, सबसे ज्यादा जो और सेवाओं में लोग हैं उनको देता है, उसकी अगर पानी की व्यवस्था नहीं की गयी तो पलायन शुरू हो जाएगा, आप सिंचाई की बात तो छोड़ो, हमको पीने के पानी के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि सरकार इस बार भी अपना जोर लगाए, भारत सरकार से बात करे, हरियाणा सरकार से बात करे। क्योंकि हरियाणा तो उस पानी का उपयोग कर रहा है, वह क्यों छोड़ेगा? कोई व्यक्ति अगर किसी भी चीज का उपयोग करता है तो वह क्यों छोड़ेगा?

सभापति महोदय, मैं बोलना तो और भी चाहता था, पर क्योंकि आप बार-बार कह रहे हैं तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री सभापति: प्लीज, समाप्त करें। श्री सुमित गोदारा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे बजट की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। अपने आपको विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी इकोनोमी का नागरिक होने के नाते

(श्री सुमित गोदारा)

गौरवान्वित महसूस करता हूं। साथ में देखता हूं कि जब अर्थव्यवस्था की बात चलती है तो आजादी से 40 साल तक जो कांग्रेस की सरकार दिल्ली में रही, प्रोटेक्शनिस्ट इकोनोमिक पालिसी के तहत निरन्तर प्रभाव रहा जिसके कारण भारत हमेशा आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ रहा और 40 साल तक साढ़े तीन परसेंट जी.डी.पी. चली। विश्व में उस जी.डी.पी. को हिंदू रेट असफ़ ग्रोथ के नाम से जाना जाने लगा कि भारत इतना पिछड़ा रहा। इन्होंने 40 साल तक गरीबी का नाम लेकर शासन किया, नारे दिये। 'गरीबी हटाओ-देश बचाओ', 'कांग्रेस का हाथ-गरीब का साथ' नारों के साथ इन्होंने शासन किया, पर इन्होंने काम कुछ नहीं किया।

उसी समय राजनीतिक पटल पर उदय होता है एक कर्मयोगी दल का, कर्मयोगी व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी का। मैं कहना चाहूंगा ये पंक्तियां हैं कि,

'भाग्यवादी लोग सदा कुछ होने का इंतजार करते हैं,
कर्मयोगी सदैव कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं,
भाग्यवादी कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता,
और कर्मयोगी सदैव हर युग में अपना भविष्य खुद लिखते हैं।'

ऐसे कर्मशील, कर्म प्रधान व्यक्तित्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधान मंत्री बने। उनके बाद देश ने जो अर्थव्यवस्था में गति पायी, भारत की विकास दर निरन्तर 7 से 8 परसेंट रही, जिससे भारत विकास की गति में आगे बढ़ा।

हम जब आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं तो याद आते हैं पी.वी. नरसिम्हा राव साहब, जो 1991 में देश के प्रधान मंत्री बने, इकोनोमिक लिबरलाइजेशन लेकर आये, चाहे उस समय के शीत युद्ध की समाप्ति के कारण हो, चाहे बैलेंस आफ पेमेंट की स्थिति के कारण हो, जो इकोनोमिक लिबरलाइजेशन आया उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी उस समय लोक सभा में बहुत बड़ा सहयोग दिया, तो वह सारा का सारा इकोनोमिक लिबरलाइजेशन देश में लाने में आसानी हुई।

मैं वाजपेयी जी के कार्यकाल की बात करूंगा कि उस समय शाइनिंग इंडिया रहा, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनोमी, जो मैंने कहा, वह निरन्तर रही। अब जब मोदी जी भारत के प्रधान मंत्री बने हैं तो देखो 2014 से 2018 भारत विश्व की सबसे तेज आर्थिक प्रगति, ग्रोथ रेट है, चाइना से भी ज्यादा है। मैं

(श्री सुमित गोदारा)

बताना चाहूंगा, कई सदस्य यहां जी.डी.पी. की बात करते हैं तो 2015 में भारत की जी.डी.पी. 8 परसेंट रही, 2016 में 8.2 परसेंट रही, 2017 में 7.2 परसेंट और 2018 में 7 परसेंट रही। यदि भारत इसी गति से आगे चलता रहा तो न सिर्फ 2024 तक पांच ट्रिलियन इकोनोमी बनेगा बल्कि 2035 तक 10 ट्रिलियन इकोनोमी बनेगा, कितने ही लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करेगा, ऐसा भारत आगे बढ़ेगा।

हम देखते हैं कि जिस तरह भारत आर्थिक रूप से समृद्ध होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है उसी तरह कांग्रेस भी हाशिये पर जाती जा रही है। यह भी एक सोचने का विषय है कि क्या कारण है कि देश में जब बी.जे.पी. आयी तब आर्थिक समृद्धि बढ़ी और कांग्रेस पीछे जाती रही। कहीं न कहीं यह है कि इन्होंने राजनीति की, गरीबी के नाम पर देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया और वैसा का वैसा अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ राजस्थान में हो रहा है।

हम राजस्थान का बजट देखते हैं। इसमें, राजस्थान के मुखिया बजट की शुरुआत ही पृष्ठ नम्बर दो पर करते हैं, पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन, हर बात यह लोगों पर ही थोपते रहे हैं। आज ये मुख्य मंत्री हैं, जब बजट पेश हुआ, उसके बाद जब मैं अपने क्षेत्र में गया तो गांवों में बजट के बारे में बात चली कि बजट कैसा रहा, तो आम लोगों की यही चर्चा रही कि राजस्थान में जब भी कांग्रेस की सरकार आयी है, अशोक गहलोत जी मुख्य मंत्री बने हैं तो खजाना खाली हुआ है। हमेशा खजाना खाली हुआ है और यही बात उन्होंने आते ही बजट में पृष्ठ दो पर ही कह दी कि वित्तीय कुप्रबंधन, दूसरों पर दोष देते हुए अपनी बात रखी। उनकी हमेशा ही सदैव की नीति रही है। इस वजह से राजस्थान इतने शासनकाल और इतने साल बीमारू प्रदेश रहा। यह तो भैरोंसिंह जी शेखावत और वसुन्धरा जी मुख्य मंत्री रहे तो राजस्थान बीमारू प्रदेश से विकास की ओर आगे बढ़ा। हमारे लिए अब यह बड़ी चिंता का विषय है कि क्या इस सरकार में कुछ विकास होगा या यह सिर्फ ऐसे ही पांच साल निकालेंगे।

बजट का पत्र पढ़ा तो इस बजट भाषण में अनेक जगह इंदिरा जी, नेहरू जी, राजीव जी का नाम लिया गया, पर मुझे कहीं भी नरसिम्हा राव जी, लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम नहीं दिखा।

बजट में आपने बात रखी, आप एक योजना लाये सामाजिक न्याय

(श्री सुमित गोदारा)

एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सौ करोड़ की राशि से नेहरू बाल संरक्षण कोष, बच्चों के लिए जो तस्करी और बाल मजदूरी है, इसको रोकने के लिए आप जो लाये, काश ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आजाद के नाम से लाते तो देश में और भी अच्छा लगता, राजस्थान में लोगों को गौरव होता।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के ऊपर आप लाये "निरोगी राजस्थान" आपका नारा, पर देखो कितने हास्य की बात है कि राजस्थान जैसा बड़ा प्रदेश और आपने उसके लिए बजट आबंटन किया है मात्र सौ करोड़ रुपये, अब सौ करोड़ में आप क्या निरोगी राजस्थान की कल्पना कर सकते हैं।

पृष्ठ संख्या पांच पर आप लिखते हो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, कि जल्दी से हम पता कर पाएं कि लोगों में क्या बीमारियां हैं। पर हम देखते हैं कि गांव में क्या स्थिति है, कितने लोग हैं जिनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है, कितने पैरालाइसिस अटैक आ रहे हैं क्योंकि कोई बी.पी. जांचने का उपकरण नहीं है, गांवों में कोई इलाज नहीं है। हम चाहेंगे कि सरकार यदि निरोगी राजस्थान की कल्पना चाहती है तो गांवों में हार्ट के पेशेंटों के लिए, डायबिटीज के पेशेंटों के लिए विशेष कैम्प लगाए, तो हो सकता है कि अपने मेडिकल कालेज और बड़े पी.एच.सी., सी.एच.सी. पर दबाव कम हो। न सिर्फ दबाव कम होगा बल्कि हम कितने इंसानों की जान बचाएंगे, इसकी कल्पना भी हम और आप नहीं कर सकते।

आपने यह बात रखी कि ए.एन.एम. की हम पोस्टें भरेंगे। मैं अपने क्षेत्र लूणकरणसर की बताना चाहूंगा कि वहां सारी की सारी सी.एच.सी. खाली हैं। लूणकरणसर में केवल 2 डाक्टर हैं। नापासर, महाजन, हर जगह सी.एच.सी. खाली हैं। 19 में से 16 पी.एच.सी. खाली हैं। अभी एक साल पूर्ण होने पर मैं सभी 152 गांवों में गया। जन सेवक आपके द्वारा कार्यक्रम में मैं सभी गांवों में गया। वहां जितने भी स्वास्थ्य उप केन्द्र हैं, उनमें जितनी भी ए.एन.एम. थीं, इस सरकार में पता नहीं ट्रांसफर का क्या गोरखधंधा चला कि वे सारी की सारी वहां से ट्रांसफर कर दीं। वे सारे के सारे उप केन्द्र बंद पड़े हैं। यह इनकी निरोगी राजस्थान की कल्पना है।

सभापति महोदय, नि:शुल्क दवा योजना की बात करते हैं कि हमने 709 दवाइयां दी हैं। माननीय कल्ला जी यहां बैठे हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि मेडिकल कालेज और ज्यादातर जगह सेंटर में इस खेती के सीजन में पायजनिंग के बहुत केस आते हैं। यह बहुत दुखद विषय है। मैं भी इसमें

(श्री सुमित गोदारा)

काफी रुचि लेता हूं, जब अस्पताल में काम होता है। उसमें जो दवाई यूज होती है, तो पर्लीडोक्सिम 40; पैम इंजेक्शन है, जो पायजनिंग के केस में काम आता है। एट्रोपाइन सल्फेट 50 एम.जी. और कोडिन एक मीटर है, जो डोज को सही मात्रा में पेशेंट को पहुंचाता हैं। ये सरकार के पास उपलब्ध ही नहीं हैं। पायजनिंग के इतने ज्यादा केस होते हैं और दवाई उपलब्ध नहीं है। आप गुण गाते हो कि 709 दवाइयां हैं, जो सबसे ज्यादा इमरजेंसी मेडिसिन हैं, वह आपके डी.डी.सी. पर उपलब्ध नहीं है। हिसाब से तो यह इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल्स में केयर यूनिट के पास होनी चाहिए।

सभापति महोदय, आप डी.डी.सी. की बात करते हो। यह है कि आपके यहां एक डी.डी.सी. रात को खुला रहेगा। अलग-अलग विंग्स हैं हास्पिटल के, यूरोलॉजी की अलग, नेफ्रोलॉजी की अलग, हर जगह की। रात को बीमार को दवा चाहिए और 9 से 3 के बाद हास्पिटल बंद होने पर वह बीमार कहां से दवाई लेकर आएगा? कोई एक भी सेंटर है जहां पूरी दवाइयां मिलती हों? नहीं मिलती हैं। यह भी व्यवस्था आपने नहीं की है लेकिन आप नि:शुल्क दवाइयों पर बातें लम्बी-चौड़ी करते हो। लोगों की सेवा पर बातें करते हो।

सभापति महोदय, पी.बी.एम. में कैंसर हास्पिटल, जब कैंसर की यहां सब जगह बात रखी जा रही है, वहां नार्थ इंडिया का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर है। मेरे पिताजी डा. आर.के. चौधरी उसके डायरेक्टर रहे। कैंसर हास्पिटल के सम्बन्ध में एक बड़ा विषय आया कि वहां पंजाब से बहुत बीमार आते हैं। बीमारों के लिए वहां पर पिछले 6 सालों से पंजाब के लोगों द्वारा लंगर की व्यवस्था की जा रही थी। अभी वहां स्थानीय प्रशासन ने बिना किसी कारण के जहां हजारों लोग खाना खाते थे, उस लंगर को वहां से बंद करके हटा दिया। सिर्फ इसलिए स्थानीय राजनीतिज्ञ लोगों को यह पसंद नहीं था कि इस तरह का काम हो, क्योंकि उनके खुद के गोरखधंधे वहां पर थे। केन्द्रीय मंत्री हरसिमरत कौर जी का मुख्य मंत्रीजी के नाम 4 फरवरी को पत्र भी दिया कि लंगर की व्यवस्था समाजसेवियों द्वारा की गयी थी, उसको वहां क्यों बंद करवाया गया।

सभापति महोदय, पी.बी.एम. हास्पिटल हमारे क्षेत्र का, सम्भाग का सबसे बड़ा हास्पिटल है। राजनीति की बात अभी चल रही थी। उद्घाटन के नाम पर 150 करोड़ के सुपर स्पेशलिटी सेंटर की मैंने अभी 295 के तहत बात

(श्री सुमित गोदारा)

उठाई थी। वह वहां पर एक साल से बंद पड़ा है। वह भी सिर्फ इसलिए कि कोई मंत्री जाए, कोई मुख्य मंत्री जाए, उद्‌घाटन करे। आम जनता अपने इलाज के लिए तरस रही है। यह है आपके निरोगी राजस्थान की बात।

पी.बी.एम. हास्पिटल में केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम जी ने 5 करोड़ से सी.एस.आर. फैसेलिटी के तहत सोलर प्लांट, एक कम्पनी लगाने के लिए तैयार है, जिससे 76 लाख रुपये महीने का बिल पी.बी.एम. हास्पिटल का बचेगा। लेकिन राजनीति के कारण उस जगह को नहीं दे रहे हैं। वह संस्था के लिए 5 करोड़ रुपये लेकर घूम रहे हैं और ये काम करने नहीं दे रहे हैं। आप निःशुल्क दवाइयां तो क्या, बीमारों के साथ यह हाल कर रहे हो।

सभापति महोदय, मैं एक चीज का जरूर स्वागत करूंगा कि कैंसर रजिस्ट्री सिस्टम जो आप लेकर आए हैं, बीकानेर में सी.टी. स्कैन कैंसर की लैब में जरूर अच्छी व्यवस्था होगी। लेकिन साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि राज्य कैंसर सेंटर जो कि जयपुर में है, उसमें आपने बजट में यह लिखा है कि इसे अगले साल से शुरू करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी इसको शुरू क्यों नहीं कर रहे हो? हर जगह कैंसर की चर्चा चलती है तो आप अभी से ही क्यों नहीं शुरू कर रहे हो? आप अगले साल का इंतजार क्यों कर रहे हो?

चिकित्सा शिक्षा की बात देखें तो इसमें सरकारी मेडिकल कालेजों की फीस हर साल 10 परसेंट बढ़ा रहे हो। गरीब बच्चा जो कि गांव से आ रहा है, वह इसको कैसे वहन करेगा। आपने ये जो मेडिकल कालेज खोले हैं, ये सोसाइटी के माध्यम से खोले हैं। इनकी फीस का क्या स्ट्रक्चर है? क्या गरीब आदमी वहन कर पाएगा, जो आप इतना बड़ा स्ट्रक्चर कर रहे हो? यहां पर कांग्रेस के कई सदस्य बोले और मुख्य मंत्रीजी भी बोले कि हमने ये मेडिकल कालेज खोले, वे मेडिकल कालेज खोले। इस पर मैं कहना चाहूंगा कि 1960 तक राजस्थान में 5 मेडिकल कालेज थे। छठा मेडिकल कालेज कोटा में भैरोंसिंह जी शेखावत साहब ने खोला। सातवां मेडिकल कालेज झालावाड़ में माननीय वसुन्धरा राजे जी ने खोला। आपने कोई मेडिकल कालेज नहीं खोले। यह इसलिए नहीं खोले क्योंकि आप दिल्ली में शासन करते थे और प्राइवेट आप ही के कांग्रेसी नेताओं के मेडिकल कालेजेज महाराष्ट्र और कर्नाटक में थे। इस कारण से आपने मेडिकल कालेज नहीं खोले। इसी वजह से राजस्थान चिकित्सा में पीछे गया। अब मोदी जी की सरकार आयी तो मेडिकल कालेज जगह-जगह खोल रहे हैं। अब जो प्राइवेट दुकानें थीं, वे बंद होने लगी हैं।

(श्री सुमित गोदारा)

सभापति महोदय, पेयजल की बात करते हैं। पेयजल के लिए आपने बजट में बातें कीं। हमारे बीकानेर से कल्ला जी मंत्री हैं। हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे यहां बीकानेर से दो-दो मंत्री हैं, कल्ला जी और भंवरसिंह जी। बीकानेर की जनता को बड़ी उम्मीद थी कि बजट में बड़ा खजाना लेकर आएंगे। लेकिन बड़ा दु:ख हुआ कि पेयजल में यह हाल है कि 70 दिन की नहर बंदी होने वाली है। उसकी माननीय मंत्रीजी ने मीटिंग तो रखी, लेकिन विडम्बना देखिए कि एक साल से बीकानेर में ट्यूबवैल के टेंडर ही नहीं हुए हैं। कंटीन्जेंसी प्लान कहां से बनेगा, ट्यूबवैल के टेंडर नहीं हुए हैं। टेंडर क्यों नहीं हुए? जी.डब्ल्यू.डी. की 2 मशीनें हैं पूरे बीकानेर में, वे कहां-कहां ट्यूबवैल खोदें। हम मंत्रीजी से निवेदन करेंगे कि उनका टेंडर जल्दी से कराएं ताकि गरीब किसानों को लाभ हो। गांवों के लिए हमने ट्यूबवैल्स के जो प्रस्ताव बनाकर एक साल में दिये हैं, वे आपने कहीं नहीं खोदे हैं। यह आपकी सरकार की गम्भीरता को दिखाती है। लूणकरणसर तहसील में 110 गांव हैं। बीकानेर तहसील में 42 गांव हैं। लूणकरणसर तहसील में सिर्फ एक ही जे.ईएन. और एक ही ए.ईएन. हैं, उनके ही भरोसे पानी की व्यवस्था है। यह तो भला हो देश की जनता का कि नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने। हमें विश्वास है कि धोरों की धरती, रेगिस्तान में 2024 तक मोदी जी की जल जीवन मिशन योजना, घर-घर जल, घर-घर नल जरूर पहुंचेगी और रेगिस्तान के गांवों में वह प्यास बुझाएगी।

सभापति महोदय, लाइट की बात, ऊर्जा की बात करते हैं। आपने सौर और पवन ऊर्जा के बारे में लिखा है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि बीकानेर को आप सोलर हब बनाओ। ऐसा अवसर आपको बार-बार नहीं मिलेगा। आप ऊर्जा मंत्री हो। लूणकरणसर में जामसर क्षेत्र है, वहां पर आप सोलर हब बनाओ। वहां न सिर्फ आप हब बनाओ, बल्कि वहां 2-3 प्लांट आए हैं, और भी प्लांट आने को तैयार हैं। लेकिन मैं तो आपको कहूंगा कि वहां पर कुछ राजनीतिज्ञों के कारण सोलर हब में कम्पनी वाले आने से डर रहे हैं। यह भी एक गम्भीर विषय है। ऐसा कौन राजनीतिज्ञों को संरक्षण दे रहा है कि कम्पनियां भी डर रही हैं? एक बात और है कि उन कम्पनियों में भी रोजगार बाहर वालों को दिला रहे हैं। ऐसे कौन राजनीतिज्ञ हैं? स्थानीय लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? जब इतनी बड़ी-बड़ी कम्पनियां आ रही हैं तो स्थानीय लोग कहां जाएंगे?

(श्री सुमित गोदारा)

किसानों को 10 हजार रुपये, जो माननीय वसुन्धरा जी ने सब्सिडी दी थी, वह 833 रुपये महीने के, किसानों को पिछले 6 महीनों से नहीं मिल रहे हैं। सरकार से बात करते हैं तो कहते हैं कि डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन किसान के खाते अभी भी खाली हैं। उसमें पैसे नहीं आ रहे हैं। कोई नया जी.एस.एस. नहीं बन रहा है, वोल्टेज की समस्या है। आपने सिर्फ 50 हजार कृषि कनेक्शंस की घोषणा की है, 50 हजार में क्या होगा? मुझे लगता है कि सामान्य वर्ग को तो अभी भी इंतजार करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, ट्यूरिज्म, पर्यटन की बात पक्ष-विपक्ष से हटकर बात है। हम देखते हैं कि भारत में एक करोड़ ट्यूरिस्ट आते हैं। उसमें से राजस्थान में भी काफी आते हैं। आपने 100 करोड़ रुपये पर्यटन विकास के लिए दिये हैं। पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ रुपये क्या मायने रखते हैं? पर्यटन में यह हम सब के लिए चैलेंज है क्योंकि यह राजस्थान की 8 परसेंट जी.डी.पी. ग्रोथ को प्रभावित करता है। यह उस जी.डी.पी. का हिस्सा है। इस पर्यटन को राजस्थान चैलेंज के रूप में ले। मैं चाहूंगा कि इसको मंत्रियों और सचिवों से अलग हटाकर के, प्राइवेट पब्लिक में लें। इसको एक टार्गेट के रूप में लेकर के बनाएं तो वह दिन दूर नहीं होगा जब राजस्थान की जनता को इस पर्यटन से रोजगार मिल सकता है। राजस्थान में पर्यटन की प्रबल सम्भावनाएं हैं, लेकिन बड़े ही दु:ख का विषय है कि आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ भैरोंसिंह जी शेखावत साहब योजना लेकर के आए थे, उससे बहुत फायदा मिला। पर्यटन से हम न सिर्फ लोगों को रोजगार दें बल्कि राजस्थान को विकास की गति पर ले जाएं।

सभापति महोदय, मैं एक विषय और आपके सामने लाना चाहूंगा कि राजस्थान में पुलिस के पास इंटरसैप्टर गाड़ियां हैं। ये अपना काम करने के बजाय लोगों को व्यवधान ज्यादा करती हैं। अनेक बार देखा है कि जो बाहर की गाड़ियां आती हैं, उनको रोका जाता है। इससे ट्यूरिज्म पर भी विपरीत असर पड़ता है। जो हमारे क्षेत्र में टैक्सी गाइड हैं, जो कि बाहर पर्यटकों को लेकर जाते हैं, वे कहते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। यहां तो बाहर की गाड़ियां देखते ही लपकते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। इससे आने वाला ट्यूरिस्ट डरता है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दिया कि वहां जाते हैं तो कोई हमें तंग नहीं करता है। इस बात पर भी सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए कि यदि हमें ट्यूरिज्म बढ़ाना है तो हमारे यहां जो आने वाला

(श्री सुमित गोदारा)

पर्यटक है, जो हमारा नारा है, 'पधारो म्हारे देश', उसको वास्तव में साकार करें। ऐसा नहीं कि कोई आदमी आये तो वह डरे कि राजस्थान में तो जाते ही लोग पैसा वसूलने के लिए तैयार बैठे हैं।

सभापति महोदय, कृषि कल्याण कोष में आपने एक हजार करोड़ दिये हैं। किसान की अकाल मृत्यु पर जो अभी 2 लाख रुपये दिये जाते हैं, उसे 10 लाख रुपये करें ताकि उस गरीब किसान को फायदा मिले।

शिक्षा की बात आयी, आपने 'नो बैग डे' का कहा, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन आपने 'नो बैग डे' में बजट का एलोकेशन तो कुछ किया ही नहीं। आप कुछ बजट की घोषणा करते कि हम यह योजना लेकर के आ रहे हैं। स्कूलों में सांस्कृतिक गतिविधियां, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, डिबेट्स करवाते, उसके लिए कम से कम बजट तो देते, बजट तो आपने कुछ आपने दिया ही नहीं। विवेकानन्द इंग्लिश मीडियम स्कूलों की आपने जो घोषणा की है, 167 जहां बाकी हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे लूणकरणसर में ऐसे क्षेत्र में खोला जाए, जहां ज्यादा गांव का क्लस्टर हो, जहां ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र के लोगों को फायदा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक गम्भीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में कालू और राजेरा, दो गांव हैं। कालू गांव में ग्राम पंचायत द्वारा, जून में वहां के सरपंच श्री शिवजी सारस्वत कन्या शिक्षा के लिये, बारहवीं के स्कूल के लिए, एक करोड़ रुपये दिये। लेकिन वहां पर एक ऐसा ए.डी.पी.सी. अधिकारी बैठा है, वह चाहता है कि सिर्फ हमारे वहां के स्थानीय कांग्रेस के नेता से उद्घाटन करवाओगे तभी वह आपका काम करने देगा, नहीं तो नहीं करने देगा। ऐसा का ऐसा ही, राजेरा गांव में बारहवीं की स्कूल, जहां पर सत्तर लाख रुपये सरकार से मिले हैं और पंचायत समिति का बजट मिलकर वह बिल्डिंग तैयार है, जुलाई से बिल्डिंग तैयार है, खराब हो रही है, पर वह ए.डी.पी.सी. इसीलिए जूनियर अधिकारी है जिसको रमसा का चार्ज दिया गया, ए.डी.पी.सी. का चार्ज, और वह अधिकारी सिर्फ राजनीतिक कारणों से नहीं चाह रहा है कि वे दोनों स्कूल खुलें।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि उद्घाटनों की बात चली तो हमारे वहां तो जो हमारे भा.ज.पा. शासन में रमसा के तहत इतने काम कराये गये थे, तीन-तीन, चार-चार कमरे अनेक स्कूलों में

(श्री सुमित गोदारा)

जो बारहवीं में क्रमोन्नत किये गये थे, उनमें भी हाल यह है कि बिल्डिंग बने एक-एक, दो-दो साल हो गये, और वहां के कांग्रेस के नेता गाड़ियों में शिलालेख लेकर चलते हैं साथ में एक लिखने वाला लेकर चलते हैं और जहां भी जाते हैं स्कूल में चिपकाते हैं कि यहां हमारे द्वारा यह काम कराया गया है। ऐसा देखकर लोग हंसते हैं कि यह तो एक-दो साल पहले काम हुआ और अभी भी शिलालेख लगा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसी के कारण राजेरा और कालू में काम नहीं होने देना चाह रहे। मैं अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाते हुए दो-तीन इश्यु और रखूंगा। आपने स्थानीय निकाय और नगरीय विकास में छह नगरपालिकाओं की घोषणा की। हमें बड़ी खुशी होती यदि आप लूणकरणसर और नापासर, दो बड़े कस्बों की भी करते, जिनको प्रदेश में पूर्व मुख्य मंत्री, वसुन्धराजी के समय नगरपालिका बनाया गया था, कांग्रेस शासन आया तो उन्होंने वापस उनको ग्राम पंचायत के रूप में परिवर्तन कर दिया।

उच्च शिक्षा में हमारे राजकीय महाविद्यालय, लूणकरणसर में एम.ए. और एम.एससी. की क्लास शुरू करते, लॉ की क्लास शुरू करते, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंहजी भाटी हमारे बीकानेर से रहे हैं, तो हमें उम्मीद थी कि हमारे लूणकरणसर और बीकानेर को देंगे पर वे क्या देंगे जब पूरे राजस्थान में ही आपकी सरकार ने कहीं कुछ नहीं दिया तो कहां बीकानेर का नम्बर आता। वैसे भी पूरे राजस्थान में आम आदमी यही चर्चा कर रहा है कि बजट तो सिर्फ जोधपुर जिले का ही है। ऐसा नहीं लगता है कि वह राजस्थान का बजट है, ऐसा लगता है कि जोधपुर के लिए ही विशेष बजट लाया गया है। मैं पी.डब्ल्यू.डी. को धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्रीजी, नरेन्द्र मोदीजी को, जिन्होंने पिछले छह वर्ष में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, फेज वन और फेज टू के नवीनीकरण के कार्य के लिए बजट दिया, जिससे सड़कों का काम हुआ। अभी हाल ही में फेज थर्ड के लिए भी राशि जारी की गयी। मनमोहन सिंहजी के दस साल का कार्यकाल था, उसमें कोई पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों के लिए राशि जारी नहीं की गयी। यह फर्क है काम में। इसके लिए पी.एम.जी.एस.वाई. थर्ड फेज में हमारे लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में 31 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण के लिए दस करोड़ की राशि आयी।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, मैं बात को समाप्त करता हुआ इतना जरूर कहूंगा कि मिसिंग लिंक की बात की है। लोग ढूंढ रहे हैं कि वह मिसिंग लिंक कहां मिस हो गयी। डेढ़ साल में इतनी मिसिंग लिंक बनायी, यह बात कह रहे हैं, हमारे तो एक ही सड़क नहीं बनायी और न ही एक किलोमीटर सड़क कहीं बनायी, न कहीं कोई कार्य हुआ। विकास पथ की घोषणा हुई, लेकिन विकास पथ हमें नहीं दिखा। पंचायती राज का तो क्या कहें, गांवों में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि पंचायत के कब चुनाव होंगे? आज इतने दिन हो गये, यह बात आम आदमी कह रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने जो बात की, कर्मयोगी कर्मशीलता की, तो काम तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। तभी तो देखो कि पंचायती राज का पुनर्गठन आजादी के बाद राजस्थान में हुआ तो दोनों बार भारतीय जनता पार्टी ने कराया, भैरोंसिंहजी शेखावत साहब और वसुन्धरा राजेजी ने कराया। कांग्रेस ने पहली बार कोशिश की, पर इनकी कोशिश से पार नहीं पड़ी।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं यही कहूंगा कि ऐसा निराशाजनक बजट था, जैसे यह सरकार रही है और जब-जब भी अशोकजी गहलोत राजस्थान के मुख्य मंत्री रहे हैं, राजस्थान हमेशा पिछड़ गया है। जनता तो इंतजार कर रही है कि कैसे तीन साल निकलें और कैसे 2023 के चुनाव आएं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और राजस्थान विकास की नयी ऊंचाइयों पर पहुंचे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गजराज खटाणा।

श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बार जो बजट पेश किया, उसमें सात बिन्दुओं पर अपना बजट पेश किया; और सबसे पहला बिन्दु उनका निरोगी राजस्थान था। निरोगी राजस्थान के बारे में हम कई दिन से चर्चा सुन रहे हैं। उस चर्चा में खास तौर से बात निकलकर आयी कि बजट जो दिया गया है, उसमें लगभग साढ़े चौदह हजार करोड़ रुपये उन्होंने बजट के लिए एलोकेशन किया है। साथ ही उन्होंने निरोगी राजस्थान प्रबन्धन कोष के लिए अलग से सौ करोड़ रुपये और दिये हैं। साथ में पन्द्रह मेडिकल कालेज खोलने और उसके साथ में अपनी भागीदारी निभाते हुए सब तरह से राजस्थान सरकार ने उसमें जो पन्द्रह मेडिकल कालेज

(श्री गजराज खटाणा)

खोले हैं, उनकी भूमि आबंटन हो गयी है और जल्दी ही उनको शुरू करने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूं कि निशुल्क दवा योजना में शायद पूरे देश में राजस्थान प्रथम है। करीब 709 नि:शुल्क दवाएं इस प्रदेश में वितरित की जा रही हैं। साथ ही पैट-सीटी स्कैन, इस तरह की मशीन यहां पर एस.एम.एस. अस्पताल में लगायी जा रही है, जिससे कैंसर रोगियों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा भी निरोगी राजस्थान में बहुत सारी योजनाएं हैं, वह आप सबके सामने हैं।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा बिन्दु उन्होंने किसानों के लिए लिया। किसानों से सम्बन्धित जितनी भी बातें थीं, वे आपने बजट में सुनी होंगी। खास तौर से बीज के सम्बन्ध में उन्होंने आठ लाख टन से बढ़ाकर बारह लाख क्विंटल बीज पैदा करने की बात की है, चौदह नयी स्वतंत्र मंडियां स्थापित करने की बात की है।

माननीय सभापति महोदय, पशुपालन के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे नये आयाम स्थापित करने के लिए बातें की हैं। मैं खास तौर से यह कहना चाहूंगा कि पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में भी पानी की कमी हो गयी है, वहां पर पशुपालन ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय बच गया है, जिससे गांव के लोग अपना जीवनयापन करते हैं। मैं खास तौर से गुजारिश करना चाहूंगा, कृषि मंत्री महोदय, गोपालन मंत्री महोदय, इस बात पर ध्यान दें कि अगर हमने अपने गांवों में पशुपालन को बढ़ावा दिया, और अब एक नयी परम्परा चल रही है जैविक खेती की, जैविक दूध का भी हम लोग देखते हैं कि यहां जयपुर में, सरस डेयरी का दूध चालीस-पैंतालीस रुपये लीटर मिल रहा है और जो आसपास में डेयरियां करके लोग गिर गाय का, दूसरी गाय का दूध ले रहे हैं, अस्सी रुपये, सत्तर रुपये लीटर तक दूध बेच रहे हैं, इसका हमें गांवों में प्रचार करके लोगों को समझाना चाहिए कि हम लोग अगर इस तरह से प्रोडक्ट का उत्पादन करेंगे, जैविक दूध का उत्पादन करेंगे और उसको हम शहर में लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से ज्यादा फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, तीसरा बिन्दु, महिला, बाल एवं वृद्ध कल्याण का है। इस बिन्दु पर मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि चाहे पिछली सरकार रही हो या कोई भी सरकार रही हो, यह जो आंगनबाड़ियों वाला झमेला है, मैं समझता हूं कि ये शायद किसी के काबू में नहीं आया। एक तो पी.डी.एस. सिस्टम में गांव में वितरण का मामला और एक आंगनबाड़ी वाला

(श्री गजराज खटाणा)

मामला, दोनों ऐसे मामले हैं, जिन पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। जिन लोगों को इनकी जरूरत है, जिन बच्चों को इनकी जरूरत है, जिन गरीब लोगों को पी.डी.एस. में सामान मिलना चाहिए, उनको सही तरीके से नहीं मिलता। जिला लेवल पर, ब्लाक लेवल पर बहुत सारी शिकायतें आती रहती हैं। राज्य सरकार ने प्रयास किये हैं और मैं समझता हूं कि इस बजट में और ज्यादा प्रयास करके इस चीज को मजबूत किया जाएगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में इस बार एक बहुत अच्छा बिन्दु बजट में रखा है। अभी तक हम लोग जितने भी अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक लोग थे, उनको 2500 रुपये प्रत्येक विद्यार्थी को उनके हॉस्टल्स में दे रहे थे। इस बार अलग से एस.बी.सी., एम.बी.सी. और ओ.बी.सी. को भी 2500 रुपये प्रत्येक विद्यार्थी को दिये जाएंगे, यह एक अच्छा बिन्दु है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने जो नया पुनर्गठन किया है, 57 नयी पंचायत समितियां और 1,456 नयी ग्राम पंचायतें बनायी हैं, मैं समझता हूं कि इससे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी छोटी यूनिट बनेंगी तो विकास के नये आयाम स्थापित होंगे, ऐसा मैं मानता हूं।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में "नो बैग डे" और साथ ही कई नये काम वहां किये हैं। 22 नये कस्तूरबा आवासीय विद्यालय खोले हैं और बच्चियों की शिक्षा के लिए अलग से नये आयाम स्थापित किये हैं।

पी.डब्ल्यू.डी. में 400 करोड़ रुपये से 20 सड़कों का नवीनीकरण का काम हाथ में लिया है। बिजली के क्षेत्र में 2,000 करोड़ रुपये का बजट अलग से रखा है। उसमें यह कहा है कि हम किसानों को दिन में ही बिजली देंगे, यह किसानों के लिए एक स्वागत योग्य योजना है।

जयपुर में दस करोड़ रुपये की लागत से खादी प्लाजा बनाया जाएगा। बुनकर संघों को अलग से दो करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ किया जाएगा। ये ऐसी योजनाएं हैं, जो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार के लिए आने वाले समय में अच्छा काम करेंगी।

साथ ही मैं अपने जिले दौसा की कुछ बातें करना चाहूंगा। दौसा में पानी एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, इसलिए बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ईसरदा बांध का प्रोजेक्ट लाये और उसके लिए 3,200 करोड़ रुपये का आबंटन किया। मैं यह भी मांग करना चाहूंगा कि इस बांध के साथ-साथ अगर हम पाइप लाइनों को भी साइमल्टेनियसली बनाएंगे तो मैं समझता हूं

(श्री गजराज खटाणा)

कि इस जिले में जल्दी से जल्दी पानी आ जाएगा और एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा।

साथ ही बांदीकुई क्षेत्र में पर्यटन विकास के दो नये क्षेत्र हैं। चांद बावड़ी, जो करीब 1,100 साल पुरानी बावड़ी बनी हुई है, उसमें पर्यटन के बहुत बड़े आयाम स्थापित हो सकते हैं। रोजाना करीब 700-800 पर्यटक वहां आते हैं। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां अलग से बजट दे ताकि इस क्षेत्र को और ज्यादा विकसित किया जा सके। साथ ही बसवा में, जहां महाराणा सांगा ने अंतिम सांस ली थी, उनकी समाधि के पुनरुत्थान के लिए, उसके जीर्णोद्धार की मैं मांग करता हूं। वहां राणा सांगा के नाम पर एक महाविद्यालय खोला जाए, ऐसी मैं मांग करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

सूचना

राजफैड की मार्फत एम.एल.ए. लैड फण्ड के दुरुपयोग का प्रस्ताव

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, कल विधान सभा स्थगित होने के बाद मैं मेरे निवास पर गया। एक आदमी मेरे पास आया और फोटो दिखायी कि यह बस स्टैण्ड है और यह श्मशान घाट है, ऐसा-ऐसा निर्माण हम करते हैं। वह राजफैड का एक आदेश भी लेकर आया कि इसके तहत आप मुझे लिखकर दे दीजिए कि इसमें एम.एल.ए. कोटे से हम निर्माण करवाएंगे।

मैंने कहा कि हम तो जिला कलेक्टर के माध्यम से, जो हमारी एजेंसीज हैं पी.एच.ई.डी., पी.डब्ल्यू.डी., उनसे करवा लेते हैं। आपकी जरूरत क्या है? उसने मुझसे पूछा कि आपको क्या मिलता है। मैंने कहा, क्या मिलना है? वह बोला, इसमें आपको चालीस प्रतिशत राशि रिश्वत के रूप में देंगे। (व्यवधान) रिश्वत के रूप में चालीस प्रतिशत राशि देंगे। हमने पहले कई पूर्व माननीय सांसदों और एम.एल.एज. के साथ काम किया है, इसलिए आप यह काम करवा लें। चूंकि हम यह काम राजफैड के माध्यम से कराएंगे, इसलिए आपके ऊपर आरोप भी नहीं लगेगा। एक सोहेल खान नाम का व्यक्ति था, जिसका टेलीफोन नम्बर 9827070136 है। यानी हम सब लोगों को बेईमान बनाने के लिए गिरोह चल रहे हैं। ये माननीय सदस्यों को बेईमान बनाना चाहते हैं।

(श्री मदन दिलावर)

मैंने उससे कहा कि आप एम.एल.एज. को भ्रष्ट बनाने का काम क्यों कर रहे हैं? मैंने उसे डांटा और वहां से भगा दिया। फिर उसने कहा कि माफ करें, मैं गलती से आ गया हूं। मैंने तो पहली बार ऐसा सुना है कि आप ऐसा काम नहीं करते हैं। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड के माध्यम से जिन लोगों ने काम कराया, उनका रिकार्ड उठाकर देख लीजिए। वह सारा काम मैंने ही किया है।

मेरा ऐसा अनुमान है कि इस राजस्थान में पिछले दस सालों में कम से कम बीस करोड़ रुपये के काम हुए होंगे जो इस सोहेल खान नाम के व्यक्ति ने राजफैड के माध्यम से कराये हैं और चालीस प्रतिशत राशि रिश्वत के रूप में दी है। इन सबकी जांच कराएंगे तो सबके चेहरे सामने आ जाएंगे कि कौन-कौन इस एम.एल.ए. कोटे और एम.पी. कोटे में बेईमानी कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती डाल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें, किसके माध्यम से काम कराये हैं और कुछ ने हमको लिखकर भी दे दिया है, उनकी भी जांच कराएं। इस संस्था, राजफैड की जांच कराएं कि अधिकारी किस आधार पर दरों को अनुमोदित कर रहे हैं और इस प्रकार के भ्रष्टाचार के खेल को खेलने की अनुमति दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि +++ नाम का महाप्रबंधक है राजफैड का, महाप्रबंधक-।। (लेखा), उसे पकड़ें और सोहेल खान को तुरंत गिरफ्तार करें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): जिसका मैंने नाम बताया और टेलीफोन नम्बर दिया, उससे गम्भीर पूछताछ करेंगे तो सबके चेहरे सामने आ जाएंगे। यह मुझे इन्फार्मेशन देनी थी।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, लम्बा नहीं कहूंगा। माननीय सदस्य ने बात उठायी है...

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। प्लीज, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सारे सदस्यों पर एक तरह से सवालिया निशान लगा है।

श्री सभापति: सरकार के संज्ञान में आ गया। जो भी मामला है, सरकार अपने आप दिखाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): राज्य सरकार ए.सी.बी. में मामला दर्ज करवाए। ए.सी.बी. में मामला दर्ज करवाकर जांच कराए।

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें। श्रीमती किरण माहेश्वरी। माननीय सदस्या, पंद्रह मिनट आपके लिए निर्धारित किये गये हैं। समय आपका शुरू होता है अब। पंद्रह मिनट बाद आप मुझे बार-बार नहीं कहेंगी कि मैंने आपको समय कम दिया।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 पर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप कुछ ग्रेस मार्क्स दे दीजिएगा।

श्री सभापति: पंद्रह सैकण्ड ग्रेस मार्क्स हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 20 फरवरी, 2020 को राज्य का बजट रखा और उस बजट की शुरुआत में ही उन्होंने अपने वक्तव्य में केन्द्र सरकार को कोसने का काम किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की नीतियां गलत हैं और उन्होंने केन्द्र सरकार की आलोचना की। मुझे लगता है कि उन्होंने यह आलोचना अनावश्यक ही की, क्योंकि वे अपना खुद का तो घर सम्भाल नहीं पा रहे हैं और दूसरों पर पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं। पहले अपने यहां पर देख लें कि राजस्थान की क्या स्थिति हो गयी है। बजट जो रखा है, वह इतना नीरस है, इसमें जो सारी घोषणाएं हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि बिलकुल ही दिखावटी है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं व खाने के कुछ और। इस प्रकार की उनकी बजट घोषणाएं हैं।

बजट में इनका जो पैरा नम्बर 3 है, उसे पढ़कर सुनाना चाहती हूं। उसमें उन्होंने कहा, देश की अर्थव्यवस्था के अधिकतर सूचकांक यह संकेत दे रहे हैं कि वर्तमान में अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। अब कल ही की बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जब अहमदाबाद आये तो उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भारत अब आर्थिक महाशक्ति भी बन चुका है। इतना अच्छा उन्होंने भारत के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत एक करिश्माई देश है। नरेन्द्र मोदी जी दिन और रात काम करते हैं, यह उसी का नतीजा है कि इतने बड़े राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति यहां आकर इतनी अच्छी बात कहते हैं।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

विश्व में अमेरिका को हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश मानते हैं। आज हमारे इस बजट में मुख्य मंत्री इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं कि अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है। वे राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर ध्यान दें कि वह कैसी है। उन्होंने पैरा नम्बर 7 में एक बात कही है। उन्होंने कहा, 13 हजार करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किये गये लेकिन कार्यों के भुगतान का भार भी हमारी वर्तमान सरकार नहीं उठा पा रही है, जिसके चलते कुछ विभागों के संवेदकों (Contractors) के बकाया बिलों के भुगतान समय पर नहीं हो पाये। भुगतान समय पर नहीं हो पाये, इसे उन्होंने एडमिट किया है, लेकिन इसके लिए आगे क्या करेंगे, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है।

इस बजट को अगर देखें तो जनता को पूरी तरह से गुमराह करने वाला है। बजट में कहीं कोई चीज ऐसी नहीं लग रही, इसलिए मैं तो यह कहूंगी कि ये जो कह रहे हैं न, देश की अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी से उतर रही है, इसके संदर्भ में उन्हें खुद को देखना है कि यह गाड़ी जो है, जो इस सरकार के इतने सारे भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं, तुष्टिकरण की इस सरकार की जो नीति है, उसी से कांग्रेस सरकार की यह जो गाड़ी है, वह पटरी से उतर रही है। कांग्रेस के लिए अगर मैं चार लाइनों में कहूं तो यह कह सकती हूं

एक परिवार की दास्तां वो कहते हैं,
घोषणाएं बड़ी-बड़ी कर पूरा उन्हें नहीं करते हैं,
झूठ वे बोलते हैं और जोर से बोलते हैं,
सत्ता के लिए देशहित से समझौता वे करते हैं।।

राष्ट्र के प्रति जो समर्पण की भावना होनी चाहिए, वह इस कांग्रेस सरकार की कभी भी नहीं रही। कांग्रेस का इस प्रकार का कभी आचरण नहीं रहा। हमने यह देख लिया। सी.ए.ए. का उन्होंने विरोध किया। जो भी केन्द्र की योजनाएं आती हैं, उनका विरोध करते हैं। इन्होंने बजट भाषण में एक और बात कही। इन्होंने कहा, करों में राज्य का हिस्सा 10,400 करोड़ रुपये कम हो गया है। वर्ष 2019-20 के बजट में इन्होंने केन्द्रीय करों से जो प्राप्ति बतायी है, वह 44,500 करोड़ रुपये है। विगत वर्ष बहुत सारी वस्तुओं पर खुद राज्य सरकार की मांग पर ही यह जो टैक्स रेट है, वह घटायी गयी थी। पूर्व में जो वैट और एक्साइज ड्यूटी है, उसे मिलाकर अधिकांश वस्तुओं के ऊपर जो 32 परसेंट का टैक्स बर्डन था, वह घटकर 18 परसेंट हो गया। यह टैक्स बर्डन कम हुआ है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

मुख्य मंत्रीजी इस बात को छिपा रहे हैं कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2019-20 में अनुदान के रूप में राजस्थान को 30,718 करोड़ रुपये दिये। केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी एवं अनुदान अगर राज्य सरकार का देखा जाए तो वर्ष 2019-20 को 66 हजार 767 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि वर्ष 2018-19 में ये मात्र 61 हजार 889 करोड़ रुपये ही मिले थे। इस प्रकार इस वर्ष में 4 हजार 878 करोड़ रुपये अधिक मिले हैं। इसलिए, यह कहना कि हमें कम अनुदान मिल रहा है, और लोगों को भ्रमित करना, यह गलत है। उसके अलावा अगर देखें तो कर्ज का जो भार है, उसमें मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान पर जो कर्ज का भार बताया है, उसमें पिछली सरकार पर इन्होंने दोषारोपण किया। इन्होंने कहा कि 3 लाख 11 हजार 374 करोड़ रुपये का कर्ज पिछली सरकार छोड़कर गयी है। आप अपने कार्यों को भी देख लो कि आपने बजट के जो आंकड़े बताये हैं वे 31 मार्च, 2020 को सकल कर्ज 3 लाख 41 हजार 354 करोड़ रुपये और 31 मार्च, 2021 तक, अगर इसी प्रकार यह बढ़ता रहा तो यह 3 लाख 75 हजार 353 करोड़ रुपये हो जाएगा। केवल दो वर्ष में कर्ज 64 हजार करोड़ रुपये बढ़ रहा है, 21 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। यह इनको देखना है। मतलब खुद अपने गिरहबान में सरकार देखे कि वह क्या कर रही है। अब सरकार यह कहती है कि बजट वर्ष 2020-21 के अन्दर केन्द्र बिन्दु, सात ऐसे संकल्प रखे हैं, लेकिन ये संकल्प नहीं हैं, माननीय सभापति जी, ये जनता के साथ में धोखा देने का सात सूत्रीय कार्यक्रम इन्होंने बनाया है, एक अभियान इन्होंने चलाया है।

अब राजसमन्द के ऊपर मैं आऊं तो राजसमन्द जिला चिकित्सालय में अधिकतर पद रिक्त पड़े हैं। पिछली बार मैंने क्वेश्चन के माध्यम से पूछा तो भी पता चला कि चिकित्सालय में फिफ्टी परसेंट से भी ज्यादा पद रिक्त हो रखे हैं। गांव के जो उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं वहां पर ए.एन.एम. नहीं, पी.एच.सी. के अन्दर देखो तो कोई कम्पाउण्डर नहीं, सी.एच.सी. के अन्दर देखो तो डाक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। अब ये कहते हैं कि निरोगी राजस्थान बनाएंगे, तो निरोगी राजस्थान बनाने के लिए पहले जो चिकित्सा का इन्फ्रास्ट्रक्चर है उसको तो आप ठीक कर लो। पहले उसको ठीक करोगे तब तो निरोगी राजस्थान के लिए जाओगे। संकल्प तो ले रहे हैं निरोगी राजस्थान। अब यही मैं कहना चाह रही हूं कि यह जो संकल्प ले रहे हैं वे संकल्प जनता के साथ में एक तरह का धोखा कर रहे हैं। इनका काम ही धोखा देना है। किसानों के

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

साथ धोखा किया। इन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि किसानों का सम्पूर्ण कर्जा हम माफ कर देंगे और कहा कि एक-दो दिन नहीं, मात्र दस दिन के अन्दर सारा कर्जा माफ कर देंगे। कांग्रेस पार्टी के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी यहां राजस्थान में आकर भाषण देकर जाते हैं कि सब कर्जा माफ कर देंगे। एक पैसे का कर्जा माफ नहीं हुआ। और तो और, जो कर्जदार थे, जिन्होंने कर्जा ले रखा था उनके ऊपर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है।

अब यह सरकार धोखा किस प्रकार से देती है, उसको आप देखो कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना केन्द्र की योजना है, उसकी बीमा राशि में जो राज्य का हिस्सा एक हजार 430 करोड़ रुपये है वह इनको जमा कराने का समय नहीं है। किसान की फसल खराब होने पर उसको बीमा की राशि नहीं मिल सकती तो किसान के साथ यह कितना बड़ा धोखा है। प्रधान मंत्रीजी ने जो किसान सम्मान निधि शुरू की, हर किसान को छह हजार रुपये सालाना मिलने हैं लेकिन राजस्थान सरकार इस किसान सम्मान निधि को भी किसान तक नहीं पहुंचा पायी। इतनी बड़ी विफलता इस सरकार की है और फिर कहते हैं हम संकल्प लेते हैं कि सम्पन्न किसान बनाएंगे। यह सम्पन्न किसान बनाने का संकल्प नहीं, यह किसानों के साथ में धोखा है, जो ये कर रहे हैं।

अब प्रधान मंत्रीजी ने इतनी अच्छी योजना बनायी और कहा कि हम जल जीवन मिशन के माध्यम से घर-घर तक जल पहुंचाएंगे। उस जल को पहुंचाने के लिए उन्होंने कहा कि फिफ्टी परसेंट पैसा आपको देना है, फिफ्टी परसेंट पैसा हम देंगे। 50 प्रतिशत पैसा जो केन्द्र से आना था, वह 429 करोड़ रुपये छह महीने पहले इनके एस्क्रो अकाउंट में आये, लेकिन उसका मैचिंग ग्रांट जो इनको देना था वह इन्होंने नहीं दिया। रिजल्ट क्या हुआ कि वह जो मैचिंग ग्रांट देना था उसके लिए राजस्थान सरकार ने कहा कि इस पैसे का तो हमने उपयोग कर लिया। कहां उपयोग कर लिया, पुरानी योजना में। अब दूसरी किश्त हमें दो। दूसरी किश्त मांग रहे हैं और आज ही हमने अख़बार में पढ़ा राजस्थान के मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि 90 प्रतिशत पैसा केन्द्र दे, 10 प्रतिशत पैसा हम देंगे। राजस्थान क्या अलग है? पूरे देश के लिए प्रधान मंत्रीजी ने पहली बार योजना बनायी, अदरवाइज तो हमेशा यह कहा जाता था कि यह जो जल है वह तो राज्य का विषय है और राज्य को निपटना है। लेकिन यहां पर केन्द्र सरकार फिफ्टी परसेंट पैसा देती है, फिर भी उसका मैचिंग ग्रांट

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

राजस्थान सरकार नहीं दे पाती, जिसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से यह योजना नहीं हो रही है।

इन्होंने डी.एल.सी. में 10 प्रतिशत कम करने की घोषणा की। राजसमन्द में अभी एक महीने पहले 20 प्रतिशत डी.एल.सी. के दाम बढ़ाये और अब इन्होंने 10 प्रतिशत कम करके क्या फायदा दिया? दूसरी तरफ स्टाम्प ड्यूटी एक परसेंट बढ़ा दी। अब जब स्टाम्प ड्यूटी एक परसेंट बढ़ाते हो तो एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से लिया, यही काम ये कर रहे हैं। वास्तविक सर्वे कराते कि कहां डी.एल.सी. इतनी अधिक है, कई जगह तो थर्टी टू फोर्टी परसेंट मार्केट प्राइस से ज्यादा है।

अब ये कहते हैं कि हम सड़कें बना रहे हैं। सड़के क्या बनायीं, राजसमन्द के अन्दर एक मिसिंग लिंक नहीं, खनन की एक रोड नहीं, किसी प्रकार का कोई गौरव पथ नहीं, कोई माइनिंग रोड नहीं, कोई स्टेट हाईवे नहीं और फिर कहते हैं कि हम सड़क बना रहे हैं। माननीय सभापति जी, एक स्कूल नहीं दिया, एक कालेज नहीं दिया, कहीं मेवाड़ में यूनिवर्सिटी बनाने की बात नहीं की, रोडवेज की जो बसें चलती थीं वे बसें बन्द कर दीं, स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स बी.जे.पी. के राज में बन्द हुआ था उसे फिर से चालू कर दिया। आजादी के समय मेवाड़ के अन्दर जो हाई कोर्ट थी उस हाई कोर्ट को भी इन्होंने छीन लिया। मेवाड़ में पिछले पचास साल से आंदोलन चल रहा है कि मेवाड़ में, उदयपुर में हाई कोर्ट आना चाहिए लेकिन यह सरकार कोई सुनवाई नहीं करती। आदिवासी बहुल क्षेत्र के अन्दर लोगों को न्याय इतना महंगा पड़ रहा है लेकिन सरकार कहने के लिए तो कहती है कि हम तो बड़े संवेदनशील हैं पर यह इनका दिख रहा है कि इनमें कितनी संवेदनशीलता है। हाई कोर्ट की बैंच के लिए भी ये केन्द्र सरकार को रिकमंड नहीं कर सकते कि यहां मेवाड़ के अन्दर उदयपुर में हाई कोर्ट दिया जाए। इसके रिकमंडेशन का एक लैटर देने तक के लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी तैयार नहीं हैं।

तकनीकी महाविद्यालय की, अगर देखें तो इसमें क्या स्थिति है कि ट्रिपल आई (आई.आई.आई.) सैल में 2019-20 में हमारे मात्र 452 युवकों को नौकरियां दीं। सैण्ट्रल प्लेसमेंट सैल में 3,142 स्टूडेंट्स ने एप्लाई किया, जो तकनीकी डिप्लोमा के कोर्सेज कर रहे हैं, उनमें से मात्र 1,025 को प्लेसमेंट मिला, यानी एक तिहाई लोगों को प्लेसमेंट मिला।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

अब बेरोजगार युवकों को जो इन्होंने भत्ता देने की बात कही थी कि हम बेरोजगार युवकों को तीन हजार रुपये देंगे, बेरोजगार युवतियों को साढ़े तीन हजार रुपये हर माह भत्ता देंगे, पर एक पैसा नहीं दिया। वैबसाइट पर जाकर अगर देखें तो छह लाख ऐसे बेरोजगार नवयुवक रजिस्टर्ड हैं लेकिन एक पैसा भी उनको नहीं मिल रहा है।

माननीय सभापति जी, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूं। हमारे यहां पर हिन्दुस्तान जिंक स्मैल्टर है और वहां पर हिन्दुस्तान जिंक की माइंस चलती हैं। उन माइंस पर जो हमारे नवयुवक हैं उनको रोजगार नहीं मिलता है और 60 से 65 प्रतिशत, जिनको रोजगार दिया है, राजस्थान के बाहर के लोगों को रोजगार दिया है। यह सरकार क्यों नहीं सुनती है कि राजस्थान का हित चाहते हो, राजस्थान के नवयुवकों को अगर रोजगार देना चाहते हो तो जितनी इण्डस्ट्रीज यहां चल रही हैं, उन इण्डस्ट्रीज को पाबन्द करो कि जो कुछ भी एम्प्लायमेंट आप दोगे उसका 70 परसेंट, 80 परसेंट एम्प्लायमेंट आपको राजस्थान के नवयुवकों को देना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार का कोई कानून ये नहीं लाते हैं। वहां यह हालत है कि पूरे क्षेत्र का पानी खराब हो गया, पूरे क्षेत्र की मिट्टी खराब हो गयी, फसल नहीं हो सकती। वहां पर आबोहवा इतनी खराब हो चुकी है, इतना प्रदूषण हो चुका है कि बार-बार हम रिपोर्ट करते हैं और यहां से आते हैं तो लीपा-पोती करके चले जाते हैं, लेकिन वहां स्थिति इतनी खराब है। मैं चाहूंगी कि इसका जवाब, जब माननीय मुख्य मंत्रीजी अपनी रिप्लाई करें तो इस पर जरूर ध्यान दें कि राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की जहां इण्डस्ट्रीज चल रही हैं और उनसे वहां जो इफैक्ट हो रहा है, वहां की जमीन खराब, वहां की आबोहवा खराब, वहां का पानी खराब हो रहा है तो उसमें वहां के लोगों को कहीं न कहीं कोई एम्प्लायमेंट तो दो ताकि वे कम से कम दो वक्त की रोटी तो खा सकें।

हमारे मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि हमारी सरकार बड़ी जवाबदेह है। अब बजरी माफिया किस प्रकार से पनप रहे हैं? सरकार इतनी लाचार है कि बजरी माफियाओं का ताण्डव नृत्य चल रहा है और जो उन बजरी माफियाओं के खिलाफ बोलता है, यहां तक कि एक प्रतिष्ठित अख़बार भी उसके खिलाफ सीरीज चला रहा है, अख़बार निष्पक्ष होते हैं, अगर उस अख़बार ने कोई बात कही है तो ध्यान से देखा जाए कि इसको कैसे सुधारा जाए लेकिन सुधारात्मक कदम नहीं ले रहे हैं...

श्री सभापति: अपनी बात दो मिनट में समाप्त करें।

(15.00 बजे)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): उन बजरी माफियाओं को बन्द करने की बात नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको संरक्षण देकर कैसे उसके ऊपर लीपा-पोती करें और कैसे और जो सारी चीजें कर रहे हैं, उसके अन्दर कोई गांव वाला रिपोर्ट कर दे तो उसी के खिलाफ कार्यवाही हो जाती है, उसी के खिलाफ झूठा केस दर्ज हो जाता है। अगर पुलिस को कहते हैं तो पुलिस कहती है माइनिंग डिपार्टमेंट देखेगा। माइनिंग डिपार्टमेंट को कहते हैं तो वे कहते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास क्या मैन पावर है।

माननीय सभापति जी, बजट में इन्होंने घोषणा की कि हम शहीद स्मारकों का निर्माण करेंगे। मेरे राजसमन्द में दो ऐसे शहीद हुए, शहीद नीमसिंह और शहीद नारायण लाल गुर्जर, ये दो शहीद हुए, जो उरी और पुलवामा की घटना में शहीद हुए। उस समय यही कांग्रेस के नेता वहां आकर कहकर गये कि हम लोग इसके अन्दर उन्हें जमीन देंगे, उनके नाम पर स्कूल का नामांकरण करेंगे, उनका एक शहीद उपवन बनाएंगे और बजट के अन्दर कहा कि शहीदों का स्मारक बनाया जाएगा। लेकिन किसी प्रकार का काम न तो नीमसिंह जी की याद में किया और न ही नारायण लालजी गुर्जर जो शहीद हुए उनके नाम पर किया। इसलिए यह शहीदों की शहादत का अपमान है। केवल बजट के अन्दर यह बात कहना, तो मैं चार लाइन में मेरी बात को समाप्त करूगी:-

ये झूठ और भ्रम से, राजस्थान नहीं बदलेगा,
तुष्टिकरण से भाईचारा नहीं पनपेगा,
थोथी बातों से विकास का द्वार नहीं खुलेगा,
कुटिल है उद्देश्य उनके,
जनता को सुराज कैसे मिलेगा, जनता को सुराज कैसे मिलेगा।

इसलिए यह झूठ का पुलिंदा जो 20 फरवरी को रखा गया, मैं उसकी बहुत भर्त्सना करती हूं। सिर्फ और सिर्फ खाली बातों से नहीं, कुछ काम करके बताएं। मुख्य मंत्रीजी ने जो यह बजट रखा है, उस बजट में ये जितनी भी सारी चीजें हैं, पिछला बजट भी हमने देखा, मात्र 42 प्रतिशत खर्च हुआ है। इस बजट को भी इन्होंने रखा, कोई जवाबदेही नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

किसी प्रकार का इसके अन्दर मुख्य मंत्रीजी की तरफ ऐसा कोई रिप्लाई नहीं है जिससे जनता संतुष्ट हो सके। धन्यवाद, जय भारत।

श्री सभापति: श्री रामनारायण मीना।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी के 20 फरवरी के बजट भाषण के समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। बहुत अच्छा भाषण अभी दे रहे थे माननीय पूर्व मंत्रीजी माननीय पूर्व सांसद महोदय, माननीय वर्तमान विधायक जी। मैं आपके ही माध्यम से बात कर रहा हूं। मैं सीधे आपसे बात ही नहीं कर सकता।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात जारी रखें आप। समय रुक नहीं रहा है, घड़ी चल रही है।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, करे कौन, भरे कौन। इस सदन में ट्रम्प साहब का नाम आया। हमारे देश में बहुत महान पुरुष हैं, क्या मोदी जी ट्रम्प से कमजोर हैं। सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय इंदिरा जी अमेरिका गयीं, अमेरिका का राष्ट्रपति इंदिरा जी को लेने एयरपोर्ट पर नहीं आया, इंदिरा जी उनके रैस्ट हाउस में नहीं रुकीं, एम्बेसी में रुकीं और अमेरिका के राष्ट्रपति को माफी मांगनी पड़ी। यह होती है देश की आन-बान-शान। कितने हजार करोड़ का सौदा होगा, उसके बाद कितना कमीशन का पैसा जाएगा, कितने डी.आर.डी.ओज. बंद होंगे, कितने आयुध निर्माण संस्थाओं के इंजीनियर कमजोर होंगे, आपने हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की तो हालत खराब कर ही दी। इसलिए मैं केन्द्र सरकार के बारे में ज्यादा अर्ज नहीं करना चाहूंगा। लेकिन इतना जरूर अर्ज करना चाहूंगा क्या देशभक्ति की बात करते हो, देश के बारे में भी सोचा करो।

सभापति महोदय, इससे अच्छा बजट इन वर्तमान परिस्थितियों में नहीं हो सकता। आप बेरोजगारी की बात करते हैं। मैं आपकी बात की ताईद करता हूं राजस्थान के उद्योग धंधों में राजस्थानवासियों का पहला हक होना चाहिए। राजस्थान में सबसे बड़ा उद्योग कौनसा है और किसके समय में लगा था। उसको गलत अधिकार किसने दिये। आज एक भी कर्मचारी ऐसे उद्योगों में नहीं है क्योंकि सरकारी नौकरियां आपने खतम कर दीं। आप तो उस पार्टी के माननीय सदस्य हो, जो रेलवे का भी निजीकरण कर रही है। ये पूंजीवादी

(श्री रामनारायण मीना)

व्यवस्था इस देश में कैसे बढ़ रही है? भारत अमेरिकी अर्थव्यवस्था, फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर कभी नहीं चल सकता। भारत की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था होगी। यह देश गांधी जी का देश है। भले ही कुछ गलत विचारधारा के लोग गांधी जी की मूर्ति को तोड़ें, भले ही गलत विचारधारा के लोग अनर्गल बातें करें। लेकिन यह देश हमारा देश है, गांधी जी का देश है, नेहरू जी का देश है, जिन नेहरू जी ने कश्मीर का टू-थर्ड हिस्सा कब्जे में कर लिया। यदि नेहरू जी नहीं होते तो कश्मीर की एक इंच जमीन नहीं आती।

मैं व्यक्तिगत तौर से सदन को अर्ज करना चाहता हूं और सदन की भावना भी है। आज भी भारत सरकार को कश्मीर पर कब्जा करना चाहिए, हम ईमानदारी से साथ देंगे। आप कहोगे तो फ्रंट पर भी जाकर लड़ेंगे, कहना छोड़िए, करना सीखिए।

आज हैल्थ के बारे में, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी यहां हैं। सबसे पहले निरोगी राजस्थान, साहब नहीं खोली, हर एम.एल.ए. को टेलीफोन गया है, सी.एच.सी. खोली जा रही है, आर्डर से। दूसरी बात इतनी जरूरी, किसान को सम्पन्न करने की बात है, किसान कैसे सम्पन्न होगा। आप पाम ऑयल बाहर से मंगा रहे हो, किसान आत्महत्या कर रहा है, भाव खतम हो रहे हैं, सरसों का भाव धरती पर जा रहा है, तिलहन कमजोर होती जा रही है। एक नयी अर्थव्यवस्था चली है। वह अर्थव्यवस्था है परमिट राज, क्योंकि ईमानदार लोगों का राज है। मैं नहीं कहता कि राफेल में खाया-पीया है। मैं नहीं कहता लेकिन किसान का गेहूं क्यों मंगाया जा रहा है, जबकि किसान के घर में गेहूं आता है। किसान कमजोर हो रहा है। अब आप बैठे-बैठे मूंछ मरोड़ो, सभापति की तरफ मोड़ो।

श्री सभापति: हर बार मना करने के बावजूद भी बात समझ में नहीं आती आपके?

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): मेरी तरफ क्यों मरोड़ते हो, आप सभापति जी का अनादर करते हो, आदर कर रहे हो, मैं तो सम्मान करता हूं आपका भी, आसन का भी। यह सर्वोच्च आसन है, इससे बड़ा आसन राजस्थान में कोई नहीं है।

यह सम्पन्न किसान वाली बात है, माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा। आज एक प्रश्न था, मैं अपनी स्पष्ट बात कहना चाहता हूं कि सर्दी से किसान की मौत हुई। प्रश्न भले ही रामगंज मण्डी वाले

(श्री रामनारायण मीना)

एम.एल.ए. साहब का था। किसान खेत में काम कर रहा है, पाणत कर रहा है, गरीब हालत में हो, कैसी भी हालत हो, उसको सर्दी लग गयी और खेती करते हुए मौत हो गयी तो मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्य सचेतक महोदय, आप इस बात को हमारी तरफ से मुख्य मंत्रीजी से कहें, ऐसे मामलों में किसान खेती करते हुए, सर्पदंश से ही नहीं, यदि सर्दी से भी उसकी मौत हो गयी, उसको सहायता राशि मिलनी चाहिए।

ये बहुत सी बातें हैं, यह होती है सम्पन्नता की बात। गर्दन हिल रही है और मुझे उम्मीद है, नेता महोदय, ये काम सम्भव है, हो जाएगा और उसी दिन मैं आप सबको मिठाई बाटूंगा।

माननीय सभापति महोदय, सरकार महिला बाल विकास को ठीक करे। इसमें रामजी राज़ी हो रहा है। इतनी बेईमानी पिछली सरकार कर गयी, न भर्ती की, न ईमानदारी से काम किया। कैंसर पीड़ित का कोई एक चार्ज है और आज भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना नहीं हो रही है। यह डिपार्टमेंट किस तरह से चल रहा है। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता लेकिन आज भी पूरा आहार लोगों को नहीं मिल रहा है। मेरे पीछे सहरिया क्षेत्र से आने वाली बहन बैठी हैं, सहरिया क्षेत्र में दोगुना आहार दिया जा रहा है। जिसको बच्चे नहीं खा सकते, जांचें हो गयीं और जांच होने के बाद कर्मचारी चिह्नित हो गये। उनके खिलाफ आज दिन तक कार्यवाही पिछली सरकार ने नहीं की, अब उसकी कार्यवाही होनी चाहिए। सहरियाओं को आजादी के बाद जितना अरबों, खरबों रुपया, आप जांच कर लें तो बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, उसमें अधिकारी शामिल हैं, बहुत तकलीफ की बात है।

दूसरा, मेरा आपसे अर्ज करना है, जैसे किसान की बात आयी। यह सही है कि किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान कैसे सम्पन्न हो, आपने सी.सी.ए. के खिलाफ भी प्रस्ताव पास किया यह दिखाने के लिए कि यह गलत है। केन्द्र सरकार हमारी बात मानती है या नहीं मानती है लेकिन उप नेता चाहें तो एक प्रस्ताव पेश होना चाहिए, किसान का जितना भी प्रोडक्ट है या किसान की खेती में जितने भी उपकरण हैं, आपने ट्रैक्टर पर 28 परसेंट लगाकर अब कर दिया होगा, दवाई पर 18 परसेंट, ट्रैक्टर के उपकरणों पर 12 परसेंट, मैं चाहता हूं, इस पक्ष में बैठे हुए भाई लोग, हम साथ देंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार ने कभी किसान पर इतना भार नहीं डाला था। आप इस जी.एस.टी. को खतम कर दो, किसान का कर्जा माफ करने की जरूरत ही

(श्री रामनारायण मीना)

नहीं पड़ेगी। जिस दिन किसान का जी.एस.टी. माफ हो जाएगा, खतम हो जाएगा, किसान अपने आप सम्पन्न हो जाएगा।

दूसरा, पारदर्शी और संवेदनशीलता की बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। मैं केन्द्र सरकार के लिए तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा लेकिन जो अधिकारी पिछली सरकार के समय में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे थे, उनको कमजोर कैसे किया जाए। यदि उनको हम कमजोर कर देंगे तो जो छींटाकशी हमारी सरकार के ऊपर हो रही है, उसमें कमजोरी आ जाएगी क्योंकि खान घूस कांड हमारे टाइम पर नहीं हुआ। यह तो सौभाग्य है कि हमारी सरकार के समय ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है लेकिन शिक्षा के मामले में बड़ी विचित्र स्थिति आ रही है। हम नियम बनाते हैं, सभापति महोदय, खेल का मैदान होना चाहिए, कक्षा कक्ष होना चाहिए। आज भी राजस्थान से कक्षा कक्ष के बारे में भारत सरकार को प्रस्ताव गये हुए हैं 60:40 का रेशो जो भी हो, भारत सरकार से कागज नहीं निकल पा रहे हैं। नरेगा का पैसा नहीं आ रहा है, न एजुकेशन का पैसा आ रहा है और फिर हिस्से की बात हो रही है। एजुकेशन का पैसा वहां से क्यों नहीं आ रहा, इसके बारे में तो, खैर, आप ज्यादा जानते हैं।

चम्बल एक ऐसा एरिया है, माननीय सभापति महोदय, चम्बल का पीने का पानी पड़ोस को नहीं दिया जा रहा है हम प्यासे हैं। एक क्रोकोडाइल पार्क वहां पैदा कर दिया, सभापति महोदय, एक किलोमीटर तक उसमें निर्माण नहीं हो सकता। भले ही बजरी माफिया बजरी निकाल रहे हों। ये चार हमारे चम्बल के जलाशय हैं, गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है, कोटा बैराज है। वहां जितने चाहो उतने मगरमच्छ पालो। इन्होंने ठेठ धौलपुर तक उसको क्रोकोडाइल पार्क कर दिया और किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, इधर से उधर कुछ नहीं कर सकता, पानी नहीं ले सकता, गांव के आदमी के लिए पेयजल योजना नहीं बन सकती। यह जो खराबी है, वह ठीक होनी चाहिए। मंत्रीजी इतने अच्छे हैं, यहां नहीं हैं, सभापति महोदय, मंत्रीजी को मैंने चार चिट्ठियां लिखीं लेकिन किसी का जवाब देने की स्थिति में मंत्रीजी शायद नहीं हैं। उनका स्वभाव है, थोड़ा भूल गए, उन्होंने कहा था कि हम विलायती बबूल को चार साल में समाप्त करेंगे। यह बहुत बड़ी, हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा दुःखदायी बात है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): खैर, जो भी है, माननीय सभापति महोदय, लेकिन इस बजट में जितना अच्छा समावेश किया गया है, सभी तरह का, यह इन परिस्थितियों में ठीक है। मैं बिजली नीति के बारे में आपसे बात करूंगा। सभापति महोदय, किसान के साथ इनजस्टिस हो रहा है। पिछला कर्जा हमसे वसूला जा रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कम से कम किश्तों में उसको वसूलें, और जो अभी कहा कि, साहब, हमारे कनेक्शन कैसे मिलेंगे। माननीय सभापति महोदय, बाड़मेर में भीलों का आंदोलन चला था। आदिवासियों को भी राजस्थान में बिजली के कनेक्शन में प्राथमिकता नहीं है, वह दी जानी चाहिए। साथ ही साथ, राजस्थान में जिस प्रकार की नीतियां बनायी जा रही हैं, उन नीतियों का मैं समर्थन करता हूं। एक हवाई अड्डा जिस तरह से पूंजीपतियों को दिया जा रहा है, माननीय डिप्टी लीडर महोदय, कोटा के हवाई अड्डे के लिए जमीन दी जा रही है, मैं चाहता हूं उसमें राजस्थान सरकार यह नोट लगाए कि इसको प्राइवेट को नहीं दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तो सरकार हमारी हो जाएगी। इसी के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और अच्छे बजट का पूरी तरह से समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजकुमार गौड़।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2020-21 पर बोलने का मौका दिया। मुख्य मंत्रीजी ने बहुत ही शानदार और जानदार बजट रखा है। इन परिस्थितियों में सब लोगों का ध्यान रखा गया। सात संकल्प लिये गये। किसी भी सरकार के लिए संकल्प को लेकर काम पूरा करना, लोगों को साथ लेकर काम करना, इससे निश्चित रूप से प्रदेश विकास की ओर बढ़ेगा। प्रदेश को जो मुख्य मंत्रीजी से उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों के अनुरूप राजस्थान विकास करेगा। यह इस बजट में दिख रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य बोल रहे हैं। माननीय सदस्य पहली बार आये हैं।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): बजट में पहला संकल्प निरोगी राजस्थान रखा गया है। निरोगी राजस्थान पर मुख्य मंत्रीजी की पहल के कारण चाहे स्कूलों में शनिवार को बिना बैग के बच्चों को बुलाने की बात की, चाहे स्कूलों के लिए जो मैदान बनाये जा रहे हैं, उसके लिए पट्टा देने की बात की गयी, निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ऐसा करने से राजस्थान निरोगी बनेगा। एक प्रयोग हमने भी

(श्री राजकुमार गौड़)

गंगानगर में किया है यू.आई.टी. के माध्यम से कि जितने पार्क हैं, उनमें ओपन जिम लगाने की कोशिश की गयी है, जिससे नौजवानों को, बच्चों को तंदुरुस्त बनने के लिए मुफ्त में सुविधा मिलेगी, अच्छा वातावरण मिलेगा। ऐसा वातावरण भी अगर हम पूरे राजस्थान में शुरू करेंगे तो मैं सोचता हूं कि जो मुख्य मंत्रीजी की कल्पना है निरोगी राजस्थान की, वह अवश्य सफल होगी।

महोदय, राजस्थान सरकार बार-बार कह रही है कि केन्द्र सरकार से जो हम लोगों को बजट मिलना चाहिए था, टैक्स के रूप में जो हम लोगों को हिस्सा मिलना चाहिए था, उसमें से हम लोगों को 10,362 करोड़ रुपया कम मिला है। इतने रुपये कम मिलने के बाद भी किसान की चिंता की गयी, गरीब की चिंता की गयी, बेरोजगार की चिंता की गयी, पानी की समुचित व्यवस्था की बात की गयी। मैं सोचता हूं कि यह बहुत बड़ी बात है। एक साथ में इतना रुपया केन्द्र सरकार से कम मिलना, उसके अलावा 2018 में जो पूर्व सरकार गयी, उस सरकार ने 13,000 करोड़ के काम तो जारी कर दिये, लेकिन वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं की, उसी का जो आज बार-बार माननीय सदस्य बोल रहे हैं, चाहे मैं डिग्गियों की बात करूं, गंगानगर में डिग्गियों का पेमेंट नहीं हुआ। चाहे पी.एच.इ.डी. डिपार्टमेंट की बात करें कि उसमें पेमेंट नहीं हुआ। सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट की बात करें कि जो हिस्सा हमारा आना चाहिए था वह नहीं आया। किसान के लिए जो सब्सिडी मिलनी चाहिए थी, उसका हिस्सा नहीं आया। सड़क के निर्माण की बात करें तो केन्द्र सरकार से जो पैसा आना चाहिए था, वह नहीं आया और वे 13,000 करोड़ के काम और जारी कर गये 2018 में, वे काम भी आने वाले 2019 में रुक गये, उनका भुगतान भी रुक गया। उस वजह से सभी सदस्यों को, मैं सोचता हूं कि दिक्कत हो रही है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जिन विभागों की मैंने बात की है, उन विभागों के काम रुके हुए हैं। आधे काम शुरू हो गए वे सड़कें बन नहीं रही हैं तो आप मेहरबानी करके जो भी वे कर गये, वह कर गये, पर आप से मेरा निवेदन है, आपके माध्यम से सरकार से, मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि तमाम इस तरह के भुगतान करवाये जाएं और भुगतान होने से वे काम भी पूरे होंगे और किसान को, मजदूर को और उस ठेकेदार को भी अपना पैसा मिल पाएगा। तमाम जब काम शुरू हो जाएंगे तो जो विकास की गति है, विकास की गति जो चल रही है, वह और तेजी से चलेगी। मेरा ऐसा मानना है।

(श्री राजकुमार गौड़)

सभापति महोदय, हर विधायक अपने क्षेत्र में काम की बात करता है। बजट चाहता है, ज्यादा से ज्यादा बजट चाहता है। ऐसे ही जब हमारे पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं तो मैम्बर आफ पार्लियामेंट भी यही बात कहता है कि मैं मेरे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा, ज्यादा से ज्यादा विकास करूंगा, केन्द्र सरकार से ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहूंगा। पर मुझे बड़ी हैरानी है कि राजस्थान को जब हमारे 10,362 करोड़ रुपये नहीं मिले और 25 के 25 हमारे मैम्बर आफ पार्लियामेंट राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी से जीतकर गये हैं, किसी एक भी मैम्बर आफ पार्लियामेंट ने यह कभी चर्चा नहीं की कि राजस्थान को आखिर यह पैसा क्यों कम मिला। अगर वे सब मिलकर कहते और आज भी इस सदन में जो भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी बैठे हैं, बड़े-बड़े नेता बैठे हैं, मैं इनसे भी कहना चाहूंगा केवल हम इन आंकड़ों में नहीं फंसें कि नहीं आप कह रहे हो कि पैसा कम मिला है, हम कह रहे हैं कि ज्यादा मिला है, अगर वाकई स्टेट को पैसा नहीं मिला है, प्रदेश को पैसा नहीं मिला तो क्या इस हाउस के सब लोगों का कर्तव्य नहीं है कि हम भारत सरकार से निवेदन करें कि हमारा पूरा हिस्सा दिया जाए? क्या हमारे मैम्बर आफ पार्लियामेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या वे अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? लोगों ने इसीलिए उनको चुनकर भेजा है कि वे हमारे हितों की रक्षा करें, राजस्थान के हितों की रक्षा करें। यह राजस्थान सरकार या कांग्रेस सरकार की बात नहीं है, यह पूरे प्रदेश की बात है। पूरे प्रदेश का किसान, मजदूर उनकी तरफ देख रहा है कि किसी तरह से पैसा आये, हमें मदद मिले और उस मदद मिलने के बाद में राजस्थान की प्रगति हो। आज हम सब लोग कह तो रहे हैं कि पी.एच.सी. नहीं है, सी.एच.सी. नहीं है, वहां बिजली का काम नहीं हो रहा, वहां कर्मचारी नहीं हैं। परंतु यही तो कारण है, अगर ये काम एक वर्ष पहले पूरे हुए होते तो शायद ये सब कर्मचारी और डाक्टर मिले हुए होते। हम अपने आप ही तो मान रहे हैं कि हमें जो करना चाहिये था, वह हम लोगों ने नहीं किया। अगर किया होता, जो आप सब साथी कह रहे हैं, अगर यह सब काम किये हुए होते तो फिर यह क्या कारण रहा कि हम कह रहे हैं कि सड़कें नहीं बन रहीं। यह क्या कारण रहा कि हम कह रहे हैं कि स्कूल नहीं बन रहे। यह क्या कारण रहा कि हम कह रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही। यह क्या कारण रहा कि हम कह रहे हैं कि खड्डे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं कमी रही है। विकास का काम एक लगातार चलने वाला काम है, वह चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, ये काम इसी तरह से लगातार चलते रहें। इसी से देश में और प्रदेश में प्रगति होगी।

(श्री राजकुमार गौड़)

मैं मुख्य मंत्रीजी को एवं चिकित्सा मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा कि इस वर्ष केन्द्र सरकार के माध्यम से 15 मेडिकल कालेजों की स्वीकृति मिली। स्वीकृति मिलने के बाद मुख्य मंत्रीजी ने कहा, चिकित्सा मंत्रीजी ने कहा कि हम इनको जल्दी ही शुरू कर रहे हैं। मैं अब जरूर निवेदन करना चाहूंगा, महोदय, क्योंकि जो मेरा गंगानगर जिला है, गंगानगर विधान सभा क्षेत्र है, वह आठ सालों से मेडिकल कालेज का इंतजार कर रहा है। बार-बार हम कहते हैं कि कब बनेगा, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब सब बाधाएं दूर हो गयीं, जमीन भी मिल गयी, जमीन भी कालेज के नाम हो गयी, अब इस कालेज का आप जल्दी से जल्दी निर्माण शुरू करें। आप शुरूआत गंगानगर से करें, हम आपका गंगानगर में स्वागत करेंगे। गंगानगर में मेडिकल कालेज प्रारम्भ हो, यह मेरा आपसे निवेदन है।

महोदय, सिंचाई के लिए बहुत बड़ी राशि रखी गयी। सिंचाई के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता है क्योंकि राजस्थान बहुत समृद्धशाली प्रदेश है किसान मजबूत है। सिंचाई के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में मैंने पिछले बजट में भी निवेदन किया था। सरकार आई.एन.जी.पी. की मरम्मत करवा रही है, 40 और 30 दिन की बंदी अलग-अलग ली जा रही है। उसके साथ में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा सरकार ने सरहिन्द फीडर की बात की, मैं कहना चाहूंगा कि फिरोजपुर फीडर की मरम्मत भी जल्दी करवाई जाए। पंजाब सरकार से जो डी.पी.आर. की बात चल रही है, फिरोजपुर फीडर की डी.पी.आर. जल्दी बने। गंग कैनाल की भी सफाई उसके साथ-साथ जल्दी हो, उनकी मरम्मत जल्दी हो, जिससे किसानों को पूरा पानी मिल सके, क्योंकि किसान आज उस पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं।

महोदय, पीने के पानी के लिए राज्य सरकार ने 8,794 करोड़ 51 लाख रुपये का बजट रखा है, बहुत अच्छा है। पीने के लिए पानी मिलना चाहिए। हर उस ढाणी में पानी पहुंचना चाहिए, ढाणी का आदमी भी आज इंतजार कर रहा है। अभी बी.जे.पी. के सदस्य बात कर रहे थे कि केन्द्र सरकार से मुख्य मंत्रीजी ने 90:10 का परसंटेज क्यों मांग लिया। क्या गलती कर दी, पैसा जितना ज्यादा आएगा, उतना काम ज्यादा होगा। राजस्थान में पानी की कमी है, अगर केन्द्र सरकार हमें दूसरे प्रदेशों से हटकर अलग से पैसा दे भी देती है तो उसमें नुकसान कहां होने वाला है? आपको तो आवाज के साथ

(श्री राजकुमार गौड़)

आवाज बनना चाहिए और केन्द्र सरकार से मांग करनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा राजस्थान को पैसा दीजिए। राजस्थान में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है और वह समस्या दूर हो।

महोदय, मैं इसके साथ यह भी कहना चाहूंगा कि हम साफ पानी देने की बात कर रहे हैं, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति: दो मिनट में बात समाप्त करें।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं कई बार निवेदन कर चुका कि पंजाब से जो जहरीला पानी आ रहा है, वह जहरीला पानी जल्दी से जल्दी बंद हो। उस पानी से कैंसर का रोग फैल रहा है और बार-बार हम इस कैंसर की बात करते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि रोजाना कैंसर का रोग फैल रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यह जहरीला पानी आना बंद हो। पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो योजनाएं बनायी हैं, उन योजनाओं में गंगानगर को भी शामिल करने की कोशिश करें। गंगानगर में बिलकुल कैनाल के साथ हमारे गांव हैं, वहां भी पानी की आवश्यकता है। चाहे मैं 6 एल.एन.पी. की बात करूं, चाहे मैं शागावाली की बात करूं, चाहे मैं ठाकरावाली ढाणी की बात करूं, यह तमाम योजनाएं हमने आपको बनाकर भेजी हैं, इन तमाम योजनाओं को आप इस बजट में सम्मिलित करें और इन योजनाओं को बनाकर लोगों को लाभान्वित करें।

महोदय, बिजली के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी के बजट में आया कि 220 के.वी. के 6 जी.एस.एस. बनाये जा रहे हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी से और मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप उसमें गंगानगर को भी शामिल करें। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है, एक तरफ पाकिस्तान का बार्डर है, एक तरफ पंजाब का बार्डर है। वहां बिजली की बहुत आवश्यकता है। मैंने पूर्व में भी आपको लिखकर दिया है, मैं चाहता हूं कि इस बजट में 400 के.वी. के ग्रिड लगाने की आप घोषणा करें, जिससे लोगों को यह सुविधा मिल पाए।

मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने गुरू नानक देव की 550वीं जयंती पर गंगानगर को सम्मिलित करते हुए गुरू नानक देव जी के नाम पर एक उद्यान और पार्क बनाने का जो डिसीजन लिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा।

महोदय, इस शानदार बजट के लिए मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना

(श्री राजकुमार गौड़)

चाहूंगा। इसके समर्थन में कहना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में प्रदेश का इससे शानदार बजट आ नहीं सकता था। आपके नेतृत्व में प्रदेश इसी तरह से बढ़ता रहे, इसी कामना के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुभाष पूनिया।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय सभापति जी, वित्तीय वर्ष 2020-21 पर मैं विचार व्यक्त कर रहा हूं। सबसे पहले तो इस बजट में पहला संकल्प लिया गया है, निरोगी राजस्थान। सभापति जी, निरोगी राजस्थान में बड़ी अच्छी बात है कि मुफ्त में दवाइयां, मुफ्त में जांच, यह अच्छा फैसला है। सभापति जी, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा क्या अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध हैं? अस्पतालों में 60 से 70 परसेंट तो चिकित्सकों के पद खाली हैं। इसलिए मैं जहां तक समझता हूं कि कैसे यह राजस्थान प्रदेश निरोगी काया को अंजाम देगा। दूसरा, जांच के उपकरण, किसी भी अस्पताल में जाते हैं तो या तो वहां उपकरण ही नहीं हैं और अगर हैं तो वे खराब पड़े हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बजट में अस्पतालों में, चाहे वह सी.एच.सी. हों, पी.एच.सी. हों, वहां जांच के उपकरण उपलब्ध करवाये जाएं, और जितने भी डाक्टर हैं, उनके जो पद खाली हैं, उनको भरा जाए। अगर कहीं डाक्टर हैं, वे रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद मेरी सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में तो ज्यादातर पद खाली हैं। एक-एक डाक्टर को दो-दो, तीन-तीन पी.एच.सी. का चार्ज है तो कैसे यह निरोगी राजस्थान होगा, मैं नहीं समझता।

दूसरा संकल्प, सम्पन्न किसान। सम्पन्न किसान में कृषि पर फोकस किया गया है। कृषि में आवारा पशु से आज किसान की जान आफत में आ रही है। किसान किस तरह से पूरी रात अपने खेत में खड़े होकर अपनी फसल की रखवाली करता है। पिछले बजट में भी नन्दीशाला के नाम पर, हर पंचायत समिति मुख्यालय पर हम नन्दीशाला खोलेंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह बजट किसान विरोधी बजट है। इस बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। किसान को गुणवत्तायुक्त बीज दिया जाए, इस तरह की इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। किसान को जो कृषि विपणन बोर्ड में सड़कें दी जाती थीं, मंडियों में अपना माल बेचने के लिए, वे भी यह सरकार बनने के बाद, एक किलोमीटर भी, कृषि विपणन बोर्ड ने हमारे जिले में तो एक भी सड़क नहीं दी है, राजस्थान की मैं कह नहीं सकता। इसलिए मैं चाहूंगा कि किसान को इस बजट में कुछ न कुछ दिया जाता तो किसान आपकी जय-जयकार करता।

(श्री सुभाष पूनिया)

रही बात किसान को बिजली देने की, वसुन्धरा जी की सरकार ने किसान को 833 रुपये बिजली पर सब्सिडी देने का काम किया था। इस सरकार ने आते ही कुछ दिन तो सब्सिडी दी, उसके बाद वह सब्सिडी भी बंद हो गयी और कहते हैं हम डी.बी.टी. के माध्यम से किसान के खाते में पैसा जमा कराएंगे। एक-एक कृषि कनेक्शन के ऊपर आज आठ-आठ, दस-दस किसान हैं, क्योंकि बंटवारा हो चुका है। इसलिए मैं चाहूंगा कि 833 रुपये की जो सब्सिडी दी थी, उसका बिजली के बिल में समायोजन किया जाए ताकि किसान लाभान्वित हों, यह भी मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा। रही बात किसान को बिजली देने की, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई कुओं से होती है। आपको भी मालूम है, आप शेखावाटी से आते हैं। अपने यहां पर किसान सिंचाई कुंओं से करता है। इस बार मेरे विधान सभा क्षेत्र में और हमारे जिले में जो इस सरकार ने 6 से 7 घंटे बिजली देने का वादा किया था, मुश्किल से 5 घंटे बिजली मिली है। बिजली की ट्रिपिंग भी बार-बार हुई है, इसलिए बिजली में भी किसान के लिए कोई सुधार नहीं हुआ। ट्रांसफार्मर जल जाते हैं तो कह देते हैं कि बजट का अभाव है। ट्रांसफार्मर हमें नहीं मिल रहे हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने 72 घंटे में जो ट्रांसफार्मर बदलने की घोषणा की थी, उसके ऊपर भी यह सरकार फेल हो चुकी है। मैं कहना चाहूंगा कि किसान को इसमें कुछ नहीं मिला है। वीसी.आर. के नाम पर किसान को परेशान किया जा रहा है। किसान का घर बैठे-बैठे पंद्रह से साढ़े सत्रह का लोड कर दिया जाता है, बिना कोई मोटर चैक किये। इसलिए किसान को राहत देने का काम आप करें, यह भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा। फसल बीमा योजना में कृषि मंत्रीजी ने जवाब दिया था कि किसानों को कितना फायदा दिया है। आप उनका प्रीमियम भी जमा नहीं करवा पाये, मैं कहना चाहूंगा कि किसान को इस बजट में आपने क्या दिया है?

शिक्षा के लिए लम्बा-चौड़ा बजट तो दिया है। ऐसा बताते हैं कि स्कूल भी क्रमोन्नत किये हैं, लेकिन जो स्कूल क्रमोन्नत हो चुके हैं, उनमें सब्जेक्ट टीचर भी नहीं हैं। जो स्कूल हैं, उनके भवनों की आप आज हालत देखें तो छात्रों के बैठने के लायक वे भवन नहीं हैं। कमरों की कमी है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बजट में अगर विद्यालयों में कमरे पर्याप्त बनेंगे तो निश्चित रूप से गरीब बच्चे उन स्कूलों में पढ़ पाएंगे। रही, उच्च शिक्षा की बात, मैं पिछले बजट सेशन से हमारे सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में हूं, 70-80

(श्री सुभाष पूनिया)

किलोमीटर के अन्दर कोई कालेज नहीं है। वहां के लोग हरियाणा में पढ़ने के लिए जाते हैं। सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र सैनिकों का क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है, तो क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं है कि उच्च शिक्षा के लिए हमारे बच्चों को 70-80 किलोमीटर जाना पड़े, तो हमें उच्च शिक्षा में भी कुछ नहीं मिला है इसलिए यह बजट छात्रों के लिए भी कोई अच्छा बजट नहीं है।

रही बात युवाओं की, युवाओं को तो सरकार ने बेरोजगारी भत्ता दे ही दिया है, उन 3,500 रुपयों का क्या हुआ? हमारे जिले में विधान सभा चुनाव में राजकुमार आये थे और आकर घोषणा करके गये थे कि किसान का सम्पूर्ण कर्जा माफ करेंगे, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 गिनकर, और हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। युवाओं को इस तरह से भ्रम जाल में फंसाकर, उनका वोट लेकर इस सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। आने वाले समय में उनको यह किसान और युवा बख्शेगा नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बजट में युवाओं को कुछ नहीं दिया गया है।

रही खेल विश्वविद्यालय की बात, झुंझुनूं से आने वाले माननीय जन प्रतिनिधि ने यहां बात उठायी थी कि पहले घोषणा हुई थी कि खेल विश्वविद्यालय झुंझुनूं को देंगेलेकिन आज तक उसके ऊपर भी कोई बात नहीं हुई। रही कानून व्यवस्था की बात, कानून व्यवस्था में तो अपन अव्वल दर्जे में हैं ही। किस तरह से एक प्रतिष्ठित अख़बार के ऊपर, इनके गेस्ट हाउस पर पुलिस ने छापामारी की है, जैसे वहां कोई आतंकवादी हो। नागौर की घटना आपने देखी होगी। चार-पांच दिन पहले मेरे यहां भी, एक भूतपूर्व सैनिक 72 साल के थे, वे अपने घर के सामने बैठे थे। बिना वजह से, थानेदार ने आकर उनको ठोक-पीटकर थाने में बंद कर दिया। हमने फोन किया क्या गलती कर दी? तो बोला कि मेरे सामने मूंछ ऐंठ कर बात कर रहा था। हमने कहा कि बात बताएं, क्या बात है, तो बोला कि मैं चैकिंग करने आया था। हमने पूछा क्या, मिला, तो उसने कहा कि इसने पूछा कि क्यों आये हो? हमारे सामने बोला और हमने उसको बंद कर दिया। उसको ठोक-पीटकर थाने में बंद कर दिया। हमने उसका मेडिकल भी करवाया है, डी.जी. साहब से भी मिले हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यह कानून-व्यवस्था का हाल है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): दो मिनट और लूंगा।

हमारे जिले में अभी गोशाआलों का अनुदान भी नहीं पहुंचा है इसलिए

(श्री सुभाष पूनिया)

मैं चाहूंगा कि गोरक्षा के लिए गोशालाओं को अनुदान दिया जाए। डीजल-पैट्रोल पर जो वैट बढ़ाने का काम किया है, माननीय सभापति महोदय, सात रुपये प्रति लीटर का डिफरेंस कम नहीं होता। यह सरकार जो कह रही थी कि हम किसी भी तरह से डीजल-पैट्रोल के भाव कम करवाएंगे, इन्होंने किसान की कमर तोड़ने का काम किया है। इसलिए यह बजट पूरी तरह से किसान विरोधी है, युवाओं के लिए भी इसमें कुछ नहीं है, छात्रों के लिए भी कुछ नहीं है। मैं इस बजट का विरोध करता हूं। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, बजट 2020 के ऊपर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमानों में, वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट की तुलना में केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सा राशि में 10 हजार 361 करोड़ 94 लाख रुपये की कटौती की गयी है। सी.एम. साहब ने बोला, सब लोगों ने सुना, राजस्थान प्रदेश की जनता ने सुना है, निंदनीय बात है। जी.एस.टी. के बाद और यूं बजट में कटौती के बाद, स्टेट के बजट को मेंटेन रखना, मैं समझता हूं कि सरकार अगर इधर वालों की भी होती तो मुश्किल होता। उसके बाद यह कहा गया है कि वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों में 12 हजार 345 करोड़ 61 लाख रुपये का राजस्व घाटा रहने का अनुमान है। उसके बाद यह भी कहा है कि राजकोषीय घाटा भी 2.99 प्रतिशत बढ़ेगा।

सभापति महोदय, पूरे प्रदेश के लिए यह एक साल का बजट महत्वपूर्ण चीज है। सभापति महोदय, इस बजट के बीच में भी सबसे पहले सात आगाज किये। पहला आगाज है, 'निरोगी राजस्थान'। यह बात सही है, आगाज बहुत अच्छा है। सदन में इस मुद्दे पर एक दिन पहले भी डिस्कस हो चुका है, पर अंजाम तक जाने के लिए हमें बहुत सारे बजट की, बहुत सारे मनुष्यों की ताकत, बहुत सारी सरकारी मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। सभापति महोदय, मुस्तैद डाक्टरों की टीम, कम्पाउंडर, ए.एन.एम.; जी.एन.एम.; दवाई वितरण, जांच की टीम, ये सारे के सारे मुस्तैद लोग हमें चाहिए। 104, 108, तमाम सुविधाओं की निरोगी राजस्थान को सफल बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी। सभापति महोदय, हमारी मांग है कि इसके साथ-साथ जो संविदाकर्मी लगे हुए हैं, लैब टेक्निशियन, लैब असिस्टेंट, 2013 की ए.एन.एम. भर्ती आज भी पैंडिंग है, उनको इस अभियान में बतौर हिम्मत के साथ शामिल किया

(श्री बलवान पूनियां)

जाए और उनको स्थायी भी किया जाए। सभापति महोदय, जब हम 'निरोगी राजस्थान' की बात करें तो इलाके के बजट की बात भी आती है। मेरे यहां गोगामेड़ी का मेला, जिसमें करीब 50 लाख लोग एक महीने के अन्दर आते हैं, वहां पर बारहमासी उत्तरी भारत के एक करोड़ लोग ढोक लगाने के लिए आते हैं। वहां सिर्फ पी.एच.सी. है, सी.एच.सी. खुलवाने के लिए हमने बजट में मांग भी रखी थी। मैं चाहूंगा कि आगे मुख्य मंत्रीजी जब जवाब दें तो हमारे क्षेत्र को लाभान्वित करने के लिए कदम उठाएंगे। सभापति महोदय, हमारे वहां मूंसरी, डूंगराना, निनाण और मराणा गांव में पी.एच.सी. खोलने की मांग हमने की है। सभापति महोदय, एम.एन.जी.वाई., एम.एन.डी.वाई. के संविदाकर्मियों को स्थायी करने की मांग भी हम नीरोगी राजस्थान के साथ जोड़कर करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, जब कृषि की बात आयी तो कृषि संकट पूरे देश में छाया हुआ है। 8 प्रतिशत बजट की भी कमी हुई है। इस वजह से मुख्य मंत्रीजी द्वारा यह भी संकल्प किया गया कि किसान का हौसला कराएं। लेकिन दूसरी तरफ कामर्शियल बैंक, जब बात आयी कर्ज माफी की, 2017 में एक आंदोलन चला राजस्थान में, उस समय भा.ज.पा. की सरकार थी। रात के एक बजे कहा कि 20 हजार करोड़ रुपये किसान का ऋण माफ करेंगे। फिर 8 हजार करोड़ पर आये। 2 हजार करोड़ ऋण माफ किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद चुनावी घोषणा के रूप में जब कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में गयी तो उन्होंने फिर कर्ज माफी की घोषणा की, 8 हजार करोड़ उन्होंने भी माफ किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं। एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कुछ भी लगाएं लेकिन आज भी किसान की वह मांग खड़ी है कि सम्पूर्ण कर्ज मुक्ति हो। अगर किसान परेशान किसी बात से है तो इस बात से है कि कामर्शियल बैंक किसानों को टार्चर करते हैं। मैं राजस्थान की सरकार से कहना चाहता हूं कि रोडा एक्ट में कार्यवाही आपका प्रशासन करता है। उसमें दो प्रतिशत और पांच प्रतिशत टैक्स लगता है। जिस तरीके से दूसरी मदों में टैक्स में छूट की है, रोडा एक्ट में भी छूट कीजिए। कामर्शियल बैंकों को एकमुश्त किसान के ऋण जमा कराने पर छूट के लिए सैटलमेंट की बात पर लेकर आइए, ताकि छापावाली की घटना, गंगानगर की घटना, किसानों के आत्महत्या की घटना प्रदेश में दोहराई नहीं जाए। किसान की जमीन की कुर्की और नीलामी से पहले किसान को नोटिस भेजा जाए कि सैटलमेंट लेकर आप आएं।

(श्री बलवान पूनियां)

एकमुश्त पैसे लेकर आप आएं, हम आपके पैसे कम करेंगे। यह तजुर्बा हमने किया है। हमारे इलाके में कोई कुर्की का नोटिस आज भी नहीं है क्योंकि हम सैटलमेंट से किसान का पैसा जमा करा रहे हैं।

सभापति महोदय, बात यहां तक नहीं रुकेगी। कामर्शियल बैंक, खासकर एस.बी.आई., अगर आप किसी भी आडिटर को बैठा कर देखेंगे, ऐसा कोई बैंक नहीं, जो किसान से पैसे ज्यादा न लेता हो, ब्याज ज्यादा न लेता हो। हमने लाखों रुपये किसानों के वापस दिलाये हैं। करोड़ो रुपये, अलग-अलग ब्रांचों की बात करें तो वापस दिलवाये हैं इसलिए राजस्थान की सरकार बाकायदा आदमी तय करे, अफसर तय करे, आडिटर तय करे कि सारे के सारे राजस्थान के किसानों को, जो एस.बी.आई. बैंक के ऋणी हैं, उनके लिए आडिट करने का काम करके दे और ज्यादा लिया हुआ ब्याज वापस वसूल कर बताए।

सभापति महोदय, जो डिग्गी की बात आयी, मैं कहता हूं कि 12,500 फार्म पोंड बनाने की बात चल रही है। इस बजट में घोषणा की गयी है। लेकिन पिछली डिग्गियों का पैसा आज भी बाकी है। पिछली डिग्गियों के भुगतान के बाद यह कदम आगे बढ़ाया जाए। आज भी राजस्थान का किसान और हिन्दुस्तान का किसान लागत का डेढ़ गुना दाम की मांग कर रहा है, स्वामीनाथन कमीशन की बात कर रहा है। राजस्थान की सरकार यहां से मांग दिल्ली तक भिजवाए, ताकि दिल्ली की सरकार इस तरफ कदम आगे बढ़ाए। हमारी यह मांग भी रहेगी कि किसान अगर एक-एक दाना खेत में पैदा करे तो सरकार उसको तुलवाने की व्यवस्था करे। हम केन्द्र और राज्य के बीच नहीं पिसना चाहते। हम हमारी फसल तुलाना चाहते हैं। जिस तरह से मंडियों के विकास की बात की गयी, मंडियां नयी खोलने की बात की गयी, जो मंडियां आज स्थापित हैं, उन मंडियों में ज्यादा से ज्यादा किसान की फसल की तुलाई की बात पूरी होनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि हमारे राजस्थान में बहुत सारे क्षेत्र में अभी-भी पानी डेढ़ हजार-दो हजार, आपके जिले में भी दो हजार-डेढ़ हजार फीट नीचे से लोग पानी उठाते हैं। राजस्थान की सरकार पाताल तोड़ बोर हर जिले में या हर तहसील में एक जरूर करवाकर दे, ताकि किसान को मीठा पानी मिल जाए और किसान खेती कर ले और पीने के पानी की सुविधा भी हो सकती है।

सभापति महोदय, जब बात आयी सिंचाई की, सरकार ने 4,557

(श्री बलवान पूनियां)

करोड़ रुपये बजट के एलोकेट किये लेकिन मेरी सिद्धमुख नहर, मेरी अमरसिंह बैराज, मेरी नोहर फीडर, जो हरियाणा से लगी हुई है, जिसमें खाला निर्माण की बात आज भी बाकी है, आज भी हैड वर्क्स की बात बाकी है। सरकारें बदली हैं, राज बदले हैं, निजाम बदले हैं, उद्घाटन करने वाले लोग बदले हैं, पत्थर लगाने वाले लोग बदले हैं, नहर बनी है, पर मोघे नहीं लगाए इसलिए मैं चाहता हूं कि बजट हमें दिया जाए। उसमें मोघे लग जाएं, खाले बन जाएं। दस साल पहले इनके राज में खाले बने थे, थोड़े घटिया बन गये, टूट गये। वे भी मरम्मत हो जाएं। अब गुस्सा करते हैं लोग, जिनकी तरफ मैं हाथ कर देता हूं। इनसे मैं मांग कर रहा हूं। हम हजारों मैट्रिक टन अन्न पैदा करेंगे। प्रदूषित पानी की बात जो मेरे साथी राजकुमार जी गौड़ कर रहे थे, हम उस नहर के अन्दर हैं जिसमें भांखड़ा का एकदम साफ सफेद नीर आता है। वह अशुद्ध नहीं है। बहुत अनाज पैदा होता है इसलिए बजट का सरकार प्रावधान करे। जब ड्रिप सिस्टम की बात आयी तो पिछले बजट में सरकार ने 14 बिराने गांव भादरा के, 14 नोहर के घोषित करने के लिए डी.पी.आर. की घोषणा की थी। उसमें सरकार आगे बढ़कर हमें बजट एलोकेट करे। एक बार में नहीं तो बार-बार किश्तों में, दो बार में, तीन बार में हमारे इलाके को नहरी घोषित करने का काम करे।

सभापति महोदय, पेयजल की बात आयी, केन्द्र की जल जीवन योजना, केन्द्र की जल शक्ति योजनाओं से जोड़कर हमारे भादरा शहर, जोगीवाड़ा, कल्याना, नेतराना, मलखेडा, छानीबड़ी, परलिका, गोगामेडी की पेयजल स्कीमों को मंजूरी देकर घर-घर में शुद्ध पानी भेजने का काम राजस्थान की सरकार करवाए, ताकि लोग प्यासे न मरें। आज भी स्थिति यह है कि नहर का पानी है, एक नहीं तीन नहरें हैं, उसके बावजूद भी आज तक पानी घर-घर पहुंचाने की स्कीम कामयाब नहीं हो पायी है। जिस तरह से परिवहन मंत्रीजी कह रहे थे कि मैंने अपने बजट से पैसे दिये, मैंने पिछले बजट में सवा दो करोड़ में से दो करोड़ रुपये पेयजल की पाइप लाइन पर खर्च किये, क्योंकि सबसे पहले सुबह उठते ही पानी की जरूरत होती है। ऊर्जा की बात आयी तो हमारे यहां सौर ऊर्जा की मुख्य मंत्रीजी ने पिछले बजट में घोषणा की थी।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, दो मिनट दे दीजिए। सौर ऊर्जा में मैंने मुख्य मंत्रीजी की घोषणा की बात का सम्मान करते

(श्री बलवान पूनियां)

हुए मेरे घर पर साढ़े चार किलोवाट का सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया। बिजली तो खूब पैदा हो रही है, परंतु रुपये सवा दो लाख लगे। हर कोई तो लगा नहीं सकता इसलिए राजस्थान की सरकार हर किसी के छत पर सौर ऊर्जा की प्लेट लगाकर, जो प्रचंड गर्मी पड़ती है पूरे राजस्थान में, उस गर्मी को हम ऊर्जा के रूप में तब्दील कर देंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। 833 रुपये जो शहर के नजदीक के किसान हैं, उनको जो सरकार छूट नहीं दे रही है, वह भी छूट देने का काम करे। सड़क में अगर बात करें तो हमारे भादरा से सादुलपुर, भादरा से सावा की सड़क और सी-65 पर आर.ओ.बी. बनने की बात थी, जो अभी तक हम बजट में नहीं ले पाए हैं। जो सड़कें एक एम.एल.ए., एक साल में पहले पन्द्रह किलोमीटर बनाते थे, अभी तक हमें मिली नहीं हैं। केन्द्र से सड़क का पैसा आया नहीं है, राज्य सड़क का पैसा दे नहीं रहा इसलिए हमें लोगों की ये बातें सुननी पड़ती हैं कि हमारे गांव को दूसरे गांव से जोड़ें।

सभापति महोदय, एक-दो छोटी-छोटी बात और बची हैं। राजस्थान प्रदेश में 53,181 नौकरियों की सरकार ने घोषणा की है, लेकिन अकेले शिक्षा विभाग में 70 हजार पद खाली हैं और सारे ही विभागों की बात करें तो लाखों पद खाली हैं। उन पदों को भरकर अच्छा सुराज करने का सरकार काम करेगी। न्याय प्रशासन की बात करें तो नागौर की घटना हमारे लिए सिर्फ एक घटना है, न कोई एस.पी. की गलती है, न कोई थानेदार की गलती है, यह गलती हमारे समाज की गलती है। यह बात मैंने पहले भी कही थी कि जो बराबरी हम कायम नहीं करने देना चाहते, ये जो जातीय सड़ांध हमारे दिमाग में है, उसी का परिणाम है कि ये क्रूर घटना हुई है। इन घटनाओं को रोक लगाने के लिए सख्त से सख्त कार्यवाही करते हुए हम 200 के 200 लोग यह संकल्प लेकर जाएं कि जाति विहीन एक सुन्दर समाज का निर्माण करें, जिससे ऐसी घटनाओं का दोहराव न हो। सैनिक कार्यालय हमारे भादरा में इसलिए खोला जाए कि मेरे जिले में सबसे ज्यादा सैनिक अगर कहीं हैं तो भादरा तहसील में हैं। सैनिक कार्यालय के लिए जो मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, वह जिला हैडक्वार्टर की बजाय हमारे क्षेत्र में खोला जाए।

सभापति महोदय, एक बात ओर बची है। मेरे भादरा में सवा सौ बीघा जमीन है, उसके लिए हम गांधी वन के नाम से नेचर पार्क बना सकते हैं, जो वन विभाग की भूमि है, उस पर कोई अतिक्रमण न हो। उसके लिए हम दानदाताओं से मदद कर देंगे लेकिन सरकार उसको आगे बढ़ाकर उसकी

(श्री बलवान पूनियां)

घोषणा करने का काम करे। हमारे यहां जो पंचायत सहायक और कम्प्यूटर आपरेटर को स्थायी करने की मांग बार-बार उठ रही है, मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी इसमें घोषणा करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, साथिनों, सहायिकाओं, पोषाहार बनाने वाली महिलाओं के मानदेय को बढ़ाने की बात भी संशोधित बजट में मुख्य मंत्रीजी कहें ताकि ये लोग पीड़ित न रहें। ई.डब्ल्यू.एस. के आरक्षण की पात्रता की अव्यावहारिकताओं को मुख्य मंत्रीजी ने खतम करते हुए जिस तरह से उन लोगों को राहत दी है, मैं समझता हूं कि ओ.बी.सी. की महिलाएं और एस.सी. की महिलाएं, जो दूसरे राज्यों से हमारे यहां शादी करके आ गयीं, मुख्य मंत्रीजी उनको भी राहत देने का काम करेंगे ताकि उन लोगों को भी न्याय मिल सके। वे भी नौकरी लग सकें।

सभापति महोदय, नरेगा में 53 लाख लोगों को जोड़ा गया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक आंकड़ा है, जो यह कहता है कि सिर्फ एक साल में 100 दिन मात्र साढ़े चार लाख लोगों ने पूरे किये हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, कह लेने दीजिए, बजट पर ही तो है।

नरेगा में साढ़े तिरेपन लाख लोगों को एक साल में रोजगार मिला, लेकिन 100 दिन किसने पूरे किये, महज साढ़े चार लाख लोगों ने। यह डिफरेंस है, जो नरेगा का दम तोड़ता है। इस डिफरेंस को मिटाने का एक ही कार्यक्रम है कि फार्म 6 भरवाइए, उससे लिखवाइए कि इतने दिन लगना चाहता है। इस पर अगर सरकार काम करेगी तो दिन भी पूरे होंगे और नरेगा भी आगे बढ़ेगी। हिन्दुस्तान की सरकार को भी नरेगा का टाइम-टाइम पर बजट देना पड़ेगा। फार्म 6 भेजने के बाद, फार्म 6 की कापी भेजने के बाद कोई बात नहीं बचती कि सरकार पैसा रोक ले।

भादरा में आई.टी.आई. खोलने की बात, स्कूल क्रमोन्नत करने की राजस्थान की सरकार ने जो घोषणा की है, मैं उसके लिए धन्यवाद भी करना चाहता हूं लेकिन स्कूल क्रमोन्नयन के साथ-साथ सब्जेक्ट खोलने की बात की है, हमारे कई गांव ऐसे हैं, जहां बहुत अच्छी शिक्षा है। अभी जो कार्यक्रम था, स्कूलों में वार्षिकोत्सव, एल्युमिनाई मीट, उस कार्यक्रम में मैं गया हूं। बहुत शानदार, जोरदार कार्यक्रम है। वहां जाते ही लोगों ने मांग की, डाबडी के स्कूल में, भिरानी के स्कूल में, जोगीवाड़ा के स्कूल में, परलीका के स्कूल में कि हमारे सब्जेक्ट खोलो। हमारे अलग संकाय खोलो।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मैं समझता हूं ये सारे काम अगले बजट में राजस्थान की सरकार करेगी। परिवहन मंत्रीजी आ गये हैं, ये रोडवेज हमारे यहां चलाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के प्रदेश का किसान मजबूत होगा। दोनों पार्टियां मिलकर, मैं इस बात से ऊपर उठकर कहना चाहता हूं कि दोनों पार्टियां मिलकर राजस्थान के जो साढ़े दस हजार करोड़ केन्द्र ने पैसे कम दिये हैं, इसके लिए हमें चाहे लड़ना पड़े, चाहे दिल्ली पैदल जाना पड़े, चाहे धरना लगाना पड़े, हमें ये पैसे लेने चाहिए ताकि राजस्थान का विकास हो। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हाकम।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): सर, मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा, कल दिल्ली में घटना घटी, उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक जवान शहीद हो गया, जो पुलिस में हैड कांस्टेबल था। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उसके परिवार को, उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। शहीद को जो सम्मान को मिलता है, वह सम्मान उसको व उसके परिवार को दिया जाए। कल उसका दाह संस्कार होगा, शहीद के सम्मान की तरह उसका दाह संस्कार किया जाए, यही मेरा सरकार से निवेदन है।

श्री सभापति: श्री रामलाल जाट।

श्री रामलाल जाट (माण्डल): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह शासन के मुखिया राजस्थान के स्वप्न दृष्टा मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने सात संकल्प, 64 पेज के माध्यम से, एक दिशा देकर, बजट प्रस्तुत किया है। प्रदेश की जनता की उम्मीद और आकांक्षाओं को पूरा करने का बहुत बड़ा निर्णय उन्होंने लिया है। आज पूरे राजस्थान की जनता मन से इस बजट को स्वीकार कर रही है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा कि ऐसा शानदार बजट पेश किया है। हालांकि हम अलग-अलग पार्टी, अलग-अलग दलीय स्थिति से जीत कर आते हैं। लेकिन जैसे प्रावधान इस बजट में किये हैं, हर बजट में ऐसे पाइंट आने चाहिए। मुख्य मंत्री ने इस बजट में प्रावधान किया, उसका समर्थन सभी को करना चाहिए।

सात संकल्प दिये हैं, निरोगी राजस्थान, सम्पन्न किसान; महिला, बाल एवं वृद्ध कल्याण; सक्षम मजदूर, छात्र-युवा-जवान; शिक्षा का परिधान; पानी, बिजली व सड़कों का मान; कौशल व तकनीकी प्रधान, इन सब चीजों

(श्री रामलाल जाट)

को करने के लिए पैसे की भी आवश्यकता होती है। उन सबका बंदोबस्त करते हुए, मेरे से पहले बोलने वाले सभी विधायक सथियों ने यह चीज रखी है कि राजस्थान सरकार के पास पैसे की कमी है। इस तरह देश की आर्थिक स्थिति आज अखबार व टीवी के माध्यम से हम सब लोग देख रहे हैं। केवल हम ही नहीं, पूरे आर्थिक सुधार, टीवी, अख़बार के माध्यम से ही नहीं, विश्व बैंक, आई.एम.एफ. ए.डी.बी. ने विकास दर को नीचे के स्तर पर बताया। मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में यह कहा है कि

''नोटबंदी से बरबादी पर वे बोलते नहीं,
जी.एस.टी. के झटकों पर मुंह खोलते नहीं,
उनके आंकड़े ही दिखाते हैं उनको आईना,
वह फिर मुकर कर सच को तौलते नहीं।''

जब नोटबंदी हुई तो भारत के अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी ने, अपन कह सकते हैं भविष्यवाणी की, उन्होंने राज्य सभा में कहा मुझे आशंका है कि आने वाले समय में हिन्दुस्तान की विकास दर 2 परसेंट नीचे जाएगी और वही हुआ। इसी चीज को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में पैरा तीन पर, आर्थिक स्थिति की सच्ची तस्वीर हम सबके सामने रखी है। पहले बोलने वाले लोगों ने अन्यथा आरोप भी लगाये। लेकिन हमारी संघीय व्यवस्था में जिस तरह राज्यों की वित्तीय स्थिति, केन्द्र के इर्द-गिर्द घूमती है, केन्द्र के निर्णय, नीति के माध्यम से ही राज्य का विकास होता है, उन्हीं चीजों में आज आर्थिक विकास की दर नीचे गयी, इस वजह से यह चीज़ें हमारे सामने आयीं। इस बजट में मुख्य मंत्रीजी ने वे चीज़ें इसमें ली हैं, जिन चीजों से प्रदेश का विकास हो सकता है।

आज आप देख सकते हैं कि जी.डी.पी. की वजह से इस बजट में 5 परसेंट ग्रोथ दर नीचे दिखाई गयी है। ये सारे आंकड़े इस किताब में ही नहीं हैं। हर अर्थशास्त्री यह कह रहा है। भारत सरकार में सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया। उन्होंने सच्ची बात कही, हिन्दुस्तान में बेरोजगारी फैलना, मंहगाई बढ़ना, इन सब चीजों के पीछे नोटबंदी का कारण है। 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिन्दुस्तान में फैली। लगभग 6.1 परसेंट बेरोजगारी पहुंची है, वह इन्हीं गलत नीतियों के आधार पर हुई। महंगाई साढ़े सात परसेंट तक पहुंचने का कारण आज गलत नीतियों की वजह है। अभी कुछ समय पहले पार्लियामेंट में यह चीज कही जा रही थी। कई अर्थशास्त्री यह चीज कह रहे हैं कि सरकार गलतियों को नहीं मानती है, गलती

(श्री रामलाल जाट)

माने तो उसमें सुधार हो सकता है लेकिन आज भी भारत सरकार उन चीजों को नहीं मान रही इसलिए हर राज्य आज विकास की दौड़ में पीछे है। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने बजट में तमाम प्रावधान किये हैं, जिससे प्रदेश का पूर्ण विकास हो सके।

पहला संकल्प निरोगी राजस्थान का है। स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछली बार मुख्य मंत्रीजी थे, तब भी नि:शुल्क दवा योजना के माध्यम से इस प्रदेश में नि:शुल्क दवा योजना चालू की। गांव में बैठे हुए गरीब किसान, मजदूर, तमाम लोगों को इस चीज का फायदा मिला। अब दुबारा सरकार आने के बाद उसका नाम भी बदला गया। आज भारत सरकार ही नहीं, विदेशों में आकलन किया जा रहा है कि नि:शुल्क दवा योजना सरकार की ऐसी स्कीम है, स्वास्थ्य का बजट निरोगी राजस्थान के माध्यम से 14 हजार करोड़ से ज्यादा बढ़ाकर दिया है। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान में निरोगी राजस्थान का नारा ही नहीं, हर बजट में, सभी लोगों को इसका सम्मान करना चाहिए। वेद-पुराणों में पहला सुख निरोगी काया लिखा हुआ है। इस चीज को मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में दर्शाया है। हर नेता इस चीज को, हर गांव में, अपने भाषण में कहे, और उस पर अमल करे तो कोई विधायक हार ही नहीं सकता। ऐसा इस बजट में मुख्य मंत्रीजी ने प्रावधान किया है। यही नहीं पिछले समय कुछ दवाइयां कम थी, नि:शुल्क दवा योजना में, उनमें और दवाइयां बढ़ायीं, किडनी, कैंसर की दवाइयां महंगी मिलती हैं, लोगों को इलाज मुहैया नहीं हो पाता है, उन चीजों को भी इसमें शामिल किया है।

सभापति महोदय, यह बजट पहला सुख निरोगी काया के माध्यम से आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य में जिस तरह का काम मुख्य मंत्रीजी ने किया है, निश्चित रूप से आम जन को इसका फायदा होगा। हालांकि विरोध करने के लिए कई तरह के भाषण भी दिये गये हैं। भारत सरकार ने आयुष्मान योजना के नाम से लागू करने का काम किया है। पिछली सरकार ने नि:शुल्क दवा योजना को भामाशाह कार्ड के माध्यम से जोड़ा। नाम भले ही बदला लेकिन इस योजना का फायदा लोगों तक पहुंचे, यह अशोक गहलोत जी की देन है। आज जनाधार के माध्यम से नि:शुल्क दवा योजना गांव-गांव तक पहुंचाने का काम इस बजट के माध्यम से किया गया। निश्चित रूप से प्रदेश के तमाम लोगों को फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, आप देख सकते हैं, आज हर विधायक की चिंता है, कई जगह डाक्टरों के पद खाली हैं, नर्स, कम्पाउंडर के पद खाली हैं।

(श्री रामलाल जाट)

पिछली बार अशोक गहलोत जी सरकार में थे तो मेडिकल कालेज भारत सरकार के सहयोग से, 75 प्रतिशत भारत सरकार की ग्रांट व 25 प्रतिशत राज्य सरकार की ग्रांट के माध्यम से, पिछली सरकार ने अपना नाम लेकर मेडिकल कालेज का नाम लिया लेकिन पिछली यू.पी.ए. सरकार और अशोक गहलोत जी की सरकार के समय राजस्थान में मेडिकल कालेज की स्थापना हुई। बाद में तीन बार उनका नाम लिया, तीन साल तक बजट में पिछली सरकार ने, लेकिन अब तक पूरे नहीं हो पाए। पिछले बजट में भी मुख्य मंत्रीजी ने 6 मेडिकल कालेज और अब 9 मेडिकल कालेज यानी 15 मेडिकल कालेज होंगे। राजस्थान में आने वाले समय में कर्जा लेने का आरोप कई बार लगाया गया। इन्फ्रास्ट्रक्चर को डवलप करने के लिए, ऐसे काम करने के लिए अशोक गहलोत जी ने इस बजट में प्रावधान किया। माननीय सभापति महोदय, इसमें केन्द्र सरकार ने 60 परसेंट का हिस्सा किया। भले ही यू.पी.ए. सरकार से कम हिस्सा इसमें किया, फिर भी राज्य सरकार बजट में पूरा प्रावधान करके 15 मेडिकल कालेज खोलने का काम कर रही है।

दूसरा संकल्प, सम्पन्न किसान का है। सरकार बनते ही एक हजार करोड़ का कृषक कल्याण कोष बनाया, उसको बढ़ाकर अभी 3,420 करोड़ रुपये का प्रावधान कर किसानों को और ज्यादा फायदा देने का काम इस बजट में किया गया। पिछली बार भी सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में कई बार आरोप लगाये, लेकिन पिछली सरकार में डिग्गी बनाना, खड्डे खोदना, नरेगा के माध्यम से कामों को चालू किया। भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए जन स्वावलम्बन के नाम से पिछली सरकार ने भी इसमें थोड़ा-बहुत कुछ किया। लेकिन वृहद् स्तर पर करते हैं तो निश्चित रूप से भूमिगत जलस्तर से किसानों को और ज्यादा फायदा होता है। इसका प्रावधान भी मुख्य मंत्रीजी ने, इसमें 12,500 नये फार्म पौंड की स्वीकृति देकर किया ताकि भूमिगत जलस्तर बढ़े। भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा तो तो जमीन का खराब पानी, फ्लोराइडयुक्त है, बीमारी फैलने का काम होता है, उन सब चीजों से छुटकारा मिल पाएगा।

(16.00 बजे)

इसके साथ ही सोलर पम्प वाली योजना भी, ड्रिप सिस्टम वाली योजना भी, मुख्य मंत्रीजी ने किसानों की उन्नति कैसे हो, आगे बढ़ें, इस चीज को पूरे तरीके से हाथ में लेकर नयी मंडियां खोलने का काम भी इस बजट के

(श्री रामलाल जाट)

अन्दर किया। 44 नयी मंडियां खोलना, पुनर्गठन करना, ताकि किसानों को सीधा अपनी फसल का दाम नजदीक की मंडी में जाकर मिल सके, उनको कहीं दूर नहीं जाना पड़े, किराया ज्यादा नहीं लगे। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में प्रावधान किया।

सभापतिजी, इसके साथ ही को-आपरेटिव में जो फसली ऋण की बात आती है, ऑनलाइन सिस्टम किया। लोन माफी की कई बार चर्चा हो चुकी है। पिछली सरकार ने ऋण माफ किया था। उसमें 50 हजार तक के ऋण माफ की बात आयी थी। वे भी पूरे नहीं कर पाये। आनन-फानन में चुनावों के समय में किन्हीं लोगों को फायदा मिला। लेकिन दुबारा जब अशोक गहलोतजी की सरकार आयी तो उन्होंने 2 लाख तक के कर्जे माफ करने का काम ही नहीं किया, उन्हीं लोगों का माफ हुआ तो नये लोग जोड़ने का प्रावधान किया। माननीय सभापतिजी, आज खुशी है कि 8 लाख से अधिक सदस्य, नये लोगों को, नये सदस्यों को 1800 करोड़ रुपये का फसली ऋण वितरित किया, एक बहुत बड़ा प्रावधान, इसमें आगे बढ़कर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हाथ में लिया।

माननीय सभापतिजी, इसके साथ ही मैं पशुपालन के लिए निवेदन करूंगा कि दूध डेयरी में जो पिछली बार 2 रुपये लीटर के जब अशोक गहलोतजी ने आम लोगों को फायदा देने के लिए घोषणा ही नहीं की, इसको अमल में भी लाये। लेकिन विपक्ष की सरकार आयी, उस समय उस 2 रुपये को बंद कर दिया। ये गाय बचाने की बात करते हैं, गाय के दूध पर इन्होंने 6 रुपये लीटर पैसा देने की बात कही, पर उलटा, जो गहलोतजी के टाइम में 2008 से 2013 के समय में 2 रुपये लीटर मिल रहा था, उसको भी बंद कर दिया। मुझे खुशी है कि घोषणा पत्र में उन चीजों को रखते हुए, नयी सरकार आते ही अशोक गहलोतजी ने वे 2 रुपये वापस चालू किये। इस बजट में आगे बढ़ाया, जारी रखा, एक बहुत बड़ा काम किया। आने वाले समय में किसानों को मजबूती मिलेगी, गाय बचेगी। इसके साथ ही गायों की कई जगह समस्या है। गांवों में जो आवारा पशु घूमते हैं, गांवों में एक्सीडेंट से कई मौतें होती हैं। उसमें गौशाला खोलने की घोषणा ही नहीं की, लेकिन आने वाले समय में भारत सरकार के सहयोग से जो सोर्टेड सीमन, जो बछड़ी ही पैदा होगी, उसके लिए भी इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रावधान किया है। तो आने वाले समय में बहुत बड़ी निजात इस प्रदेश को घूमते हुए आवारा पशुओं से मिलेगी। इस बजट के अन्दर यह प्रावधान किया गया है।

(श्री रामलाल जाट)

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही, इनके तीसरे संकल्प में महिला, बाल, वृद्ध के कल्याण की योजना रखी। इसमें एक हजार करोड़ की इन्दिरा महिला शक्ति की निधि के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण का कदम बढ़ाया। इसके साथ ही 800 करोड़ रुपये, जो किशारी बालिकाओं, धात्री महिलाओं, गर्भवती महिलाओं, जो 35 लाख से ज्यादा बच्चों को, जो ऑनलाइन सुविधा, जिसमें कई बार करप्शन, पोषाहार में हर बार शिकायतें मिलती हैं, उस चीज को भी आई.टी. के माध्यम से, जो 150वीं महात्मा गांधीजी की जयंती है, ग्राम स्वराज, 75वीं जयंती है राजीव गांधी जी की, जो आई.टी. के निर्माता हैं, उन चीजों को इस बजट में शामिल किया ताकि आई.टी. के माध्यम से करप्शन रुके। ये सारी चीजें इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, सभापतिजी, शामिल की हैं।

निश्चित रूप से, सबसे बड़ा काम, यह ई.डब्ल्यू.एस. के आरक्षण की पात्रता की अव्यावहारिक शर्तें हटाकर, 8 लाख रुपये तक की आय का सर्टिफिकेट बनने की जो दिक्कतें आ रही थीं, एक बहुत बड़ा काम इस बजट के अन्दर किया। वे बेरोजगार लड़के, जो गरीब हैं, वे जो इसमें पात्रता रखते हैं लेकिन कई बार कागजों की दिक्कतें आती थीं, उन चीजों को हल्का करने का काम भी किया। राजस्थान में आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड बनाने की भी घोषणा की। ये तमाम चीजें, जब अलग-अलग बोर्ड बनेंगे, उनकी समीक्षा होगी, प्रदेश में भ्रमण होगा, वहां की समस्याएं आएंगी, तो इस बजट के माध्यम से आने वाले समय में उन सभी लोगों को फायदा मिल पाएगा। यह काम इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है। अल्पसंख्यकों के लिए भी 41,60,00,000 का प्रावधान किया। मैं समझता हूं कि काफी हद तक इस बजट में तमाम वर्ग को हाथ में लेते हुए मुख्य मंत्रीजी ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है।

चौथा संकल्प, सक्षम मजदूर, छात्र-युवा-जवान, सब लोगों को इसके अन्दर हाथ में लिया है। आज स्किल डवलपमेंट के माध्यम से 'फिट राजस्थान, हिट राजस्थान' का एक नारा ही नहीं दिया, जो 'खेलो इंडिया' आसाम में हुआ और आज यहां पर, वह भी नये युवा लड़कों के लिए प्रावधान किया। 8,000 खिलाड़ियों ने उन खेलों में भाग लिया। जो पदक की राशि थी, वह भी बढ़ायी ताकि आने वाले समय में यहां का नौजवान युवा फिट रहे, स्वस्थ रहे। यह काम भी इस बजट के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने

(श्री रामलाल जाट)

किया। इसके साथ ही दो प्रतिशत आरक्षण देकर, जो पुरानी परम्परा थी, पिछले कुछ समय से सरकारों ने बंद कर दिया, दो प्रतिशत उन खिलाड़ियों को अलग से नम्बर मिलेंगे ताकि नौकरी के अन्दर भी उनकी भागीदारी, हक बन सके। ये काम भी इस बजट के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है।

उद्योग धंधों के साथ ही, जो खास तौर से खनिज में आज हर सदस्य इसकी चिंता कर रहा है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामलाल जाट (माण्डल): माननीय सभापति महोदय, अवैध बजरी की बात भी आयी। आज यह क्यों हो रहा है। इसके पीछे, माननीय सभापतिजी, आप भी इस विभाग को सम्भालते रहे हैं। आपके बाद पांच साल पिछली सरकार रही। उन्होंने एक खनन पट्टा भी खातेदारी के अलावा कहीं दिया हो तो आप बताओ। अवैध बजरी क्यों नहीं होगी। किसी लड़के को एक कमरे में बैठा दें। कमरा बंद कर दें, कहें दस दिन तक इसी में रहेगा तो वह शौच भी उसी में करेगा, पेशाब भी उसी में करेगा। तो आप माइनिंग दे नहीं रहे हो। राजस्थान में हर जगह मिनरल्स हैं। मिनरल्स की आपने कोई नीति नहीं बनायी। खातेदार को भी आक्शन में डाला जबकि यह चीज होनी नहीं चाहिए।

माननीय सभापतिजी, आपके बाद इस नीति को कुछ लोगों के स्वार्थ की खातिर किस तरह तोड़ा-मरोड़ा गया। इसमें एक भी पट्टा राजस्थान में इश्यू नहीं हो पाया। इसलिए अवैध बजरी हो, या अवैध माइनिंग का काम हो, आज पुलिस के माध्यम से लड़ाई भी हो रही है। कई लोगों के गाड़ियां भी चढ़ा दी गयी हैं। इसके पीछे जो सबसे पहला कारण है कि नयी नीति उस समय थी, उसकी समीक्षा करके वापस नयी लायी जाए ताकि जो अवैध खनन हो रहा है, उससे भी छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही वन विभाग में जिस तरह का पर्यावरण दूषित हो रहा है, दिल्ली में आये दिन सुप्रीम कोर्ट यह डाइरेक्शन दे रहा है। आज ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट यह चीज हर जगह कह रहा है। कई जगह इंडस्ट्रीज, उद्योग लगे हुए हैं। आज वहां ट्रीटमेंट प्लांट में जीरो डिस्चार्ज से पानी नहीं निकल पाता है। हरित राजस्थान का उस समय जो सपना अशोक गहलोतजी ने दिया, अगर यह सरकार उसको आगे बढ़ाती तो निश्चित रूप से अब तक कितने पेड़ बड़े होते और पर्यावरण भी दूषित था, वह सही हो पाता। मैं समझता हूं इन गम्भीर बीमारियो से जहां-जहां राजस्थान जूझ रहा है, वन

(श्री रामलाल जाट)

विभाग और पर्यावरण विभाग को भी सम्भाला जाता तो निश्चित रूप से अच्छा काम हो पाता।

(16.06 बजे)

(श्री ज्ञानचंद पारख, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापतिजी, इसके साथ-साथ मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में जल के लिए, पानी के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है। हालांकि ठीक बात है, इसमें जो राज्य सरकार, भारत सरकार का हिस्सा है, उसमें बढ़ाने की बात की है। यह हमेशा होता आया है। कई राज्यों को 90-90 प्रतिशत तक भारत सरकार ग्रांट दे रही है। इस बजट में मुख्य मंत्रीजी ने जिक्र किया है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, मेरे से पहले बोलने वाले सदस्यों की 'हां' में 'हां' मिलाते हुए मैं निश्चित रूप से इसमें चाहूंगा, यहां के सारे एम.पी. और एम.एल.ए. मिलकर दबाव बनाएं तो हर घर में पानी पहुंचाने का काम मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में जो प्रावधान किया, वह पूरा कर पाएंगे। इसके अन्दर 16 जिलों को लिया है। आने वाले समय में पूरे राजस्थान का हर घर स्वच्छ पानी पीए, यह काम भी, माननीय सभापति महोदय, इस बजट में किया गया।

इसके साथ ही कुछ ऐसी चीजें हैं, जो सड़कों से सम्बन्धित हैं। माननीय सभापति महोदय, प्रावधान तो आपने किया, मेरे कुछ सुझाव भी इसमें हैं। जहां डी.एम.एफ.टी. फंड की सड़कें भी गांवों में बनायी जाती हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कें भी गांवों में बनती हैं, मिसिंग लिंक योजना की भी सड़कें बनती हैं। लेकिन जहां माइनिंग एरिया है, उस जगह इसकी थिकनैस नहीं बढ़ाई जाती है। हर बार हम मीटिंग्स में यह चीज कहते हैं। अगर इंजीनियर सड़कों को, सभापतिजी, जहां-जहां माइनिंग एरिये में सड़कें किसी भी मद में बनाएं, उनकी मोटाई, थिकनैस, अगर वह सारी बढ़ाई जाए तो वे सड़कें टूटें नहीं। 6 महीने के अन्दर वे सड़कें टूट जाती हैं। इसलिए हालांकि बजट में सड़कें बनाने का प्रावधान किया लेकिन इस चीज के लिए मेरा सुझाव है। अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से लम्बे टाइम तक सड़कें चल पाएंगी।

इसके साथ ही इस बजट में और काफी, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में भी 'खूब काम मांगों' अभियान चलाया, जिसके माध्यम से लोगों को इसका फायदा मिल पाया। साथ ही इसका छठा संकल्प, पानी, बिजली की जो

(श्री रामलाल जाट)

बात आयी, माननीय सभापति महोदय, बिजली में राजस्थान में पहली बार, किसानों को जो सबसे बड़ी दिक्कत आती थी, इंडस्ट्रीज को भी दिन में बिजली मिलती थी, छोटे कारखानों को भी दिन में मिलती थी लेकिन किसान एक ऐसा आदमी था, ऐसा मजदूर था जिसको कभी दिन में बिजली नहीं मिला करती। मिलती तो ट्रिपिंग होती, 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे भी बड़ी मुश्किल से मिलती। लेकिन पहली बार इस बजट में दो ब्लाक्स में दिन में किसानों को बिजली देने का भरोसा और विश्वास दिलाया। निश्चित रूप से यह काबिल-ए-तारीफ है।

आने वाले समय में, सोलर कनेक्शन के बजट में, इसमें 8,794 करोड़ 91 लाख का प्रावधान भी किया गया है लेकिन इसके साथ ही बिजली में ग्रिड सिस्टम, जो जगह-जगह बनाये गये, इसमें मेरा एक सुझाव है। प्रतिपक्ष के माननीय नेता भी मौजूद हैं। माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां बिजली की छीजत होती है, या जहां चोरी होती है, तो जो बिजली निगम हैं, इन निगमों में, जिन जिलों में या जिस फीडर पर चोरी कम है या चोरी है ही नहीं, बिलकुल जीरो, उन किसानों को उनकी रेट में कुछ बैनिफिट दिया जाए। कई जिलों में कई फीडर्स पर बहुत ज्यादा चोरी होती है। कोई छोटी जोत किसान की है, मुझे यह याद है कि जब 1998-2003 में मिनिमम चार्ज माफ किया। गुलाब सिंहजी आज नहीं रहे, माननीय सभापति महोदय, जो अभी वर्तमान में मौजूद हैं, श्री सी.पी. जोशी साहब, एक कमेटी बनायी श्री अशोक गहलोतजी ने, तो 2002-03 के अन्दर मिनिमम चार्ज कमेटी में माफ किया था। हालांकि, बाद में आपकी गवर्नमेंट आयी तो उसको जारी रखा, उसमें बिल पर छाप लगाने का काम आपकी गवर्नमेंट ने कर दिया था। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अब समाप्त करें।

श्री रामलाल जाट (माण्डल): माननीय सभापति महोदय, वह बिजली का मिनिमम चार्ज माफ करने का काम भी श्री अशोक गहलोतजी ने पिछली बार किया था। उन्हीं चीजों को अगर इसमें थोड़ा-सा और दुरुस्त किया जाए तो जहां पर चोरी, जिस फीडर पर बिलकुल ही नहीं है, वहां के किसानों को राहत दी जाए तो निश्चित रूप से और ज्यादा किसानों को राहत मिलेगी और ज्यादा फायदा हो पाएगा।

माननीय सभापति महोदय, बाकी इस बजट के माध्यम से वह तमाम

(श्री रामलाल जाट)

चीजें, सातवां संकल्प जो कि कौशल व तकनीकी प्रधान का है, यह बहुत बड़ा काम है। जो नौजवान रोजगार लेने के लिए, जो बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं इस तकनीकी के माध्यम से पहली बार ट्रेन करके उनको रोजगार मुहैया करवाया जाएगा, इस काम के लिए इस बजट के अन्दर प्रावधान किया गया है।

इस बजट का आम लोग निश्चित रूप से स्वागत कर रहे हैं। मैं मेरे मन से भी न सभी लोगों की भावना के आधार पर माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई दूंगा और पुरज़ोर शब्दों में इस बजट का समर्थन करता हूं। माननीय सभापतिजी, आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री खुशवीरसिंह।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने वर्ष 2020-21 का बजट प्रस्तुत किया, उसके समर्थन में मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सात संकल्पों के साथ में राजस्थान का बजट प्रस्तुत किया। सभी वर्गों का, सभी घटकों का, सभी क्षेत्रों का, सभी विभागों का ध्यान रखते हुए सीमित संसाधनों में, विपरीत परिस्थितियों में। आज देश के आर्थिक हालात क्या है, नोटबंदी के बाद में देश की आर्थिक स्थिति पर क्या संकट आया, जी.एस.टी. के बाद में देश की आर्थिक स्थिति में कितनी गिरावट आयी है, बावजूद उसके माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत ही शानदार बजट प्रस्तुत किया है लेकिन उस बजट में कुछ सुझाव और प्रस्ताव भी मैं देना चाहूंगा। यह नहीं है कि मात्र समर्थन सरकार को दिया और हर बात पर 'हां' में 'हां' की जाए। हम उस स्थान पर खड़े हैं, मारवाड़ की जनता ने मुझे जातिवाद के विरुद्ध और विकास के नाम पर यहां पर जिता कर भेजा है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे वह दिन याद है नोटबंदी का, जब टी.वी. पर हम देखते थे कि लम्बी-लम्बी लाइनें लगती थीं, लोग अपना पैसा, अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा, बैंकों के आगे रात-दिन खड़े रहकर, पूरी-पूरी रात इंतजार करते थे। अपनी उस गाढ़ी कमाई का पैसा निकलवाने के लिए पुलिस के डंडे भी खाये होंगे, कइयों के शादियां भी थीं, कइयों के घर में लाश भी पड़ी रही, लेकिन ऐसी स्थिति उस वक्त पैदा कर दी गयी थी। ऐसा क्या कारण आ गया, क्या संकट हो गया? मैं आज भी दावे के साथ यह कहता हूं कि जितनी राशि छपी नहीं, नोट उससे ज्यादा जमा हो गये।

(श्री खुशवीरसिंह)

माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने यह स्टेटमेंट दिया था, मुझे वह दिन याद है कि चंद घंटों के बाद में यह रुपये कागज के टुकड़ों में तब्दील हो जाएंगे। उन टुकड़ों के लिए उन्होंने यह कहा था कि 30 नवम्बर के बाद में जो राशि जमा नहीं करवा पाएंगे, वे आर.बी.आई. के अन्दर जमा करवा सकते हैं। मैं देश के प्रधान मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आपके उस वक्तव्य का क्या हुआ जो आपने यह बात कही थी कि 30 नवम्बर के बाद में अगर पैसा शेष रह भी जाएगा और लाखों लोगों के पास में गाढ़ी कमाई का पैसा रह गया, आज दिन तक उसका हिसाब आर.बी.आई. नहीं दे पायी कि कितनी राशि जमा हुई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र से मेरी बात को प्रारम्भ करना चाहूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सात संकल्पों के साथ में यह बजट रखा। सबसे पहला संकल्प है निरोगी काया और फिर माया, फिर सब कुछ, निरोगी काया के लिए मैं यह कहना चाहूंगा और उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो सूत्र दिये हैं उसमें हर चीज के लिए बजट की आवश्यकता नहीं होती है। आपको कुछ इच्छा शक्ति भी प्रबल करनी होगी और हमें कुछ समर्पण भाव के साथ में, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे राज्य के लिए कुछ करना होगा।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पहला सूत्र दिया है, "शुद्ध के लिए युद्ध", यह मिलावट एक ऐसी चीज है, माननीय सभापति महोदय, दूध में जिस तरह से मिलावट की जा रही है, जो जहरीले पदार्थ मिलाये जा रहे हैं, खाद्य पदार्थ जिसकी वजह से जीवन संकट में हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह चिंता जाहिर की है। मैं इस गांधीवादी नेता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसे खाद्य पदार्थ, जो जीवन के लिए हानिकारक हो सकते हैं, जीवन संकट में आ सकता है, उनके लिए उसे सख्त से सख्त सज़ा फांसी की भी दी जाए तो कम है, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा।

आपसे मैं एक छोटा-सा उदाहरण शेयर करना चाहूंगा कि हमारी पर्यावरण समिति के साथ हमने चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, पाली, इन जिलों में भ्रमण किया था। उस वक्त जब हम समिति में गये तो वहां के अधिकारियों ने मिठाई हमारे समक्ष रखी। उस मिठाई के ऊपर एक सफेद कलर का जो वर्क लगा हुआ था फोइल, आज दिन तक उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया। पिछले

(श्री खुशवीरसिंह)

सदन में भी मैंने यह बात कही थी कि यह किस मैटीरियल का बना हुआ है, किस चीज का, यह व्हाइट कलर की फोइल जो ऊपर लगी हुई है, वर्क जो लगा हुआ है, यह किस चीज का है? आज दिन तक राजस्थान प्रदेश को, हमारी सरकार को यह पता नहीं है कि यह क्या चीज है।

मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस चीज का भी तुरंत जवाब दे कि किस चीज की बनी हुई है जो हम सभी मिठाई के ऊपर सफेद चीज को चांदी समझकर खा रहे हैं। यह "शुद्ध के लिए युद्ध" और यह निरोगी राजस्थान' प्रथम कड़ी के विषय हैं। इसके साथ ही मैं निरोगी राजस्थान पर यह कहना चाहूंगा कि हमें इसके लिए आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना होगा।

माननीय सभापति महोदय, आर्गेनिक खेती, आज पंजाब के लोग राजस्थान से गेहूं खरीद कर खा रहे हैं और वहां के गेहूं हमारे यहां पर आ रहे हैं। उसके अन्दर फर्टिलाइजर और पेस्टीसाइड इतना अधिक डाला हुआ है कि वे ज़हरीले गेहूं हो गये हैं। तो मैं यह चाहूंगा कि मंडियों में भी आर्गेनिक खेती के लिए प्रमाणीकरण की व्यवस्था सरकार द्वारा हो और उसके लिए अलग से खरीद की व्यवस्था की जाए। आज हजारों लोग आर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हैं लेकिन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और प्रामाणिकता नहीं है। यदि उपलब्ध भी है तो प्रामाणिकता सरकार की तरफ से नहीं हो पा रही है, तो मैं यह चाहूंगा कि इस ओर भी सरकार ध्यान दे और मंडियों में अलग से व्यवस्था की जाए।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने निशुल्क दवा योजना, नि:शुल्क जांच योजना प्रारम्भ की। विश्व स्तर पर इसकी बहुत ही सराहना हो रही है और यह बहुत ही सही कदम है। जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की, वह इस प्रदेश के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने करके दिखाया। लेकिन मैं सरकार से यह भी साथ में चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज डाक्टर्स के पद रिक्त पड़े हैं, 65 सब सेंटर्स खाली पड़े हैं, नर्सिंग स्टाफ की कमी है। पिछली बार भी मैंने अपने वक्तव्य में यह बात कही थी, माननीय मंत्री महोदय से, लेकिन आज पुन: इस बात को दोहराना चाहूंगा कि उन पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए तब ही हमारी जनता को राहत मिल पाएगी।

(श्री खुशवीरसिंह)

इसके साथ में, मैं नये पी.एच.सी. सैंटर खोलने की भी बात करूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ विधान सभा क्षेत्र है। माननीय सभापति महोदय, मारवाड़ विधान सभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जो पाली जिले के अन्दर सबसे पिछड़ा क्षेत्र रहा है। बाकी सब जगह आप जैसे सक्षम व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने बहुत विकास कराया है, यह मैं कह सकता हूं लेकिन यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं चिरपटिया, फुलाद और कोट सोलंकियान के लिए पी.एच.सी. मांग करूंगा। कई सब सैंटर्स के लिए भी मैं मांग करूंगा। मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत ही शानदार जो एक काम करके दिखाया है, इस बजट में कि प्राइवेट हास्पिटल्स को दुर्घटना केस होने पर उन्हें भर्ती करना और इलाज करना कमप्लसरी होगा। यह देश के अन्दर दूसरा ऐसा कदम है माननीय सभापति महोदय, मुझे बचपन के वे दिन याद हैं, जब कोई दुर्घटना हो जाती थी तो सैकड़ों लोग निकल जाते थे और पास में वह व्यक्ति तड़प रहा होता था, लेकिन हाथ लगाने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता था, क्योंकि पुलिस के चक्कर काटने पड़ते और पुलिस सबसे पहले उसी व्यक्ति को पकड़ती कि तुमने बताया, तुम चलो पुलिस थाने के अन्दर। लेकिन मैं स्व. प्रधान मंत्री राजीव गांधीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा एक ऐसा निर्णय पारित किया कि कोई भी व्यक्ति उस तड़पते हुए व्यक्ति को हास्पिटल ले जा सकता है, पुलिस उसको पूछ नहीं सकती। दूसरा कदम हमारे मुख्य मंत्री गहलोत साहब ने उठाया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं किसानों की बात कहना चाहूंगा कि गहलोत साहब ने किसानों के लिए भी चिंता की है। अभी हमारे माननीय सदस्य, मेरे से पूर्व बोले हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि किसान की मृत्यु अगर सर्दी से हो जाती है और उस दायरे में नहीं आता, यह दुर्भाग्य है हमारा। किसान सर्दी में पानी दे रहा है, पिलाई कर रहा है और उस ठण्ड के अन्दर हम हीटर लगाकर गर्मी में बैठते हैं, रात को हीटर में सोते हैं। अगर किसान नंगे बदन ठण्ड में पानी दे रहा है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो मैं चाहूंगा उस किसान को कम से कम पांच लाख रुपये दिये जाएं, यह मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा और इस चीज की जो कमी है, उसको भी दूर किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी चाहूंगा कि आज मेरे पाली जिले के अन्दर बिजली में छह हजार की पैंडेंसी चल रही है, 2012 की पैंडेंसी

(श्री खुशवीरसिंह)

एग्रीकल्चर के कनेक्शन की चल रही है। मैं चाहूंगा कि सरकार उनके लिए सोलर की व्यवस्था करे। इससे मेंटीनेंस की समस्या समाप्त, कटिंग की समस्या समाप्त, बिजली कटौती की समस्या समाप्त हो जाएगी। सोलर पम्प दस घंटे तक पानी निकालता है तो क्यों नहीं सरकार सोलर में तब्दील करे।

माननीय सभापति महोदय, एक बात सुनने में आ रही है कि अब सरकार जो अनुदान बिलों के अन्दर दे रही है, वह अनुदान खातों में जाएगा। यह बात सबसे पहले किसके जेहन में निकली? इस बात को किसने छेड़ा है? मैं चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाए। ऐसी बात क्यों आ रही है? जब आपके किसान के बिजली के बिल में किसी तरह के भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है, उसके बावजूद यह बात कह रहे हैं कि खाते में जमा कराएंगे। एक खाते में दस लोगों के नाम हैं। मेरे खुद के जमीन है, मेरे बिजली का कनेक्शन है, वह मेरे नाम से नहीं है। मैं कहां-कहां चक्कर काटता रहूंगा। इसके लिए भी जो पूर्ववत् व्यवस्था है, वह लागू रहनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 'नो बैग डे' किया। यह वास्तव में कभी का हो जाना चाहिए था। मैं कहना चाहूंगा एक यह ऐसी कल्पना है और यह एक ही घटना ऐसी होगी कि इस प्रदेश के अन्दर क्रांति लेकर आ जाएगी। आज जो हालात बच्चों के हम देख रहे हैं, आज सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों का और अभिभावकों का सम्पर्क इस भौतिकवाद के अन्दर कट गया है। वे समय नहीं दे पा रहे हैं लेकिन यह व्यवस्था गहलोत साहब ने जो की है कि शनिवार के दिन अभिभावक भी वहां पहुंचेंगे। उन बच्चों के अन्दर प्रतिस्पर्धा की भावना होगी, आपस में लगाव होगा और कई नवाचार होंगे। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र एक विशेष भौगोलिक परिस्थिति पर बसा हुआ है। वह अरावली की तलहटी के अन्दर है। अरावली की तलहटी में हमारे ढलान अधिक होने से नदियों में बारिश का पानी बहकर चला जाता है। हम आंखों में मात्र पानी पटक सकते हैं लेकिन उस पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। मैं चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, पिछली बार 2003 में जब मैं बारहवीं विधान सभा में था, मैंने मेरे मेडन स्पीच में यह बात कही थी कि चम्बल का पानी लाना सम्भव है, ग्रेविटी से अरावली की तलहटी तक आ सकता है,

(श्री खुशवीरसिंह)

भीलवाड़ा होते हुए भीम और भीम से राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के समानांतर हमारी नदियों में पानी लाया जा सकता है। चम्बल का वह बाढ़ का पानी जो बाढ़ में बहकर बर्बाद हो जाता है, उस पानी को लाया जा सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे विधान सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय को, जब वे केन्द्रीय मंत्री रहे तो उस सपने को साकार करके भीलवाड़ा तक ले आये। अब गहलोत साहब ने यह बात कही कि भीम और देवगढ़ तक वह पानी आ सकता है। तो शायद नहर के लिए भी सर्वे करवा दिया जाए कि नहर से भी वह पानी हमारे अरावली तक पहुंच सकता है।

माननीय सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन पानी की दृष्टि से भौगोलिक परिस्थिति से बहुत विपरीत है। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जिन 16 जिलों के नाम लिए हैं, उनमें मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र एक ऐसा विधान सभा क्षेत्र है, जहां हम पानी की दृष्टि से बहुत पीछे हैं। वहां स्लाइन वाटर ज्यादा है, वहां फ्लोराइड अधिक है। मैं चाहूंगा कि जे.जे.एम. योजना के अन्दर और मुख्य मंत्री महोदय ने जिन 16 जिलों की घोषणा की, उसमें इसको शामिल करते हुए मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र को अधिक से अधिक बजट दें। इसके साथ ही एक सुझाव देना चाहूंगा कि जवाई पेयजल योजना, जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा और अभी हाल ही में मेरे विधायक चुनने के बाद में मुख्य मंत्री महोदय ने तृतीय चरण की स्वीकृति जारी कर दी और कार्य भी प्रारम्भ हो गया लेकिन तकनीकी तौर पर वह कमी रह गयी है क्योंकि अरावली की तलहटी में बसे हुए गांव हैं, वहां अरावली की तरफ पानी लिफ्ट किया जा रहा है तो वे पूरे के पूरे पाइप फट रहे हैं, विफल हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि उन्हें पुनः तब्दील करके अरावली के ऊपर की तरफ रिजर्व जोन बनाए जाएं, वहां से फिर ग्रेविटी से पानी गांवों में सप्लाई किया जाए तो यह सफल होगी, नहीं तो यह पूर्णत: विफल है। आज जो जवाई प्रोजेक्ट का पानी है, वह क्षेत्र में कहीं नहीं मिल पा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अब सड़कों की बात निवेदन करना चाहूंगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा और इस सदन में जो माननीय सदस्य विराजमान हैं, माननीय भरत सिंहजी, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। जब 2012-13 का बजट प्रस्तुत किया। आपने विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के दो महत्वपूर्ण राज्यीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग 61 और राज्यीय राजमार्ग 62 को स्वीकृति बजट के अन्दर जारी कर दी थी।

(श्री खुशवीरसिंह)

दुर्भाग्य है इस देश का, कि सरकार परिवर्तन होने के बाद में पिछली सरकार ने, हमारे जन-प्रतिनिधि कमजोर रहे और उन सड़कों को रिव्यू के नाम से बंद कर दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा आपसे मुझे विश्वास है कि आपके द्वारा स्वीकृत की गयी, और तत्कालीन हमारे पूर्व मंत्री और सदस्य विराजमान हैं, भरत सिंहजी, जब इन्होंने यह राज्यीय राजमार्ग स्वीकृत किये, माननीय सभापति महोदय, वे निरस्त हो गये तो मैं चाहूंगा कि एडी.बी. परियोजना के तहत इसमें राशि पड़ी हुई है। राज्यीय राजमार्ग 62, मुझे मालूम है 2016 में गडकरी साहब जब आये थे और इन्होंने आनन-फानन में दो बार घोषणा कर दी पाली में आकर, कि इसको राष्ट्रीय राजमार्ग बना दिया जाएगा और 15 दिन में कार्य प्रारम्भ हो जाएगा लेकिन वह कार्य तो नहीं हो पाया। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से चाहूंगा आपसे मेरी करबद्ध विनती है कि यह लाइफ लाइन कहने वाली जो मारवाड़ जंक्शन की सड़क है, इसकी स्वीकृति प्रदान कराएं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि पिछली बार काली घाटी की सड़क माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय ने स्वीकृत की थी। दुर्भाग्य इस बात का है कि उस सड़क से अब माइंस के 80 -80 टन के ट्रोले उतर रहे हैं और वह सड़क बनते ही टूटनी शुरू हो गयी है। उस सड़क की क्षमता 16 से 20 टन की है और 80 टन के ट्रोले उस पर चल रहे हैं, तो मैं परिवहन मंत्री महोदय से चाहूंगा कि सख्ती से इसको लागू किया जाए और ऐसे वाहनों को रोककर उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, दो महत्वपूर्ण बिन्दु हैं।

श्री सभापति: थोड़ा जल्दी कर दें आप।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, इसके लिए सबसे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सरकार को सुचारु रूप से चलाने के लिए आज हमारे रिक्त पद इतने हैं, चाहे किसी भी सरकारी विभाग को ले लें। आज पटवारियों की काफी कमी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं, बाहर जिले से पटवारी आ जाते हैं और वे दो-तीन महीने रहते हैं, फिर छोड़कर चले जाते हैं। वे एक ही स्थान पर अपना निवास स्थान कर लेते हैं।

(श्री खुशवीरसिंह)

गांवों में जब लोग पूछते हैं कि पटवारी साहब कहां हैं, तो साहब नाडोल में मिलेंगे, नारलाई में मिलेंगे। जब वे जाते हैं तो उनकी नकल देने की दरें दस-दस गुणा बढ़ जाती हैं। आज हमें जूझना पड़ रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा ऐसी व्यवस्था करें कि जितने भी रिक्त पद हैं, वे सभी भरे जाएं, चाहे वे किसी भी विभाग के हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उन लोगों का भी स्थायीकरण किया जाए। स्थायीकरण से ही कार्य सुचारु रूप से चलता है। नरेगा कम्प्यूटर आपरेटर, पैराटीचर्स, प्रेरक, एन.आर.एच.एम., रोजगार सहायक, विद्यार्थी मित्र, लेखा सहायक, आंगनबाड़ी और पोषाहार बनाने वाले... (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मुझे दो मिनट संरक्षण प्रदान करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें। जो मुद्दे की बात है, वह आप जल्दी कर दें।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि इस बार पर्यावरण नीति बनायी जाएगी। आपको मालूम है पर्यावरण नीति के लिए यह कितनी कठिन डगर है और कितना कठोर कदम है। इसके लिए आप और हम सब बहुत भली-भांति से जानते हैं। आज पाली के हालात और पाली की नदियों के क्या हालात हैं? आज पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है और पाली की फैक्ट्रियों में गीली लकड़ी जल रही है, आज बायलर्स उससे चल रहे हैं, कोयला नहीं मिल रहा है, गैस नहीं आ रही है। आज ये हालात हैं, उनके बारे में भी हमें सोचना होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस बार माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 'वन विकास निगम' का गठन किया है। माननीय सभापति महोदय, दो मिनट का संरक्षण दें। यह पूरे प्रदेश से सम्बन्धित इश्यु है। मैं निवेदन करना चाहूंगा मुख्य मंत्री महोदय से, यह जो 'वन विकास निगम' है, यह पूर्व में दो बार बन चुका है। यह मात्र आई.एफ.एस. को एडजस्ट करने के अलावा कुछ नहीं है। उनको यह भी मालूम नहीं है कि लघु वन उपज क्या चीज होती है, कैसे इसका विस्तार किया जाए, कैसे इसका प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके लिए मैं यह कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि इसके हालात वही हो जाएंगे जो 1980 के दशक के अन्दर अरावली

(श्री खुशवीरसिंह)

प्रोजेक्ट, जो जापान गवर्नमेंट ने दिया था, उसके पैसे किस चीज के लिए आये थे जबकि सभी विभाग वालों ने कम्प्यूटर खरीद लिये, गाड़ियां खरीद लीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिये, भर्तियां कर लीं, पर वृक्षारोपण नहीं हो पाया।

एक मिनट में मैं मेरी बात समाप्त करूंगा।

इसी तरह कैम्पा का जो गठन किया गया है यह एक महत्वपूर्ण चीज है। सभापति महोदय, कैम्पा के अन्दर मैंने एक प्रश्न किया, यह सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि क्या वन विभाग द्वारा करवाये गये एवं कराये जा रहे समस्त योजनाओं के समस्त वृक्षारोपण एवं परिसम्पत्तियों को भारत सरकार में ई-ग्रीन वाच पालिसी जी.पी.एस. कोआर्डिनेट पोर्टल पर डाटा अंकन के निर्देश दिये गये हैं? सभापति महोदय, यह क्या है? 2015 में यह आदेश दिया गया है कैम्पा के माध्यम से, लेकिन एक की भी पालना नहीं हुई। अगर पालना हो जाए तो उन अधिकारियों की पोल खुल जाए कि उनको अपडेट देना पड़ता है। आप और हम बैठे सैटेलाइट से देख सकते हैं कि उक्त वृक्षारोपण के अन्दर उस क्षेत्र में कितने वृक्ष जीवित हैं और कितने वृक्ष मर चुके हैं।

मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: अब आप बैठें। श्री बाबुलाल (झाड़ोल)।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): माननीय सभापति महोदय जी, आज बजट 2020-21 के इस वाद विवाद में सभी माननीय सदस्यों ने आलोचना-समालोचना, अपनी-अपनी बात पक्ष में और विपक्ष में कहने का प्रयास किया।

सभापति महोदय जी, मैंने भी इस बजट भाषण को कई बार पढ़ा। यह बजट भाषण की जो कापी है, बहुत सुन्दर है इसमें निरोगी राजस्थान प्रिंट करके हमको एक बहुत अच्छी अभिभाषण की प्रति दी। इसमें 242 बिन्दुओं पर और सात संकल्पों के साथ में प्रदेश की जनता को शब्द जाल में उलझाने का काम किया है। ऐसी कोई भी घोषणा या ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगी कि जिससे जनता जनार्दन का कुछ भला हो सकता है। मैंने पूरा प्रयास किया कि पढ़ करके कुछ निकाल पाऊं लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं।

सभापति महोदय जी, हमारे उप नेता, प्रतिपक्ष ने जो चिंता व्यक्त की, आपने कई बिन्दुओं पर सवाल खड़े किये हैं, वास्तव में सत्य है। अभी

(श्री बाबुलाल)

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि केन्द्र सरकार से हमको जो बजट मिलना चाहिए था, हमारे हक का पैसा नहीं मिल रहा। मैं कहना चाहूंगा कि हम एक कहावत कहते हैं कि 'नाच न जाने-आंगन टेढ़ा'। केन्द्र सरकार में जो हमारे हक का पैसा है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन जो दिया है, आप उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र तो दो कि हमने यह उपयोग कर लिया, यहां कर लिया। इसके बाद आप मांगोगे तो वह देने वाला आपको कभी भी मना नहीं करेगा। आप मांगते रहेंगे, काम करेंगे नहीं, तो बिना हिसाब का कोई साहूकार भी हमको उधार नहीं देता है, न पैसा देता है।

सभापति महोदय जी, बजट भाषण में यह आर्थिक समीक्षा है। इसको भी मैंने पढ़ा है। इसमें कई बिन्दु हैं, सारे बिन्दुओं पर तो मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन कुछ में कहूंगा। आपने निरोगी राजस्थान की बात कही है, आपने कहा कि हम पूरे राजस्थान को निरोगी कर देंगे, अब बिल्कुल कोई बीमार नहीं होगा। लेकिन जमीनी स्तर पर क्या हालत है, इसको भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए।

काफी माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात कहता हूं। आपने हास्पिटल खोले, वहां बिखरी हुई आबादी है, दूर-दूर तक गांव बसे हुए हैं, हास्पिटल्स की संख्या कम है। आपके नियम कुछ भी होंगे, लेकिन जहां बिखरी हुई आबादी है उन क्षेत्रों के लिए नियमों में शिथिलता देते हुए आप नये हास्पिटल भी खोलें। इसी के तहत मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे झाड़ोल में लम्बे समय से लोगों की मांग आ रही है कि यहां हास्पिटल खोलो, हमारे काफी दूर पड़ता है, हम जा नहीं पाते हैं। इस कारण से अकाल मौत भी हो जाती है, दुर्घटना होती है तो उनको जो प्राथमिक उपचार मिलना चाहिए, वह मिल नहीं पाता है। बागपुरा में, ऐसे ही हमारे थोबावाड़ा में, ऐसे ही डैया काफी दूर है, गुजरात से लगता हुआ, वे लोग गुजरात जाकर इलाज कराते हैं, ऐसे ही कोटडा में झूंड़ा का क्षेत्र है।

सभापति महोदय जी, हास्पिटल्स हैं। आपने दवाइयां फ्री कर दीं। अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं, होना चाहिए, अगर गरीब आदमी को मुफ्त में एक गोली भी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं गरीब घर का रहने वाला हूं, गरीबी को जानता हूं। उसके पास पैसा नहीं होता है। वह इलाज भी कराना चाहता है लेकिन वह रोता है कि मैं पैसा कहां से लाऊं। अच्छी बात है,

(श्री बाबुलाल)

लेकिन उन हास्पिटल्स की हालत क्या है, उनमें पर्ची लिखने वाला डाक्टर नहीं है, उन दवाइयों का क्या करेंगे? इसका जवाब भी मुख्य मंत्री दें।

मैं आपके सामने झाड़ोल की जो स्थिति है वह बताना चाहूंगा। झाड़ोल हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। उसमें एक भी डाक्टर नहीं है, 10 की पोस्टिंग है, और 10 के 10 खाली हैं, दो की प्रतिनियुक्ति कर रखी है। अब ये हास्पिटल्स कैसे चलेंगे, वहां की जनता कैसे दवाइयों का लाभ लेगी? इसी प्रकार से ओगणा में 5 की पोस्ट है, तीन कार्यरत हैं और दो खाली हैं। ऐसे ही कोटड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, चार हैं और चारों में से चारों ही खाली हैं। ऐसे एक-एक की गिनती करूंगा तो बहुत लम्बा समय हो जाएगा, स्थिति यह है। इसलिए मैं चाहूंगा वहां हम कम से कम रिक्त पदों को भरने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जनता जनार्दन को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा।

आगे चलकर के आपने कहा, किसानों के विषय में हम सुनते-सुनते ऐसे हो गये कि कब तक सुनेंगे किसानों के लिए, किसानों का हम भला कर देंगे, किसानों को ऊपर उठा देंगे, किसानों को अब समस्या नहीं रहेगी, यह बातें तो हम सुनते ही आये हैं। अब आपने किसानों की चिंता खुद की है। बजट में आपने एक हजार करोड़ रुपये के कृषक कल्याण कोष की स्थापना की, अच्छी बात है। 13 तारीख को आपका बजट पास हो जाएगा, वित्त विधेयक पास हो जाए उसके भी बाद में आप जादू का डंडा घुमाएंगे और राजस्थान के किसानों का भविष्य बदल जाएगा, किसान का जीवन स्तर ऊपर उठ जाएगा। कैसे सम्भव है, आज तक तो आपने किया नहीं। बहुत लम्बे समय तक राजस्थान की धरती पर, हिन्दुस्तान की धरती पर आप लोगों ने, हिन्दुस्तान की जनता ने, राजस्थान की जनता ने आपके हाथ में सत्ता सौंपी, फिर भी आज हम किसानों के लिए यह चर्चा करते हैं, किसानों का आज कुछ हुआ नहीं।

केन्द्र सरकार ने योजना बनाकर, चाहे अटलजी हों, चाहे मोदी जी की सरकार हो, किसान को ऊपर उठाने के लिए, किसान का जीवन स्तर ऊपर उठे, किसान की जो फसल है उसका उसको उचित मूल्य मिले, उचित दाम मिले, इसका प्रबंध करके उस किसान को ऊपर उठाने का काम किया है।

सभापति महोदय जी, कुछ जिक्र मैं आपकी आर्थिक समीक्षा को लेकर करूंगा। आप लोगों में एक कला है, अगर पिछली सरकार ने जनता जनार्दन के लिए, उनके भले के लिए कोई योजना बनायी है, उसको हम बंद

(श्री बाबुलाल)

कर देंगे, या तो उसका नाम बदल देंगे। हमें कोई तकलीफ नहीं, आप नाम बदल दो, कुछ भी करो, लेकिन योजना तो चालू रखो। गुरु गोलवलकर योजना है, बहुत अच्छी योजना है। जनता के सहयोग से आप परिसम्पत्तियों का निर्माण करेंगे। 90 परसेंट सरकार का हिस्सा होगा 10 परसेंट जनता जनार्दन देगी। उनकी भागीदारी से वहां जनता जो भी चाहेगी उन परिसम्पत्तियों का निर्माण करेगी, लेकिन आपने इसको बंद कर दिया। एक माननीय सदस्य ने तो यह कहा कि गोलवलकर कौन है, मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि गोलवलकर आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए तो आपको संघ की शाखा में जाना पड़ेगा तब जाकर आपको समझ में आएगा गुरु गोलवलकर कौन है। वे हिन्दुस्तान की आत्मा थे, प्रखर राष्ट्रवादी थे।

सभापति महोदय जी, अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर हमारा विभाग यह काम करता है, उस विभाग की स्थिति क्या है। जनजाति क्षेत्र में केन्द्र प्रवर्तित योजना और राज्य मद में बजट कितना मिला, 639.64 करोड़ रुपये। आपने उसमें से व्यय कितना किया, आपने मात्र 287.99 करोड़ रुपये व्यय किये। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह बजट क्या केवल दिखावे के लिए है? यह तो हमें बताएं। अब आपका यह सत्र खतम हो रहा है। इस बजट का आपने कोई उपयोग नहीं किया।

सभापति महोदय, एक-एक योजना का मैं आपसे जिक्र करुं, आपने गाय, भैंस, बकरी देने का काम किया था। इसमें आपका लक्ष्य 2 हजार का था और आपकी उपलब्धि 218 रही। व्यक्तिगत पम्प सैट से वहां का आदिवासी अपने खेतों की पिलाई कर सकता है। इसी से उसका जीवन स्तर उठेगा। लेकिन आपने पम्प सैट दिये ही नहीं। आपने जो लक्ष्य रखा था, वह 215 रखा था। उस उप योजना क्षेत्र में कितने लोग हैं? इतने ही लोग रहते हैं क्या? क्या यह आप बढ़ा नहीं सकते? इसका एरिया बढ़ा नहीं सकते? इसका पैसा बढ़ा नहीं सकते? क्या उनका हक इन पैसों पर नहीं है? लेकिन आपके 215 के लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि 2 रही है। इसमें जो आपने खर्चा किया है, 21.50 लाख का लक्ष्य था और इसमें से 0.20 लाख खर्च किया है। अब यह कहां का विकास है?

सभापति महोदय, मैं अगर एक-एक विषय का कहूंगा तो ऐसा लगता है कि आपने केवल दिखावे का बजट हमारे सामने रखा है। इसी तरह से

(श्री बाबुलाल)

जनजातीय क्षेत्र के प्रतिभावान छात्रों की छात्रवृत्ति, इसमें 4,223 का लक्ष्य था और आपने एक रुपया खर्च नहीं किया। आप इससे क्या बताना चाहते हो? आप कम से कम यह तो बताएं कि हमने कुछ उपलब्धि प्राप्त की है। हमने कुछ किया है। आपने किया क्या है जो आप वाहवाही लूटने का काम करते हो?

सभापति महोदय, इसमें एक चीज में आपने पूरा का पूरा 100 प्रतिशत खर्च किया है। इसमें मुझे संदेह है इसलिए कहना चाहता हूं। यह कथौड़ी, सहरिया जनजाति के लिए नि:शुल्क घी, दाल, तेल आदि का वितरण है। इसमें आपने 100 परसेंट खर्चा किया है। अब यह वास्तव में हुआ है कि नहीं हुआ है, जब वहां जाकर के देखेंगे तो पता चलेगा। उनको मिला भी है कि नहीं मिला है? इसमें 1,21,237 का लक्ष्य था और इतना ही आपने खर्च कर दिया। इसी प्रकार से एक और है खैरवा जनजाति के व्यक्तियों के लिए, इसमें भी दाल, घी सब यही है। इसमें भी 21,411, यह भी पूरा का पूरा खर्च किया है। जब आप जवाब दें तो बताएं कि इसको वास्तव में खर्च किया है या केवल कागजों में ही दिखाने का काम किया है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से कृषि, पशुपालन और उद्यानिकी विकास कार्यक्रम में 1,45,870 का लक्ष्य था और खर्चा निल है। इस बजट में क्या है? हम क्या बताना चाहते हैं? आप वाहवाही तो लूट रहे हैं लेकिन क्या हमें बताने का प्रयास करेंगे कि क्या किया है?

सभापति महोदय, मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बातें कहना चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): थोड़ा सा ही कहकर के खतम कर देता हूं।

श्री सभापति: थोड़ा-सा नहीं, अब एक मिनट में ही अपनी बात को आप समेट लें।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): अगर आप 2 मिनट देंगे तो मैं कुछ कह पाऊंगा। आदिवासी क्षेत्र से हूं।

सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्कूल तो भारतीय जनता पार्टी के राज में खूब खुल गये। कुछ माध्यमिक खुले, उच्च माध्यमिक खुले, प्राथमिक भी खुले। आपने कहा कि बंद करने का काम किया। जहां आवश्यकता नहीं हो, और हम केवल सरकार का खर्चा करते

(श्री बाबुलाल)

रहें, यह भी ठीक नहीं है। जहां आवश्यकता हो, वहां खुलने चाहिए। हमने खोले भी हैं।

सभापति महोदय, विद्यालय भवनों की क्या स्थिति है? पिछली बार भी मैंने कहा था कि वहां के भवन जर्जर हालत में हैं। वहां पुराने भवन हैं। बरसात में खैरवाड़ा स्थित एक स्कूल का भवन गिर गया था। उसमें दो बच्चों की मौत हो गयी थी। मैं चाहूंगा कि वहां आप नये भवनों का निर्माण कराएं। कोटड़ा में तथा अन्य जगहों पर भी ऐसे विद्यालय भवन हैं जो खपरैल के हैं। वे अंग्रेजों के समय के बने हुए भवन हैं। उनमें आज भी विद्यालय चल रहे हैं। आप यह बताएं कि उन विद्यालयों में कैसे बालक पढ़ेंगे? विद्यालय भवनों के साथ ही वहां अध्यापकों की कमी है। मैं शोर्ट में ही कह रहा हूं। एक अध्यापक से ही विद्यालय चल रहे हैं। वहां पर बच्चा क्या पढ़ेगा? पहले तो हम उन आवश्यकताओं की पूर्ति करें। जहां स्टाफ नहीं है, वहां हम लगाएं।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कह देता हूं, एक कुसुम योजना है। उस योजना में 30 परसेंट केन्द्र सरकार का, 30 परसेंट राज्य का और 30 परसेंट हम नाबार्ड से लोन ले करके काश्तकारों को सोलर ऊर्जा से कृषि कनेक्शन देंगे। आपकी बिजली का जो व्यय होता है, वह नहीं होगा। आपने पिछले बजट में यह कहा था कि हम कुसुम योजना के अन्तर्गत किसानों को सोलर ऊर्जा से कृषि कनेक्शन देंगे। लेकिन आपने एक भी नहीं दिया। इससे आप क्या बताना चाहते हैं?

सभापति महोदय, खेल की बात बहुत हुई। उस क्षेत्र से लिम्बाराम जैसे अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी ने ख्याति प्राप्त की। उसने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया। वहां प्रतिभाएं हैं लेकिन खेल छात्रावास नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि जब मुख्य मंत्रीजी अपना रिप्लाई दें तो झाड़ोल में एक खेल छात्रावास भी खोलें तो अच्छा होगा। सभापति महोदय, इस बजट का मैं विरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव): सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस विधान सभा में 20 तारीख को 2020-21 के लिए जो बजट पेश किया, उसका समर्थन करते हुए मेरी बात कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, कुल मिलाकर ये जो आंकड़ों के कारीगर, होशियार आदमी हैं और अपने-अपने दल के हिसाब से कुछ हिसाब रखना चाहते हैं,

(श्री अमीन खां)

काबू रखना चाहते हैं, वे तो अलग-अलग बात कहते हैं, लेकिन स्टेट और देश के सियासी हालात किसी से छिपे हुए नहीं हैं। इस वक्त केन्द्र राज्य का असहयोग कर रहा है। इस असहयोग में मुख्य मंत्री ने बड़ी समझदारी से और अच्छे सलाहकारों से सलाह लेकर बजट पेश किया है। यह तारीफ के लायक है। इससे ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं थी।

सभापति महोदय, मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूं कि बजट में इन्होंने जितनी भी बातें कही हैं, उससे पता चलता है कि वे आम पब्लिक और पीड़ित इंसान को भूले नहीं हैं। दिल्ली में एक प्राइवेट हास्पिटल था। जिसमें लीवर बदलने के इलाज की व्यवस्था थी। पहली बार राजस्थान के सवाई मानसिंह अस्पताल में लीवर बदलने का इंतजाम हुआ। इसका एक सफल आपरेशन हुआ। स्टेट के मुख्य मंत्री इसके लिए तारीफ के लायक हैं धन्यवाद के पात्र हैं। यह वह खतरनाक रोग है जिसका नाम सुनकर ही इंसान अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। उससे बचाव करना रहमी इंसान का काम है। इसके साथ ही कैंसर की बीमारी भी एक खतरनाक बीमारी है। आधुनिक जमाने में डी.ए.पी., यूरिया, कैमिकल्स, गंदे नाले के पानी से जो फसलें, सब्जियां पैदा होती हैं, उससे खतरनाक रोग पैदा होते हैं। इन खतरनाक रोगों के लिए भी एस.एम.एस. और जोधपुर के मथुरादास हास्पिटल में बजट में शानदार इन्तजाम करके आधुनिक और अच्छे काबिल डाक्टरों को रखा जा रहा है जिससे गरीब इंसान मौत के घाट उतरने से बच सकता है। यह एक बहुत बड़ी रहम की आदत है, उसका हम अशोकजी गहलोत को धन्यवाद देते हैं।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही साथ मैं लम्बी बात कहने का आदी नहीं हूं, यह कहना चाहूंगा कि इंसान को कुछ दिमाग सहन करने का रखना चाहिए और कुछ अपनी बात समझदारी और दिमाग की ताकत से मजबूती से रखनी चाहिए। कांग्रेस वाले जब उधर बैठते हैं तो कहते हैं कि बी.जे.पी. ने रूला दिया, बी.जे.पी. वाले उधर बैठ गये तो सारी तकलीफ बता रहे हैं। मैं बैठा-बैठा सुन रहा हूं। राजसमन्द में कुछ नहीं उदयपुर में कुछ नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं, मेडिकल में कुछ नहीं, साहब, आप पांच साल कहां गये थे। वह पूरा इंतजाम करके ही जाते तो आपको यह कहने की गुंजाइश नहीं बचती। फिर हम रोते कि इन्होंने अपने-अपने एरिये में बहुत शानदार विकास कर दिया और हमको पीछे छोड़ दिया। ये गलत बातें करना, देश की पार्लियामेंट में या किसी स्टेट की असेम्बली में सही नहीं है। हम लाखों

(श्री अमीन खां)

आदमियों की नुमाइंदगी करने पहुंचे हैं। अपन एक दूसरे को फंसाने के लिए यहां नहीं आये हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए यहां नहीं आये हैं। अपन आये हैं ईमानदारी और देशभक्ति, मजबूत राष्ट्र और मजबूत स्टेट रहे, कमजोर से कमजोर इंसान को सफलता दिलाओ, यह राज्य का और जनता के नुमाइंदों का असली काम है।

माननीय सभापति महोदय, आप और हम सब जानते हैं कि इंसान सिवाय पढ़ाई के सबल नहीं हो सकता, और पढ़ाई पर बी.जे.पी. की गवर्नमेंट ने, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, प्राइवेट सैक्टर को खूब छूट दे रखी है। हम गरीब तबके के लोग इसके खिलाफ हैं। मालदार आदमी, पैसे वाले आदमी, दो नम्बर का धंधा करने वाले आदमी तो उन स्कूलों, कालेजों के जरिये और प्राइवेट कोचिंग की जरिये सक्षम हो जाएंगे। जहां गरीब क्षेत्र है, जहां सदियों से अनपढ़ लोग रहे हैं, उन स्कूलों में 50 परसेंट मास्टर मौजूद नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह तो अच्छा कर रखा है कि राजस्थान निरोगी काया लेकिन आज के हालात में किसी भी जिले में सब सैंटर 50 परसेंट से ज्यादा भरे हुए नहीं हैं। पी.एच.सी. और सी.एच.सी. को देखो तो वहां डाक्टर 50 परसेंट से ज्यादा नहीं हैं। मेरे क्षेत्र में चार पी.एच.सी. ऐसे हैं, जहां पर न कोई डाक्टर है, न कोई कम्पाउण्डर है और न कोई नर्स है, तो इस हालत में हम 'निरोगी काया' किस तरह से कामयाब करेंगे। कम से कम एक नर्स की पोस्ट जहां पर है वहां पर वह अबेर-सबेर होनी ही चाहिए। उस मरीज की बात तो सुनने वाला वहां कोई इंसान हो। पी.एच.सी. जहां खुलता है वहां पर कम से कम एक डाक्टर रहना चाहिए ताकि मरीज की बात तो सुने। खोलने के वक्त भी यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास बजट कितना है, उससे ज्यादा इकाई खोलो ही मत। यह हम हमारी बात कहना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अभी मैंने कृषि मंत्रीजी से बात की। मैंने कहा कि मंत्रीजी, पशुपालन का देखें तो सबसे ज्यादा पशुपालक पश्चिमी राजस्थान में हैं। पश्चिमी राजस्थान में जिस एरिये से मैं आता हूं, वहां सबसे ज्यादा पशुपालक रहते हैं। हमारे उस इलाके में हमारे दादे-परदादे, साल में घर में एक बोरी बाजरी बापरते थे, यह कोई नहीं मानेगा, साल में पूरे घर में एक बोरी बाजरी काफी थी। नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी, ये साल में ढाई सौ ग्राम भी बाजार में जाकर नहीं खरीदते थे। ऐसे हजारों परिवार थे। उसके पीछे कारण

(श्री अमीन खां)

था पशुओं का, लोग दही पीते थे भूख लगती थी तो दूध पी लेते थे, साण्डियों का दूध पी लेते और बाजरी का मुट्ठी भर दाळा, दाल दूध में, घी में पी लेते, पूरे दिन की उनकी खुराक पूरी हो जाती।

आज उस पशुपालक एरिये के, जिस तरह से जमाना है, वे पशु खतम हो गये। एक तो चाइना का बाजार में ये रेडीमेड सामान पता नहीं कैसा आने लगा है। हमारे यहां भेड़ की ऊन 150 रुपये किलो बिकती थी, आज भेड़ की ऊन के 15 रुपये नहीं मिलते। तो अब भेड़ कौन रखेगा क्योंकि उस भेड़ में गुजारा ही नहीं होगा। भेड़ तो अभी भी लोग रख रहे हैं, आर्मी की वजह से क्योंकि आर्मी के ठेकेदार ज्यादा बकरे मीट के लिए नहीं खरीदते हैं, भेटा खरीदते हैं, उस भेटे की खरीद की वजह से कुछ लोग भेड़ रखते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अब गाय है, गाय तो इंसान को सब कुछ, तंदरुस्त रखने में, आर्थिक हालात में मदद करने और छाछ व दूध का अच्छा इंतजाम करने में इंसान का एक सहायक थी लेकिन अब गाय खतम हो रही है। खतम एक तो पुराने जमाने में चाहे हिन्दू थे या मुसलमान थे, हम लोग साथ ही रहते थे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आठ बजे तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय आठ बजे तक बढ़ाया जाता है।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अमीन खां (शिव): माननीय सभापति महोदय, गाय की असली नस्ल हो और असली नस्ल के सिवाय कोई भी, कोई भी आदमी भागी गाय घर में रखना नहीं चाहता। पर असली नस्ल के लिए पूरे गांव में, पूरी गायों में बढ़िया दुधारू गाय, बढ़िया शक्ल-सूरत की गाय, उस गाय के बछड़े को अलग

(श्री अमीन खां)

रखते थे। बाकी जितने भी बछड़े होते थे उन सबको बधिया करते थे, ताकि गाय की नस्ल कोई खराब पैदा न हो जाए। आज बछड़े को कोई बधिया करेगा तो गौवंश काटने का जुर्म हो जाएगा, वह आदमी जेल जाएगा तो अब कौन बधिया करे? मैं यह चाहता हूं कि कुदरत ने इस जमीन और आसमान के बीच में जितने भी जीव-जंतु पैदा किये हैं उनमें सबसे ज्यादा कीमती जीव इंसान है, इंसान से बाकी सब जीव परे हैं। बाकी जितनी भी चीजें कुदरत ने पैदा की हैं वे इंसान की शोहरत के लिए ही पैदा की हैं, तो जब अपन औरत की नसबंदी करा सकते हैं, जब अपन मर्द की नसबंदी करा सकते हैं तो गाय के बछड़े की नसबंदी करना कौनसा बड़ा पाप हो गया? हां, उसको काटना पाप है उसको किसी को खिलाना पाप है, लेकिन एक असली गाय, जिससे आर्थिक हालात पशुपालक के सुधरें उसमें यह होना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री अमीन खां (शिव): माननीय सभापति महोदय, कृषि मंत्रीजी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी आधुनिक युग है। आप भी काश्तकार आदमी हैं, आप मेहरबानी करके इस आधुनिक युग की दवाई लाओ। अच्छा सांड बचे, रद्दी सांड न रहे और गाय के पेट में बछड़ा पैदा ही न हो बछड़ी पैदा कराएं तो गाय की नस्ल कुछ दिन रहेगी। मेरी 81 साल उम्र हो गयी है, मैं डाक्टरों से पूछता हूं तो वे मुझे सलाह देते हैं कि भैंस का घी तो मत खाना, आपको नुकसान हो जाएगा, गाय का असली घी अगर आपके घर में हो तो रोजाना तो नहीं, चार-पांच दिन में एक बार खा लीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। जय हिन्द। धन्यवाद।

(17.00 बजे)

श्री सभापति: श्री गोपी चन्द मीणा।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट भाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इस हेतु धन्यवाद। आपके माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र जहाजपुर के अन्तर्गत नेशनल हाईवे 148-डी उप खण्ड मुख्यालय के मध्य से गुजरता है। भारी वाहनों की गहमागहमी के चलते दिन-प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सामुदायिक चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र, जहाजपुर में संसाधनों का अभाव है एवं पूरे क्षेत्र में चिकित्सकों एवं ए.एन.एम. जी.एन.एम. के अधिकांश

(श्री गोपी चन्द मीणा)

पद रिक्त हैं। अत: मैं माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि रिक्त पदों को भरते हुए ट्रोमा सैंटर खोला जाए तथा अमरगढ़ सब-सेंटर को क्रमोन्नत करते हुए पीएच.सी. में तब्दील किया जाए ताकि दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों का समय पर इलाज हो सके।

माननीय सभापति महोदय, संसाधनों के अभाव में चिकित्सा विभाग में 108 एम्बुलेंस नाकारा पड़ी हुई हैं। कुछ दिन पहले सीएच.सी., जहाजपुर में प्रसव के दौरान निर्धन परिवार की महिला की मौत डाक्टर की लापरवाही से हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से उक्त महिला के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता राशि प्रदान किये जाने की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के महाविद्यालय के अन्तर्गत एवं उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय में प्रोफेसर, व्याख्याता एवं विषय अध्यापकों के पद सहित स्टाफ के अन्य कार्मिकों के पद लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं। उन पर नियुक्ति करते हुए राजनीतिक, द्वेषतापूर्ण जातिगत आधार पर बड़ी संख्या में तबादले किये गये। उन तबादलों को निरस्त किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, जहाजपुर मुख्यालय पर महाविद्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु राशि का आबंटन किया जाए। साथ ही नामांकन के आधार पर राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरसिया; राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गड़बोडिया व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, आगरिया के तहसील कोटड़ी के विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाए। साथ ही उप खण्ड मुख्यालय कोटड़ी में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने की महती आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षकों की राजकीय विद्यालयों में नियुक्ति नहीं होने से विद्यार्थियों को आई.टी. क्षेत्र की प्रथम पंक्ति का ज्ञान भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, कानून-व्यवस्था की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए बताना चाहूंगा कि प्रदेश की कानूनव्यवस्था लचर अवस्था में है। चोरी, डकैती, अपहरण, महिला अत्याचार व भ्रष्टाचार का खुला खेल दिन-प्रतिदिन देखने-सुनने को मिल रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के अन्तर्गत पुलिस कार्मिक मूल ध्येय से भटक कर बजरी, शराब एवं आकंठ

(श्री गोपी चन्द मीणा)

भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पुलिस अधिकारी कार्यवाही के नाम पर खानापूर्ति करते हुए समय व्यतीत करते हैं। अपराधी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ खुले में सार्वजनिक रूप से मंच साझा करते हैं। मेरे द्वारा विधान सभा में इस विषय को रखा जाता है तो हमें अवगत कराया जाता है कि अभी जांच चल रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करता हूं कि प्रदेश के अन्तर्गत पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत के चलते अवैध बजरी खनन रुकने के विपरीत फल-फूल रहा है। सरकार द्वारा मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत बनास नदी के किनारे पर खातेदारों की निजी जमीन पर बजरी की उपलब्धता नहीं होने के उपरांत भी लीजों का अवैध आबंटन कर बजरी माफिया को अवैध खनन करने का खुला अवसर प्रदान कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को तो राजस्व की हानि हो ही रही है, दूसरी ओर अवैध बजरी खननकर्ताओं को खुली छूट दे रखी है। अत: जनहित में बजरी की अवैध लीजों का आबंटन रद्द किया जाए।

(17.05 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति-जनजाति के 2017-19 ओर 2019-20 में जो प्रकरण बढ़े हैं, तुलनात्मक एवं निस्तारण स्थिति का अध्ययन करने पर ध्यान में आता है कि अनुसूचित जाति पर अत्याचार सम्बन्धी दर्ज प्रकरणों, जैसे हत्या, गम्भीर चोट, दुष्कर्म, बलात्कार, गम्भीर क्षति, एस.सी.-एस.टी. एक्ट एवं अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमों में एस.सी. में कुल 47.47 प्रतिशत की वृद्धि एक साल में हुई है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार सम्बन्धी दर्ज प्रकरणों में 64.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उक्त वृद्धि कानून-व्यवस्था की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन का ध्येय वाक्य, 'आमजन में विश्वास-अपराधियों में डर', इसका बिलकुल उल्टा ही क्षेत्र में चरितार्थ हो रहा है। यह कांग्रेसी शासन के मुखौटे को चरितार्थ करता है।

मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत सोप स्टोन एवं मार्बल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। किंतु सरकार द्वारा स्थानीय स्तर पर लघु उद्योगों को स्वीकृति प्रदान नहीं किये जाने से सारा का सारा रॉ-मैटेरियल बाहर जा रहा है और बाहर से तैयार होकर पुन: राजस्थान में ही बेचा जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप बाहरी उद्योगपतियों को भारी मुनाफा हो रहा है। अत: निवेदन है कि स्थानीय स्तर

(श्री गोपी चन्द मीणा)

पर लघु उद्योगों की स्थापना की जाए। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कच्चे उत्पाद की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के चलते इस्पात कारखाना खोले जाने की सम्भावना सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा जहाजपुर तहसील एक जनजातीय बहुल क्षेत्र है। आपके माध्यम से मैं सदन के नेता से निवेदन करना चाहता हूं कि जहाजपुर में 52 प्रतिशत जनजाति समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो कि आर्थिक रूप से सम्पन्न नहीं हैं। अत: सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एकलव्य माडल रेजीडेंशल विद्यालय खोला जाए। ग्राम पंचायत गुढ़ा में जमीन पर्याप्त है। इसी तरह बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका छात्रावास सरसिया, लुहारिकला व ईटूनंदा में राजकीय बालिका छात्रावास खोलकर एक सार्थक प्रयास करना चाहिए ताकि गरीब तबके के लोगों को शिक्षा से जुड़ने का अवसर मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, बनास नदी व अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य राजा जन्मेजय की नगरी जहाजपुर के अन्तर्गत हाल ही में माताजी श्री स्वस्ति भूषण के तप, भक्ति व शक्ति से जैन समाज के भगवान बीसवें तीर्थंकर अवतार मुनिसुव्रतनाथ जिनबिम्ब भगवान की सुन्दर प्रतिमा भूगर्भ से प्रकट हुई है, जिसकी स्थापना स्वस्ति धाम में विशाल जहाजनुमा मंदिर में की गयी है।

इसके अतिरिक्त धारा नगरी दौड़ में महादेव जी का अति प्राचीन स्थान, अति प्राचीन माता घाटारानी का शक्तिपीठ मंदिर, विश्व में एकमात्र रूठी रानी का महल, अति प्राचीन मांगट देव का स्थान, गाडैली स्थित महादेव मंदिर व बैरीखान स्थित प्राकृतिक महादेव मंदिर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अत: उक्त स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की महती आवश्यकता है, जिसके परिणामस्वरूप सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार की बिजली नीति की ओर इंगित करते हुए बताना चाहता हूं कि सरकार ने बिजली की दरों में इजाफा कर मध्यम वर्ग पर भार डाल दिया है। जबकि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी, जिसके द्वारा आम जनमानस को बिजली का करंट लगे। किंतु सरकार इस वादे के साथ सत्ता में आयी कि

(श्री गोपी चन्द मीणा)

हमारे द्वारा बिजली की दरों में इजाफा किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। मैं अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के अन्तर्गत अतिवृष्टि के परिणामस्वरूप किसानों की फसलें नष्ट हो गयीं।

इस प्राकृतिक आपदा के क्षण में राज्य सरकार को चाहिए था कि किसानों के बिजली के बिल माफ हों, किंतु इसके उलट किसानों से अवैध वसूली के नाम पर उनकी वी.सी.आर. भरी जा रही है। शामिल काश्तकार जो पांच-पांच भाई हैं, उनका शामिल कुआं है, उनके लोड के नाम वी.सी.आर. बनायी जा रही है, जबकि ओसरे के आधार पर वे दिन निकालते हैं। एक कुएं में पांच मोटरें पड़ी हैं तो एक कनेक्शन है, 5 एच.पी. का, और जब नम्बर आता है, तब वह मोटर चलाता है लेकिन मोटर पड़ी रहने के कारण लोड सैंटिग के नाम पर विभाग उनकी वी.सी.आर. बना रहा है।

माननीय सभापति महोदय, 'तू डाल-डाल, मैं पात-पात' की कहावत सार्वजनिक निर्माण विभाग में मेरे क्षेत्र में परिलक्षित कर दी गयी है। राज्य सरकार में परिवर्तन के साथ ही जिले के डी.एम.एफ.टी. फण्ड को किसी की नजर लग गयी।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): जनता द्वारा निर्वाचित जन प्रतिनिधियों द्वारा विकास कार्यों के प्रस्ताव भिजवाये गये हैं। बहुत सारे प्रस्ताव पैंडिंग हैं। एम.डी.आर.-56- रोपा से कोटाज सड़क, रावतखेड़ा से घाटारानी सड़क, सरसिया से मेड़िया सड़क, जामोली से भरी कला सड़क, खजूरी से बाकरा-टीटोड़ा-जागीर सड़क, पिपलून्द व खजूरी बाइपास सड़क, कोटड़ी बाइपास सड़क।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी। कनक्लूड करें आप।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, सरकार की आबकारी नीति की ओर इंगित करते हुए बताना चाहूंगा कि पूर्व मुख्य मंत्री महोदया माननीय वसुन्धरा राजे ने 2004 में जो छोटे-छोटे व्यापारियों व शराब की दुकान पर कार्य करने वाले सेल्समैन के साथ ही अन्य गरीबों को भी रोजगार उपलब्ध कराने की मंशा से बहूद्देशीय आबकारी नीति लागू कर एक साहसिक कार्य किया था, जिसे वर्तमान सरकार ने नीतिगत बदलाव करते हुए खतम करने का कुत्सित प्रयास किया है।

श्री सभापति: कनक्लूड करें, माननीय सदस्य।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): सरकार की आबकारी नीति को देखते हुए लग रहा है कि कुछ दिन पहले सरकार ने शराबबन्दी का नाटक जनता को गुमराह करने के लिए किया था। करोड़ों रुपये का लक्ष्य बढ़ाकर प्रदेश की गरीब जनता पर भार बढ़ाया जा रहा है।

श्री सभापति: श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी। विराजिए-विराजिए।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री महोदय ने वित्तीय वर्ष 2020-21 का जो बजट सदन में प्रस्तुत किया, वह प्रदेश के समग्र विकास के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से और समाज के सभी वर्गों, किसानों, पशुपालकों, महिलाओं, छात्रों, युवाओं, औद्योगिक-व्यापारिक संगठनों, सिविल सोसायटियों के सुझावों और विचारों को ध्यान में रखते हुए भरपूर लाभ और खुशियां बांटने वाला यह बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन, कि मेरी यह प्रबल कामना है कि मैं प्रत्येक देशवासी के आसूं पोंछ सकूं, इस पवित्र उद्देश्य से भी कहीं आगे बढ़कर मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में प्रदेशवासियों के लिए व्यवस्थाएं की हैं। मेरे हिसाब से यह बजट शानदार है, यह बजट जानदार है, यह बजट वजनदार है, यह बजट मजेदार है, यह बजट दमदार है, यह बजट राजस्थान की जनता के विकास में असरदार है और हमारा मुख्य मंत्री, जो ट्रस्टी है, राजस्थान में वफादार है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा मेरे भीलवाड़ा जिले और मेरे सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के लिए जो घोषणा इस बजट में की गयी है, उसके लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं, विधि मंत्रीजी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप भी पधार गये हैं और आपका भी इसमें पूरा सहयोग रहा है। लम्बे समय से सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के रायपुर उप खण्ड मुख्यालय पर न्यायालय की स्थापना नहीं थी और 2003 से क्षेत्र की तथा वकीलों की बराबर मांग चल रही थी। इस मांग को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सी.जे.एम. एण्ड ए.सी.जे.एम. कोर्ट की रायपुर उप खण्ड मुख्यालय पर खोलने की अभी इस बजट में घोषणा की है, मैं क्षेत्र के लोगों की तरफ से, मेरी तरफ से हृदय से मुख्य मंत्रीजी और विधि मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं।

इसके अलावा भी हमारे भीलवाड़ा जिले में सांगानेर क्षेत्र में कोठारी नदी पर हाई लेवल ब्रिज की जो घोषणा की है, इसके लिए भी भीलवाड़ा जिले की जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूं।

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

शहीद स्मारकों के लिए निर्माण की स्वीकृति दी, यह देशभक्ति को प्रेरित करने वाला कदम है तथा शहीदों को अमर रखना और उनकी यादों को ताजा करने के लिए बहुत बड़ा कदम है। इसके लिए भी मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जिले के बिजौलिया ब्लाक में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नहीं था, उसकी भी मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की, उसके लिए भी मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। गुलाबपुरा में स्वतंत्र कृषि मण्डी की स्थापना, जो जन-आकांक्षाओं को परिलक्षित करती है, इसके लिए भी मुख्य मंत्रीजी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।

डी.एल.सी. दरों में जो 10 प्रतिशत की कमी की है उसके लिए भी मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करते हैं। राज्य कर्मचारियों के डी.ए. में पांच प्रतिशत की वृद्धि की और वह भी ऐसे समय में, जब केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को मिलने वाली राशि में से 10 हजार करोड़ की कटौती कर दी गयी, पर मुख्य मंत्रीजी ने कर्मचारियों को यह चीज दी है। इसके लिए भी मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करते हैं।

ई.डब्ल्यू.एस., आर्थिक पिछड़ा वर्ग को प्रमाण पत्र देने के लिए चल-अचल सम्पत्ति का जो प्रावधान था उससे एक भी सर्टिफिकेट मेरे क्षेत्र में नहीं बन पा रहा था। उसमें इस शर्त को मुख्य मंत्रीजी ने हटाया, जिससे आर्थिक पिछड़ा वर्ग के बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है। यह सराहनीय कदम उस युवा पीढ़ी के लिए है और आने वाली पीढ़ी इसका लाभ उठाएगी। इसके लिए राजस्थान के आर्थिक पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे हैं, वे मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करते हैं। राजस्थान में आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड का निर्माण करने का निर्णय करके राज्य सरकार सभी वर्गों के उत्थान के अपने संकल्प को साकार कर रही है, इसके लिए भी आभार व्यक्त करते हैं।

अभी राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा था कि हिन्दुस्तान जिंक में 60 परसेंट मजदूर-कर्मचारी बिहार और बंगाल के लगे हुए हैं, बिलकुल सही बात उन्होंने कही है। मैं उनकी बात का समर्थन तो करता हूं लेकिन समर्थन के साथ-साथ उनसे यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि यह हिन्दुस्तान जिंक, जो नेहरू जी और इंदिरा जी के समय में चली और अटल जी के जमाने में, यह जो भारत सरकार का उपक्रम था, इसको वेदान्ता ग्रुप को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके उन मजदूरों के साथ कुठाराघात किया। उस वक्त आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

चाहिए था कि प्राइवेट कम्पनियों को बेचकर इस हिन्दुस्तान जिंक का सत्यानाश क्यों कर रहे हैं। उस वक्त आपको यह ध्यान में क्यों नहीं आया? दूसरी बात आपने कहा मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे कि सत्ता के लिए समझौते, तो मुख्य मंत्रीजी गांधीवादी विचारों के हैं और सत्ता के लिए समझौते वे कभी नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार में आतंकवादियों को प्लेन से कंधार छोड़ने वाले लोग और कश्मीर की सरकार बनाने वाले लोग हमें आरोपित कर रहे हैं कि हम सत्ता के लिए समझौते करते हैं। चोर को चांदनी नजर आती है, यह मेरा इसमें कथन है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए-विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। माननीय सदस्य, आप इसी पर बोलिए, इधर नहीं।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): मदन जी, आपको बोलना है तो आप मेरे बीच में खूब बोलें लेकिन जब आप बोलेंगे तो फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। मेरी आवाज आपसे कमजोर नहीं है।

श्री सभापति: वे भी नहीं बोलेंगे और आप अपनी बात ही कहें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): सभापति महोदय, युवाओं के लिए राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने जो बात कही है कि 'फिट राजस्थान-हिट राजस्थान', फिटनेस अगर राजस्थान की आने वाली पीढ़ी की सही होगी तो राजस्थान को हिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। फिट राजस्थान बनाने के लिए मुख्य मंत्रीजी ने सिर्फ यह नारा नहीं दिया है, मुख्य मंत्रीजी ने, राज्य में जो खेल हो रहे हैं, उसकी तर्ज पर पिछले समय में गांवों में ब्लाक स्तर पर और जिला स्तर पर ग्रामीण खेल-कूद होते थे उन खेलों से खिलाड़ी निकलते थे। खिलाड़ी हमेशा स्वस्थ होता है और निरोगी रहता है। खिलाड़ी तैयार करने के लिए गांवों में, ब्लाक स्तर पर जो प्लेटफार्म हैं उनको पुन: चालू करने का जो फैसला किया है, यह सरकार का बहुत सराहनीय कदम है। इसके लिए खेल मंत्री और हमारे मुख्य मंत्रीजी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। खिलाड़ियों के लिए ओलम्पिक और एशियन गेम्स में गोल्ड मैडल, सिल्वर मैडल, ब्रोंज मैडल जीतने पर पुरस्कार राशि में जो बढ़ोतरी की है, उस बढ़ोतरी का भी स्वागत योग्य कदम है। युवाओं के लिए 53 हजार सरकारी नौकरियों की घोषणा इस बजट में अलग-अलग विभागों के लिए मुख्य मंत्रीजी ने की है। यह सबसे बड़ा स्वागत योग्य कदम है। पचास हजार युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ते हुए उनको स्वरोजगार के लिए ऋण देने और रोजगार से

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

जोड़ने की जो घोषणा है, इसका भी मैं स्वागत करता हूं। राज्य की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए ब्लाक एवं जिला स्तरीय खेलों का आयोजन करने के लिए, खाली घोषणा ही नहीं की है, इसमें पांच करोड़ का जो बजट प्रावधान रखा है, इससे सरकार की नीयत साफ झलकती है। सरकार की इच्छा शक्ति है कि खेलों को बढ़ावा मिले। प्रदेश के खेलों को बढ़ावा देने के लिए, अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए संविदा पर विभिन्न खेलों के पांच सौ कोच, जो आज से पहले कभी नहीं लगे, खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी की, कोचों की स्वीकृति दी, जो फिट राजस्थान और हिट राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

सभापति महोदय, स्कूलों में शनिवार को 'नो-बैग डे', मुख्य मंत्रीजी की इस सोच की तारीफ करनी चाहिए। सरकार की इतनी तारीफ करनी चाहिए, जिसकी कोई सीमा नहीं हो। सामने की सरकार ने कर्मचारियों को नौकरी में फाइव-डे वीक का आदेश किया था। लेकिन, मुख्य मंत्रीजी ने उन नन्हे-मुन्ने बच्चे और युवा बच्चे, जो स्कूलों में पढ़ते हैं और रोज सोमवार से शनिवार तक, बच्चे बैग का बोझ उठाकर स्कूलों में जाते हैं और संडे के रोज भी होमवर्क करने में लग जाते हैं, तो ये 'नो-बैग डे' आने वाली पीढ़ी को इतनी मजबूती देगा कि निरोगी राजस्थान में आने वाली पीढी के लिए 'नो बैग डे' का यह आदेश मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि उस दिन बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, सांस्कृतिक आयोजन करेंगे, अभिभावक और टीचर्स की मीटिंग होगी, बच्चों की पढ़ाई की समीक्षा होगी। तो महीने में चार दिन जो बच्चों का आयोजन रखा है, यह बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और खेल के प्रति भी बच्चों की भावना बढ़ेगी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति भी बढ़ेगी।

निरोगी राजस्थान के लिए सौ करोड़ का फण्ड सिर्फ इसलिए दिया है कि हर जिले में इसका प्रचार-प्रसार हो, अच्छी तरह से हर जिले में इसकी व्यापक समीक्षा हो, लोगों को जानकारी दी जाए कि निरोगी राजस्थान कैसे बनाया जाए। इसके लिए हर जिले में एक करोड़ के फण्ड की व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है।

मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए अलग से अथोरिटी का गठन करके, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की है। यह कदम प्रदेशवासियों को स्वस्थ एवं निरोगी जीवन देने की दिशा में अभूतपूर्व निर्णय है। हर जिले में मिलावट

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

की जांच के लिए लैब और जांच रिपोर्ट को ऑनलाइन उपलब्ध कराने से मिलवाटखोरों पर तुरन्त कार्यवाही हो पाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े सभी विभागों के लिए 2020-21 में 14 हजार 533 करोड 37 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): अभी मैं तो, सर, बोला ही नहीं हूं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नि:शुल्क दवा योजना, नि:शुल्क जांच योजना चालू की, इसकी देश और दुनिया में तारीफ हो रही है। आज जो हमारे प्रधान मंत्रीजी हैं, मुख्य मंत्रीजी के पिछले कार्यकाल में, जब गुजरात के मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने यहां एक टीम भेजकर, गहलोत जी ने ये कौन सा जादू का डण्डा घुमाया है और उसकी समीक्षा करके गुजरात में लागू करने का उन्होंने प्रयास किया था। आयुष्मान भारत की जो योजना है, वह योजना मोदी जी द्वारा राजस्थान में मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना और नि:शुल्क जांच योजना से बनायी हुई योजना है। हिन्दुस्तान का पहला राज्य है राजस्थान। नि:शुल्क दवा योजना में कैंसर, किडनी जैसी बीमारियों की दवाओं को शामिल करते हुए 709 तरह की दवाइयां राजस्थान की सरकार फ्री में उपलब्ध करवा रही है। अभी सभी माननीय सदस्य कह रहे थे, हमारे यहां कम्पाउण्डर नहीं है, ए.एन.एम. नहीं है, डाक्टर नहीं है, खाली है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने चिकित्सा मंत्रीजी से पूछा कि कांग्रेस की सरकार के बनने के बाद कितने डाक्टरों को आपने घर भेज दिया, कितने कम्पाउण्डरों को घर भेजा, कितनी नर्सों को घर भेजा, हिसाब-किताब बताइये। उन्होंने कहा, कैलाश जी एक को भी घर नहीं भेजा। मैंने इतने हजार डाक्टर लगाये, सात हजार कम्पाउण्डर ले रहा हूं, ए.एन.एम. की भर्ती चल रही है, मैं तो लेने का काम कर रहा हूं। तो फिर ये पोस्टें खाली कब से हैं। इसका हिसाब किताब तो कर लो। ये पोस्टें आपके समय से खाली हैं। आप लोग कोई भर्ती नहीं कर पाये, आप लोग कुछ लगा नहीं पाये। अब मुख्य मंत्रीजी 15 मेडिकल कालेज खोल रहे हैं। 15 मेडिकल कालेज जब राजस्थान में चालू हो जाएंगे, सभापति महोदय, मैं कह सकता हूं राजस्थान को निरोगी राजस्थान बनाने में, ये डाक्टर जो इन मेडिकल कालेजों से निकलेंगे, मील के पत्थर साबित होंगे। ये मेडिकल कालेज मील के पत्थर साबित होंगे। यह मुख्य मंत्रीजी का, चिकित्सा मंत्रीजी का सराहनीय कदम होगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, घायल आदमी को 108 या कोई भी ले जाता है, सरकारी अस्पताल दूर होता है तो निजी अस्पताल में नहीं झेलते थे, उसका इलाज नहीं हो पाता था। सरकार ने यह फैसला लिया है कि किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का जो भी निजी अस्पताल इलाज नहीं करेगा।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। प्लीज, सहयोग करें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): तो उसके खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी। मैं तो बोला ही नहीं सर।

श्री सभापति: सहयोग करें, प्लीज।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): मैं तो बोला ही नहीं।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): सरकार का सराहनीय कदम है और मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। आपने नहीं बोलने दिया, आपका भी धन्यवाद।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सभापति महोदय, आज बजट पर चर्चा के सम्बन्ध में पक्ष और विपक्ष ने सबने अपना वक्तव्य दिया। हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बजट की जो शुरुआत की है, सात संकल्पों के माध्यम से इसकी शुरुआत की है। उनका पहला ही संकल्प निरोगी काया रहा है। आज अगर इस सदन में हम आये हैं तो कहीं न कहीं हमारी काया स्वस्थ है, हम स्वस्थ हैं इसलिए आ पाये हैं। हम इस राज्य का विकास चाहते हैं, इस राज्य का उद्धार चाहते हैं तो सबसे अधिक चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ही ध्यान देना पड़ेगा।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने आज तक जो मिलावटखोरी हो रही थी, जो डुप्लीकेट सामान मार्केट में बिक रहा था, खाद्य पदार्थ जो बन रहे थे, उनमें जो मिलावट हो रही थी, उसके लिए ठोस कदम उठाया और अथोरिटी का गठन किया। आज सभी ने इस बजट की तारीफ भी कर दी, बुराइयां भी कर दीं लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सदन को वास्तविक स्थिति क्या है, उसके बारे में बताना चाहता हूं। आज मेरा चौरासी विधान सभा क्षेत्र गुजरात का बार्डर है, मेरे विधान सभा क्षेत्र से गुजरात जस्ट स्टार्ट होता है और उधर से मध्य प्रदेश स्टार्ट होता है, उस क्षेत्र

(श्री राजकुमार रोत)

से आता हूं। आज जब निरोगी काया की बात हो रही है तो गुजरात के दो से तीन जिला कलेक्टर, डूंगरपुर कलेक्टर को लैटर लिखते हैं। उस लैटर में कहते हैं कि डूंगरपुर इलाके से और बांसवाड़ा जिले से जो मरीज आ रहे हैं, उन मरीजों का हीमोग्लोबिन, खून बहुत कम है। यह दुखद बात है इस साल, इस सत्र में और इससे पहले हर साल तीन सौ से चार सौ शिशुओं की मृत्यु होती है।

हर बार बजट होता है, पिछली बार बी.जे.पी. गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी दिया था। इस बार कांग्रेस गवर्नमेंट है, उन्होंने भी दिया है लेकिन हमें यह ध्यान रखना जरूरी है और यह सोचना पड़ेगा कि क्या वह बजट धरातल पर वास्तव में लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, डाक्टर बना रहे हैं, उनको भेज रहे हैं, पर उनकी क्या स्थिति है वहां। आज जब हमारे लोग गुजरात में जाते हैं तो हमें यह लगता है कि डूंगरपुर से ज्यादा, हमारा जो जिला हास्पिटल है, वहां से ज्यादा लोग गुजरात में इलाज करवाने जाते हैं। आज डूंगरपुर का जो मुख्य चिकित्सालय है, उसकी बात बताऊं, दो महीने पहले ही हमारे डूंगरपुर के जो पूर्व विधायक थे, पूर्व सांसद भी रहे हैं, उनसे और वर्तमान सी.ई.ओ. से एक मशीन का उद्घाटन करवा दिया। एनलाइजर मशीन थी, उसका उद्घाटन करा दिया था। विभाग के अधिकारियों को पता था कि यह मशीन खराब है। यह सोचना पड़ेगा कि अगर जनप्रतिनिधि को विभाग के अधिकारी बेवकूफ बना रहे हैं तो जनता को कितना बेवकूफ बनाते होंगे। आज की स्थिति यह है कि उस जिला हास्पिटल में 8 से 10 मशीनें खराब पड़ी हुई हैं। कोई नहीं देख रहा है। आज सीएच.सी. बनी हुई हैं, कई ऐसी सी.एच.सी. बनी हुई हैं, जो साल भर पहले ही बनी हैं और आज बारिश के समय उनमें पानी टपक रहा है। डाक्टर हैं, सब अपना-अपना क्लिनिक खोलकर बैठ गये हैं। जब ड्यूटी रहती है, उस समय भी क्लिनिक पर बैठे रहते हैं। कई बार रात के समय में यह स्थिति रहती है कि कोई भी डिलीवरी हो या कुछ भी हो या तो उसको प्राइवेट में जाना पड़ेगा या फिर उसको वहां से रिलीव कर देते हैं, वह गुजरात चला जाता है। यह स्थिति बनी हुई है।

सभापति महोदय, यह जो सिस्टम है, कहीं न कहीं इस सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा। बजट हर बार होगा, हर वक्त होगा, कोई भी सरकार आएगी लेकिन जो वास्तविक समस्या है, जो जड़ है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आज किसानों के लिए बात हुई। हमारे देश की राजनीति होती है या

(श्री राजकुमार रोत)

राज्य की राजनीति होती है, सभी सरकारें होती हैं, किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। आज किसान अनाज पैदा करता है। हमें यह सोचना है कि हम एक माचिस बनवा रहे हैं, एक फैक्ट्री में कोई पानी की बोतल बन रही है तो उसकी रेट फिक्स है लेकिन किसान जो अनाज पैदा कर रहा है, उसकी रेट फिक्स क्यों नहीं है? यह सोचने का विषय है। किसान जब अनाज पैदा करता है, उसकी पैदावार होती है तो उसकी रेट बहुत गिर जाती है और वह किसान गिड़गिड़ाता है। वापस जब बुवाई होती है तो उसकी रेट बढ़ जाती है, उस समय बड़े-बड़े उद्योगपति, अपन सब जानते हैं, सब इकट्ठा करके, जब मार्केट में उसकी शार्टेज हो जाती है, उस समय ये बाहर निकालते हैं, तो उस पर सोचना पड़ेगा।

आज हमारे इलाके में अभी लोन माफी हुई, कुछ हद तक हुई। राष्ट्रीयकृत बैंक्स हैं, उनकी नहीं हुई है लेकिन उस इलाके में एक ऐसी स्थिति हुई, मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि लोगों को किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनको किस तरह से ठगा जा रहा है। एक ग्राम पंचायत है, चौकी ग्राम पंचायत, उस ग्राम पंचायत के आठ से दस ऐसे लोग हैं, जो उन लोगों को बाहर ले जाकर लोन दिला रहे हैं या सरकार की योजना से दिला रहे हैं। उनके नाम पर उनसे अंगूठा लगवा दिया और दो-दो, तीन-तीन लाख रुपये का लोन उन लोगों से ले लिया। आज वे लोग न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं। वे मेरे पास भी आये थे। मैंने भी कहा कि एफ.आई.आर. करवाओ, तो हमारे एस.पी. साहब के पास गये। आज भी, जिस आदमी ने उन लोगों के साथ ठगी की है, उस आदमी ने पहले से ही उनसे स्टाम्प पर अंगूठा लगवा रखा है कि मैंने इनको पैसे दिये। इस तरह सरकार की योजना के नाम पर उन लोगों को लूटा जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाह रहा हूं, सभापति महोदय, कि इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, उनकी जांच की जाए और उन पर कठोर कार्रवाई की जाए।

आज इस बजट में जनजाति विभाग के लिए जो शिड्यूल्ड एरिया है उस एरिये के जो बेरोजगार हैं, उन बेरोजगारों के लिए, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 5,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने की बात कही है और 15,000 युवाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देने की बात कही है। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे बड़ा उस क्षेत्र में मुद्दा था कि हमने जनजाति विभाग बना दिया। आज वर्षों से उस विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो होस्टल वार्डन हैं,

(श्री राजकुमार रोत)

किराये पर लाए जाते थे, दूसरे विभाग से लाए जाते थे। पहली बार जनजाति के होस्टल वार्डनों का कैडर बना दिया गया। उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उस इलाके में कई तरह के हॉस्टल्स बन गये हैं और एक गरीब परिवार का बच्चा उस हास्टल पर ही निर्भर रहता है कि मैं होस्टल में रहूंगा, छह साल निकाल लूंगा, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लूंगा। मैं भी आज सदन में आया हूं, मैंने भी दो साल हास्टल में रहकर शिक्षा ग्रहण की है तो मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि उसका और भी सुधार करे।

आज इस सदन को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बांसवाड़ा का दौरा किया था। उन्होंने उस समय बताया था कि शिड्यूल्ड एरिया है, शिड्यूल्ड एरिये का जो अभिभावक है, वह राज्यपाल है। राज्यपाल चाहें जो प्रावधान शिड्यूल्ड एरिये में कर सकते हैं। उस एरिये के लिए जनजाति सलाहकार समिति बनी हुई है। सलाहकार समिति में विधायक होते हैं, कुछ पांच-एक सामाजिक लोग होते हैं। वह सलाहकार समिति सरकार को, राज्यपाल को अपनी बात पहुंचाती है। लेकिन सभापति महोदय, मैं उस तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूं कि पिछली गवर्नमेंट में बीजे.पी. से नन्दलाल जी हमारे मंत्री थे। उस समय एक घटना हुई। उन्होंने, डूंगरपुर में एक प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में अपनी बात रखी, अपनी जो भावना थी, रखी और अपना जो दु:ख था, वह रखा। दूसरे ही दिन उनसे मंत्री पद छीन लिया गया। कुछ महीनों में, जो सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है, वह मंत्री हुआ करता था और पिछली गवर्नमेंट में सलाहकार समिति का अध्यक्ष मुख्य मंत्री महोदय को बना दिया गया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सभापति महोदय, मैं तो पांच मिनट ही बोला हूं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें अब।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सभापति महोदय, हमें 10 मिनट मिले हैं।

मैं उस बात को बता रहा था कि मुख्य मंत्री महोदय को सलाहकार समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। तो यह जानना पड़ेगा कि हमारे राज्य के जो मुख्य मंत्री हैं वे इतने व्यस्त रहते हैं, वह एक सलाहकार समिति के

(श्री राजकुमार रोत)

अध्यक्ष बनेंगे तो किसको सलाह देंगे। तो इस तरह की घटना हुई है। उस इलाके में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने वन भूमि में जो वनाधिकार पट्टे देने की बात की, उस इलाके में कुछ हद तक दिये गये हैं और कुछ प्रक्रियाधीन हैं। जिन लोगों को वनाधिकार पट्टे मिले हैं, उन लोगों के लिए मुर्गी पालन, बकरी पालन जैसी योजनाएं बनायी हैं। विशेषकर उस एरिये में, जो पूरे देश में फेमस है, कड़कनाथ करके एक मुर्गा होता है, वह पूरे देश में फेमस है। वह मुर्गा भी काला होता है, उसकी मीट भी काली होती है, उस मुर्गे का ब्लड भी काला होता है और वह बहुत पौष्टिक है। उस इलाके में, मैं उसके साथ-साथ यह भी कहना चाह रहा हूं कि वन अधिकार पत्र जिन लोगों को मिले हुए हैं वहां एक महुए का फूल होता है और जो महुआ होता है और दु:ख होता है उस बात को लेकर कि सरकार ने देसी दारू के लिए, गंगानगर शुगर मिल्स से कैमिकल्स से देसी दारू बनकर उस इलाके में बिक रही है। लेकिन सरकार ने जो देसी महुआ है, जो एक औषधि है, ओरिजिनल जो बनता है, उससे अच्छी-अच्छी बीमारी भाग जाती है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। मैं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री को, सरकार को अवगत कराना चाह रहा हूं कि उसको कहीं न कहीं ऐसे मोडिफाइड करके उस महुए के जूस का क्योंकि लोग उनके स्वास्थ्य के लिए वहां बनाते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री चन्द्रभान सिंह।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सर, दो मिनट।

श्री सभापति: समाप्त करें। अब हो गया।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सर, शिक्षा की जो बात हो रही है।

श्री सभापति: समाप्त करें। बिलकुल समाप्त करें। श्री चन्द्रभान सिंह।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सर, यह एक तरह का +++ है। हमें 10 मिनट मिले थे, 6 मिनट ही बोले हैं।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सर, +++? हमें 10 मिनट मिले थे, पार्टी के हिसाब से।

श्री सभापति: विराजिए। 10 मिनट से ज्यादा बोल दिये आप।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सर, दो मिनट।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): बिल्कुल सर। सर, शिक्षा की बात होती है उस इलाके में...

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): बिलकुल, सर।

सर, उस इलाके में जो शिक्षा की स्थिति है, आज रमसा के तहत बिल्डिंग्स बनती हैं। बनती हैं, उसके तीन-चार साल बाद उनमें पानी टपकने लग जाता है। मैंने एक स्कूल का दौरा किया। हमारी जो व्यवस्था बनी है, उस व्यवस्था के बारे में आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि दूध दिया जाता है बच्चे को, फिर खाना दिया जाता है। बच्चा सात-साढ़े सात बजे स्कूल में जाएगा तो वह गिलास लेकर लाइन में लगेगा। दूध पीने जाएगा, 9:00 बज जाएंगे और 10:00 बजे फिर खाने के लिए लाइन में लगेगा। यह इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है तो बच्चा कहां पढ़ेगा? एक हैंडपम्प लगा हुआ रहता है, उसको थाली मिलती है, और एक स्कूल में 80 से 90 बच्चे रहते हैं वे लाइन से लगेंगे और 90-90 थालियां धोएंगे तो एक घंटा उसमें लगेगा। इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है, सभापति महोदय, मैं इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि हमें एक तरह का कोई न कोई ऐसा प्रावधान रखना चाहिए।

श्री सभापति: अब समाप्त करें। ज्यादा सुझाव मत दीजिए। अब समाप्त करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। अंत में, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि उस इलाके में स्कूल में जो बच्चा जाता है वह डर सा महसूस करता है। डर सा महसूस करता है कि मैं कुछ गलत नहीं बोल दूं। क्योंकि वह अपने बचपन से 5 साल तक अपने अभिभावकों के साथ रहता है। वह ऐसी भाषा सीखता है, वह मातृभाषा है। स्कूल में जाने के बाद उसको सीधी हिन्दी और इंग्लिश बोली जाती है तो वह बच्चा डरता है। तो आपसे निवेदन है, सदन से, कि जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार ने पांचवी तक की शिक्षा अपनी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए प्रावधान किया है तो वर्तमान सरकार भी अपने राज्य में, हमारे इलाके में विशेषकर, जो भीली भाषा है, मातृभाषा है, उसमें अध्ययन कराने का प्रावधान करे। सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह जी।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय,

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदय के बजट भाषण पर पक्ष-विपक्ष में चर्चा हो रही है। केवल सदन ही नहीं अपितु पूरा प्रदेश परिचित है कि यह बजट केवल प्रदेश के जनहित को ध्यान में रखते हुए पेश नहीं किया है, यह केवल जोधपुर के लिए घोषणा की है। पूरे राजस्थान के बजट में से 40-50 परसेंट बजट जोधपुर के लिए दिया है। मुख्य मंत्री महोदय को यह सोचना चाहिए कि उनके लिए सभी जिले समान हैं, पूरा राज्य उनका है, केवल जोधपुर के बारे में सोचना गलत है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने इस बजट में कुल सात संकल्प प्रस्तुत किये हैं। इसमें उन्होंने निरोगी राजस्थान की कल्पना की है। निरोगी राजस्थान तब होगा जब हास्पिटल्स में डाक्टर होंगे, नर्सिंग कर्मचारी होंगे। पूरे राजस्थान में 50 परसेंट डाक्टरों की कमी है, नर्सिंग कर्मियों की कमी है। आप फ्री दवाई की बात कर रहे हैं, पर दवाई लिखने वाला और दवाई देने वाला अगर काउंटर पर नहीं होगा तो निरोगी राजस्थान कैसे हो पाएगा, इसकी कल्पना आप लोगों को करनी चाहिये।

बजट में आप घोषणाएं तो बड़ी-बड़ी कर देते हैं, अभी सुबह शिक्षा के बारे में रामलाल जी ने एक प्रश्न पूछा था कि आपने 50 प्राइमरी स्कूल खोलने की बात की थी, केवल दो स्कूल खोले। इसी उदाहरण से पता लगाया जा सकता है। चावल बनाते हैं तो उसमें से एक दो चावल का ही टैस्ट करते हैं, यह उदाहरण है।

माननीय सभापति महोदय, यह पूरा बजट केवल घोषणा मात्र है। नि:शुल्क दवाई के बारे में बात की। चित्तौड़गढ़ में सैटेलाइट हास्पिटल की बात कही, चित्तौड़गढ़ में कैथ लैब की स्थापना के बारे में बात करूं, हास्पिटल की हालत बहुत खराब है। साफ-सफाई की जो व्यवस्था होती थी, जो पैसा आता था, वह पैसा आ नहीं पा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिला हैड क्वार्टर है, वहां बहुत बड़ा हास्पिटल है। एक साल सरकार बने हुए हो गया लेकिन हास्पिटल की हालत बहुत खराब है। नये डाक्टर लगे नहीं हैं, काफी डाक्टरों के ट्रांसफर हो गये हैं। मेवाड़ में वह बहुत बड़ा हास्पिटल है, एम.पी. के लोग भी वहां इलाज कराने आते हैं। इसलिए हास्पिटल के बारे में भी आप सोचें, नयी भर्ती भी करें, नर्सिंग कर्मचारी भी लगाएं।

दूसरा संकल्प था किसानों का, पशुपालन एवं सिंचाई का। किसानों के

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

बारे में चुनाव से पहले आप लोगों ने काफी घोषणाएं कीं, काफी बातें कीं कि हम पूरा कर्जा माफ कर देंगे, वह कर देंगे। पर आज किसान उस बात को लेकर दुःखी है कि सरकार ने जो हमारा सम्पूर्ण कर्जा माफ करने की बात की थी, ऊंट के मुंह में जीरे के समान आपने हल्का सा को-आपरेटिव के माध्यम से, केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से, भूमि विकास बैंक के माध्यम से कहीं 50 हजार, कहीं 10 हजार, कहीं 5 हजार रुपये माफ कर दिये और आज किसान दर-दर की ठोकरें खा रहा है। इसलिए किसान आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गंवा कर भी दुःखी है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। अगर आज राजस्थान में चुनाव होते हैं तो अगर 200 में से 200 भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोक सभा में ऋण माफी के मामले को लेकर 25 में से 25 सीटें आयीं। अभी भी आप किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ कर दें तो आपके लिए अच्छा हो सकता है, इस बारे में भी आप सोचें।

पशुपालन के बारे में अभी अमीन खां साहब ने काफी अच्छी बात बतायी कि किसानों के लिए उन्नत किस्म की गायें, भेड़ें कैसे पाल सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, उसके बारे में गवर्नमेंट क्या कर सकती है। कैसे डेयरी के बारे में छूट दे सकते हैं। कैसे उन्नत किस्म के सांड हम उपलब्ध करा सकते हैं, इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है।

सिंचाई में, जो नहरों में टूट-फूट है, नहरों का पैसा जो पहले पास कर रखा है, वह पैसा भी नहीं आया। हमारे यहां एक बहुत बड़ा साकेड़ा बांध है, उसके लिए पहले सरकार ने 10-12 करोड़ रुपये पास भी किये लेकिन आज वह काम एक साल से बंद पड़ा है। आप किसानों के बारे में सोचते हुए उस साकेड़ा बांध का काम भी चालू कराएं। लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया, मुआवजे के पैसे भी आये हुए हैं केवल सरकार की कमी की वजह से वह काम नहीं चल पा रहा है। मैं चाहूंगा कि उस साकेड़ा बांध का काम भी आप चालू करें।

आपने फसल खराबा की बात की थी। हमारे इलाके में काफी फसल खराबा हुआ, उसका पैसा भी नहीं आया है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि फसल खराबा के पैसे भी आप दिलाएं।

महिला एवं बाल विकास के बारे में आंगनबाड़ी महिलाओं को परमानेंट करने की आप लोगों ने बात की थी। उनका मानदेय काफी कम है, उसको

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

बढ़ाने की बात की थी लेकिन इस बजट में आपने ऐसा कुछ नहीं किया। पहले भी जो केन्द्र ने मानदेय बढ़ाया, वह आपने बढ़ा दिया और आप लोगों ने वाहवाही ले ली, लेकिन वह मोदी जी का बढ़ाया हुआ है, आप भी अपनी तरफ से कुछ हिस्सा बढ़ाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जो दिन-रात उन बच्चों को पालती हैं, पोषाहार खिलाती हैं, उनके बारे में भी आप सोचें, क्योंकि वे बहुत ज्यादा गरीब प्रवृत्ति के लोग हैं। छोटे-छोटे गांवों में छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं, उनके बारे में भी आप सोचें।

आपने संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का भी वादा किया था, वह भी आप लोगों से हो नहीं पाया, वह भी आप करें। एक आपने सबसे बड़ा वादा किया था कि युवा बेरोजगारों को हम भत्ता देंगे। आज आप इस बजट की वाहवाही लूट रहे हैं और आप धन्यवाद भी दे रहे हैं, लेकिन मन में तो आप भी दुःखी हैं कि हम धन्यवाद नहीं दें तो करें क्या, हम सरकार में बैठे हुए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जब आप पंचायती राज के चुनाव प्रचार में जाएंगे तो वे लोग आपको डांटेंगे जरूर, झपटेंगे जरूर क्योंकि आप लोगों ने उनको भत्ता देने की बात की और वे युवा बेरोजगार आप लोगों की चपेट में आ गये और आप लोगों की सरकार बना दी, आज आप उनको भत्ता दे नहीं पाये। अभी भी आप भत्ता दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, 27 तारीख को जब रिप्लाई देंगे तो उसमें युवा बेरोजगारों को भत्ता देने की बात भी आप कर लें।

मजदूर, छात्र, युवा, जवान के बारे में कहा। खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता बढ़ाया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा लेकिन खिलाड़ियों का जितना भत्ता बढ़ाना चाहिए, वह नहीं बढ़ाया। जो बच्चा खेलने जाता है उसको टी.ए., डी.ए. काफी कम मिलता है, इसलिए आप उनका टी.ए., डी.ए. भी बढ़ाएं। श्रमिक कार्डों का एक-एक साल से पैसा बाकी है इसलिए श्रमिक कार्ड भी नहीं चल पा रहे हैं। अभी बी.डी.ओ. उसको देखता है, कभी कोई दूसरा अधिकारी देखता है, श्रमिक कार्ड को भी आप चालू कराएं, उसके बारे में भी सोचें।

शिक्षा के बारे में, स्कूलों को बंद करने की या मर्ज करने की बात हुई उस समय इस साइड में आप लोग बैठे थे, उस समय काफी चर्चा की, काफी हल्ला भी मचाया, काफी बातें कीं कि आप लोगों ने गलत स्कूल बंद कर दिये। उन स्कूलों को अगर आप वापस चालू करना चाहें तो आप चालू कर सकते हैं। एक-सवा साल हो गया लेकिन आपने उसमें कोई स्कूल चालू नहीं किया। स्कूलों में कोई भर्ती भी नहीं हो पाई, इस बारे में भी आप सोचें। आप भर्तियां

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

कर देंगे तो स्कूल चल पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अच्छे सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल भी बने हैं। सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। एक काम आपने जरूर किया है, उनके ट्रांसफर जरूर किये हैं, उसके अलावा आपने नयी भर्ती करने की कोशिश नहीं की, इस बारे में भी आप सोचें। विद्यालयों के भवन खराब हैं, उनके लिए साल भर से आपने कोई पैसा नहीं दिया, इस बारे में भी सोचें। डी.एम.एफ.टी. फंड के माध्यम से माइनिंग का पैसा हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में भी पड़ा हुआ है, काफी यू.सी. भी कमप्लीट हो गये, पूरे काम भी हो गये लेकिन उनका पेमेंट भी नहीं मिला है। स्कूल के भवन भी बन गये हैं लेकिन वह पैसा जारी नहीं हुआ, सरकार ने रोक रखा है। नया काम आप प्लानिंग से करें लेकिन जो पुराने काम हो गये हैं, उस डी.एम.एफ.टी. फंड का पैसा भी आप दिलाएं। माडल स्कूल में टीचर्स भी लगाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं बिजली के बारे में बताना चाहता हूं, बिजली के बिल के बारे में आपने कहा कि हम बिल नहीं बढ़ाएंगे, किसानों को आप लोगों ने भ्रमित भी किया। आज सुबह मदन दिलावर जी कह रहे थे कि रात के समय लाइट आ रही है। हमारे जिले में भी रात के समय आप लाइट दे रहे हैं, जिसकी वजह से काफी किसानों की मौतें भी हुई हैं। इससे किसान काफी दुःखी भी हैं इसलिए लाइट दिन के समय भी दें। आपने लोड बढ़ाने की बात की, अधिकारी ने घर बैठे तीन के पांच कर दिये, पांच के साढ़े सात कर दिये, साढ़े सात के दस कर दिये, दस के बारह कर दिये, बारह के पन्द्रह कर दिये, घर बैठे कनेक्शनों के लोड बढ़ा दिये, इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है। घर बैठे जो लोड बढ़ाया गया है, उसको वापस सही करें। आज किसानों के खेतों में पानी नहीं जा पा रहा है। ट्रिप पर ट्रिप आये जा रहे हैं, उसके बारे में भी आप सोचें। बिजली का जो लोड बढ़ाया है, उसके बारे में भी आप सोचें। जो कनेक्शन आप काट रहे हैं, हर बार मार्च में बिल जमा होते हैं, यह भी मैं बता सकता हूं, पर आपने बिल के माध्यम से, बिजली चोरी के माध्यम से करोड़ों रुपये किसानों के लगा दिये, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है। आज किसान दुःखी है। अभी फसल की पिराई का टाइम है और आपने कनेक्शन काट दिया। लोग पैसा जमा नहीं करा पाये, वे जमीन गिरवी रखकर, फसलें गिरवी रखकर बिल जमा करवाकर, आप भी किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में भी आप सोचें। माननीय सभापति महोदय, बिजली का घरेलू कनेक्शन दें। उनके बिलों में

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

खेत का कनेक्शन बढ़ाकर खेत के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, उनके बारे में आपको सोचने की जरूरत है। क्योंकि आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, आप किसानों की भावना के अनुसार उनसे वोट लेकर आये हैं तो आपको भी बिजली के सम्बन्ध में किसानों के लिए सोचने की जरूरत है। किसानों के लिए बिजली-पानी अनिवार्य चीज है, उसके बारे में आप सोचें।

माननीय सभापति महोदय, पानी की बात करूं। आपने एम.एल.ए. फंड में भी केवल एक करोड़ 12 लाख रुपये दिये हैं, वह पैसा भी आप पूरा दे दें। क्योंकि पीने के पानी की जरूरत है। आज हर साल एक एम.एल.ए. को 100 हैंडपम्प या सिंगल फेज देते हैं, अब की बार वह भी नहीं दिया, उसको भी आपको देने की जरूरत है। किसानों को कहां-कहां दिक्कत हो रही है, कहां जरूरत है, वहां हम लगाने की कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, सड़कों की बात करूं। पहले पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री युनूस खान जी थे, वसुन्धरा जी थीं, उन्होंने काफी रोड्स पास कीं, काफी काम भी हो गये और काफी काम चल भी रहे हैं, पर साल-डेढ़ साल से वे काम यहीं के यहीं खड़े हैं। माननीय उदयलाल जी साहब, चित्तौड़गढ़ जिले का मामला है, आप जरूर देखें क्योंकि आप वहां से सांसद भी रहे हैं, वहां से मंत्री भी हैं। जो रोड्स के काम रुके हुए हैं, जो बनेसर, शम्भुपुरा, सावा, वे करीब 18-20 करोड़ रुपये के काम हैं, वे रुके हुए हैं, मिट्टी उड़ रही है। एक लेड़ावन से पदेसर, जो कि आपके विधान सभा क्षेत्र में भी आता है, उसमें भी मिट्टी उड़ रही है, वहां पर गिट्टी डाली हुई है, उसका काम भी आप करवाएं। जितने भी रोड के काम बंद हैं, मैं सोचता हूं कि आप रोड के काम पूरे करवाएं, क्योंकि वे काम बंद पड़े हैं। (व्यवधान)

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): ...(व्यवधान) फाइनेंस की स्वीकृति आयी नहीं, गिट्टी डाल दी और काम शुरू कर दिया वोट के लिए, बजट आएगा तब काम शुरू हो जाएगा। उसकी वजह आप फर्जी काम करके यहां आकर बैठ गये, इसलिए आपको धन्यवाद। अगर उस समय स्वीकृति लेकर बैठते तो शायद यह बात करने का अवसर नहीं मिलता।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, विराजिए। आपको इनको रिप्लाई थोड़े ही देना है। विराजिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आज मंत्रीजी को यह कहना चाहता हूं कि उसका काम भी पास हो गया, पहली

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

किश्त भी आ गयी है, पदेसर वाले शम्भुपुरा रोड की, यदि यह नहीं हो तो मैं, जो कहें, करने के लिए तैयार हूं, मैं रिजाइन देने के लिए तैयार हूं। मतलब, फर्स्ट किश्त आ गयी है, सैकण्ड किश्त आयी, उसके बाद आप लोगों ने काम रुकवाया। आप वहां के मंत्री हैं, आप वहां से सांसद रहे हैं, उसी एरिये से सांसद रहे हैं। आपको काम कराने की जरूरत है। मंत्री महोदय, मैं आपको सही बात कह रहा हूं। आप भावुक मत हों।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): 000

श्री सभापति: मैं अलाउ नहीं करूंगा, माननीय मंत्री महोदय। अंकित नहीं होगा।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): 000

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): मैं कागज लाया हूं। उनके मेरे पास कागज हैं। जो सैंक्शन हुए हैं, उनके पास मेरे पास कागज हैं, उनके कागज मैं आपको बताना चाहता हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें। मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट।

श्री सभापति: विराजिए। मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): मुझे आपका संरक्षण चाहिए। माननीय सभापति महोदय, पंचायत राज की बात करूं, चुनाव भी आप टाइम पर करवाते, जो आप नहीं करवा पाए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, इतने मासूम तरीके से दो मिनट मांग रहे हैं।

श्री सभापति: यह कतई बर्दाश्त के बाहर है।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, टोल माफी की बात हुई, उस टोल को माफ कर दिया था, उसे वापस चालू किया है। स्कूलों के क्रमोन्नयन की बात हुई, उसका भी करवाएं। नन्दीशाला खोलने की बात हुई। नन्दीशाला नहीं खोली, वे खोलें। आप गायों के बारे में सोचें, गायें आपका भला करेंगी। अग्नि शमन यंत्र खरीदने की बात हुई, वह भी नहीं किया। मिसिंग लिंक रोड भी आप लोगों ने नहीं दिये। सभापति महोदय, पूरे राजस्थान में दलितों के साथ जो अत्याचार हुए हैं, उसको देखने की जरूरत है। उसके लिए सोचने की

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

जरूरत है, वह भी आप सोचें। आप संविदाकर्मियों को स्थायी करें। रोडवेज कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाने की बात है, उसका भी करें। वसुन्धरा जी ने अम्बेडकर भवन बनाया, आपने तो कोई अम्बेडकर भवन नहीं बनाया है। हमारे वहां पर कई फैक्ट्रियां हैं और नयी फैक्ट्रियां भी आ रही हैं। युवाओं को भत्ता देने की बात करें।

श्री सभापति: कनक्लूड करें। श्रीमती इन्द्रा।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): बजरी माफिया की बात करें। पुलिस के द्वारा जो फर्जी केस बनाये जा रहे हैं, वे फर्जी केस नहीं बनाएं। मैं पूरे बजट का विरोध करता हूं। यह बजट राजस्थान के लिए बिलकुल भी अच्छा बजट नहीं रहा है। आने वाले दिनों में आप अच्छी घोषणाएं करें। चित्तौड़ जिले के बारे में कुछ करें, इसके बारे में आप जरूर सोचें।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। मैं अलाउ नहीं करूंगा। आप बैठिए। कोई मतलब नहीं है। आपके बोलने वाले माननीय सदस्य का मुझे समय काटना पड़ेगा।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, हमें बजट 2020-21 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। सभापति महोदय, वर्तमान में राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब ने जो बजट पेश किया है, इस बजट में सेहत, शिक्षा, युवाओं, किसानों सहित हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। यह बजट प्रदेश के आमजन को राहत देने वाला बजट है। केन्द्र सरकार के द्वारा नोटबंदी, जी.एस.टी. लागू करने के बाद आज आर्थिक स्थिति अत्यधिक कमजोर है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इन परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा बजट पेश किया है। माननीय सभापति महोदय, यशस्वी मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब द्वारा प्रदेश के चहुंमुखी विकास हेतु निरोगी राजस्थान, सम्पन्न किसान, महिला, बाल वृद्ध कल्याण, सक्षम मजदूर, युवाओं, पानी, बिजली, सड़कों, कौशल व तकनीकी, इन सात संकल्पों के द्वारा बजट पेश किया गया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसमें जनता को सभी सुख देने का ध्यान रखा है। जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जिनकी इंसान को धरातल पर आवश्यकताएं होती हैं, उन सभी चीजों को देने का मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में महत्वपूर्ण काम किया है।

(श्रीमती इन्द्रा)

आदरणीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहला संकल्प 'निरोगी राजस्थान' का लिया है, जिसमें 14 हजार 533 करोड़ 37 लाख रुपये का प्रावधान रखा है और 100 करोड़ रुपये के 'निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष' के गठन की घोषणा की गयी है। मेडिकल कालेजों की घोषणा की गयी है। चहुंमुखी विकास के लिए मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है। चिकित्सा के लिए कई बार मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरे यहां बौंली के अन्दर जो हास्पिटल है, उसके अन्दर 30 बैड हैं। हम मांग करते हैं, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि बैड्स की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी जाए ताकि लोगों को आसानी से चिकित्सा सुविधाएं मुहैया हो सकें। इसके अलावा पीपल्दा, पलासौद, घाटा निनवाड़ी, बपुई, बिछोछ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का भी हम अनुरोध करेंगे।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गरीब किसान निवास करते हैं, जो ज्यादातर कृषि पर निर्भर रहते हैं। सभापति महोदय, मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर हैं। किसानों के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत ही अच्छी घोषणाएं बजट में की हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जंगली गायें हैं, वे काफी ज्यादा हैं। उनके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गौशालाओं की घोषणा की है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी बामनवास, बौंली और मित्रपुरा में गौशालाएं खोलने की कृपा करें, इससे किसानों को राहत मिल पाएगी। माननीय सभापति महोदय, बजट में नगरपालिकाओं की घोषणा की गयी है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगी कि बामनवास को भी नगरपालिका का दर्जा दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने खेलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है और बहुत बड़ी घोषणाएं की हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही है कि खेलों के अन्दर बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाये हैं। मैं चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक स्कूल के अन्दर खेल मैदान का आवश्यक रूप से प्रावधान किया जाए। उसमें खेलों को सुनिश्चित किया जाए। बच्चों को आवश्यक रूप से उसमें खिलाने के लिए पाबंद किया जाए, जिससे बालकों को खेलों से अधिक से अधिक लाभ मिल सके। सरकार ने खेलों में दो प्रतिशत नौकरियों का भी प्रावधान किया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी।

(श्रीमती इन्द्रा)

(18.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, एक विशेष मुद्दे पर सदन में बात करना चाहूंगी कि आज जो सबसे बड़ी बुराई चल रही है, विशेष मुद्दा जो है, वह बजरी के अवैध खनन का चल रहा है। इससे अपराध बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। हम सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि कोई ठोस नीति बनाकर इस समस्या का निस्तारण किया जाए ताकि सरकार की आय बढ़ सके और आम जनता को फायदा मिल सके। कुछ लोगों के निजी स्वार्थ के खातिर इस अपराध को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए विचार करना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्रीजी और सरकार से आग्रह करना चाहूंगी।

दूसरी बात करना चाहूंगी, बेरोजगार युवाओं की। हमारी सरकार ने बजट में 53 हजार भर्तियों की घोषणा की है। हम माननीय मुख्य मंत्रीजी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मैं एल.डी.सी. भर्ती, 2018 पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। हर बार एससी./एस.टी. के बैकलाग पदों को जोड़ा गया है लेकिन 2018 की भर्ती के अन्दर 1,200 के लगभग बैकलाग पिछली 2013 की भर्ती के पड़े हैं, इनको इस बार जोड़ा नहीं गया। युवा बेरोजगार परेशान हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य मंत्रीजी को शायद इसका ध्यान नहीं होगा। अगर होता तो जरूर इस काम को करते। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि ये जो 1,200 के लगभग बैकलाग भर्तियां पिछली 2013 की पड़ी हैं, उनको 2018 के अन्दर जोड़ा जाए।

माननीय सभापति महोदय, यह पहला बजट है जिसमें सिक्खों के गुरू नानकदेव का भी जिक्र किया गया है। यह बजट आमजन के हर सुख को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। मैं इसका समर्थन करते हुए सरकार एवं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री नरेन्द्र नागर।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 20 तारीख को जो बजट पेश किया गया है, यह बजट पूरे राजस्थान में निश्चित रूप से सभी वर्गों के लिए निराशाजनक बजट पेश हुआ है। 'पहला सुख निरोगी काया', माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है। जब-जब भी राजस्थान में सरकार रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, चाहे पूर्व में कांग्रेस सरकार रही

(श्री नरेन्द्र नागर)

है, नि:शुल्क दवा योजना, नि:शुल्क जांच योजना और भामाशाह के द्वारा, पूर्व सरकार के द्वारा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वारा इलाज करवाया जाता था। बहुत सराहनीय कदम पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी का था। लोगों ने उस योजना की बहुत तारीफ की थी क्योंकि भामाशाह कार्ड, जिनको दो रुपये किलो राशन के गेहूं, जिनके खाद्य सुरक्षा में नाम थे, उनको केवल भामाशाह कार्ड लेकर जाना था, उनका इलाज निश्चित रूप से होता था। चूंकि सरकार बदल गयी। सरकार बदलने के बाद लगा कि भामाशाह कार्ड में पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी का फोटो है, उसकी वजह से बहुत दिनों तक यह चर्चा हुई कि इसको किस प्रकार से बंद किया जाए। निश्चित रूप से आपकी सरकार है, बंद करना चाहिए आपको, परंतु इसमें बहुत सारी दिक़्क़तें आयी हैं। वर्तमान में बहुत सारे मरीजों का इसकी वजह से इलाज नहीं हो पाया। वर्तमान में जो नये कार्ड बन रहे हैं, जन आधार कार्ड बन रहा है, वापस इसमें इलाज किया जा रहा है। 'आयुष्मान भारत', जो केन्द्र की योजना है, केन्द्र सरकार ने लागू किया है और राजस्थान की सरकार ने उसको लागू किया है, निश्चित रूप से आप भी धन्यवाद के पात्र हैं।

हमेशा पूर्व में मुख्य मंत्री और सरकार के द्वारा हर बजट भाषण में जिस प्रकार से बात की जाती है कि इतने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलेंगे, इतने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलेंगे, इतनी शय्याएं हम बढ़ाएंगे। परंतु वर्तमान में किस प्रकार के हालात हैं? हमारे पास डाक्टर्स नहीं हैं, हमारे पास मेल नर्स नहीं हैं, कम्पाउंडर नहीं हैं, इसके बावजूद भी हम पी.एच.सी. खोलेंगे, सी.एच.सी. खोलेंगे। जहां आलरेडी पी.एच.सी. खुली हुई है जहां आलरेडी सी.एच.सी. है, वहां पर डाक्टर नहीं हैं। सरकार बदलने के बाद जिस प्रकार से डाक्टर्स को हटा दिया गया है, वास्तव में सामुदायिक भवन में दो-दो डाक्टर्स के भरोसे अस्पताल चल रहा है। दुर्भाग्य है कि किस प्रकार से हम निरोगी इस राजस्थान को करना चाहते हैं? जिस प्रकार से नि:शुल्क दवा योजना लागू की है, दवाओं की संख्या बढ़ाई है परंतु डाक्टर वहां नहीं है। इस कारण से बहुत दिक्कत लोगों को आ रही है।

माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेद के लिए बीच में जितने भी प्रश्न हुए, उनमें बहुत-सी जगह तो राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति है, जबकि आयुर्वेद के लिए कहा जाता है कि आयुर्वेद के इलाज का कोई साइड-इफैक्ट नहीं होता है। पूरा देश इससे इलाज कराना चाहता है। परंतु स्थिति ऐसी है कि बहुत-सी जगह तो डाक्टर नहीं है, न कम्पाउंडर है, न कोई स्टाफ है, वहां पर

(श्री नरेन्द्र नागर)

ताले लगे हुए हैं। इस प्रकार की स्थिति वर्तमान में आयुर्वेद की है। इसके लिए भी सरकार को कहेंगे कि नयी वैकेंसी लाकर भर्ती करना चाहिए, जिससे कम से कम डाक्टर न हो तो कम्पाउंडर से अस्पताल तो चालू हो।

भारत कृषि प्रधान देश है और यहां पर 70 प्रतिशत लोग किसान हैं। किसानों की स्थिति जिस प्रकार की दिनों-दिन होती जा रही है, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, प्रकृति के प्रकोप हमेशा से किसानों पर हर साल या एक-दो साल छोड़कर होते आए हैं। इसके बावजूद भी केन्द्र सरकार द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस के द्वारा समर्थन मूल्य बढ़ाया जाता है। समर्थन मूल्य बढ़ने के बावजूद आज बाजार की क्या स्थिति है? आज हम बात करें, अभी पूर्व में उधर त्रिवेदी साहब जो कह रहे थे, मीना साहब जो कह रहे थे कि वर्तमान में सरसों का भाव 3,600-3,700 रुपये है, जबकि उसका समर्थन मूल्य 4,400 है। समर्थन मूल्य घोषित होने के बाद यह तय हो कि किसान की जितनी भी फसल है, वह निश्चित रूप से तुले। यह सुनिश्चित होना चाहिए। यदि बाजार भाव कम होता है तो कहीं न कहीं जो बीच का अन्तर है, उसको सरकार को वहन करना चाहिए, तब जाकर किसानों की स्थिति अच्छी हो सकती है। किसान अन्नदाता है, किसान किस प्रकार से अन्न पैदा करता है।

वर्तमान में बिजली की स्थिति आप सबको पता है। रात को थ्री-फेज बिजली दी जाती है। सरकार ने घोषणा की है कि आगे आने वाले तीन साल में हम दिन में बिजली देने की व्यवस्था करेंगे। परंतु सरकार आगे आने वाले तीन साल की कैसे व्यवस्था करेगी? सरकार ने पिछला बजट जो पेश किया, उसमें 40 परसेंट काम तो हुए नहीं, 60 परसेंट काम बाकी हैं। आज अनिता जी पूर्व में मुझको बता रही थी, माननीय अशोक गहलोत साहब का पिछले, दस साल पहले 2009 का जो बजट था, उसमें कहीं न कहीं चेंज करके आपने ये वर्तमान का बजट पेश कर दिया। उनके पास आंकड़े हैं, जब वे बोलेंगे तब बताएंगे। निश्चित रूप से इस प्रकार की स्थिति है। माननीय रामलाल जी ने बार-बार इस प्रकार का प्रश्न उठाने का प्रयास किया कि पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी घोषणाएं कीं, कितनी लागू कर पाये? इस पर ध्यान सरकार को देना चाहिए। इस पर दबाव बनाना चाहिए। बजट पास होते ही कोशिश करनी चाहिए कि आगे आने वाले समय में कम से कम 80 परसेंट काम निश्चित रूप से हों। हम मानते हैं कि पूरे काम नहीं हो सकते। 20 परसेंट काम रह सकते हैं, परंतु 80 परसेंट काम तो हों।

(श्री नरेन्द्र नागर)

किसानों पर विशेष रूप से सरकार ध्यान दे। सरकार ने माना है और विपक्ष ने सरकार को बार-बार घेरने का काम किया है। विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई है कि पिछले समय में खरीफ की फसल में पूरे राजस्थान में खराबा हुआ। उसका सरकार ने मुआवजा दिया है। मुआवजा देने के बाद स्थिति यह है कि ऊर्जा विभाग द्वारा वर्तमान में टार्गेट तय कर दिये गये हैं कि किसानों से पैसा वसूला जाए। सरकार यह मानती है कि खरीफ की फसल के लिए सरकार ने मुआवजा दिया है। सरकार यह मान रही है किसानों को दो बार या तो खरीफ में पैसा किसानों को आता है या रबी के समय में किसान का पैसा आता है। माननीय मंत्री महोदय, जब खरीफ की फसल खराब हो गयी तो रबी की फसल में जो पहली फसल आएगी, वह भी मार्च के पहले सरसों की फसल नहीं आ रही। मार्च में जब आपकी सरसों की फसल आएगी, जबकि सरसों ज्यादा नहीं होती और गेहूं तो अप्रैल-मई में आते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस वसूली को आप रोकें। आप जबर्दस्ती किसान का ट्रांसफार्मर उतार रहे हैं। किसान गेहूं को जो अंतिम पानी है, वह पानी नहीं दे पा रहा है। किसान दर-दर की ठोकर खा रहा है। हमें बार-बार फोन कर रहा है परंतु हम क्या करें? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की स्थिति को रोकें ताकि आगे आने वाले अप्रैल-मई में किसान का जो बाकी पैसा है, उसको आप वसूलें।

सरकार के द्वारा विशेष रूप से शिक्षा के बारे में बात की गयी। शिक्षा के लिए मैं कहना चाहता हूं 2003 से 2008 तक, मैं जब पहली बार राजस्थान की विधान सभा में आया, उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी थीं। उन्होंने एक आदेश से हर पंचायत में सैकण्डरी स्कूल खोलने का काम किया। उसके बाद 2013-2018 तक, मैं वापस आया, तब एक आदेश से सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलने का काम किया। मुख्य मंत्रीजी ने उस समय प्रयास किया कि रमसा के अन्दर, अभी वर्तमान में रमसा के अन्दर नाबार्ड योजना के मार्फत लोन लेकर काम चल रहा है, काम की स्थिति इस प्रकार की है कि ठेकेदारों ने काम बंद कर दिये। लगभग एक साल से उनको बजट के रूप में एक रुपया नहीं मिल रहा है। उनकी जितनी स्थिति थी, उतना उन्होंने काम किया, उसके बाद काम रुका पड़ा है। सीनियर स्कूल में 12वीं तक क्लासें होती हैं। बच्चों को बैठने की दिक्कत आती है। पुराने भवन को तोड़कर वहां नया भवन बनाया जा रहा है इसलिए पेड़ के नीचे बच्चे शिक्षा कैसे प्राप्त कर

(श्री नरेन्द्र नागर)

सकते है, सरकार को प्रयास करना चाहिए, बजट देना चाहिए। बार-बार सदन में चर्चा हुई।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): दो मिनट में कर रहा हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछली सरकार के द्वारा, चाहे एम.एल.ए. अनुशंसा की तरफ से मिसिंग लिंक सरकार ने सैंक्शन किये थे, उनकी पहली किश्त मिल चुकी थी, उनके काम चालू हो गये थे, गौरव पथ के रूप में काम चल रहे थे, उनके काम लगभग 10-20 परसेंट तक पूरे हो गये, एक साल से वे काम रुके हुए हैं। पहले तो फिर भी ग्रेवल सड़क थी, ग्रेवल सड़क की जगह उसमें मिट्टी डाल दी, बरसात के बाद उसमें बहुत दिक्कत आयी है। एक साल से सारे काम रुके हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नयी घोषणा को तो आप ताक पर रखो, जो पूर्व की घोषणा थी उसको पूरी करो। हमेशा जो भी सरकार रही है, चाहे आप 2008-2013 में रहे, 2013 की स्थिति मुझे पता है, हमने राजस्थान में टी वी, अख़बार के माध्यम से, अशोक गहलोत जी मुख्य मंत्री थे, जहां-जहां वे गये, उस समय जो तत्कालीन एम.एल.ए. थे, या अपने आपको प्रत्याक्षी समझते थे, उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्रीजी यह घोषणा करो, तो मुख्य मंत्री ने कालेज खोल दिया, मुख्य मंत्रीजी नगरपालिका बनाओ, तो नगरपालिका की घोषणा कर दी। जो-जो घोषणा तत्कालीन सरकार ने की, जब वसुन्धरा जी सरकार में आयीं तो उन्हें भी दिक्कत आयी।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्योंकि तत्कालीन सरकार होती है, जाते-जाते जो कहा जाता है, निश्चित रूप से घोषणा करती है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान का बजट है, उससे निराशा हाथ लगी है। राजस्थान में उदासीनता है। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती निर्मला सहरिया।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें समाज के सभी वर्गों, किसान, दलित, गरीब, मजदूर का ध्यान रखा गया है। यह बजट राजस्थान को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने वाला बजट है। पिछली भा.ज.पा. सरकार के कुशासन और गलत नीतियों के कारण इन्होंने प्रदेश को खस्ता हाल

(श्रीमती निर्मला सहरिया)

अर्थव्यवस्था सौंपी थी। हमारे मुख्य मंत्री अपनी संवेदनशीलता, मेहनत से प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी को इस विशेष बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहती हूं।

हमारे देश के शिक्षित युवा बेरोजगार भटक रहे हैं। पिछली सरकार ने 2013 के विधान सभा चुनाव के समय पार्टी के घोषणा-पत्र में 15 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। भा.ज.पा. की सरकार ने रोजगार शिविर लगाने में भी 339 करोड़ रुपये खर्च किये थे। पांच साल में केवल 765 लोगों को ही नौकरी दी। भा.ज.पा. की सरकार ने बेरोजगार युवाओं को गुमराह किया लेकिन हमारे मुख्य मंत्रीजी ने पिछले बजट में 75 हजार की घोषणा की। बजट में 53 हजार बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का निर्णय लिया। पूरे प्रदेश में युवा सरकार के इस निर्णय से खुश हैं, मैं इसके लिए मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं।

सभापति महोदय, इस बजट में सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगंज, जिला बारां में विकास की कई सौगातें दी हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के नाहरगढ़ में 132 के.वी. जी.एस.एस. की मांग काफी समय से चली आ रही थी, जिसका सरकार ने ध्यान रखा और मेरे विधान सभा क्षेत्र को यह तोहफा दिया, मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। सरकार ने मेरे समरानिया और नाहरगढ़ में भी स्वतंत्र मंडियों की घोषणा की, उसके लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। विकास की ऐतिहासिक घोषणाओं के लिए मैं मेरे क्षेत्र की जनता और मेरी तरफ से मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में सात संकल्प पेश किये हैं। निरोगी राजस्थान योजना को पहले स्थान पर रखा है। निरोगी राजस्थान के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हमारे मुख्य मंत्रीजी जनता के स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु अच्छा कार्य कर रहे हैं।

सभापति महोदय, प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बैड्स की कमी होना बड़ी समस्या थी, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी व चिकित्सा मंत्री ने इस ओर ध्यान दिया। प्रदेश के 150 अस्पतालों में एक हजार बैड़ दिये, इससे रोगियों को काफी सुविधा मिली।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र

(श्रीमती निर्मला सहरिया)

किशनगंज की कुछ समस्याएं हैं, उनसे राज्य सरकार को अवगत कराना चाहूंगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में आपात स्थिति में इलाज करने के लिए राज्य सरकार की ओर से खोले गये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में विशेषज्ञों की नियुक्ति नहीं होने से रैफर अस्पताल बनकर रह गया है। लोगों को गम्भीर परिस्थितियों में बारां रैफर कर दिया जाता है। ज़िले में डाक्टर, ए.एन.एम., जी.एन.एम. की प्रतिनियुक्तियां की गयी हैं। चिकित्सक और नर्सिंग कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। पूरे इलाक़े के स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था रिक्त पदों के चलते चरमरा रही है। अस्पतालों में संसाधनों का अभाव है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र, सीमावर्ती इलाका है, इस ओर विशेष ध्यान देकर चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरा जाए। चिकित्सा सेवा विस्तार हेतु कदम उठाए जाएं।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ज्वलंत समस्या है। जलवाड़ा, बराना, नाहरगढ़ स्टेट हाईवे-72 पर देगनी गांव के पास रपट हर बारिश में डूब जाती है। वाहन चालकों को किशनगंज होते हुए जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। जलवाड़ा, बराना, नाहरगढ़ स्टेट हाईवे-72 पर देगनी गांव के पास स्थित पानल नदी पुलिया पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण करवाया जाए, ताकि वहां की जनता को लाभ मिल सके। पार्वती की देगनी पुलिया पर बड़े हादसे हो चुके हैं। सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि देगनी पुलिया पर बड़ा पुल बनाया जाए। मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग से चाहती हूं कि वे भी मेरे 132 देगनी पर बहुत बड़ा पुल बनवाएं।

सभापति महोदय, किशनगंज में पर्यटन की काफी सम्भावनाएं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए विधान सभा क्षेत्र से होकर ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर के तहत नेशनल हाईवे 27 गुजर रहा है। कोटा, बूंदी एवं झालावाड़ पहुंचने वाले पर्यटक इसी हाईवे से होकर मध्य प्रदेश के शिवपुरी, ग्वालियर, खजुराहो एवं कान्हा नेशनल पार्क, ऊनो अभयारण्य, उत्तर प्रदेश के झांसी सहित विभिन्न स्थानों के लिए गुजरते हैं।

वर्तमान में मेरे शाहाबाद में देशी-विदेशी पर्यटकों का ठहराव नहीं है। मैं चाहती हूं कि मेरे शाहाबाद उप खण्ड में पर्यटकों का ठहराव हो। इसके लिए वहां एक बड़ी बिल्डिंग बनायी जाए। पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि शाहाबाद में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाये।

(श्रीमती निर्मला सहरिया)

सभापति महोदय, शाहाबाद के जंगल हाड़ौती में सबसे सघन वन क्षेत्र हैं। वहां करीब 30 साल पहले तक टाइगर का मूवमेंट बना रहता था। वर्तमान में पैंथर, भालू, जरख सहित अन्य वन्य जीव यहां पर विचरण करते हैं। शाहाबाद से सटे मध्य प्रदेश के जंगल को ऊनो अभयारण्य में बदला गया। लेकिन अभी तक शाहाबाद के वन क्षेत्र को अभयारण्य का दर्जा नहीं मिला। मेरी सरकार से मांग है कि इसका विशेष ध्यान रखकर शाहाबाद के वन्य क्षेत्र को अभयारण्य का दर्जा मिले।

सभापति महोदय, शाहाबाद के उप खण्ड मुख्यालय पर खिलाड़ियों के लिए भी एक स्टेडियम दिया जाए, जिससे मेरे क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को काफी लाभ होगा। वहां खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन में काफी समस्या हो रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि शाहाबाद उप खण्ड मुख्यालय ...(व्यवधान) खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम का निर्माण कराया जाए।

श्री सभापति: कितने पन्ने और हैं?

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): मैंने ज्यादा नहीं बनाया है, साहब।

सभापति महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमारी सरकार प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अच्छा काम कर रही है। उच्च शिक्षा में बालिकाओं की शिक्षा को नि:शुल्क कर दिया गया है। सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र है। वहां अधिकांश आबादी निर्धन है। शाहाबाद में पोलीटेक्निक कालेज नहीं होने से होनहार विद्यार्थी, जो तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन 40 किलोमीटर दूर बारां अथवा कोटा नहीं जा सकते, मेरा सरकार से अनुरोध है कि शाहाबाद में पोलीटेक्निक कालेज खोला जाए। सभापति महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्य मंत्रीजी मुझे इसमें पूरा आश्वस्त करेंगे। साथ ही आपने जो मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जगसी राम।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अलाउ नहीं करूंगा। विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज, प्लीज सहयोग करें। माननीय सदस्य, बहुत सदस्य बोलने वाले हैं, 8 बजे हाउस एडजोर्न हो जाएगा। आप बार-बार क्यों इंटरवीन करते हैं।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय सभापति महोदय, आज बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका आभार, धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, शांति रखें।

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, 20 फरवरी, 2020 को माननीय मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण में प्रथम एवं द्वितीय पृष्ठ पर मुख्य मंत्रीजी केन्द्र और गत भा.ज.पा. सरकार को कोसते नजर आये।

भारतीय अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए सुदृढ़ करने की मंशा से केन्द्र सरकार देश के प्रत्येक नागरिक को स्वावलम्बी बनाकर अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा रही है। भारत के आम देशवासी को आयुष्मान भारत जैसी शानदार स्कीम से निरोगी भारत के निर्माण में जुटी केन्द्र सरकार विविधता में एकता को बरकरार रखते हुए भारत के कोने-कोने में विकास की गंगा बहाने के लिए आमजन के हितार्थ पर्याप्त योजनाएं और स्कीम्स लांच कर चुकी है। अन्य प्रदेश इन योजनाओं और स्कीम्स का लाभ प्रदेश की जनता को दे रहे हैं।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार की बुराई का बखान करने वाली राजस्थान सरकार आमजन के लिए केन्द्र सरकार की योजनाओं और स्कीम्स के लक्ष्य पूरे नहीं कर पा रही है। प्रदेश सरकार समय पर बजट खर्च ही नहीं कर पा रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत हो या वित्त आयोग, प्रदेश को आबंटित बजट के जनवरी, 2019 से जनवरी, 2020 तक के आंकड़े देखें जाएं तो साफ झलकता है कि प्रदेश सरकार काम ही नहीं करना चाहती है और केन्द्रीय योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों को देना ही नहीं चाहती है।

सभापति महोदय, वर्ष 2013 से 2018 तक की गत भा.ज.पा. सरकार पर ठीकरा फोड़ने वाली प्रदेश सरकार पहले जब सत्ता में आयी थी, तब भी अपने दिवालियेपन का रोना रोती रही। आज भी खजाना खाली होने का राग अलाप रही है। अपने बयानों से, अपने कर्मों से प्रदेश की साख को बट्टा लगाया जा रहा है। ऐसी हालत में बाहरी लोग प्रदेश में निवेश करने से भी डर रहे हैं। आज सरकार का ब्यूरो आफ इन्वेस्टमेंट विभाग हाथ पर हाथ रख कर बैठा है।

(श्री जगसी राम)

सभापति महोदय, सरकारी भुगतान रोके जा रहे हैं। कर्मचारियों को समय पर पेंशन और ग्रेच्युटी, आहरण, सेवानिवृत्ति पर देय आर्थिक लाभ, यहां तक कि वेतन वृद्धि भी समय पर नहीं दी जा रही है। यही हाल सरकारी विभागों में विभिन्न आधारभूत कार्य करने वाले श्रमिकों, ठेकेदारों का भी है। उनके बिलों का भुगतान आज तक नहीं किया जा रहा है।

सभापति महोदय, बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बढ़-चढ़कर फख्र के साथ समूचे प्रदेश को अपना परिवार बताकर बड़े-बड़े संकल्पों का बखान किया है, मैं आपके माध्यम से इनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा।

पहला संकल्प निरोगी राजस्थान है। सभापति महोदय, 'निरोगी राजस्थान' के नाम से आपने जो बड़ी-बड़ी बातें कही हैं, डेंगू को नोटिफाइड डिजीज की घोषणा करने के बावजूद इलाज के उपचार में निर्धारित मापदण्डों की पालना नहीं की जा रही है। जनवरी, 2019 से अब तक प्रदेश की सरकारी चिकित्सा इकाइयों में नवजात शिशुओं की अकाल मौतों से समूचा प्रदेश वाकिफ है। सभापति महोदय, प्रदेश सरकार निजी चिकित्सा संस्थाओं, निजी मेडिकल कालेजों, निजी दवा विक्रेताओं, इम्प्लांट विक्रेताओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है।

सभापति महोदय, प्रदेश की राजकीय चिकित्सा इकाइयों में आप देखने जाएं तो पूरे प्रदेश के अन्दर चिकित्सकों की बिलकुल कमी है। इस मौके पर मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान और विशेषकर सिरोही जिले तथा मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर के अन्दर सबसे ज्यादा चिकित्सकों के पद रिक्त पड़े हैं। जबकि मुख्य मंत्रीजी 'निरोगी राजस्थान' कह रहे हैं, ऐसे 'निरोगी राजस्थान' नहीं माना जाएगा।

सभापति महोदय, प्रदेश के स्वास्थ्य से जुड़े अहम मुद्दे, मिलावट का सरकार में बोलबाला चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की जनता गंदे पानी और गंदे नालों में पैदा किये जा रहे बहुत कीटनाशकों के भरपूर उपयोग से उत्पन्न फसलें, मसाले, सब्जियां, फल आदि खाने को मजबूर है। सरकार के पास न तो जांच करने के लिए लैब मशीन है और न ही जांचने वाले लोग हैं, न ही कोई रोकने वाले हैं और न ही कोई टोकने वाले हैं। सभी को जहर खिलाया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, इस राज में यही नहीं प्रदेश में आम जनता के बीच जन-जन को स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा

(श्री जगसी राम)

है। दिल्ली जैसा प्रदूषण प्रदेश में पैर पसारने लगा है। माननीय सभापति महोदय, सरकार सोई हुई है, ऐसा है गहलोत साहब का 'निरोगी राजस्थान'। पहले आम बजट में जो बीमार किया जा रहा था, पहले आमजन को बीमार किया जा रहा है और फिर जनता क्लीनिक भी वहां खोला जा रहा है, जहां पर उनकी आवश्यकता नहीं है, वहां पर हास्पिटल खोला जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा संकल्प 'सम्पन्न किसान' है। जब किसानों की बात की जा रही है तो मैं इस अवसर पर यह बताना चाहूंगा कि किसानों की ऋण माफी नहीं की जा रही है, जिसका वादा कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में किया था। आज प्रदेश के लाखों किसान सरकारी वित्तीय संस्थानों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋण भार से दबे पड़े हैं और किसानों को अपनी पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, पैदावार को खरीदने की माकूल व्यवस्था भी नहीं की जा रही है। किसान को अपनी पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। किसान अपने राजस्व मामले सुलझाने के लिए जिला मुख्यालय, सम्भागीय आयुक्त कार्यालयों में चक्कर खा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, टिड्डी, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से पीड़ितों को अपने खसरा, रकबा खराबे के हिसाब से मुआवजा नहीं मिल रहा है और बीमित ऋणी किसानों को दुर्घटनाओं के क्लेम आदि भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बीमा कम्पनियां नहीं दे रही हैं।

बिजली की दरें बढ़ा दी गयी हैं। किसानों के लिए जब अनुदान बंद होगा तो किसानों की कमर टूट जाएगी और वे बिजली का बिल जमा नहीं करवा पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, हालात यहां तक खराब हो गये हैं कि प्रदेश में कोई किसान आत्महत्या करता है तो उसकी जिम्मेदारी लेने और उसकी फाइल, पत्रावली चलाने के लिए सरकार के पास कोई जिम्मेदार विभाग नहीं है। प्रदेश के किसान का हाल बेहाल है। इस राज में यह तो मैंने मुख्य-मुख्य बिंदुओं पर ही प्रकाश डाला है।

आपका जो तीसरा संकल्प है, जो कि मुख्य मंत्रीजी ने दिया है, 'महिला, बाल एवं वृद्ध कल्याण'। जब महिला, बाल एवं वृद्ध कल्याण की बात कर रहे हैं, आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित, पीड़ित, अपराधों से ग्रसित है तो वह प्रदेश की महिला है। बलात्कार, छेड़खानी के सरकारी आकड़े भी यह बयान कर

(श्री जगसी राम)

रहे हैं। बच्चे असुरक्षित हैं, माननीय सभापति महोदय, गायब हो रहे हैं, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति के लिए मजबूर हो रहे हैं। मूक-बधिरों के सरकारी संस्थान बंद कर दिये गये हैं। 'मिड डे मील' की गुणवत्ता नयी बीमारी का घर बना हुआ है। 'मिड डे मील' की जब बात करें तो, माननीय सभापति महोदय, आज सरकारी स्कूलों के अन्दर 'मिड डे मील' और जो दूध वाली स्कीम है, उसके लिए देने के लिए भी सरकार के पास में पैसा नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात को दो मिनट में समाप्त करें।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय सभापति महोदय, मैं यह स्पष्ट बात बताना चाहूंगा कि चौथा संकल्प 'सक्षम मजदूर, छात्र-युवा-जवान' है। मजदूर की श्रमिक डायरी भी नहीं बनायी जा रही है। माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, प्रदेश के श्रम कार्यालयों में भ्रष्टाचार की मंशा के लम्बित आवेदनों का अम्बार लगा हुआ है। सभी जिलों के हालात एक समान ही हैं। श्रमिकों के अध्ययनरत बच्चों को बीच सत्र में नियमों में फेरबदल कर छात्रवृत्ति से वंचित किया गया है। प्रदेश के लाखों मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई में बाधा पैदा कर दी गयी है। युवा, छात्र, जवान, प्रत्येक वर्ग के पीड़ित छात्र-छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। माननीय सभापति महोदय, छात्र पत्रावली, पहचान नहीं किया जा रहा है। प्रदेश के युवा वर्ग को बेरोजगारी भत्ते का सपना दिखाकर उनकी कमर तोड़ दी गयी है। प्रदेश के प्रतियोगी युवा सड़कों पर नजर आ रहे हैं, वे आंदोलनरत हैं। न तो सरकार समय पर अभ्यर्थनाएं ले रही है और न ही प्रदेश के कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा समय पर सरकारी भर्तियां की जा रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपने पांचवां जो संकल्प दिया है, मुख्य मंत्रीजी ने दिया है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जगसी राम (रेवदर): सिर्फ दो मिनट। मैं मेरी बात को पूरी कर रहा हूं।

श्री सभापति: श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्री जगसी राम (रेवदर): पांचवां संकल्प, 'शिक्षा का परिधान।'

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री जगसी राम (रेवदर): प्रदेश के स्कूलों में भवन, पेयजल, खेल मैदान ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें। विराजिए। अंकित नहीं होगा। श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्री जगसी राम (रेवदर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। अंकित नहीं होगा। अब आप विराजिए। सहयोग करें। माननीय सदस्य, सहयोग करें। काफी लोग बोलने वाले हैं। प्लीज, आप विराजिए।

श्री जगसी राम (रेवदर): 000

श्री सभापति: विराजिए। आप विराजिए। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है, आप समय खराब मत करिए।

श्री जगसी राम (रेवदर): 000

श्री सभापति: आप विराजिए, अंकित नहीं होगा। विराजिए। यह बार-बार किस बात की जिद है?

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने ...(व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट, माननीय सदस्य। जितने भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, आठ बजे यह हाउस एडजोर्न हो जाएगा। आप बार-बार इस तरह से इंटरवीन करके बाकी जो लोग बोलने वाले हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। दस मिनट का समय आपको दिया जा रहा है, मेहरबानी करके आप समय का ध्यान रखें और आवश्यक रूप से बैठ जाएं। श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोकजी गहलोत ने 20 जनवरी, 2020 को जो बजट राज्य की जनता को दिया है, वह बजट निश्चित रूप से बहुत बढ़िया बजट है, लोक हित में है, मैं उसके समर्थन में अपनी बात प्रारम्भ कर रहा हूं।

सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजट से पहले विरासत में हमको जो स्थिति मिली, उस स्थिति पर हमें विचार करना चाहिए। गत सरकार से 3 लाख 10 हजार करोड़ का ऋण-भार मिला। तेरह हजार करोड़ के पैंडिंग कार्यों का भुगतान मिला, जो आनन-फानन में गत सरकार ने करवा लिए और भुगतान करके नहीं गयी। ऐसी स्थिति में भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट दिया, उसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इसमें राजस्व प्राप्तियां भी ज्यादा हैं और राजस्व व्यय भी गत वर्ष की तुलना में ज्यादा है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): हमें सरकार वापस दे दो, हम कर देंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण के पैरा 3 में जो बात अंकित की है कि संघीय व्यवस्था में राज्यों की वित्तीय स्थिति काफी हद तक केन्द्र सरकार की नीतियों एवं निर्णयों पर निर्भर करती है। अधिकांश सूचकांक यह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है।

यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि विरासत में जो आर्थिक परिप्रेक्ष्य हमें मिला है, जिन परिस्थितियों में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह बजट राज्य को दिया है, उन पर विचार करना जरूरी है, एक्सटर्नल जो ऋण है वह अपने देश पर 500 प्लस बिलियन डालर है। बी.एस.एन.एल. जो देश की इतनी इम्पोर्टेंट संस्था है, 14 हजार करोड़ रुपये के ऋण-भार में है। स्टील अथोरिटी आफ इंडिया 286 करोड़ रुपये के ऋण-भार में है। एयर इंडिया में 4,600 करोड़ रुपये का लोस है और इसी प्रकार बी.एच.ई.एल. में 219 करोड़ रुपये का लोस है। इंडियन पोस्ट में 15 हजार करोड़ रुपये का लोस है। आप अगर बैंकों की बात करें तो यस बैंक 600 करोड़ रुपये के लोस में है। यूनियन बैंक 1,190 करोड़ रुपये के लोस में है। पी.एन.बी. 4,750 करोड़ रुपये के लोस में है। एक्सिस बैंक 112 करोड़ रुपये के लोस में है। पांच एयरपोर्ट बेच दिये गये हैं। रेलवे को बेचना चाहते हैं। नेशनलाइज्ड बैंक्स का मर्जर करने के बाद स्थिति ज्यादा बुरी हुई है। 36 जो सबसे बड़े देश के कर्जदार हैं, वे देश के बाहर भाग चुके हैं और 2.40 लाख करोड़ रुपये के जो लोन्स हैं, बड़े-बड़े घरानों के, माफ कर दिये गये हैं। बी.एस.एन.एल. में 54 हजार कर्मचारियों का जाब और जाने वाला है। आटो इंडस्ट्री में एक मिलियन जोब को लेड-आफ कर दिया गया है। इसी प्रकार से जब ऐसी स्थिति देश में चल रही है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसका पूरा का पूरा प्रभाव राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ना लाजमी है, क्योंकि संघीय व्यवस्था में राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, वह प्रभावित होती है।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सात संकल्प माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने लिए हैं, वे निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसा के काबिल हैं और हमारे राज्य का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा, चाहे वह बालक हो, चाहे बालिका हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे गरीब हो, चाहे

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

दलित हो, चाहे अमीर हो, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सबकी नीड्स को यह बजट पूरा करता है।

दूसरा, सात संकल्पों के अलावा राज्य में दो बोर्ड बड़े महत्वपूर्ण बनाये गये हैं, दो संगठन बड़े महत्वपूर्ण बनाये गये हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड, ताकि जो 10 परसेंट आरक्षण सवर्णों को मिला है, उसका बहुत अच्छी तरह से परिचालन हो सके, वह रैगुलेट हो सके और वास्तव में उनको फायदा मिल सके। दूसरा, जो बोर्ड आफ इन्वेस्टमेंट अंडर द चेयरमैनशिप आफ द सी.एम. आया है, उससे सिंगल विण्डो एक्ट भी आएगा और वन स्टाप वन शाप का जो कान्सेप्ट है, वह फलीभूत होगा। दूसरा, इसमें जो नीतियां प्रस्तुत की गयी हैं, उनका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा और पूरे दिल से उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा, महिला कल्याण नीति, राजस्थान फार्मर प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन नीति, हस्तशिल्प नीति। एक जो काडर बनाने की बात आयी है, वह बजट में बहुत शानदार है। कम्प्यूटर टीचर्स का अलग कॉडर बनेगा और राजीव गांधी ई-कंटेंट बैंक खोला जाएगा। कोचिंग हब, जो प्रताप नगर में 65 हजार वर्गमीटर में खोला जा रहा है, वह भी विद्यार्थियों के कैरियर के लिए, कोचिंग की व्यवस्था से फायदा उठाने के लिए घूम रहे हैं, उन लोगों के लिए यह कोचिंग हब बहुत काम आएगा। इस बजट के माध्यम से जो कोष स्थापित किये गये हैं, उनकी भी मैं प्रशंसा करता हूं। जैसे कृषक कल्याण कोष है, इंदिरा महिला शक्ति निधि है, निरोगी राजस्थान प्रबन्धन कोष है, नेहरू बाल संरक्षण कोष है, पर्यटन विकास कोष है। यह सब कोष इस प्रकार के हैं कि जो राज्य की जनता के विभिन्न वर्गों को बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाएंगे और किसी-न-किसी प्रकार से इनका लाभ प्रदेश की जनता को किसी-न-किसी रूप में मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। सबसे बड़ी समस्या मेरे विधान सभा क्षेत्र पिलानी की पानी की है। चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल का कंसेप्ट पेपर और डी.पी.आर. कम्पनी ने बना लिया है। विभाग ने, एक पीडीकोर कम्पनी है, उसको आर्डर दिया था। पिलानी विधान सभा क्षेत्र के लिए 551 करोड़ की वह योजना बनी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन की योजना, जो भारत सरकार की है, उसमें सरकार का हिस्सा 50 प्रतिशत है। हालांकि 90 प्रतिशत के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने केन्द्र

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

सरकार को निवेदन कर दिया है। जब नोर्थ-ईस्ट स्टेट्स को 90 प्रतिशत मिल रहा है, केन्द्र शासित प्रदेशों को 90 प्रतिशत मिल रहा है तो राजस्थान की विकट परिस्थितियां हैं, यहां पर क्यों नहीं मिले? लेकिन आज की परिस्थितियों में भी 50 प्रतिशत जो गवर्नमेंट आफ इंडिया से आएगा, 551 करोड़ का है, 275 करोड़ वहां से आता है, तो राज्य को आधा पैसा ही खर्च करना पड़ेगा। मैं निवेदन करता हूं कि मलसीसर में जो प्रोजेक्ट का इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप किया हुआ है, झुंझुनूं जिले में ही, वहां सब कुछ तैयार हो चुका है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मंडरेला से पाइप लाइन जा रही है। उनको चिड़ावा से खाली जोड़ना है जिससे पिलानी विधान सभा क्षेत्र को वहां से पानी मिल सकता है। मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि 27 तारीख को जब माननीय मुख्य मंत्री महोदय जवाब दें तो पिलानी विधान सभा क्षेत्र में जो पेयजल का संकट सामने आ रहा है, उसके लिए जरूर घोषणा करें कि कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट से इसी सत्र में, इसी साल में पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा। दूसरा, हो यह रहा है कि लाइनें हमारे यहां से जा रही हैं। मंडरेला से लाइनें जा रही हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र से लाइनें जा रही हैं। जैसे कोई ट्रेन, माननीय सभापति महोदय, आपके घर के सामने से जा रही हो और आपको उसमें चढ़ने नहीं दें, यह स्थिति हो रही हे। जब पाइप लाइन जा रही है तो फिर हमें उसका फायदा मिलना चाहिए। हमारे यहां से पाइप लाइन जा रही है। चिड़ावा को कनैक्ट करना है और पानी की समस्या साल्व हो रही है तो मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करता हूं कि यह समस्या दूर होनी चाहिए। वहां बहुत गम्भीर स्थिति है। नाइट्रेट, फ्लोराइड और टी.डी.एस. की मात्रा, डब्ल्यू.एच.ओ. की बात छोड़िए, जो हमारे यहां परमिशनेबल लिमिट है, उससे भी बहुत ज्यादा अधिक है। इससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। वहां पर कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल का पानी आएगा, लोगों को पीने का पानी तो कम से कम मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, जो खेतों में कुएं हैं, उनका जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है। इसी संदर्भ में मैं निवेदन करता हूं कि कृषकों के लिए जिनके कुएं सूख रहे हैं, उनमें से प्रत्येक कृषक को कम से कम एक कुण्ड नरेगा के माध्यम से स्वीकृत करना चाहिए ताकि वे वर्षा का जल संग्रहित करके अपने पीने के पानी की पूर्ति कर सकें।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरा

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

निवेदन करना चाहता हूं पिछली बार सरकार ने बजट में उप खण्ड स्तर पर महाविद्यालय खोलने की बात की थी। मेरा चिड़ावा बहुत पुराना उप खण्ड है और वहां राजकीय महाविद्यालय नहीं है। मैंने विधान सभा में एक प्रश्न किया था, उसका जवाब आया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। मेरे यहां का जो इलाका है, वह गरीब किसानों का है, दलितों का है, निर्धनों का है, वे प्राइवेट कालेजेज में, प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। वहां की लड़कियां दूर नहीं जा सकतीं और इस कारण लड़कियों ने पढ़ना बंद कर दिया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि चिड़ावा में जो उप खण्ड स्तर है, वहां पर राज्य सरकार की नीति के अनुसार चिड़ावा में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना चाहिए। अगेन, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं मैंने अनेक बार कह दिया है और मैं आभार भी प्रकट करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय का भी एक्नोलेजमेंट मेरे पास आया है, माननीय हायर एजुकेशन मिनिस्टर का भी आया है और सैक्रेटरी के यहां से भी आया है कि वे करेंगे। मुझे उम्मीद है कि 27 तारीख को इस बात की घोषणा होगी।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से एक निवेदन बहुत इम्पोर्टेंट है, जब पिछली बार हमारी पूर्व मुख्य मंत्री महोदया ने गौरव यात्रा निकाली थी तो हमारे युवा साथियों के, एन.एस.यू.आई. और यूथ कांग्रेस के नौजवानों के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया था। उनका लोकतांत्रिक अधिकार था कि वे शांतिपूर्ण ढंग से अपने नारे लगाएं, गलत नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाएं। मैं माननीय विधि मंत्री महोदय, जो अभी सदन के अन्दर मौजूद हैं, माननीय धारीवाल साहब, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एन.एस.यू.आई. और यूथ कांग्रेस के नौजवानों के विरुद्ध गलत मुकदमा, वह मुकदमा भी क्या लगाया है कि आपने पशुओं को ट्रेन करके महारानी की यात्रा के सामने ला दिया। हमारे एन.एस.यू.आई. के लोग कब से पशुओं को ट्रेन करने लगे, मेरी यही समझ में नहीं आया। मुकदमा नम्बर 197/18 झुंझुनूं जिले का बगड़ थाना, वहां यह मुकदमा कांग्रेस के नौजवानों के विरुद्ध लगा हुआ है। मैं विनम्र निवेदन करता हूं, मैं पहले भी आपको लिखकर दे चुका हूं, वह मुकदमा वापस होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 81 रोड्स की लिस्ट मैंने भेजी है। जो बजट देखा है, उसमें रोड स्पेसिफाई कर दी

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

गयी है कि हमारी रोड्स का क्या होगा। मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि रोड्स के लिए मुझे भी और मेरे जो दूसरे एम.एल.ए. साथी हैं, उनको कुछ-न-कुछ पैसा मिलना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अंत में निवेदन करता हूं कि चिड़ावा में पोलोटैक्निक कालेज की व्यवस्था नहीं है, वह खोला जाए। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: समाप्त करें, धन्यवाद। श्री अमृतलाल।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, यह नेता, प्रतिपक्ष और उप नेता दोनों ही गायब हैं। अजमेर में लोकेशन पायी गयी है।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): यहां तीर-कमान किसके हाथ में है, बता दो साहब।

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा। विराजिए, प्लीज, सहयोग करें।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2020-21 पर बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। 2020-21 का मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया, लच्छेदार बजट भाषण में खूब मेजें थपथपायीं। मैं बताना चाहूंगा आपने 7 संकल्पों, 64 पेज और 242 बिन्दुओं पर रखा। हमारे सहकारिता मंत्रीजी मेवाड़ से आते हैं। ये उस मेवाड़ के रीति-रिवाज, शौर्य और वीरता से भली-भांति परिचित हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो सात संकल्प हैं, मैं निरोगी राजस्थान पर नहीं जाऊंगा, न सम्पन्न किसान पर जाऊंगा, न महिला तथा बाल कल्याण पर जाऊंगा, न सक्षम मजदूर और युवाओं पर जाऊंगा। शिक्षा की बात, पानी, बिजली और सबका मान, कौशल तकनीकी। मैं यह कहना चाहूंगा हम 2013 से लेकर 2018 तक थे। बानसूर से माननीय विधायक, शकुन्तला जी रावत हमारे बीच में हैं। माननीय सभापति महोदय, आप नहीं थे, मैं चिकित्सा मंत्रीजी को यह कहना चाहता हूं, आप और हम साथ में खेले हैं। अजमेर में खेले हैं, ईमानदारी की बात कह रहा हूं मैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपकी सीट दिखवानी पड़ेगी मुझे। आपकी सीट में कोई प्राब्लम है क्या?

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): मैंने 25 साल की नौकरी अजमेर में की। हमारे उप मुख्य सचेतक महोदय और हम भी साथ में खेले हैं। मेवाड़ की बात आप जानते हैं। सड़कों का अनुभव आपको भी है, आप जब विधायक 2013 से 2018 में थीं, आपको बहु त सड़कें मिलीं, मिसिंग लिंक सड़कें भी मिलीं।

श्री सभापति: अपने खुद की समस्याओं के बारे में बोल दीजिए ताकि समय नहीं मांगना पड़े। कहां माननीय विधायक और कहां माननीय कर रहे हो आप। अपनी समस्याएं बोलिए आप।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): एक भी नहीं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिए। अंकित नहीं होगा, विराजिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): पंचायत के मामले में मेरे विधान सभा क्षेत्र में 153 करोड़ जयसमंद झील का, नहरों के सुदृढ़ीकरण का पैसा मुझे 2013-18 में मिला। 500 से ऊपर सड़कें मिलीं, पेयजल प्रत्येक गांव में, और जो शिक्षा की बात आती है, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर 12वीं करने का आपको भी पंचायतों का मिला, हमें भी मिला। यह बात मार्के की है, सही है, सत्य है।

चिकित्सा, मेरे क्षेत्र में सात प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु उप-स्वास्थ्य केन्द्र हमने प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर खोलने का काम किया। किसानों की बात आती है, मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब 4 दिसम्बर को आये, उन्होंने घोषणा की कि किसानों का दो लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, युवाओं को 3,500 रुपये देंगे। यह सारी बात होने के बाद, अगर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषणा कर जाएं और सही तरीके से नहीं हो। आज महिला परेशान है, युवा परेशान है, मजदूर परेशान है।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा विस्तार में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगा। चिकित्सा मंत्रीजी, मैं लगातार 14 महीने से प्रयास कर रहा हूं, आपके नजदीक आने का, लेकिन आप बिलकुल जगह नहीं दे रहे हैं। हंस लेंगे, काम कर लेंगे। मेरे सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में सामान्य हास्पिटल है, उदयपुर जिले के बाद सबसे बड़ा हास्पिटल है, पूरा जनजातीय क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र है, वहां 200 बैड का हास्पिटल करने की जरूरत है। अगर आपका और हमारा 25 साल का नाता रहा है तो आप जोर-शोर से सामान्य हास्पिटल सलूम्बर की घोषणा करें।

(श्री अमृतलाल मीणा)

दूसरा, सभापति महोदय, मेरे जयसमंद झील विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। उस झील की परिधि में 93 विलेज हैं, 72 गांव सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र के और 21 गांव लसाड़िया पंचायत समिति और धरियावद विधान सभा क्षेत्र में, उनको शुद्ध पेयजल पिलाने की योजना है वह अभी तक आपके विभाग में ही पड़ी है। उसको मंगा करके उसकी परिधि में जो लोग निवास कर रहे हैं, उनको शुद्ध पेयजल पिलाने की व्यवस्था की जाए।

दूसरा, मैं यह कहना चाहूंगा, हमारे सहकारिता मंत्रीजी भी विराजमान हैं, माही का पानी बह करके गुजरात जाता है। अगर उस पानी को रोक करके, धरियावद के पास दांतलिया डैम है, जयसमंद को हमेशा के लिए भर करके, वल्लभनगर है, मावली है, सहकारिता मंत्रीजी, निम्बाहेड़ा तक भी ले जा सकते हैं, इतना पानी है। सभापति महोदय, आपने जयसमंद झील की सैर की या नहीं की, आप देखें तो मुम्बई का जो दरिया है...

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): करा दो न।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): साहब, अब के ले जाऊंगा, आपको भी ले जाने वाला हूं।

मुम्बई का जो सीन देखते हैं, इस प्रकार से जयसमंद, पानी इतना दूर दराज है, वाकई में आपमें से किसी ने भ्रमण किया होगा, तो वह बह करके जाए जयसमंद भरने के लिए। तीसरा, टीडी नदी पर पानी बह करके सोम-कमला-अम्बा और कडाणा डैम होते हुए गुजरात जाता है। वहां सिंगटवाड़ा के अन्दर टीडी नदी पर एक एनीकट बनाकर के अगर डाया को भरा जाए और भरकर के उदयपुर को सप्लाई किया जाए तो वहां के लोगों को हमेशा-हमेशा के लिए पानी भी मिलेगा और किसानों को खेती करने के लिए भी पानी उपलब्ध होगा।

चिकित्सा मंत्रीजी, आप ध्यान से सुनना क्योंकि आप मुख्य मंत्री के नजदीकी हैं।

एक माननीय सदस्य: पायलट साहब के हैं।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): पायलट साहब के भी हैं और मुख्य मंत्रीजी के भी। बिलकुल चालाक हैं ये, कभी इसमें चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं।

सलूम्बर नगरपालिका क्षेत्र है, वर्षों से डाली गयी पाइप लाइन, जो जर्जर हो चुकी है, उस पर कोई विचार नहीं किया, सरकार के पास विचाराधीन है, 5 करोड़ 50 लाख की, उसको आप करें।

(श्री अमृतलाल मीणा)

स्टेट हाईवे 32, हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, उप मुख्य मंत्रीजी हमारे बीच में नहीं हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है, सहकारिता मंत्रीजी, चिकित्सा मंत्रीजी और हमारे कृषि मंत्रीजी तो इतने सज्जन हैं, सादा हैं और बहुत शीतलता वाले हैं, हमने पिछले 14 महीने में कभी इनका इस प्रकार का क्रोध नहीं देखा। तो मेरा यह निवेदन है कि मेरी जो पीड़ा है, वेदना है, समस्या है, वह आप अवश्य मुख्य मंत्रीजी के पास पहुंचाएं। स्टेट हाईवे 32-ए ऋषभदेव-बलुआ-सराड़ा-जयसमंद-जगत-जामेश्वर सड़क के सुदृढ़ीकरण, चौड़ाईकरण के लिए का कोई प्रावधान नहीं किया गया। यह 2017 में स्टेट हाईवे 32-ए घोषित हो चुका है, इसको आप अवश्य करें।

पूर्व सरकार में, जो मैंने हमारी बानसूर की विधायक महोदय से निवेदन कर ही दिया, मिसिंग लिंक का मामला है। पिछले दो बजटों में, 2019 से 2020 में, सभापति महोदय, शायद आप भी परेशान हैं, आपके कार्यकर्ता भी आपके पास आते होंगे, रोड की बात करते होंगे, पुलियाओं की बात करते होंगे, आप हमारी परिवेदना अवश्य मुख्य मंत्रीजी के पास पहुंचाएं ताकि अभी जो रिप्लाई हो उसमें मिसिंग लिंक सड़क के बजट की घोषणा अवश्य करें।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): कीर की चौकी से ऋषभदेव स्टेट हाईवे 53, जो हमारे सहकारिता मंत्रीजी के वहां से स्टार्ट होता है, स्टेट हाईवे 53 और ऋषभदेव को जोड़ता है, उसमें 15 किलोमीटर की जो शेष रोड है, वह आप दें। संगमेश्वर पुल का कांग्रेस सरकार में शिलान्यास हुआ था, बी.जे.पी. सरकार ने 24 करोड़ दिये और अभी रुका हुआ है, उसका भी बहुत जल्दी निर्माण कराया जाए।

सभापति महोदय जी, दो मिनट का समय जरूर देना, कलर के हिसाब से देना।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें, अपनी बात समाप्त करें।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में शिक्षा के क्षेत्र में हमने कई बार लिखा है, शिक्षा मंत्रीजी हमारे बीच में मौजूद नहीं हैं, इनको बजट भी खूब मिला है, पिछला बजट भी खूब मिला है, 15 हजार कक्षा कक्षों का निर्माण करेंगे, अभी हमारे क्षेत्र में एक भी नहीं हुआ। हमारा पूरा जनजातीय क्षेत्र है, ट्राइबल बैल्ट है, बिलकुल दूरदराज का क्षेत्र है और पहाड़ियों पर मकान हैं। उसमें जाने-आने के लिए जिस प्रकार के स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, वह नहीं हुई।

(श्री अमृतलाल मीणा)

पूर्व में जल संसाधन विभाग के स्वीकृत गोमती नदी पर मूलेश्वर का एनीकट है। वह एनीकट 2017 में पास हुआ है, 18 करोड़ का है। अगर उसका निर्माण हो जाता है...। विश्व की प्रसिद्ध जयसमंद झील, जिसमें हाडा रानी है, चिकित्सा मंत्रीजी, जिन्होंने सर काटा था, काट करके अपने पति को दिया था, वे किशनगढ़ लड़ने के लिए जा रहे थे, ऐसी हाडा रानी के महल, सलूम्बर व महाराणा प्रताप स्मारक और समाधि के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। इसमें बजट का प्रावधान करने का मेरा आपसे निवेदन है। क्योंकि मेवाड़ वीरों की भूमि है, मीराबाई का देश भी कहा जाता है, पन्नाधाय का देश भी कहा जाता है, महाराणा प्रताप की कर्म भूमि और वीर भूमि भी कहा जाता है, हाडा रानी की भूमि भी कहा जाता है, विश्व के मीठे पानी की झील के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। उदयपुर से बांसवाड़ा-रतलाम सड़क में जो छूटी हुई 15 किलोमीटर की सड़क है, जो वन क्षेत्र में आती है...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): सर, बस एक मिनट। पूर्व में सराड़ा औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया जाए। साहब, एक मिनट का समय लूंगा।

ग्रामीण क्षेत्र मुख्यालयों को रोडवेज बसों से जोड़ा जाए, हमारे रोडवेज मिनिस्टर आये नहीं, लेकिन मेरी उनसे मन में बात हो चुकी है बिलकुल। सामुदायिक चिकित्सालय, सलूम्बर में 200 बैड का करने की बात कही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर, सहकारिता मंत्रीजी का अब आया है, ग्राम सेवा सहकारी समिति नितांत आवश्यक है। वाकई में है, आप तो उस एरिया को जानते हैं, भलीभांति जानते हैं, परिचित हैं, नजदीक हैं, पड़ौसी हैं, मिलते हैं लेकिन इलेक्शन में थोड़े दूर रहते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): विधान सभा क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने के लिए कोई कार्ययोजना नहीं है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में वन क्षेत्रों में आ रही सड़कों का...

श्री सभापति: अब आप इनको बाकी समस्याएं मिलकर बता देना। श्री पानाचन्द मेघवाल।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): साहब, एक मिनट। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि भामाशाह योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना, जल अभियान, ग्रामीण गौरव पथ, शहरी गौरव पथ,

(श्री अमृतलाल मीणा)

मुख्यमंत्री राजश्री, पालनहार, न्याय आपके द्वार, राशन वितरण पारदर्शिता अन्नपूर्णा भंडार, अन्नपूर्णा रसोई और हैल्पलाइन 181, आदर्श विद्यालय...

श्री सभापति: हो गया, हो गया, अब आप विराजिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): और स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत, प्रधानमंत्री जनधन...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें, प्लीज।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री आवास योजना... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। श्री पानाचन्द मेघवाल।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): आपने बोलने का समय दिया और आप सबने सुना, उसके लिए मैं कोटि-कोटि बधाई दूंगा। धन्यवाद। जय हिन्द। जय राजस्थान।

(19.00 बजे)

श्री सभापति: श्री पानाचन्द मेघवाल।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे मुख्य मंत्रीजी के द्वारा प्रस्तुत बजट 2020-21 पर बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।

मेरे पूर्व वक्ताओं ने यहां पर कई प्रकार की बातें बोली हैं। इनका सिद्धांत है, इनकी कार्यशैली में है। एक दिल्ली में बैठकर बोलते हैं और ये यहां बैठकर बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आप तो बजट पर बोलो। (व्यवधान)

श्री सभापति: जांच करवाओ।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मुझे चिंता है, माननीय सदस्य के स्वास्थ्य की, आप मेरे हवाले करो इनको, जांच करानी पड़ेगी।

श्री सभापति: हां, आप इनके स्वास्थ्य की जांच कराओ। माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है, चाहे 2019-20 की बात करो या 2020-21 की बात करो, चाहे गरीब की बात करो, मजदूर की बात करो, नौजवान की बात करो,

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

विद्यार्थी की बात करो, पूंजीपति की बात करो, हर वर्ग को कहीं न कहीं से लुभाने का और उसका साथ देने का प्रयास किया गया है।

श्री सभापति: लगता है आपमें से कोई गम्भीर नहीं है। हाउस एडजोर्न करें, जब गम्भीर नहीं हो तो। प्लीज शांति रखें, माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय सभापति महोदय, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जिस प्रकार से इनकी कार्यशैली रही है, उस कार्यशैली से तंग आकर राजस्थान की जनता ने आज इनको विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर किया और हमारे नेता, माननीय अशोक जी गहलोत और उप मुख्य मंत्री सम्माननीय पायलट साहब के नेतृत्व में राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, सुअवसर के लिए राजस्थान की कमान इनके हाथों में सौंपी। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वह अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपके यह क्या हो रहा है? विराजिए, अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर: 000

श्री सभापति: क्या प्राब्लम है आपको?

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, ज्यादा मत बोलो। नीचे बैठ जाओ ...(व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, यह केस नम्बर दो।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): भारतीय जनता पार्टी की रीति है, 'अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा'। हमारा सिद्धांत है, 'सत्य कहेंगे स्पष्ट कहेंगे, कहेंगे न सुन्दर झूठ, चाहे कोई खुश हो या चाहे जाए रूठ'।' हम सत्य कहते हैं, कभी झूठ पर सत्ता हासिल नहीं कर सकते।

श्री सभापति: आप इधर की तरफ मुखातिब रहें। आप उनको इनवाइट मत करिए, आप इधर आसन की तरफ बात करें।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): आज पूरा देश जाति और धर्म के नाम पर जल रहा है, हमारे देश के प्रधान मंत्री को उस तरफ देखने का समय नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप दो-चार मिनट बजट पर बोल लो ताकि आपके क्षेत्र की बात आ जाए। यह अन्तरराष्ट्रीय स्तर छोड़ करके सीधे-सीधे अपने क्षेत्र पर आ जाओ आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, देश जरूरी है देश। (व्यवधान)

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय सभापति महोदय, जब पूरा देश जल जाएगा तो बजट क्या काम आएगा? आज पूरे देश का हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसान हो, मजदूर हो सब अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं कि आगे आने वाला जो सूर्य उदय होगा हम देखेंगे या नहीं देखेंगे। आज दिल्ली में जो हालत है, वह आपसे और हमसे छिपी हुई नहीं है। वहां केन्द्र की पूरी सरकार बैठी हुई है फिर भी वहां पर आज जिस प्रकार से पत्रकार मर रहे हैं, जिस प्रकार से मजदूर मर रहे हैं, जिस प्रकार से नौजवान मर रहे हैं वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। मेरा आपके माध्यम से यहां पर विराजमान 200 सदस्यों से निवेदन है कि यह लोकतंत्र है, सत्ता आएगी और जाएगी लेकिन इस लोकतंत्र को बचाना आपका और हमारा कर्तव्य है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र की बात करो, शिक्षा के क्षेत्र की बात करो, पेयजल की बात करो, सड़क की बात करो, रोजगार की बात करो या अन्य किसी प्रकार के क्षेत्र की बात करो, जो एक-एक चीज़ इसमें ली है और जो सात संकल्प हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने लिये वे कोई संकल्प नहीं हैं, एक वादा है, एक चिंतन है कि राजस्थान के सात करोड़ लोगों ने, जिन्होंने चुनकर मुझे राजस्थान का भाग्य उदय करने के लिए यहां पर पहुंचाया है, मेरी चिंता होनी चाहिए, मेरा मन होना चाहिए कि मैं उनका विकास किस प्रकार से कर सकूं।

आज 14 महीने के कार्यकाल में चाहे बिजली की समस्या की बात करो, किसान की मृत्यु की बात करो, जिस प्रकार से हमारे नेता, प्रतिपक्ष ने कहा था कि मैं असत्य नहीं बोलता हूं और उनके पटल पर निकला, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हाड़ौती में 72 किसानों ने आत्महत्या की थी। सभापति महोदय, यहां पर ये जो मंत्री बैठे हुए थे और जो आज विपक्ष में बैठे हैं, इनका एक शब्द नहीं निकला, इनका एक व्यक्ति उनके घर पर सांत्वना देने के लिए नहीं गया। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह गम्भीर बात है। (व्यवधान) विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं होगा। विराजिए आप, प्लीज।

श्री मदन दिलावर: 000

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): आज किसान के लिए आंसू बहाने की बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। प्लीज, प्लीज, प्लीज, सहयोग करें।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने किसान की पीड़ा को समझने का प्रयास किया।

श्री सभापति: एक मिनट। आप लोग बोल चुके, जिन माननीय सदस्यों को बोलना है सुबह से यहां पर बैठे हुए हैं आप नहीं चाहते कि वे बोलें? बोलना है तो फिर आप शांति से बैठे न। आप तो बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, पहले-पहले बोल लिये। अब जो लोग शाम तक बैठे हुए हैं वे नहीं बोलेंगे तो उन लोगों को कितनी पीड़ा होगी।

मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि कृपया शांत रहें। जो माननीय सदस्य बोलने के लिए बाकी बचे हुए हैं उनको बोलने का समय है, आप उनको बोलने दें और गम्भीर नहीं हैं तो फिर हाउस एडजोर्न करते हैं।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): साहब, आधा टाइम तो इसमें वेस्ट कर देते हैं।

श्री सभापति: हाउस एडजोर्न करें फिर? आप इस तरह से मत करिए और माननीय सदस्य, मैं आपको वार्न करता हूं, यह बहुत गलत बात है। आपका हर बात पर खड़ा होना जरूरी नहीं है। प्लीज शांत रहें, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय सभापति महोदय, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने किसान की पीड़ा को समझा। उन्होंने देखा कि किसान रात के 12 बजे खेत मैं खड़ा रहता है, उसकी पीड़ा को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है और इस बजट में घोषणा की कि आने वाले तीन साल में पूरे राजस्थान के किसानों को सुबह से लेकर शाम तक बिजली जाएगी, रात को कोई किसान खेत में नहीं जाएगा। यह हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री समझ सकते हैं।

यहां पर विराजमान नेता बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर सकते हैं लेकिन इस राजस्थान के विकास में जो काम किया है, चाहे 1998 से 2003 के कार्यकाल की बात करो या 2008 से 2013 के कार्यकाल की बात करो या

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

अभी वर्तमान कार्यकाल की करो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन बढ़ोतरी का काम किया, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री गहलोत जी ने किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का काम किया, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने किया, किसान का कर्जा माफ करने का काम किया, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने किया। आप आज केवल बातें कर सकते हो, केवल सिद्धांतों की बात कर सकते हो। आप इस परिसर में आकर गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सकते हो, लेकिन आप मीटिंग में बैठते हो तो गोडसे की बड़ाई करते हुए आपको शर्म नहीं आती है। आज पूरा देश देख रहा था कि अमेरिका का राष्ट्रपति राजघाट पर जाकर इस देश के महान नेता को नमन कर रहा था। उनके साथ हमारे देश के प्रधान मंत्री थे। लेकिन उनकी संसद में महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति को आपने तवज्जोह दी है, यह शर्म की बात है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने, चिकित्सा की बात करते हैं, निरोगी राजस्थान का सपना बनाया। क्योंकि हम जिस गांव से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, जिस देश से आते हैं, जिस शहर से आते हैं, वहां पर हमने हजारों लोगों को मरते हुए देखा है, कोई टीबी की बीमारी से मरता है, कोई कैंसर की बीमारी से मरता है, कोई हार्ट अटैक से मरता है। उस गरीब के परिवार में इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता है। इस पीड़ा को हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने समझने का प्रयास किया। उन्होंने सर्वप्रथम एक घोषणा की कि राजस्थान में जो दवाइयां भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बंद की गयी थीं, उनको चालू किया जाएगा। जो संख्या कम थी वह बढ़ाकर 709 की गयी है। राजस्थान के चिकित्सालय में जो जांचें नहीं होती थीं, चाहे वह सीटी स्कैन की बात हो, एम.आर.आई. की बात हो, ई.सी.जी. की बात हो, कई प्रकार की लगभग सौ जांचें राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने निःशुल्क करने का प्रयास किया। यह है राजस्थान का लोकप्रिय मुख्य मंत्री, जो किसान की पीड़ा को समझ सकता है, मजदूर की पीड़ा को समझ सकता है।

मैं चिकित्सा मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि आज बाहर हमारे फार्मासिस्ट, जिनकी कोई बड़ी बात नहीं है, वे धरने पर बैठे हुए हैं। हम सरकार के प्रतिनिधि हैं, उनका जो कैडर है, हमारा कोई प्रतिनिधि जाकर उनसे बात करे, उसमें कोई राजकोषीय हानि होने वाली नहीं है इसलिए उनकी

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

समस्या पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। पत्रकार भाई, जो यहां बैठकर और राजस्थान के कोने-कोने में निवास करने वाले लोगों की बात को राजस्थान के पटल तक और दिल्ली की केन्द्र की सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनकी समस्या के समाधान के लिए भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। उनकी जो आवश्यकता है, उनकी जो मांग है उन पर भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे जिले में शहीद राजमल नाम से एक व्यक्ति जम्मू कश्मीर की घाटी में शहीद हुआ था। हमारे जिले में अब तक केवल एक व्यक्ति शहीद हुआ है। लम्बे समय से उसके नाम से राजकीय जिला चिकित्सालय के नाम की मांग जिला प्रशासन द्वारा सामाजिक संगठनों के द्वारा की जा रही है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब माननीय मुख्य मंत्री महोदय का रिप्लाई हो तो राजकीय चिकित्सालय, बारां का नाम शहीद राजमल मीणा के नाम से करने का प्रयास करें।

सभापति महोदय, मेरे जिले में बारां शहर मुख्यालय पर एक आर.ओ.बी. की मांग लम्बे समय से चल रही है। बारां जिला, जहां की पापुलेशन डेढ़ लाख लाख है, 50 हजार एक तरफ रहते हैं और एक लाख एक तरफ रहते हैं, बीच में रेलवे क्रासिंग होती है। वहां पर डबल ट्रैक का काम हो चुका है, हर 15 मिनट में ट्रेन आती है, माल गाड़ी आती है और वहां पर हर 15 मिनट में फाटक लग जाता है। कई लोगों की हार्ट अटैक से वहां मौत हो चुकी है। वह स्वीकृत है, उसके लिए केवल बजट जारी करना है। यह मैं मुख्य मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): मेरे विधान सभा क्षेत्र में अटरू कस्बा है, जहां पर 3 ग्राम पंचायतों को मिलाकर के अटरू, खेड़लीगंज और रतनपुरा हैं। वहां की पापूलेशन 30-32 हजार है। मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि उसको अगर नगरपालिका बना दिया जाए तो वहां जो 3 ग्राम पंचायतें हैं, उनके अलग-अलग कार्य क्षेत्र होते हैं, फर्जी पट्टों का प्रकरण रहता है, उन सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगी।

सभापति महोदय, कर्मचारियों की जो चुनाव के समय में मांग थी, हम लोगों ने उनको जाकर आश्वासन भी दिये थे कि अगर हमारे कार्य-क्षेत्र में

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

होगा तो हम निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। 2004 के बाद जो सरकारी कर्मचारी सेवा में आये हैं, उनकी पेंशन की जो मांग है, उसका अच्छे विधि ज्ञाताओं से अध्ययन करवाकर उनकी समस्या का समाधान कराया जाए।

सभापति महोदय, आज हमारा राजस्थान खुशहाल है। हमारे नेता जब सत्ता में रहते हैं, तब भी राजस्थान में रहते है और सत्ता में नहीं रहते, तब भी राजस्थान में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता में रहते हैं तब राजस्थान में रहते हैं और सत्ता में नहीं रहते तब उनका पता नहीं होता है।

श्री सभापति: समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): राजस्थान की जनता की पीड़ा को, राजस्थान के किसान की पीड़ा के बारे में बार-बार सभी कहते हैं कि केन्द्र बजट नहीं दे रहा है। यह सत्य है। हमारे राजस्थान की 7 करोड़ जनता ने इनके 25 के 25 सांसद चुनकर दिल्ली की केन्द्र सरकार में भेजे। हमारे सांसद अब एक बार भी नहीं बोल रहे हैं कि राजस्थान का जो हिस्सा है, चाहे वह वित्तीय संसाधनों के अनुसार हो या मापदंडों के अनुसार हो, वह क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए, मंत्री पद बचाने के लिए मुंह नहीं खोल रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्तियों को हमने चुनकर भेजा। राजस्थान की जनता इस बात के लिए कोस रही होगी कि जिनको हमने चुनकर भेजा है, वे राजस्थान के विकास और हिस्से के लिए क्यों नहीं बात कर रहे हैं?

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जो बजट हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका बहुत-बहुत समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से यह बजट राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाएगा।

श्री सभापति: श्री बलवीर सिंह लूथरा।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): सभापति महोदय, वर्ष 2020-21 के बजट में माननीय सदन के नेता ने अपने गृह क्षेत्र जोधपुर को विशेष तवज्जोह दी है। हमारे श्रीगंगानगर जिले को बिलकुल इग्नोर किया गया। मुझे खुशी होती, यदि सदन के नेता प्रत्येक विधान सभा में पापूलेशन और जरूरत के हिसाब से बजट का आबंटन करते।

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

सभापति महोदय, माननीय सदन के नेता ने वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में पहला संकल्प निरोगी राजस्थान का लिया। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि पिछले वर्ष के बजट भाषण में श्रीगंगानगर जिले में मेडिकल कालेज की घोषणा की थी। आज तक न तो मेडिकल कालेज के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी और न ही मरीजों के लिए कोई विशेष सुविधा उपलब्ध करायी गयी। अभी तक कार्यवाही कागजों तक ही सीमित है। धरातल पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाया गया। मेडिकल उपकरण भी उपलब्ध नहीं करवाए गये।

सभापति महोदय, श्रीगंगानगर जिले की सीमा पंजाब से लगती है। पंजाब से आने वाले दूषित पानी को पीकर इस क्षेत्र के लोग कैंसर एवं हृदय रोग जैसी गम्भीर बीमारियों से पीड़ित हैं। इन बीमारियों के समुचित इलाज की हमारे जिले में कोई व्यवस्था नहीं है। अगर मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की बात करूं तो मेरे यहां 2 ही कस्बे हैं। शेष आबादी गांवों एवं ढाणियों में निवास करती है। दोनों कस्बों रायसिंहनगर एवं श्रीविजयनगर में पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान में रायसिंहनगर में कुल 13 पद डाक्टरों के स्वीकृत हैं, जिनमें से रिकार्ड में 6 डाक्टर नियुक्त हैं। उसमें भी एक डाक्टर को प्रतिनियुक्ति पर कहीं बाहर भेजा हुआ है। पांच में से एक सर्जन, एक शिशु रोग विशेषज्ञ है और तीन डाक्टर्स एम.बी.बी.एस. हैं। एनेस्थिसिया का डाक्टर ही नहीं है।

सभापति महोदय, श्रीविजयनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 8 डाक्टरों के पद स्वीकृत हैं, मगर वहां स्थायी रूप से एक ही डाक्टर काम कर रहा है। बाकी डाक्टरों में न तो कोई सर्जन है, न कोई विशेषज्ञ है। किसी प्रकार की यहां स्थायी नियुक्ति नहीं है। यहां पर न ही कोई स्थायी रूप से एम्बुलेंस की व्यवस्था है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में कोई भी ट्रोमा सेंटर नहीं है। जब-जब भी दुर्घटना होती है तो घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक उपचार के तुरंत बाद रैफर कर देते हैं। ऐसे मरीज को या तो श्रीगंगानगर ले जाना पड़ता है, जो कि यहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, या फिर बीकानेर, जो कि यहां से 180 किलोमीटर की दूरी पर है। गम्भीर रूप से घायल मरीज अक्सर इलाज के अभाव में रास्ते में ही दम तोड़ देता है। ऐसे में निरोगी राजस्थान का संकल्प कैसे पूरा होगा? जबकि अस्पतालों में डाक्टर्स ही नहीं हैं,

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

दवाइयां नहीं हैं। इससे राजस्थान निरोगी कैसे होगा? यह मेरी समझ से परे है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि चिकित्सा विभाग में संविदा पर लगे कर्मचारियों को स्थायी करें। ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी आर.एम.पी. डाक्टर्स कार्य करते हैं, उनको स्वास्थ्य मित्र की संज्ञा देकर प्रैक्टिस करने की कानूनी मान्यता दें। माननीय चिकित्सा मंत्री यहां विराजमान हैं। उम्मीद है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की चिकित्सा आवश्यकताओं को ये पूरा करेंगे।

सभापति महोदय, सदन के माननीय नेता ने दूसरा संकल्प लिया, सम्पन्न किसान। हमारे श्री गंगानगर जिले के किसान कर्ज से तंग आकर आये दिन आत्महत्याएं कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ही 2 किसानों ने कर्ज से परेशान होकर कीटनाशक दवाओं का सेवन करके आत्महत्या कर ली। प्राकृतिक आपदाओं, ओलावृष्टि, टिड्डी दल द्वारा खराब हुई किसानों की फसलों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। पिछले वर्ष 2019 में ओलावृष्टि से फसल खराबे का पूरा मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला है। ऋण वसूली के लिए किसानों की जमीनें कुर्क की जा रही हैं, नीलाम की जा रही हैं। ऋण वसूली के नाम पर एस.डी.एम., तहसीलदार 5-5 प्रतिशत तक इंसेंटिव के रूप में किसानों से कमीशन वसूली करते हैं। राजस्व मंत्री यहां सदन में विराज रहे हैं। कृपया ये इस पर अवश्य ध्यान दें।

सभापति महोदय, इस बजट में सरकार ने किसानों की आगामी रबी की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने की किसी भी प्रकार की कोई नीतिगत घोषणा नहीं की। फसल खरीद केन्द्रों की भी घोषणा नहीं की। पिछले वित्तीय वर्ष 2019 में एक भी किसान की डिग्गी सफाई नहीं की। इसके अलावा न ही किसी प्रकार का डिग्गियों पर अनुदान दिया गया। पिछली बार भा.ज.पा. सरकार द्वारा किसानों को जितनी डिग्गियों की स्वीकृति जारी की गयी थी, किसानों ने येन-केन-प्रकारेण ऋण आदि लेकर के डिग्गियों को बना लिया। मगर कांग्रेस सरकार द्वारा इन डिग्गियों के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि रोक करके किसानों के साथ विश्वासघात किया गया।

सभापति महोदय, पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर नन्दीशाला खोलने की घोषणा की थी, मगर आज तक इस ओर

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

कोई ध्यान नहीं दिया गया। आवारा पशुओं के नियंत्रण के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। सरकार द्वारा पिछले बजट में पशुपालक किसानों को मुफ्त बीमा करने की घोषणा की गयी थी लेकिन इसका लाभ एक भी पशुपालक किसान को नहीं दिया गया।

भूमिहीन किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गयी। कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था, मगर सरकार द्वारा सहकारी बैंकों का नाम मात्र का कर्जा माफ करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली गयी।

सभापति महोदय, पिछले बजट भाषण में फिरोजपुर फीडर की मरम्मत की बात रखी थी। आज तक उसकी मरम्मत नहीं हो सकी। पिछले बजट भाषण में ही हुसैनीवाला हैड से 45 आर.डी. बीकानेर कैनाल की सफाई हेतु एक करोड़ की घोषणा करके सरकार ने झूठी वाहवाही लूटी। मगर आज तक उस नहर की सफाई नहीं हुई, जिससे बरसाती समय में किसानों के हिस्से का लाखों क्यूसेक्स पानी पाकिस्तान जाता रहा। पूरा पानी नहीं मिलने की वजह से भी किसानों की फसलें बरबाद हुई। ऐसे में किसानों के लिए जो वर्षों पुरानी कहावत है, किसान का बेटा कर्ज में जन्म लेता है और कर्ज में ही मर जाता है, सही सिद्ध होती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मार्मिक अपील करता हूं कि किसानों की सम्पूर्ण कर्जा माफी करके, किसानों के साथ किये गये वायदों को पूरा करें ताकि किसान आराम की जिंदगी जी सके। अन्यथा आने वाले समय में राजस्थान का किसान कांग्रेस सरकार को कभी माफ नहीं करेगा।

सभापति महोदय, तीसरा संकल्प, महिला, बाल एवं वृद्ध कल्याण। आंगनबाड़ी वर्कर, आशा सहयोगिनी, ए.एन.एम. का मिक्स अप करने पर इन सबका भला होने वाला नहीं है। इससे तो अच्छा होता कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आशा सहयोगिनियों के मानदेय में वृद्धि की जाती और उन्हें स्थायी कर दिया जाता। चूंकि ये सभी कार्यकर्ता प्राय: गरीब घरों की महिलाएं हैं, मानदेय वृद्धि से ये अपने घर, परिवार और बच्चों का बेहतर भरण-पोषण कर पातीं, ये प्रदेश की महिला, बाल एवं वृद्ध जनों की एवं समाज की बेहतर तरीके से सेवा कर पातीं।

सभापति महोदय, बालक हमारे प्रदेश की अमूल्य निधि हैं। मुझे खुशी होती यदि सरकार इन बालकों के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य की कोई नवीन

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

योजना शुरू करके इन गरीब बालकों को बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाती। संकल्प करते हैं महिला, बाल कल्याण का, पर हमारी बच्चियों की शादी के लिए शुभ शक्ति योजना में मिलने वाली 55 हजार की राशि सरकार द्वारा बंद कर दी गयी। पालनहार, बेसहारा बच्चों को सुविधा नहीं मिल रही है। वृद्धजनों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। कुछ वृद्धजनों की तो पेंशन ही बंद कर दी है।

सभापति महोदय, चौथा संकल्प, सक्षम मजदूर, छात्र, युवा, जवान, इस बात की तो मुझे खुशी है कि सदन के नेता ने प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए इनामी राशि बढ़ाकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है। मगर आम मजदूर, छात्र, युवा, जवान के कल्याण और उनका भविष्य बनाने के लिए किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गयी। बेहतर होता कि बेरोजगार युवाओं के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था करते। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था करते। छात्रों को बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करते। उनकी उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देने का प्रावधान करते।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में पिछले बजट में शहीद भगत सिंह कालेज के सरकारीकरण की घोषणा की गयी थी। मगर आज तक इस महाविद्यालय के लिए कोई वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गयी है और न ही छात्रों को किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर सुरक्षित विधान सभा क्षेत्र है। इसमें ज्यादातर अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। गरीबी की वजह से यहां के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं है। ऐसे में पांचवां संकल्प, शिक्षा का, कैसे पूरा हो सकता है। ब्लाक स्तर पर शिक्षा के लिए, जो पूर्व में रायसिंहनगर के लिए बजट पास हुआ था, रामजीवाला में जमीन अलाट होने के बावजूद भी आगे की कार्यवाही नहीं हुई। जबकि अन्य दूसरी जगहों पर काम चालू हो चुका है। श्रमिकों को मिलने वाली सभी सुविधाएं इस सरकार ने बंद कर दी हैं। ऐसे में मजदूरों का भला कैसे होगा?

माननीय सभापति महोदय, सदन के नेता का छठा संकल्प, पानी, बिजली, सड़कों का माना है। मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की सीमा पाकिस्तान से सटी हुई है। सीमावर्ती अधिकांश गांवों में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है। आज भी सीमावर्ती गांवों के लोग टैंकरों से पानी डलवाते हैं,

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

जिसकी उनको कीमत अदा करनी पड़ती है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वाटर वर्क्स की जो स्कीमें स्वीकृत की गयी थीं, उन योजनाओं पर कोई कार्य शुरू नहीं करवाया गया। श्रीविजयनगर कस्बे में नया वाटर वर्क्स बनना प्रस्तावित है। इसके लिए जिला कलेक्टर द्वारा गांव तीन-ए में श्रीसूरतगढ़ आई.जी.एन.पी. नहर के पास पचास बीघा भूमि का आबंटन विभाग को दिनांक 18.12.2018 को कर दिया गया है, मगर आज तक विभाग द्वारा डी.पी.आर. तैयार कर सक्षम कार्यालय में नहीं भिजवायी गयी है। श्रीविजयनगर का वाटर वर्क्स सन् 1976 का बना हुआ है, जो कि काफी पुराना एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। कस्बे की आबादी एवं क्षेत्र काफी बढ़ चुका है। कस्बे के आसपास काफी कालोनियां बस चुकी हैं, वर्तमान का वाटर वर्क्स क्षेत्र को पानी की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है। पिछले वर्ष के बजट की चर्चा में मैंने पी.एच.ई.डी. मंत्री माननीय बी.डी. कल्ला साहब को भी इससे अवगत करवाया था।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश गांव एवं ढाणियां बिजली से वंचित हैं। सड़कों की हालत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। जो सड़कें मरम्मत एवं नव निर्माण के लिए स्वीकृत की जा चुकी हैं, कार्य निर्माण पूरा करने की अवधि, अनुमानित लागत राशि के बोर्ड तो लगे हुए हैं, मगर उन सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया गया है। पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारियों से बात करते हैं तो जवाब मिलता है कि सरकार से बजट नहीं मिल रहा है। ठेकेदारों द्वारा पूर्ण किये गये कार्यों का भुगतान नहीं किया गया है, भुगतान नहीं मिलने की वजह से उनके द्वारा काम रोक दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की अधिकांश सड़कें कच्ची हैं, खरंजा लगी सड़कें बेहद खराब स्थिति में हैं। डामर रोडें मरम्मत के अभाव में बेहद खराब स्थिति में हैं। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की सप्लाई रात को की जाती है। इस वर्ष जबर्दस्त ठण्ड पड़ी। हमारा गंगानगर जिला प्रदेश में सबसे ज्यादा सर्द रहा। प्रदेश के सभी किसान भाइयों को खेती के लिए रात्रि में बिजली उपलब्ध करवाये जाने पर उन्हें शारीरिक एवं मानसिक कष्ट उठाना पड़ता है। राजस्थान प्रदेश का सबसे ज्यादा ठण्ड पड़ने वाला एवं सिंचित जिला श्रीगंगानगर है लेकिन बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि श्रीगंगानगर जिले को कृषि कार्य करने के लिए, दिन में बिजली उपलब्ध

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

करवाने के लिए तीसरे चरण में वर्ष 2023 में रखा गया है। जबकि इस जिले को दिन में कृषि कार्यों के लिए बिजली उपलब्ध करवाने के लिए पहले चरण में रखना चाहिए था।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, जिले को तीसरे चरण में रखना हमारे जिले के किसानों के साथ सरासर अन्याय है, धोखा है, ज्यादती है। अंत में मैं यही कहूंगा कि बजट बेहद निराशाजनक और दिशाहीन है, इससे राजस्थान की जनता का भला होने वाला नहीं है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, आपने बजट पर चर्चा के लिए मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

वर्ष 2020-21 का बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 20 तारीख को सदन में पेश किया। यह सरकार का एक आर्थिक एजेण्डा है। आने वाले एक साल में सरकार तय करेगी कि किस-किस योजना में कितना-कितना पैसा खर्च करना है और कौन-कौनसी योजनाओं की प्राथमिकता है, इसे सरकार ने इस बजट डाक्युमेंट से सदन को अवगत कराया है।

यह आर्थिक वृद्धि का रोड मैप है। वर्तमान में जी.डी.पी. की 11 परसेंट से अधिक ग्रोथ हमारे है, जिसमें 25 परसेंट कृषि का योगदान है, 30 परसेंट इण्डस्ट्री का, 40 परसेंट सेवा क्षेत्र का, सभी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सबके लिए अलग-अलग राशि तय की है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस बजट में किसी प्रकार का उपभोक्ता कर नहीं लगाया गया और 130 करोड़ रुपये की रियायत राजस्थान सरकार ने आम व्यक्ति को देने का प्रयास किया है। आज से करीब 15-20 दिन पहले केन्द्र सरकार का बजट पेश हुआ, इस बजट के आंकड़े और उस बजट का लेखा-जोखा भी देश के सामने है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो केन्द्र सरकार का बजट था, उस बजट को अगर आप देखेंगे कि किस-किस सेक्टर में कितना-कितना पैसा खर्च किया है, यह देश की जनता के सामने है। 2014 के बाद में पहला केन्द्र सरकार का बजट था। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, उसमें कोई ऐसी घोषणा नहीं की गयी और राजस्थान को उस बजट से खास तौर से इग्नोर किया गया है। हमें उम्मीद थी

(श्री जगदीश चन्द्र)

कि देश के प्रधान मंत्री राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए हमारे लिए स्पेशल अनाउंसमेंट करेंगे लेकिन किसी तरह का अनाउंसमेंट नहीं किया गया। आज विश्व बैंक, आई.एम.एफ., एशियन डवलपमेंट बैंक और जो दूसरी संस्थाएं हैं, जिनका अनुमान है कि पहली दफा देश की जी.डी.पी. में भारी गिरावट है। आज से तीन महीने पहले हिन्दुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी थी मूडीज आर्गनाइजेशन की ओर से, जिसमें कहा गया था कि हिन्दुस्तान की जो जी.डी.पी. है वह तीन से पांच परसेंट के बीच में रहने की उम्मीद है। पहली दफा नोटबंदी के बाद में इतनी ज्यादा जी.डी.पी. गिरी है कि आज केन्द्र सरकार उसको संभालने में बिलकुल सक्षम नहीं है। यह देश के साथ सरकार ने धोखा किया है। एक गलत फैसले की वजह से आज सारा देश इस बात को भुगत रहा है। आज इस देश में महंगाई का जो आंकड़ा है, पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा इस देश में है। माननीय प्रधान मंत्रीजी और उनके दूसरे साथी रोजाना चर्चा करते हैं कि एक करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, एक नयी इण्डस्ट्री पालिसी आएगी, नये-नये आयाम स्थापित होंगे। कृषि के क्षेत्र में कितनी बातें रखी गयीं लेकिन इनके वे सारे के सारे वादे और आंकड़े फेल हो गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, सबसे ज्यादा गिरावट प्रोडक्शन में है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है और उसके बाद में कंस्ट्रक्शन में है। तीन सेक्टर ऐसे हैं, जिनमें बहुत ज्यादा गिरावट है। इसके साथ-साथ एक साल पहले ही राजस्थान के एक अख़बार में छपा था, इस सरकार के गलत फैसलों की वजह से 14 लाख लोग आटोमोबाइल इण्डस्ट्री में बेरोजगार हो गये हैं। एक में तो 50 हजार व्यक्ति, हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी मोटर कम्पनी थी, मारूति, उससे बेरोजगार हो गये हैं। उसने अपने लोगों को निकाल दिया है। इसके बाद टाटा आटोमोबाइल, हुण्डई और दूसरी आटोमोबाइल इण्डस्ट्री के जो लोग थे, उन्होंने अपने लोगों को निकाल दिया। यह इस बात का संकेत है कि देश कहां जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि महंगाई दिसम्बर, 2019 में 7.5 परसेंट दर्ज की हुई है। यहां तक कि कृषि क्षेत्र की विकास दर में भी कमी आयी है और 10,362 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने राजस्थान के हिस्से के टैक्स के पैसे काट लिये हैं। माननीय सभापति महोदय, केन्द्रीय करों में हिस्से के रूप में 46,411 करोड़ 8 लाख

(श्री जगदीश चन्द्र)

रुपये देने का अनुमान था, जिसको घटाकर 44,461 करोड़ 86 लाख रुपये संशोधित अनुमान के हिसाब से हमें दिया जाना है। 2019-20 के संशोधित अनुमानों में इसे घटाते हुए 36,059 करोड़ 14 लाख रुपये कम दिये गये हैं। केन्द्रीय करों की राशि में 10 हजार करोड़ रुपये के आस पास हमारी कटौती कर दी गयी है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने जो सात संकल्प लिए हैं, सात संकल्पों में समाज के सारे तबकों को शामिल किया गया है। उनमें स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इण्डस्ट्री का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, इसके साथ-साथ सामाजिक लोक कल्याणकारी योजनाओं का क्षेत्र हो, सबका इसमें ध्यान रखा गया है। सबको, जिसका जितना हिस्सा बनता था, जो जरूरत के हिसाब से हमारे पास में पूंजी अवेलेबल है, प्रदेश में जो रिसोर्सेज हैं, सरकार के रेवेन्यू के हिसाब से बांटने की कोशिश की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि केन्द्र सरकार का सबसे ज्यादा रेवेन्यू कस्टम और सेंट्रल एक्साइज से आता था। उसके साथ-साथ, जब हमारा देश आजाद हुआ, पूर्व प्रधान मंत्री और इस देश के निर्माता, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कुछ पी.एस.यू. की स्थापना की थी, जो बड़ी-बड़ी नवरत्न कम्पनियां थीं। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि सरकार टैक्स से चलती है और इसके साथ-साथ देश में जो डवलपमेंट की जरूरत है, उसकी पूर्ति करने के लिए ये पी.एस.यू. बनाये गये थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं, पूरे देश के अन्दर किस तरीके से पी.एस.यू. का हाल हो गया है। संघीय ढांचे की वजह से हमें केन्द्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ रहा है। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि केन्द्र सरकार ने जी.एस.टी. का जो पैसा था, वह आज तक राजस्थान को नहीं दिया है। इससे ज्यादा इस स्टेट के साथ में दुर्व्यवहार की बात नहीं हो सकती।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरोगी राजस्थान की चर्चा की गयी है। निरोगी राजस्थान की चर्चा सदन में आज से तीन-चार दिन पहले भी हुई थी, जिस पर 14,533 करोड़ रुपये के बजट का स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रावधान किया गया है। इसमें 100 करोड़ रुपये अकेले निरोगी राजस्थान के माध्यम से सरकार देगी। इसमें मिलावटखोरी रोकने की बात है, एजुकेशन की बात है, मेडिकल कालेज खोलने की बात है, हमारे पी.एच.सी. खोलने की बात है या दूसरे जो

(श्री जगदीश चन्द्र)

सरकार के छोटे-छोटे अस्पताल खोलने की बात है, सरकार की जांच एजेंसीज की बात है और दवाइयों के सम्बन्ध में जो बजट में व्यवस्था की गयी है, मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत बड़ी बात की है। प्राथमिकता के आधार पर उन्होंने इस प्रदेश को स्वस्थ रखने का जो फैसला किया है, वह बिलकुल ऐतिहासिक फैसला है। इसके साथ-साथ, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि जिस तरह से कैंसर जैसी बीमारी राजस्थान में पांव पसार रही है, उसकी रोकथाम के लिए राज्य में कैंसर संस्थान का ऐलान किया गया है। मेरा आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध है कि राजस्थान के सबसे पीड़ित श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले, जहां कैंसर की सबसे ज्यादा बीमारी है, वहां कैंसर का कोई न कोई संस्थान सरकार को खोलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 3,420 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें 12,500 फार्म पोन्डों का निर्माण, 150 करोड़ रुपये का प्रावधान ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए किया गया है। 19 करोड़ रुपये का प्रावधान, 30 हजार हैक्टेयर जमीन का प्रावधान अतिरिक्त सिंचाई करने के लिए किया गया है। माननीय कृषि मंत्रीजी हमारे बीच बैठे हैं। ये बधाई के पात्र हैं कि 25 हजार सोलर पम्प राजस्थान की जनता को इस बजट में दिये जाने का प्रावधान है। यह ऐतिहासिक फैसला राजस्थान की सरकार ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, किसानों की समस्याओं को देखते हुए मुझे याद है, जब सरकार बनी थी, सरकार बनने के साथ में किस तरह से यूरिया के लिए लम्बी-लम्बी लाइनें लगी हुई थीं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीन स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार बनी थी, और यूरिया की सप्लाई केन्द्र सरकार करती है, तीनों स्टेट्स की यूरिया की सप्लाई को केन्द्र सरकार ने रोक दिया था। पूरे प्रदेश में हाहाकार मच रहा था। माननीय कृषि मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने विवेक से, सक्षम नेतृत्व से किसानों के लिए यूरिया की पूर्ति की है। ये धन्यवाद के पात्र हैं।

इस बजट में राजस्थान सरकार ने दो लाख टन यूरिया, एक लाख टन डी.ए.पी. के अग्रिम भण्डार का प्रावधान किया है, जिसमें तीस करोड़ का प्रावधान हम लोगों ने किया है। इसके साथ-साथ सरकार के बीज वितरण की

(श्री जगदीश चन्द्र)

जो हमारी संस्थाएं हैं, जो जी.एस.एस. के माध्यम से, के.वी.एस. के माध्यम से गांवों में बीज वितरण की जो व्यवस्था की गयी है, उसमें 200 आउटलेट्स 200 मण्डियों में खोले जाएंगे। सरकार की तरफ से उन मण्डियों में नि:शुल्क भूमि प्रदान की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार के किसान को बीज के बारे में कोई समस्या पैदा न हो।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास में 6,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें गांव की सड़कों, नरेगा और दूसरी योजनाओं को शामिल किया गया है। पर्यटन में सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है। राजस्थान एक ऐतिहासिक प्रदेश है। दूरदराज से, दुनिया के दूसरे कोनों से लोग हमारे इस प्रदेश में पर्यटन के लिहाज से आते हैं। सौ करोड़ का जो प्रावधान किया गया है, अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षा के परिधान की बात की है, मैं बधाई देना चाह रहा हूं, आजादी के बाद राजस्थान के इतिहास में 39,524 करोड़ और 27 लाख एकमात्र शिक्षा के लिए देने की व्यवस्था की है, यह एक ऐतिहासिक फैसला है।

राजस्थान सरकार की मंशा है, प्रदेश के सारे सरकारी स्कूल ठीक हों और वे सभी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हों, जिससे ग्राम और देहातों के बच्चों को आगे बढ़ने के अवसरों से वंचित न रहना पड़े। राजस्थान में जो स्कूल बंद कर दिये गये थे, राइट टू एजुकेशन के माध्यम से उस क्राइटेरिया में पिछली सरकार ने स्कूल बंद किये थे, उन सभी स्कूलों को खोलने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, टीचर्स की जहां कमी थी, उसकी भरपाई का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाह रहा हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): मैं बात करना चाह रहा हूं कम्प्यूटर शिक्षक और कस्तूरबा गांधी आवासीय योजनाएं, जो हास्टल की बनायी हैं, ये अपने आपमें बहुत बढ़िया हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने संस्कार देने के लिए नैतिक शिक्षा देने के लिए शनिवार के दिन 'नो बैग डे' का अनाउंसमेंट किया है। यह अपने आपमें निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक फैसला है।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि समय की पाबंदी है, मेरा बोलने का नम्बर भी लास्ट में आया है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले और इसके साथ-साथ, राजस्थान जो कि खेती पर

(श्री जगदीश चन्द्र)

निर्भर है, जिसकी 25 परसेंट जी.डी.पी. का हम योगदान करते हैं, इसमें जल संसाधन और सिंचाई क्षेत्र के लिए 4,557 करोड़ और 87 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है, 44 किलोमीटर की री-लाइन का काम आगामी वर्षों में शुरू हो रहा है और 17 किलोमीटर का सरहिन्द फीडर का काम शुरू हो रहा है, जिसका हमने पंजाब सरकार से एम.ओ.यू. किया है।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट और लूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि जब देश के प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह थे, ये ही लोग थे, जब बजट पेश होता था तो हमेशा इनका स्टेटमेंट आता था कि यह आंकड़ों का मायाजाल है। कल जब हिन्दुस्तान में यू.एस.ए. के राष्ट्रपति आये हुए थे। जो हिन्दुस्तान की 134 साल पुरानी पार्टी है, उसके अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा दिये गये डिनर में भी नहीं बुलाया गया। इससे ज्यादा भेदभाव क्या हो सकता है, यह बड़े शर्म की बात है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं, 134 साल पुरानी पार्टी, जिसमें 11 परसेंट वोट बेस है, उसके अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया, यह अपने आपमें अफसोस की बात है।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि सादुलशहर क्षेत्र के लिए 1,872 क्यूसेक्स पानी जो पिछले बीस साल से हम मांग रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूं कि कम से कम भाखड़ा का ध्यान रखें। हजारों एकड़ जमीन बंजर हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा अगर इस पर गौर नहीं किया गया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजें। श्री जब्बर सिंह सांखला।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2020-21 की इस चर्चा में बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में सुबह से हम सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, मैं भी इस सदन का एक नया सदस्य हूं। बजट की यह किताब जो कि 64 पेज की है, इसमें तीस पेजों पर जोधपुर का नाम है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपने चीफ व्हिप से कहकर अपना नाम लिखवाएं और फिर बोलें खड़े होकर।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): सभापति महोदय, अगर ये लोग नहीं चाहते कि कोई नया मैम्बर बोले तो मैं बैठ जाता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप अपनी बात कहें, समय समाप्त हो रहा है।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): सभापति महोदय, मैं नया हूं। इनसे कहें कि प्लीज डिस्टर्ब न करें। जो खरी बातें हैं, उन्हें सुनना सीखें। 64 पेज की इस किताब में 30 पेजों पर जोधपुर का नाम है। यह बजट राजस्थान का नहीं होकर, केवल और केवल मात्र जोधपुर जिले का बजट है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोल रहे हैं, आप उन्हें बोलने दें।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): सभापति महोदय, साथ ही निरोगी राजस्थान की बात हम सुबह से कर रहे हैं, सभी सुन रहे हैं। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र आसीन्द की बात करूंगा। आसीन्द और बदनौर में जो एम्बुलेंस हैं, वे बिलकुल खटारा हालत में हैं। मेरे यहां से भीलवाड़ा 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। सरकार की एम्बुलेंस के भरोसे पर अगर किसी मरीज को भीलवाड़ा ले जाया जाए तो शायद रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाए। इस तरह की खटारा एंबुलेंस दोनों जगह, बदनौर और आसीन्द में हैं। साथ ही, सभापति महोदय, पूरे ब्लाक में स्टाफ की कमी है। गुलाबपुरा, आसीन्द, बदनौर, हुरड़ा, सभी जगह पर डाक्टरों की कमी है। शम्भुगढ़ में डाक्टर नहीं हैं।

साथ ही, हम सिंचाई की बात करें, सिंचाई विभाग का मेरे आसीन्द में खारी बांध नाम का बहुत बड़ा डैम है। सभापति महोदय, पूरे आसीन्द और हुरड़ा की सिंचाई खारी बांध के डैम से ही होती है। अभी इस बारिश में उसकी 21 फीट की भराव की क्षमता है और साढ़े सत्रह फीट पानी उसमें आया था। बारिश के दिनों में मैंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात की थी क्योंकि एरिये की पूरी नहरें टूटी हुई हैं। उन नहरों के बारे में मैंने चर्चा की। सिंचाई विभाग के ए.ई.एन., जे.ई.एन. और एस.ई. साहब, सबने कहा कि हम मरम्मत का काम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इस बांध में पानी आएगा ही नहीं। दस साल में पहली बार पानी आया।

सभापति महोदय, साढ़े सत्रह फीट पानी था। तीन बार सिंचाई हुई। तीनों ही बार आधे से ज्यादा पानी बेकार गया। वहां के गड्ढे भर गये। जो छोटे-मोटे तालाब थे, उनमें चला गया। पानी बिलकुल बेकार हुआ। साथ ही

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

सभापति महोदय, बदनौर उप खण्ड में भोजपुरा फीडर के नाम से एक बहुत बड़ा फीडर है, जिसका काम लगभग 35 से 40 साल पहले स्टार्ट हुआ।

सभापति महोदय, भोजपुरा फीडर का काम लगभग 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि 90 प्रतिशत भोजपुरा फीडर का काम पूरा हो चुका है। केवल और केवल 10 प्रतिशत काम वहां और बाकी है। वह काम पूरा हो जाए, 10 प्रतिशत काम के भरोसे लगभग पिछले 10 सालों से काम बाकी पड़ा है और बंद पड़ा है। जो काम हो रखा था, वह भी लगभग टूट चुका है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि जो काम बाकी है, इस बजट में आप उस काम को लें और भोजपुरा फीडर का जो काम बाकी है, उसे पूरा कराएं। उस फीडर का काम पूरा होने से बदनौर उप खण्ड के लगभग 150 से 200 गांव जल से प्रभावित होते हैं। सभापति महोदय, इससे उनके सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी और पीने के पानी की व्यवस्था भी वहां हो जाएगी।

सभापति महोदय, शिक्षा की हम बात करें तो आज यहां बहुत बड़ी-बड़ी बातें हो रही थीं। सहाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने भीलवाड़ा जिले का नाम लिया और उसमें गुलाबपुरा शहर का भी नाम लिया है। गुलाबपुरा शहर मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है। सभापति महोदय, मैंने पिछले सत्र में भी चिल्ला-चिल्लाकर शिक्षा मंत्रीजी से आग्रह किया था और एक बार पुन: मैं सदन में बोलना चाहता हूं कि राजस्थान के प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर बारहवीं तक की सरकारी स्कूल है। सभापति महोदय, 30 से 35 हजार की आबादी होने के बावजूद गुलाबपुरा शहर में आज भी 12वीं तक की सरकारी स्कूल नहीं है। मैं कालेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 12वीं तक की बात कर रहा हूं। सरकारी विद्यालय आज भी गुलाबपुरा में नहीं है और सरकार का ध्यान इस ओर गया ही नहीं है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे और इसी बजट में गुलाबपुरा में महाविद्यालय और 12वीं तक की स्कूल की घोषणा करे।

सभापति महोदय, पिछली सरकार के समय ईरास और उजियाणा, दोनों पंचायत हैडक्वार्टर हैं, वहां की स्कूलों की जो बिल्डिंग्स हैं वे पूरी तरह से टूट चुकी हैं, पट्टियां लटकी हुई हैं। वहां के छात्र-छात्राएं हैं, वे बाहर पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। दोनों जगह की बिल्डिंग्स डी.एम.एफ.टी. फण्ड के माध्यम से पास हो

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

चुकी हैं, पर इस सरकार ने आते ही वे सारे काम रोक दिये, जो अधर में पड़े हैं। मैं चाहूंगा कि इसी बजट में ईरास और उजियाणा, ये दोनों विद्यालय लें। साथ ही मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में जहां भी कक्षा कक्ष नहीं हैं, जहां कमी हैं, वहां पर आप कक्षा कक्ष भी इसी बजट में लें।

सभापति महोदय, मैं पी.डब्ल्यू.डी. की बात करूंगा। कटार एक पंचायत हैडक्वार्टर है जो बदकिस्मती से मेरा खुद का गांव है। वहां कृषि विपणन बोर्ड की सड़क बनी हुई थी। वह पिछले 8-10 सालों से टूटी हुई है। इन 12 महीनों में वहां की जनता ने चार या पांच बार वहां धरना-प्रदर्शन किया, रोड जाम किया, बहुत आंदोलन किये, लेकिन आज तक किसी ने सुनवाई नहीं की। पिछले सत्र और पिछले बजट सत्र में मैंने कहा भी था। सभापति महोदय, कुछ सड़कें हैं, जिनके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा। कटार से रघुनाथपुरा, कटार चौराहे से कटार; कटार से चांदसेन, ज्ञानगढ़; पड़ौदा से काल्यास; आकड़सारा से विजयनगर चौराहा, बदनौर; लालपुरा भीम से बादसी, गांगलास से हरिपुरा...

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): सभापति महोदय, मुझे तो पांच मिनट हुए हैं और दस मिनट का समय आपने दिया है।

ये जो मेरे विधान सभा क्षेत्र की सड़कें हैं, ये बनी नहीं हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बजट में इन सारी सड़कों को लें और इन सड़कों का काम जल्द से जल्द करवाएं।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान पर्यटन की तरफ दिलाना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में सवाईभोज मंदिर गुर्जर समाज का अन्तरराष्ट्रीय स्तर का मंदिर है। पिछली सरकार में हमारे यहां यशस्वी वसुन्धरा जी मुख्य मंत्रीजी थीं, तब उन्होंने वहां आकर ढाई करोड़ रुपये की एक घोषणा की थी। दुबारा नहीं आने से वह घोषणा अटकी हुई पड़ी है। मैं चाहूंगा और सरकार से आग्रह करूंगा कि वह जो ढाई करोड़ रुपये की घोषणा है, उसको आप फिर से करें। सवाईभोज मंदिर का डवलपमेंट आप कराएंगे तो भगवान आपका भला करेंगे और मेरा भी करेंगे। मैं भी नया हूं, वहां के लोग याद करेंगे कि यह नया लड़का जीतकर गया है तो कुछ लेकर आया है।

सभापति महोदय, भीण्डर से रामगढ़ मेगा हाईवे सड़क, जो वाया करेड़ा और आसीन्द होते हुए पास हो रखी है, उसका काम अधर में अटका

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

हुआ है और इस बजट में भी उस सड़क को नहीं लिया गया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि आप भीण्डर से रामगढ़ सड़क को भी लेंगे तो उस पूरे एरिया का भला हो जाएगा।

सभापति महोदय, इस बजट में, बेरोजगारी भत्ते की जो घोषणा कांग्रेस की सरकार के नेताओं ने की थी, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जी ने बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की थी कि प्रत्येक बेरोजगार को 3,500 रुपये माह के दिये जाएंगे, तो वह भी आप चालू कराएं। साथ ही, पूरे राजस्थान के किसानों को एक जुमला दिया गया था कि किसानों के दो लाख रुपये तक के सम्पूर्ण कर्जे माफ कर दिये जाएंगे। आज किसान रो रहे हैं, किसानों के कुर्की के आदेश आये हुए हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 400-450 कुर्की के आदेश आये हुए हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि आप लोगों ने जो ऋण माफी का वादा किया था वह भी आप निभाएं।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): केवल एक मिनट ही, सभापति महोदय।

साथ ही, बिजली की बात यहां हम सब लोग कर रहे थे और सुन रहे थे। सभापति महोदय, अभी बिजली की दरें डोमेस्टिक और कामर्शियल के जो कनेक्शंस हैं, उनमें बढ़ाई हैं। बड़े जोर-शोर से सभी नेताओं ने कहा था कि किसानों की बिजली की दरें नहीं बढ़ायी हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि आपने 833 रुपये, जो किसानों की सब्सिडी दी जा रही थी, वह नहीं दी है; बन्द कर दिये हैं तो वे 833 रुपये भी किसानों के तो एक हिसाब से देखा जाए तो बढ़े हुए ही हैं। इसलिए आप यह दावा नहीं करें कि हमने किसानों की बिजली में कुछ नहीं बढ़ाया है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री रामनिवास गावड़िया।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): सभापति महोदय, केवल एक मिनट।

श्री सभापति: समाप्त करें। समाप्त करें। विराजिए आप।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): सभापति महोदय, केवल एक मिनट।

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) समय खराब मत करिये। मैं अलाउ नहीं करूंगा, मैंने नाम बुला दिया। क्यों समय खराब कर रहे हैं आप? अलाउ नहीं करूंगा, विराजिए। श्री रामनिवास गावड़िया। विराजिए।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): 000

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री सभापति: नारायण जी, आप विराजो। बेनीवाल साहब, विराजिए आप। अंकित नहीं होगा। विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए आप। (व्यवधान) मैं दे रहा हूं संरक्षण, आप विराजिए। माननीय सदस्य, परम्पराएं सीख लीजिये। विराजिए।

श्री रामनिवास गावडिया (परबतसर): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, आज आपने 2020-21 के इस बजट की चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए और सीमित संसाधन के बावजूद जो बजट सरकार ने प्रस्तुत किया है, निश्चित तौर पर उस बजट में तमाम उन बुनियादी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश की 7 करोड़ जनता को ध्यान में रखते हुए, अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, महिलाओं को सुरक्षा, बुजुर्गों का सम्मान और निरोगी राजस्थान का जो तोहफा प्रदेश की जनता को दिया है, निश्चित तौर पर यह फैसला स्वागत योग्य है।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिन बुनियादी बातों का ध्यान रखा, आज इस बात के लिए राजस्थान का तमाम नौजवान धन्यवाद देता है कि आज देश के जो हालात हैं, आर्थिक विकास की दर जिस निचले स्तर पर गिरी हुई है और पिछले 45 वर्षों से आज बेरोजगारी आसमान को छू रही है उसी दरमियान माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 53 हजार नौजवानों को रोजगार देने की इस बजट में घोषणा की है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को राजस्थान के नौजवानों की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आज इस बजट चर्चा में मैं मेरे क्षेत्र की बात को ध्यान में रखते हुए आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि परबतसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का मुद्दा मैंने बजट में पिछली बार भी दोहराया था और आज पुन: मैं आपके माध्यम से सरकार और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि किशनगढ़-हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर स्थित परबतसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उन तमाम मापदण्डों को पूरा करता है, चाहे वह आउटडोर-इन्डोर की हो, चाहे लोकेशन की बात हो। मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां ट्रोमा सेंटर खोलकर और बैड बढ़ाकर परबतसर की जनता को आप आशीर्वाद प्रदान करें। पिछले कई वर्षों से जिस तरह की मांग परबतसर के आम किसान की, आम अवाम की रही है, मुझे

(श्री रामनिवास गावडिया)

उम्मीद है कि आप मुख्य मंत्रीजी के रिप्लाई में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करके ट्रोमा सेंटर खोलने का मुझे आश्वासन देंगे।

इसके साथ ही, एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी., नेशनल रूरल वाटर सेनिटेशन प्रोग्राम के तहत परबतसर की लगभग 500 अचिन्हित ढाणियों को जोड़े जाने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी से मैं दरख्वास्त करता हूं। इसके साथ ही, जल जीवन मिशन योजना के तहत विधान सभा परबतसर की उन ढाणियों को घर-घर कनेक्शन से जोड़ा जाए जो कुचामन एवं नावां पंचायत समिति के अन्तर्गत आती हैं।

माननीय सभापति महोदय, हम लोग उस पावन धरा से आते हैं, जहां वीर तेजाजी महाराज ने जन्म लिया। वहां पर लोगों में त्याग और समर्पण का भाव है। मैं पिछले कई दशकों से देखता आ रहा हूं कि पूरे पश्चिमी राजस्थान में, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से सम्बन्ध रखते हों लेकिन तेजाजी महाराज के नाम पर, उनका जयकारा लगाकर सब नेता वोट बटोरने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि परबतसर पशु मेला वीर तेजाजी के नाम से प्रसिद्ध है, पूरे देश में और पूरे पश्चिमी राजस्थान में तेजाजी महाराज की विशेष मान्यता रही है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह आग्रह करूंगा कि पहले कई बार मैंने भी तेजाजी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए मांग उठायी है। आज माननीय मुख्य मंत्रीजी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पर्यटन विभाग को सौ करोड़ रुपये का जो बजट दिया, उसके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि तेजाजी महाराज के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, जो हमने वहां से एस्टीमेट बनाकर भेजा, उसको बजट रिप्लाई में सम्मिलित करते हुए, पूरे पश्चिमी राजस्थान के उन नौजवानों, किसानों को, जो उनको लोक देवता के रूप में मानते हैं, उनको आप आशीर्वाद प्रदान करेंगे।

इसके साथ ही, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमेशा संवेदनशीलता दिखाते हुए अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और किसान को किस तरह खुशहाल किया जा सकता है, इन बातों पर जोर दिया है। उसी के तहत हमारे कई माननीय सदस्य आज कह रहे थे कि आर.टी.ई. के नियमों के विरुद्ध इन्हीं की सरकार ने पूर्व में एकीकरण के नाम पर कई

(श्री रामनिवास गावडिया)

स्कूलों को बंद किया। आज राजसमन्द से आने वाली सदस्या ने भी इस बात को रखा और इसके अलावा अन्य सदस्यों ने भी इस बात को रखा कि पिछले डेढ़ वर्ष में सरकार ने उन स्कूलों के लिए क्या किया। मुझे आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने आज ही लगभग एक हजार स्कूलों को, जिनको पूर्ववर्ती सरकार ने एकीकरण के नाम पर बंद किया था, पुन: आदेश निकालकर शुरु किया है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों के विरोध में, किसानों के बच्चों को ध्यान में नहीं रखते हुए, इन लोगों ने जरा सा भी नहीं सोचा कि वे व्यक्ति जो गांव, ढाणी में रहते हैं, उनके बच्चे कहां पढ़ेंगे, किस तरह वे लिखेंगे। आने वाले समय में जिस नौजवान के लिए, जिस बच्चे के लिए हर जगह कहा जाता है कि वह समाज का भविष्य है, देश का भविष्य है, आप लोगों ने उनके ऊपर कुठाराघात किया।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके साथ ही, निरोगी राजस्थान और कृषि के माध्यम से 3,430 करोड़ रुपये का बजट इसमें शामिल किया गया है। जल संग्रहण के लिए 12,500 फार्म पोण्ड को भी इन्होंने बजट में शामिल किया। उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को, कृषि मंत्रीजी यहां विराजमान है, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके साथ मैं आपके माध्यम से दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरह से नौजवानों के लिए राजस्थान की सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है, हमारे विपक्ष में बैठी पार्टी के लोगों से, आप लोगों से भी विनती करूंगा कि राजस्थान की 7 करोड़ की जनता ने 25 के 25 सांसद आपके यहां से जिताकर भेजे, आप लोगों ने वादा किया था कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसानों को खुशहाल करेंगे, आप सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप सब लोग केन्द्र में बैठी सरकार से आग्रह करें। पिछले 45 वर्षों में अगर बेरोजगारी की समस्या ज्यादा बढ़ी है तो वर्तमान में बढ़ी है। आप नौजवानों को रोजगार देने के लिए बात करें। देश की जी.डी.पी. आज जिस तरह से गिर रही है, उसके लिए आप बात करें। आने वाले समय में राजस्थान का नौजवान और किसान आप लोगों को आशीर्वाद देगा और हम सब लोगों को दुआ देगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): इस लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर आज हम सब लोगों को इस बात के लिए चर्चा करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि किस तरह राजस्थान के नौजवान और किसान का भला हो सकता है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए, माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, बहुत देर से दर पर आंखें लगी थीं, हुजूर आते-आते बहुत देर कर दी। आठ बजे तक का सदन है और आपने 7 बजकर 55 मिनट पर मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि हम आपसे संरक्षण की बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं और हमारी पार्टी का जो समय है, उसके लिए भी हम बोलने की बड़ी तमन्ना लेकर आपके यहां आये हैं। सुबह 11 बजे से लेकर 8 बजे तक हमने इंतजार भी किया। मेरी आपसे उम्मीद यही थी कि आप नये आने वालों का संरक्षण करेंगे, चूंकि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को हर मुद्दे पर अलग समय भी मिलना चाहिए।

श्री सभापति: आप सीधे-सीधे मुद्दे पर आकर बात करें तो आपकी बात आ जाएगी।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सर..

श्री सभापति: मुद्दे पर आकर अपनी बात कहें, आपको बोलने का मौका दिया, आप बोलिए।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): मुद्दा कुछ नहीं है। मुद्दा यही है कि आपने मुझे खड़े होने का मौका दिया, धन्यवाद-धन्यवाद।

श्री सभापति: सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 26 फरवरी 2020 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.57 बजे बुधवार, दिनांक 26 फरवरी 2020 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सोलर उत्पादन को बढ़ावा देने की कार्ययोजना

182. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार की सोलर उत्पादन को बढ़ावा देने की कोई कार्ययोजना है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में सोलर विद्युत उत्पादन योजना लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितने मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार किसानों की कम उपजाऊ जमीनों पर सोलर ऊर्जा उत्पादन के संयंत्र लगाकर विद्युत उत्पादन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार ने राज्य में सोलर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नयी सौर ऊर्जा नीति-2019 जारी की है। जिसमे वर्ष 2024-25 तक प्रदेश में 30,000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	विवरण	क्षमता
1.	ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र/सोलर पार्क	24,000 मेगावाट
2.	विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादन	4,000 मेगावाट
3.	सोलर रूफ टाप	1,000 मेगावाट
4.	सोलर पम्प	1,000 मेगावाट

(2) लक्ष्यों का निर्धारण वर्षवार न कर बिन्दु संख्या एक के अनुसार किया गया है।

(3) जी हां। विद्युत वितरण निगमों के 33/11 के.वी. सब स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी में अनुपयोगी/बंजर भूमि पर किसान 0.5 मेगावाट क्षमता से 2 मेगावाट क्षमता तक के विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सभी इच्छुक आवेदकनकर्ताओं से सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने अथवा भूमि लीज पर देने के प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे। कुल 12853 प्रस्ताव प्राप्त

(ऊर्जा मंत्री)

हुए हैं। इस योजना के अन्तर्गत सौर ऊर्जा उत्पादकों के चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है। इस योजना के तहत विद्युत की खरीद 25 वर्ष तक 3.14 रुपये प्रति यूनिट की दर से की जाएगी।

जैतारण में जवाई परियोजना से मीठा पेयजल उपलब्ध कराने की योजना

191. श्री अविनाश (जैतारण): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जैतारण में जवाई परियोजना का कार्य वर्तमान में बन्द है?

(2) उक्त परियोजना का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?

(3) क्या सरकार उक्त परियोजना से वंचित विधान सभा क्षेत्र जैतारण के अन्य सभी गांवों को भी उक्त परियोजना से जोड़कर आम लोगों को मीठा पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेंज पर रखें।

(4) जैतारण क्षेत्र में जवाई परियोजना की कुल स्वीकृत राशि, भुगतान राशि व शेष राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार जवाई बांध के पुनर्भरण की योजना को शीघ्र स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेंज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र जैतारण के 125 ग्रामों सहित कुल 133 ग्रामों (विधान सभा क्षेत्र सोजत के 8 ग्राम सम्मिलित) में सतही जल स्रोत जवाई बांध आधारित जवाई पेयजल परियोजना के पैकेज पंचम एवं कलस्टर परियोजना-तृतीय से लाभान्वित करने हेतु कार्यादेशित अनुबंधक फर्म मैसर्स गेमन इंडिया लिमिटेड, मुम्बई द्वारा इस परियोजना का कार्य माह अप्रैल, 2019 से नहीं किया जा रहा था।

फर्म द्वारा दिनांक 06.12.2019 से परियोजना का कार्य पुन: प्रारम्भ किया गया तथा दिनांक 02 फरवरी, 2020 से कार्य पूर्ण रूप से बन्द है।

(2) अनुबंधक फर्म द्वारा उक्त पेयजल परियोजना का 76 प्रतिशत कार्य अब तक पूर्ण किया गया है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

फर्म द्वारा परियोजना के कार्य उक्तानुसार अधूरा छोड़ने एवं बंद कर देने तथा शेष रहे कार्य प्रारम्भ नहीं करने की स्थिति में, अनुबंध की शर्तों के अनुसार विभाग द्वारा उक्त अनुबंधक फर्म को आबंटित कान्ट्रेक्ट रिसाइण्ड करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में सम्मिलित कुल 216 ग्रामों में से 125 ग्रामों की अभिकल्पित पेयजल मांग के अनुरूप ही परियोजना के विभिन्न अवयवों का अभिकल्पन करते हुए स्वीकृत परियोजना का 76 प्रतिशत कार्य उक्तानुसार अब तक पूर्ण किया जा चुका है।

इस प्रगतिरत परियोजना में जैतारण क्षेत्र के शेष रहे 91 ग्रामों की पेयजल मांग सम्मिलित नहीं होने के कारण, इन ग्रामों को उक्त परियोजना से जोड़ा जाना तकनीकी रूप से व्यवहारिक नहीं है।

(4) विधान सभा क्षेत्र जैतारण एवं सोजत के कुल 133 ग्रामों को जवाई पेयजल परियोजना से लाभान्वित करने हेतु मैसर्स गेमन इंडिया लिमिटेड, मुम्बई को राशि रुपये 315.50 करोड़ (निष्पादन लागत रुपये 291.84 करोड़ तथा संचालन एवं संधारण लागत रुपये 23.66 करोड़) का कार्यादेश दिनांक 04.10.2013 को जारी किया गया।

परियोजना की निष्पादन लागत रुपये 291.84 करोड़ के विरुद्ध रुपये 221.70 करोड़ की राशि अब तक व्यय हुई है तथा रुपये 70.14 करोड़ की राशि वर्तमान में शेष रही है।

(5) जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत जवाई बांध के पुनर्भरण की योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) मैसर्स वाप्कोस लिमिटेड, गुड़गांव द्वारा तैयार करने का कार्य प्रगतिरत है। परियोजना की हाइड्रोलोजी का अनुमोदन केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा किया जा चुका है तथा डिजाइन्ड फ्लड रिपोर्ट भी केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त हो चुकी है। सेडिमेन्टेशन एवं इन्टरस्टेट आसपेक्ट से सम्बन्धित विषय केन्द्रीय जल आयोग में विचाराधीन है।

डी.पी.आर. के फिजिबल पाये जाने पर स्वीकृति उपरांत आवश्यक संसाधनों की उपलब्धतानुसार कार्य कराया जाना विचाराधीन है।

सदन में नहीं लिया जा सका तारांकित प्रश्न एवं उसका उत्तर

बूंदी व कोटा जिले के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

197. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोवरायपाटन): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार के समक्ष उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो बूंदी व कोटा जिले के कौन-कौन से विद्यालयों के? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विभागीय प्रस्तावों के अनुसार उक्त विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विद्यालय क्रमोन्नति के सम्बन्ध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राज., बीकानेर से दिनांक 30.07.2019 एवं दिनांक 26.09.2019 को जन घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या 7.9 के क्रम में प्रस्ताव भिजवाये गये हैं जो परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(2) बजट घोषणा 2019-20 के प्रावधानों के अनुसार 600 रा.उ.प्रा.वि. को रा.मा.वि. में तथा 500 रा.मा.वि. को रा.उ.मा.वि. में क्रमोन्नत करने का लक्ष्य रखा गया है। क्रमोन्नति हेतु वित्तीय प्रावधानान्तर्गत, स्थानीय मांग एवं निर्धारित मानदण्डों तथा समग्र स्थिति का गुणावगुण के आधार पर आंकलन करने के पश्चात् सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

खो-नागोरियान पुलिस थाने में अखबार वितरक की हत्या के दर्ज प्रकरण की जांच

180. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जयपुर शहर के खो-नागोरियान थाने के अन्तर्गत अखबार वितरक की हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ था? यदि हां, तो कब? उक्त प्रकरण में मुल्जिमों की गिरफ्तारी पर पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पुलिस थाना खो-नागोरियान, जयपुर (पूर्व) आयुक्तालय में अखबार वितरक की हत्या के सम्बन्ध में प्रकरण संख्या 562/2019, धारा 30 आई.पी.सी. दिनांक 05.09.2019 को पंजीबद्ध हुआ है। उक्त प्रकरण में बाद अनुसंधान मुल्जिम रफीक खान पुत्र श्री अब्दुल गफूर को दिनांक 10.09.2019 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया जा चुका है एवं मुल्जिम के खिलाफ चार्जशीट नम्बर 268/2019, दिनांक 04.10.2019 को किता की जाकर माननीय न्यायालय में 05.10.2019 को पेश की जा चुकी है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

जवाई नदी के तटीय गांवों में तटबंध का निर्माण

181. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि वर्षा ऋतु में जवाई नदी में पानी की आवक से तटीय गांवों में पानी भर जाता है, जिससे जान माल की हानि होती है? यदि हां, तो क्या सरकार तटीय गांवों के लिए तटबंध बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जवाई नदी में पानी की आवक अधिक होने की स्थिति में तटीय गांवों की भूमि/गावों में पानी भरता है। जवाई नदी के किनारे तटबंध बनाने के कार्य, मांग एवं आवश्यकतानुसार महानरेगा योजना अन्तर्गत प्रस्तावित कर स्वीकृति उपरान्त संसाधन उपलब्धतानुसार करवाये जाना प्रस्तावित है।

मावली के पुलिस थानों में नफरी बढ़ाने की कार्ययोजना

182. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली के थाने मावली, फतहनगर, घासा, डबोक, सुखेर व प्रताप नगर में नफरी की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या सरकार उक्त थानों में नफरी बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त थानों व उप-अधीक्षक कार्यालय स्टाफ के लिए क्वाटर्स की कोई व्यवस्था है? यदि नहीं, तो उक्त व्यवस्था कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मावली विधान सभा क्षेत्र के थाना मावली, फतहनगर, घासा, डबोक, सुखेर व प्रताप नगर में नफरी की वर्तमान स्थिति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। नफरी बढ़ाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं मांग के मध्य संतुलन रखकर ही निर्णय लिये जाते हैं।

(2) मावली विधान सभा क्षेत्र के थाना मावली, फतहनगर, घासा, डबोक, सुखेर व प्रताप नगर में वर्तमान में उपलब्ध क्वाटर्स की सूचना परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है। पुलिस अधीक्षक, उदयपुर से मावली विधान सभा क्षेत्र के थानों के लिए 13 अपर सबोर्डिनेट क्वाटर्स तथा 46 लोअर सबोर्डिनेट क्वाटर्स के निर्माण के प्राप्त प्रस्ताव आगामी योजना में स्वीकृति हेतु सम्मिलित किये हुए हैं। भविष्य में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु बजट प्राप्त होने पर जिला/यूनिटों की मांग पर आनुपातिक आधार पर बजट आबंटित किया जाएगा। उप-अधीक्षक कार्यालय स्टाफ के लिए वर्तमान में राजकीय क्वाटर्स की व्यवस्था नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कार्मिकों के मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी

183. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि राज्य के सरकारी कार्मिकों का केन्द्र की तर्ज पर एक वित्तीय वर्ष में 2 बार (जुलाई और जनवरी माह) महंगाई भत्ता बढ़ाये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो राज्य सरकार ने जुलाई, 2019 एवं जनवरी,

(श्री नारायण सिंह देवल)
2020 में प्रदेश के कार्मिकों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। बजट घोषणा 2020-21 के बिन्दु संख्या 200 में राज्य कार्मिकों को मंहगाई भत्ते में जुलाई 2019 से 5 प्रतिशत (12% से 17%) की वृद्धि किये जाने की घोषणा की गयी।

केन्द्र सरकार द्वारा आगामी मंहगाई भत्ते के आदेश जारी होने के पश्चात् ही राज्य सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर मंहगाई भत्ते में वृद्धि किये जाने पर विचार किया जाता है।

नोखा कृषि उपज मण्डी के अन्तर्गत आने वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना

184. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी नोखा के अन्तर्गत कई गांव अब तक सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत 5 वर्षों में उक्त कृषि उपज मण्डी के अन्तर्गत कितनी सड़कों का निर्माण किया गया एवं निर्माण में कितना व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार के पास उक्त गांवों में सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव लम्बित हैं, जहां पर अब तक सड़कें नहीं बनी हैं? यदि हां, तो कितने और कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि कृषि उपज मण्डी नोखा के अन्तर्गत कई गांव अभी तक सडकों से नहीं जुड़े हैं। गांवो को जोड़ने की नोडल एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग, नोखा से प्राप्त सूचना के अनुसार कृषि उपज मण्डी समिति, नोखा के अन्तर्गत पांच गांव अभी तक सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ " पर उपलब्ध है।

(2) विगत पांच वर्षों में कृषि उपज मण्डी समिति नोखा क्षेत्र के अन्तर्गत 14 सड़कों के 33.50 किमी लम्बाई का निर्माण किया गया है एवं

(कृषि विपणन मंत्री)

निर्माण पर राशि रू. 759.10 लाख का व्यय हुआ है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। कृषि विपणन निदेशालय स्तर पर कृषि उपज मण्डी समिति, नोखा के सड़क निर्माण स्वीकृति का कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कृषि उपज मण्डी समिति, नोखा को क्षेत्र में 16 सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु जन प्रतिनिधियों से दिनांक 10.02.2020 को 4 पत्र प्राप्त हुए हैं। पत्रों में उल्लेखित सड़कों का विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर में शराब ठेकों के आबंटन से प्राप्त राजस्व

185. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बाड़मेर में वर्तमान में सरकार द्वारा कितने शराब के ठेकों का आवंटन किया गया है एवं उनसे प्रति माह कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है? विगत एक वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में विगत एक वर्ष में कितनी शराब परिवहन के दौरान अथवा डिपो में नष्ट हो गयी अथवा खराब हो गयी, का माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में 167 देशी मदिरा समूहों तथा 18 भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर दुकानों का आबंटन हो रखा है। गत वर्ष 2018-19 में इनकी संख्या क्रमशः 168 एवं 18 थी।

गत एक वर्ष में बाड़मेर जिले में शराब ठेको से औसतन प्रतिमाह राशि 20.66 करोड़ रुपये आबकारी राजस्व के रूप में प्राप्त हो रही है। गत एक वर्ष के राजस्व प्राप्ति (फरवरी, 2019 से जनवरी, 2020 तक) प्राप्त राजस्व का विवरण परिशिष्ट ''1'' पर संलग्न है।

(2) बाड़मेर जिले में गत एक वर्ष में भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर परिवहन के दौरान नष्ट हुई शराब की मात्रा क्रमशः 40,905 बोतलें एवं 52,045 बोतलें है। जिसका मासिक विवरण परिशिष्ट “2” पर संलग्न है।

(आबकारी मंत्री)

बाड़मेर जिले में देशी मदिरा के कुल 02 डिपो बाड़मेर तथा बालोतरा में राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड द्वारा संचालित हैं। जिनमें माह जनवरी, 2019 से जनवरी, 2020 तक कुल (4,093.53+6,440.91)10,534.44 बल्क लीटर देशी मदिरा परिवहन के दौरान क्षति हुई। जिसका मासिक विवरण परिशिष्ट संख्या "3" एवं "4" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रतरेड़ी कलां ग्राम पंचायत (बाड़मेर) का भवन निर्माण

186. श्री अमीन खां (शिव): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर की पंचायत समिति गडरा रोड की ग्राम पंचायत रतरेड़ी कलां में पंचायत भवन नहीं बना है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बान्दासर के भवन का निर्माण अब तक अपूर्ण है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। डी.एन.पी. क्षेत्र (Desert National Park) में होने के कारण ग्राम पंचायत रतरेडी कलॉ में पंचायत भवन नहीं है। भवन निर्माण की एन.ओ.सी. हेतु वन विभाग को पत्र क्रमांक एस.पी. 01 दिनांक 23.09.2019 से आवेदन कर दिया है। परन्तु अभी तक वन विभाग से एन.ओ.सी. अप्राप्त है।

(2) ग्राम पंचायत बान्दासर के कार्यालय भवन निर्माण की राशि रुपये 35.35 लाख की स्वीकृति जिला परिषद द्वारा आदेश क्रमांक 17242, दिनांक 03.10.2016 के द्वारा जारी की जा चुकी है। ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री आपूर्ति हेतु दिनांक 02.03.2018 को फर्म को आदेश दिया गया, परन्तु उक्त कार्य पर फर्म द्वारा सामग्री आपूर्ति नहीं करने के कारण उक्त कार्य लिंटल स्तर तक ही हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा निविदत फर्म को नोटिस जारी कर दिया गया है।

इस कार्य के निर्माण में लापरवाही बरतने वाले तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही दिनांक 06.02.2020 के द्वारा प्रारम्भ कर दी गयी है।

सलूम्बर में संगमेश्वर पुलिया का निर्माण

187. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में संगमेश्वर पुलिया का वर्ष 2008 में सोम नदी के पास उद्घाटन भी कर दिया गया था, किन्तु उक्त का निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ है?

(2) क्या सरकार उक्त पुलिया का निर्माण शीघ्र कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में संगमेश्वर पुलिया हेतु वर्ष 2013 में शिलान्यास किया गया था। परन्तु समुचित स्वीकृत राशि के अभाव मे कार्य सम्पादन नहीं कराया गया। संशोधित स्वीकृति के पश्चात् दो बार निविदा आमंत्रण किया गया, परन्तु प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त नहीं होने के कारण कार्यादेश नहीं दिया जा सका।

(2) जी हां। उपरोक्त पुलिया निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, जो कि दिनांक 18.03.2020 को प्राप्त की जाएगी। उपरोक्त निविदा प्राप्त होने पर नियमानुसार स्वीकृति उपरान्त कार्य प्रारम्भ कराया जा सकेगा।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण

188. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत प्रदेश में बेस लाइन सर्वे 2019 तक कुल कितने शौचालय विहीन परिवार थे तथा नये शौचालय बनाने के लिए कुल कितनी संख्या में स्वीकृतियां जारी की गयीं? शौचालय निर्माण के पश्चात स्वीकृत राशि का कितनों को भुगतान करना शेष है तथा कितने भुगतान के लिए अपात्र घोषित कर दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतों को सरकार द्वारा खुले में शौच से मुक्त (ओ.डी.एफ.) तक घोषित कर दिया गया है तथा कितनी ग्राम पंचायतें (ओ.डी.एफ.) होने में शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत प्रदेश में बेसलाइन सर्वे 2012 में शामिल, LOB एवं NOLB अभियान के अन्तर्गत जोड़े गये शौचालय

(पंचायती राज मंत्री)

विहीन परिवार, पात्र शौचालय विहिन परिवारों की जारी स्वीकृतियां एवं भुगतान से शेष शौचालय विहीन परिवारों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	विवरण	संख्या
1	बेसलाइन सर्वे 2012 में शामिल शौचालय विहीन परिवार	72,80,188
2	ओ.डी.एफ. घोषणा पश्चात सर्वे से वंचित LOB अभियान 2018-19 में जोडे गये शौचालय विहीन परिवार	3,38,379
3	ओडीएफ घोषणा पश्चात NOLB अभियान 2019-20 में सर्वे से वंचित पात्र जोड़े गये शौचालय विहीन परिवार	8,43,109
4	बेसलाइन सर्वे 2012 में आदिनांक तक कुल शौचालय विहीन परिवार	82,32,947
5	BLS 2012 एवं LOB/NOLB से हटाये गये अपात्र परिवार	10,61,949
6	बेसलाइन सर्वे 2012 में शुद्ध पात्र शौचालय विहीन परिवार	71,70,998
7	पात्र शौचालय विहीन परिवारों की जारी स्वीकृतियां	64,07,383
8	भुगतान से शेष शौचालय विहीन परिवार	9,44,862

जिलेवार विवरण परिशिष्ट-''अ'' पर वर्णित है।

(2) राजस्थान प्रदेश की समस्त 9,894 ग्राम पंचायतें ओ.डी.एफ. घोषित कर दी गयी हैं। कोई भी ग्राम पंचायत ओ.डी.एफ. होने से शेष नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अनूपगढ़ में गुरु गोलवलकर योजना के तहत विकास कार्य

189. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गुरु गोलवलकर योजना के तहत ग्राम पंचायतों के शमशान, कब्रिस्तान, हड्डारोडी की चारदीवारी एवं अन्य सुविधाओं के विकास कार्य किये जाते हैं? यदि हां, तो वर्ष 2016 से दिसम्बर, 2019 तक विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की किन-किन ग्राम पंचायतों में उक्त योजना के तहत सुविधाएं विकसित की गयी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती संतोष)

(2) उक्त योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016 से जन सहभागिता के आधार पर कितनी-कितनी राशि कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों के लिए जमा हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त राशि में से कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में गुरु गोलवलकर योजना के तहत कितने कार्य स्वीकृत हुए हैं? कितने कार्य पूर्ण हो गये हैं और कितने लम्बित हैं? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2016 से दिसम्बर, 2019 तक अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट "1'' के अनुसार है।

(2) ग्राम पंचायतवार/कार्यवार प्राप्त जन सहभागिता राशि (राशि रु. 15.69 लाख) का विवरण परिशिष्ट-''1'' के कालम संख्या 8 के अनुसार है।

(3) योजनान्तर्गत वर्ष 2016 से दिसम्बर 2019 तक कुल 16 कार्य स्वीकृत हुए जिनमें 15 कार्य पूर्ण व 01 कार्य प्रगतिरत है। कार्यों का विवरण ग्राम पंचायतवार परिशिष्ट-''1'' अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आहड़ के राजकीय संग्रहालय में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने की कार्य-योजना

190. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय संग्रहालय, आहड़, उदयपुर में विगत चार वर्षों में कितने देशी व विदेशी पर्यटकों ने संग्रहालय का अवलोकन किया एवं उक्त से कितनी आय प्राप्त हुई? प्रतिदिन कितने पर्यटक आने का औसत रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संग्रहालय में पर्यटकों की रुचि बढ़ाने के लिए विगत चार वर्षों में क्या प्रयास किये गये?

(3) विगत चार वर्षों में संग्रहालय में कितनी नवीन पुरातत्व महत्व की वस्तुएं एवं कलाकृतियां अतिरिक्त रूप से संग्रहित की गयीं? उक्त पर वर्षवार कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय संग्रहालय, आहड़, उदयपुर में गत 4 वर्षों में देशी व विदेशी पर्यटकों की संख्या, इससे हुई आय एवं प्रतिदिन पर्यटक आने का औसत परिशिष्ट ''अ'' पर वर्णित है।

(2) उक्त संग्रहालय में पर्यटकों की रुचि बढ़ाने के लिए गत 4 वर्षों में अनेक प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। स्कूलों से सम्पर्क कर विद्यार्थियों को संग्रहालय का अवलोकन करवाया गया। देशी-विदेशी पर्यटकों को इतिहास एवं संस्कृति के प्रति जागरुक करने के लिए विश्व विरासत दिवस, विश्व संग्रहालय दिवस, विश्व पर्यटन दिवस एवं राजस्थान दिवस पर संग्रहालय का नि:शुल्क भ्रमण करवाया गया। बजट घोषणा के तहत उक्त संग्रहालय में संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के कार्य करवाये गये, जिससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई।

(3) गत 4 वर्षों में संग्रहालय में कोई नवीन पुरातत्व महत्व की वस्तुऐं एवं कलाकृतियां अतिरिक्त रूप से संग्रहित नहीं की गयीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बामनवास में खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत

191. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कितने हैण्डपम्प किस-किस स्थान पर चालू हैं तथा किस-किस स्थान पर बंद पड़े हैं व कितने हैण्डपम्प नकारा हो चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में अधिकांश हैण्डपम्प खराब हो चुके हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या को देखते हुए नकारा हैण्डपम्पों के स्थान पर नये हैण्डपम्प लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बौंली एवं बामनवास की विभिन्न पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत दिनांक 14.02.2020 तक की स्थिति के अनुसार कुल स्थापित 3,649 हैण्डपम्पों में से 3,322 हैण्डपम्प क्रियाशील,

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

218 हैण्डपम्प नाकारा, 96 हैण्डपम्प सूखे एवं 13 हैण्डपम्प वर्तमान में मरम्मत योग्य खराब हैं। वांछित विवरण क्रमशः परिशिष्ट-''अ'', ''ब'', ''स'' एवं ''द'' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्तानुसार सूखे एवं नाकारा हैण्डपम्प स्थायी रूप से खराब होने के कारण इन्हें सुधारने का कार्य तकनीकी रूप से व्यवहारिक नहीं है। दिनांक 01.04.2019 से प्रारम्भ हुए 43वें विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के अन्तर्गत दिनांक 14.02.2020 तक उक्त क्षेत्र में मरम्मत योग्य खराब पाये गये कुल 1,028 हैण्डपम्पों में से 1,015 हैण्डपम्प मरम्मत उपरांत जल योजनाओं अन्तर्गत चालू कर दिये गये हैं तथा शेष रहे एवं समय-समय पर खराब होने वाले हैण्डपम्पों को उक्त अभियान में सतत प्रक्रिया के तहत सुधारने का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

(3) पेयजल की आवश्यकता, भूजल की उपलब्धता एवं गुणवत्ता तथा हैण्डपम्प निर्माण हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप इनका निर्माण सतत प्रक्रिया के तहत कराया जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र बामनवास में वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 (दिनांक 14.02.2020 तक) की अवधि में कुल स्वीकृत 104 नवीन हैण्डपम्पों के निर्माण के विरुद्ध 67 हैण्डपम्प निर्माण एवं स्थापना उपरांत चालू किये गये हैं एवं 13 हैण्डपम्पों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उक्तानुसार शेष रहे 24 हैण्डपम्पों में से 3 हैण्डपम्पों का निर्माण इनके चयनित स्थान तक रिग मशीन की पहुंच नहीं होने के कारण नहीं हो सका है। बजट घोषणा अन्तर्गत स्वीकृत एवं शेष रहे 21 हैण्डपम्पों के निर्माण हेतु माननीय विधायक, बामनवास के पत्र दिनांक 14.02.2020 द्वारा नवीन प्रस्तावित स्थानों की संशोधित सूची विभाग में दी गयी है।

इस प्रकार पूर्व में स्वीकृत हैण्डपम्पों के स्थान परिवर्तन किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तावों की पुन: संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर इनका निर्माण कार्य सम्पादित कराया जाना प्रस्तावित है।

वांछित विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शाहपुरा में ट्यूबवैल खोदने पर व्यय राशि

192. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

(1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा में वित्तीय वर्ष 2017-18 से दिसम्बर, 2019 तक कितने ट्यूबवैल व हैण्डपम्प किस-किस गांव व कस्बे में खोदे गये और प्रत्येक ट्यूबवैल व हैण्डपम्प पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी? वर्षवार व ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या खोदे गये सभी ट्यूबवैलों व हैण्डपम्पों में पानी की उपलब्धता होने पर चालू कर दिया गया या कम पानी व पानी की अनुपलब्धता के कारण बन्द कर दिया गया या अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र, शाहपुरा-बनेड़ा में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सामान्य एवं सुचारु बनाये रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 से माह दिसम्बर, 2019 की अवधि में नलकूपों (थ्री-फेज एवं सिंगल फेज) एवं हैण्डपम्पों के निर्माण हेतु जारी स्वीकृतियों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) दो संवर्धन/पुनर्गठित पेयजल योजनाओं अन्तर्गत अन्य कार्यों सहित 2 नवीन थ्री-फेज नलकूपों के निर्माण सहित योजनाओं हेतु राशि रुपये 164.38 लाख की जारी स्वीकृति के विरुद्ध, इन जल योजनाओं में प्रावधित 2 नलकूप निर्माण उपरान्त चालू किये जाकर इनसे पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है। इन योजनाओं पर रुपये 113.20 लाख की राशि का भुगतान माह जनवरी, 2020 तक किया गया है।

(ख) सौर ऊर्जा आधारित 18 सिंगल फेज बोरवेल के निर्माण एवं स्थापना कार्य हेतु राशि रुपये 144.75 लाख की जारी स्वीकृति के विरुद्ध, समस्त 18 बोरवेल निर्माण एवं सोलर पैनल की स्थापना उपरान्त चालू कर दिये गये हैं। इनके निर्माण एवं स्थापना कार्य पर रुपये 70.03 लाख की राशि का भुगतान माह जनवरी, 2020 तक किया गया है।

(ग) 128 नवीन हैण्डपम्पों के निर्माण हेतु राशि रुपये 94.72 लाख की जारी स्वीकृति के विरुद्ध 119 हैण्डपम्प निर्माण उपरान्त चालू कर दिये गये हैं एवं इनके निर्माण पर रुपये 76.59 लाख की राशि व्यय हुई है। शेष रहे 9 हैण्डपम्पों का निर्माण निर्धारित स्थान तक रिग मशीन की पहुंच नहीं होने एवं स्वीकृत स्थान पर पूर्व से ही हैण्डपम्प स्थापित होने के कारण नहीं हो सका है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उक्त नलूकपों, सौर ऊर्जा आधारित सिंगल फेज बोरवेल तथा हैण्डपम्पों की स्वीकृति एवं प्रगति सम्बन्धी पूर्ण विवरण क्रमश: परिशिष्ट ''अ'', ''ब'' एवं ''स'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त वर्णित जल योजनाओं अन्तर्गत भूजल की पर्याप्त उपलब्धता अनुरूप प्रावधित 2 नलकूप निर्माण उपरांत चालू किये जाकर इनसे पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है।

इसी प्रकार सौर ऊर्जा आधारित 18 सिंगल फेज बोरवेल एवं 119 हैण्डपम्प स्वीकृति अनुरूप निर्धारित स्थानों पर ही निर्मित किये गये हैं तथा विभिन्न जल योजनाओं के अन्तर्गत ये सिंगल फेज नलकूप एवं हैण्डपम्प वर्तमान में क्रियाशील अवस्था में हैं। विवरण संलग्न परिशिष्ट-''अ'', ''ब'' एवं ''स'' में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झालावाड़ सुपर पॉवर प्लांट में अनियमितता के प्रकरण

193. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में झालावाड़ सुपर थर्मल पावर प्लांट में कितने संवेदकों, फर्मों को कौन-कौनसे कार्य का ठेका दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत 5 वर्षों में इन संवेदकों, फर्मों को झालावाड़ थर्मल में प्रशासन द्वारा कितना-कितना भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत 5 वर्षों में झालावाड़ थर्मल पावर प्लांट की आडिट कब-कब की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विगत 5 वर्षों में झालावाड़ सुपर थर्मल पावर प्लांट में वित्तीय अनियमितता के कितने प्रकरण सामने आये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में झालावाड़ सुपर थर्मल पावर प्लांट में संवेदक/फर्मों/ठेकेदारों को दिये गये कार्य का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) विगत 5 वर्षों में संवेदकों/फर्मों/ठेकेदारों को थर्मल प्रशासन द्वारा किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) विगत 5 वर्षों में झालावाड़ थर्मल पावर प्लांट की आडिट रिपोर्ट का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

(4) विगत 5 वर्षों में झालावाड़ सुपर थर्मल पावर प्लांट में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता का एक प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसका विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झुंझुनूं नगर परिषद् को स्वच्छ भारत मिशन के तहत आबंटित राशि

194. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

नगर परिषद् झुंझुनूं को स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक कितनी राशि आबंटित कर कितने वाहन उपलब्ध करवाये गये हैं तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नगर परिषद् झुंझुनूं को स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत अब तक कुल 620.88 लाख रुपये आबंटित किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

व्यक्तिगत शौचालय हेतु अनुदान	153.36 लाख रुपये
सार्वजनिक शौचालय	8.83 लाख रुपये
सामुदायिक शौचालय	19.34 लाख रुपये
मूत्रालय निर्माण	5.70 लाख रुपये
ठोस कचरा प्रबन्धन कार्य हेतु	398.51 लाख रुपये
प्रचार प्रसार (IEC) हेतु	26.78 लाख रुपये
क्षमता संवर्धन हेतु	8.36 लाख रुपये
योग	**620.88 लाख रुपये**

नगर परिषद् झुंझुनूं द्वारा क्रय किये गये वाहनों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। वर्तमान में सभी वाहन चालू स्थिति में हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगर विकास न्यास में सेवानिवृत्त कार्मिकों को मेडिकल डायरी की सुविधा

195. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री संजय शर्मा)

(1) क्या प्रदेश में अन्य विभागों की तरह नगर विकास न्यास व प्राधिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के पश्चात् मेडिकल डायरी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त में कार्यरत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात उक्त सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश में अन्य विभागों की तरह नगर विकास न्यास/प्राधिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के बाद मेडिकल डायरी की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) उपरोक्तानुसार।

कोटा में नई एल.ई.डी. लाइटें लगाने वाली कम्पनी के विरुद्ध शिकायतें

196. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत छह वर्षों में कोटा शहर में पुरानी एवं खराब रोड लाइटों को बदलकर नई एलईडी रोड लाइटें लगाए जाने का तथा नवीन एल.ई.डी. रोड लाइटें लगाने के कार्य का अनुबंध नगर निगम एवं नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा किसी निजी एजेंसी से किया गया था? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कम्पनियों को कार्यादेश के तहत कितनी नई एल.ई.डी. लाइटें लगानी थीं तथा कितनी लाइटों को बदला जाना था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अनुबन्ध के तहत कम्पनी ने कितने स्थानों पर कितनी एल.ई.डी. लाईटें लगायीं तथा कितनी लाइटों को बदला? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार को उक्त अवधि में उक्त कम्पनी की कोई शिकायत प्राप्त हुई? यदि हां, तो क्या तथा उक्त शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा शहर में पुरानी व खराब रोड लाइटों को बदलकर नई एल.ई.डी. रोड लाइटें तथा नवीन एल.ई.डी. रोड लाईटें लगाने का अनुबंध नगर निगम कोटा द्वारा दिनांक 04.02.2015 व नगर विकास न्यास कोटा द्वारा दिनांक 12.05.2017 को भारत सरकार के उपक्रम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड दिल्ली के साथ किया गया। अनुबन्ध का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) नगर निगम सीमा क्षेत्र में 36,272 एल.ई.डी. लाइटें लगानी थीं, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा 36,879 लाइट्स लगाई गयीं। इनमें से 29,498 लाइटों को बदला गया तथा 7,381 लाइट्स नई लगाई गई।

नगर विकास न्यास सीमा क्षेत्र में कुल 16,500 एल.ई.डी. लाइटस लगानी थीं, जिसमें से 11,974 पुरानी लाइटों को बदला गया एवं 2,118 नयी एल.ई.डी. लाइट लगायी गयीं।

(3) उक्त अनुबन्ध के तहत नगर निगम कोटा क्षेत्र में 36,879 लाईटें 65 वार्डों में लगायी गयीं। जिनका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

नगर विकास न्यास कोटा क्षेत्र में उक्त अनुबंध के तहत 14,092 लाइटें लगायी गयी। जिसका विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(4) उक्त अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों एवं शिकायतों पर की गई कार्यवाही तथा लगायी गयी शास्ति का विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चित्तौड़गढ़ के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

197. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में कितने पशु चिकित्सालय किस-किस श्रेणी के कहां-कहां पर कब से संचालित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पशु चिकित्सालयों में कितने-कितने पद किस-किस श्रेणी के कब से सृजित हैं तथा उक्त पदों में से वर्तमान में कितने पद कब से किस कारण से रिक्त हैं? चिकित्सालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले के कई पशु चिकित्सालय प्रशासन की लापरवाही से बंद पड़े हैं, इस कारण जिले के पशुओं को उक्त चिकित्सालयों का लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो ऐसे कितने चिकित्सालय हैं, जो बंद पड़े हैं, एवं क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में स्वीकृत श्रेणीवार पशु चिकित्सालयों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जिला चित्तौड़गढ़ के पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

पशु चिकित्सालयों में पदों का सृजन संस्था के स्वीकृत/क्रमोन्नत होने के साथ ही किया जाता है।

(3) जी नहीं। जिला चित्तौड़गढ़ के श्रेणीवार कुल स्वीकृत 64 पशु चिकित्सालयों में से 7 पशु चिकित्सालय स्टाफ के अभाव में वर्तमान में अक्रियाशील हैं। जिन्हें नजदीक की पशु चिकित्सा संस्थाओं के माध्यम से आवश्यकतानुसार पशु चिकित्सा शिविर आयोजित कर विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मालपुरा की ग्राम पंचायतों में नन्दीशाला व कांजी हाउस की स्थापना

198. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उप खण्ड मालपुरा व टोडारायसिंह नगरपालिका व प्रत्येक ग्राम पंचायत में नन्दीशाला एवं कांजी हाउस खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। सरकार द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित बजट 2019-20 में आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नन्दीशालाएं स्थापित करने बाबत घोषणा की गयी है।

पचपदरा रिफाइनरी में कार्यरत कम्पनियां

199. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

पचपदरा रिफाइनरी की प्रमुख विशेषताऐं क्या हैं और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है एवं रिफाइनरी में कौन-कौनसी कम्पनियां कार्य कर रही हैं और अब तक उनके द्वारा कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है? उक्त

(श्री मदन प्रजापत)

कार्य को कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? कम्पनीवार, कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पचपदरा रिफाइनरी की प्रमुख विशेषताएं तथा वर्तमान में इसकी स्थिति परिशिष्ट ''1'' पर उपलब्ध है।

रिफाइनरी राज्य सरकार एवं भारत सरकार के उपक्रम एच.पी.सी.एल. की संयुक्त परियोजना है। अत: रिफाइनरी निर्माण हेतु एच.पी.सी.एल. राजस्थान रिफाइनरी लि. (एच.आर.आर.एल.) कम्पनी कार्यरत है। कम्पनी द्वारा रिफाइनरी निर्माण का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है तथा अक्टूबर, 2022 तक रिफाइनरी का मैकेनिकल वर्क पूरा करने का लक्ष्य है। रिफाइनरी कार्यों की प्रगति परिशिष्ट ''1'' में अंकित है। कम्पनीवार कार्यवार विवरण परिशिष्ट-''2'' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झालावाड़ में चयनित निर्धन परिवारों को वितरित राशन सामग्री

200. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में निर्धनता सीमा रेखा से नीचे के परिवारों को गेहूं, चावल, चीनी एवं अन्य वस्तुएं किस-किस मूल्य पर वितरित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) झालावाड़ जिले में वर्ष 2019 में प्रतिमाह निर्धन परिवारों को कितना गेहूं, चावल, चीनी एवं अन्य खाद्य वस्तुएं वितरित की गयी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में कितने चयनित निर्धन परिवार हैं एवं शेष कितने आवेदन लम्बित हैं? उक्त का निस्तारण कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में निर्धनता सीमा रेखा से नीचे के परिवारों को वितरित की जा रही राशन सामग्री की दर का विवरण निम्नत: है:-

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

वस्तु	दर
गेहूं (अन्त्योदय बी.पी.एल. स्टेट बी.पी.एल.)	1 रु. प्रति किग्रा
चीनी	24.50 रु. प्रति किग्रा
केरोसीन	38.80 रु. प्रति किग्रा

(2) झालावाड़ जिले में वर्ष 2019 में प्रतिमाह निर्धन परिवारों को वितरित की गयी राशन सामग्री का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है

(3) झालावाड़ जिले में माह दिसम्बर 2019 में खाद्य सुरक्षा योजना में 1,09,415 परिवार चयनित हैं जिले में 2,734 आवेदन लंबित हैं जिनका निस्तारण निर्धारित समयावधि में कर दिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ए.पी.एल. परिवारों को गेहूं का वितरण

201. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में बी.पी.एल. अन्त्योदय खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों को राशन का गेहूं दिया जा रहा है? यदि हां, तो प्रदेश में कितने प्रतिशत लोगों को राशन वितरित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में बी.पी.एल. के अलावा ए.पी.एल. परिवारों को भी राशन का गेहूं बढ़ी हुई दरों पर देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में माह जनवरी 2020 में भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के लिए स्वीकृत 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सीमा के विपरीत 97.98 प्रतिशत लोगों को राशन वितरित किया जा रहा है तथा राजस्थान राज्य की 2011 की जनसंख्या 6.86 करोड़ के विपरीत 63.70 प्रतिशत लोगों को राशन वितरित किया जा रहा है।

(2) विभागीय अधिसूचना दिनांक 27.09.2018 में उल्लेखित बी.पी.एल. के अलावा 31 समावेशन श्रेणियों के ए.पी.एल. परिवार, जो खाद्य सुरक्षा सूची में पात्र हैं, उन्हें 2 रु. प्रति किलो की दर से राशन का गेहूं दिया जा रहा है खाद्य सुरक्षा सूची में जो एपीएल परिवार शामिल नहीं हैं, उनको राशन का गेहूं देने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

कोटा में बसों पर कैरिज लगाने पर जुर्माना

202. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा में कितनी बसें कैरिज लगी हुई संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये आदेश दिये गये हैं कि बसों पर कैरिज नहीं हो? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त आदेशों की पालना करवाई जा रही है?

(3) क्या कैरिज लगाने पर जुर्माने का प्रावधान है? यदि हां, तो विगत एक वर्ष में कितना जुर्माना वसूला गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मंजिली गाड़ी (Stage Carriages) के ऊपर यात्री के सामान की सुरक्षा के लिए बस की छत पर कैरिज लगाये जाने का प्रावधान है परन्तु ठेका गाड़ी (Contract Carriages) की छत पर कैरिज लगाने का प्रावधान नहीं है। उक्त प्रावधानों के अनुसार कोटा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 48 वाहनों की छत पर नियमान्तर्गत कैरिज लगाया हुआ है। नियम विरुद्ध छत पर कैरिज लगाये जाने पर समय-समय पर अवैध संचालित यात्री वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही के दौरान कोटा रीजन में 62 बसें कैरिज लगाकर संचालित होती पायी गयीं, जिनके मौके पर ही चालान किये गये।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। कान्ट्रेक्ट कैरिज बसों पर कैरिज लगाया जाना परमिट शर्तों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार के अपराध के लिए आर.टी.ए. रिजोल्यूशन संख्या 01/2017/27313, दिनांक 12.01.2017 के तहत जुर्माना निर्धारित किया गया है। प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

इस वित्तीय वर्ष में बसों की छत पर व्यवसायिक सामान के परिवहन करने पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	जिला	चालानों की संख्या	प्रशमन राशि (लाखों में)
1	कोटा	25	2.50
2	बूंदी	12	0.60
3	झालावाड़	5	0.30

(परिवहन मंत्री)

क्र.सं.	**जिला**	**चालानों की संख्या**	**प्रशमन राशि (लाखों में)**
4	बारां	14	1.40
5	रामगंज मण्डी	6	0.60
योग		**62**	**5.40**

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बूंदी से वाया नैनवा घाड होकर जयपुर के लिए रोडवेज बस का पुनर्संचालन

203. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि बूंदी से वाया नैनवा घाड होकर जयपुर की राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस के संचालन को बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? उक्त बस बंद करने का क्या कारण रहा, जबकि उक्त रास्ते पर हमेशा यात्रियों की संख्या ज्यादा है? क्या सरकार उक्त बस को पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राजस्थान परिवहन निगम की बूंदी से जयपुर वाया नैनवा घाड वाहन का अक्टूबर, 2017 से मार्च, 2019 तक संचालन किया गया जिसका आय/यात्रीभार का विवरण परिशिष्ट ''1" पर संलग्न है। सीमित संसाधनों के कारण उक्त वाहन का संचालन बंद कर दिया गया।

वर्तमान में निगम के सीमित संसाधनों के कारण उक्त बस को पुन: प्रारम्भ करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विद्यालयों के नामकरण के मानदण्ड

204. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नामकरण के आधार क्या हैं तथा सरकार द्वारा इस हेतु क्या मानदण्ड बनाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मानदण्डों की पालना हो रही है? यदि हां, तो किस प्रकार से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र महुवा में उक्त मानदण्डों की पूर्ण पालना नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों व किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नामकरण के आधार एवं मानदण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र/आदेश परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी हां। विद्यालयों के नामकरण हेतु उक्त परिपत्र/आदेशों के अनुसार नामकरण संबंधी कार्यवाही की जाती है।

(3) जी नहीं।

(परिपत्र पुस्तकालय में रखा गया)

टोडाभीम (करौली) के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्यों के पेंशन प्रकरण का निस्तारण

205. श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, टोडाभीम, जिला करौली में वर्ष 1993 से 1998 के मध्य प्रधानाचार्य के पद पर किन-किनका कब-कब पदस्थापन रहा? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालय में उक्त अवधि में कौन-कौन प्रधानाचार्य कब-कब, किस-किस आधार पर सेवानिवृत्त किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सभी प्रधानाचार्यों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया? यदि हां, तो किन-किन का व कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त लम्बित पेंशन प्रकरणों का निस्तारण कब तक कर दिया जाएगा तथा क्या सरकार समय पर निस्तारण नहीं करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, टोडाभीम, जिला सवाई माधोपुर, वर्तमान जिला करौली में वर्ष 1993 से 1998 के मध्य संस्था-प्रधान के पद पर निम्नांकित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य कार्यरत रहे हैं:-

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

नाम संस्था प्रधान	**पदनाम**	**कब से**	**कब तक**
उर्मिला गुर्जर	प्रधानाध्यापक	01.01.93	06.07.94
सज्जन कटारा	प्रधानाचार्य	07.07.94	02.01.95
किरण पाटनी	प्रधानाचार्य	15.09.95	03.03.96
मनोहर शर्मा	प्रधानाचार्य	04.07.97	07.08.98

(2) उक्त विद्यालय में वर्ष 1993 से 1998 के मध्य कोई भी प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त नहीं हुआ है।

(3) उक्त में से कोई भी प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त नहीं होने के कारण किसी का पेंशन प्रकरण शेष नहीं है।

(4) प्रश्नोत्तर के खण्ड संख्या 2 व 3 के अनुसार।

भादरा के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति

206. श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र भादरा में ऐसे कितने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें सौ से अधिक नामांकन होने के उपरान्त भी शारीरिक शिक्षक ग्रेड-तृतीय के पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र भादरा में कुल रा.उ.प्रा.वि. की संख्या 76 है। विभाग द्वारा स्टाफिंग पैटर्न हेतु जारी दिशा-निर्देश, दिनांक 21.04.2016 के अनुसार रा.उ.प्रा.वि. में 120 से अधिक नामांकन पर शारीरिक शिक्षक का पद आबंटित किया गया था। वर्तमान में स्टाफिंग पैटर्न हेतु जारी दिशा-निर्देश, दिनांक 28.05.2019 के अनुसार पूर्व सत्र के अंतिम नामांकन को आधार मानकर 105 से अधिक नामाकंन वाले विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक का पद आबंटित किया गया है। विधान सभा क्षेत्र भादरा में शारीरिक शिक्षक ग्रेड-तृतीय के रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण निम्नानुसार है:-

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

क्र. सं.	**विद्यालय का नाम**	**विद्यालय में नामांकन (सत्र 2019-20)**	**शारीरिक शिक्षक ग्रेड-3**		
			स्वीकृत पद	**कार्यरत**	**रिक्त**
1	रा.उ.प्रा.वि., शेरडा	110	1	0	1
2	रा.उ.प्रा.वि., रामबास	121	1	0	1
3	रा.उ.प्रा.वि., घोटडा पट्टा	123	1	0	1